निर्धनता और आज़ादी

वैश्विक आर्थिक विकास का विषय अवलोकन

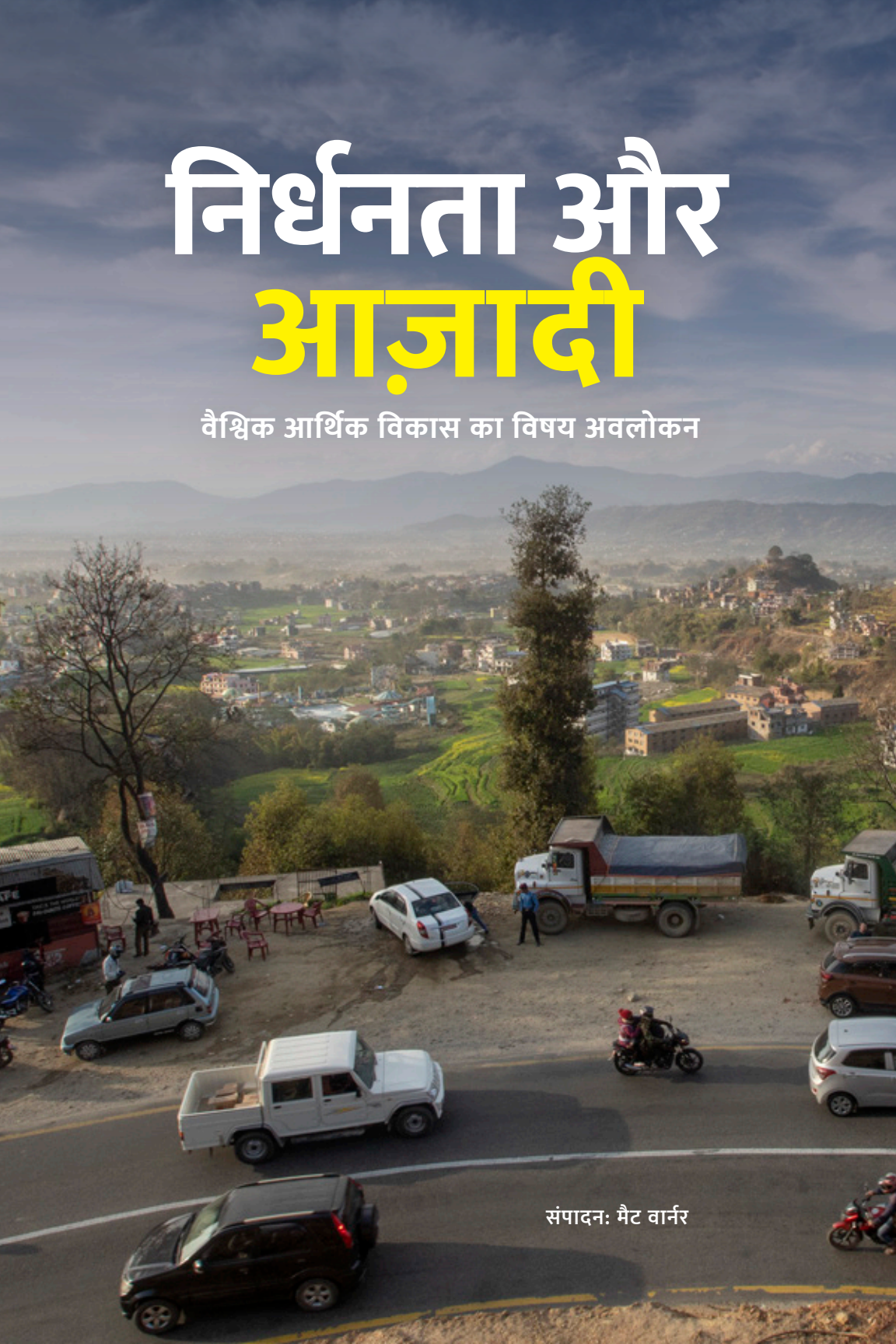

संपादन: मैट वार्नर

निर्धनता और आज़ादी

वैश्विक आर्थिक विकास का विषय अवलोकन

मैट वार्नर द्वारा संपादित

PovertyandFreedom.org

निर्धनता और आज़ादीः वैश्विक आर्थिक विकास का विषय अवलोकन
कॉपी राइट : एटलस नेटवर्क 2019

सर्वाधिकार सुरक्षित
मूल प्रकाशनः संयुक्त राज्य अमेरिका

संपादनः मैट वार्नर
सह-संपादनः मेलिस्सा मन्न, केसी पिफर और ए.जे. स्कियेरा
संपादन और रचनात्मक सहयोगः डेविड लैम्पो
आवरण चित्रः बरनाट परेरा
आवरण सज्जाः किलस्विच कलेक्टिव के मेरेडिथ रेसॉफ्ट

आइएसबीएनः
ईबुक आइएसबीएनः

एटलस नेटवर्क
टू लिबर्टी सेंटर
7075 विल्सन बुलेवर्ड
सुइट 310
अर्लिंगटन, वर्जिनिया 22203

www.atlasnetwork.org

‘आमतौर पर दुनिया में कोई व्यक्ति ग़रीब नहीं होता है। ये लोग हैं जो ग़रीब स्थानों पर रहते हैं।’

— लेंट प्रिचेट, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी

‘आधुनिकता का रहस्य यह है कि हम सभी के पास व्यक्तिगत तौर पर थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है जबकि सामूहिक रूप से हम सभी विशाल ज्ञान संपदा का उपयोग करते हैं।’

— रिकॉर्डो हॉसमैन, दि एटलस ऑफ इकोनोमिक कम्प्लेक्सिटी

‘संपदा ज्ञान है और इसकी उत्पत्ति क्रमिक विकास से हुई है।’

— एरिक बेनहॉकर, दि ऑरिजन ऑफ वेल्थ

‘भले ही वैश्विक कल्याण का एक संकुचित, सरल, यंत्रवत्, न्यूनतावादी रूप हमारी विरासत हो, लेकिन आवश्यक नहीं कि यही हमारा मुकद्दर हो।’

— बेन रामालिंगम, एड ऑन द एज ऑफ केऑस

आभारोक्ति

एटलस नेटवर्क टीम, उदार सहयोग के लिए जॉन टेंपल्टन फ़ाउंडेशन और स्मिथ फैमिली फ़ाउंडेशन का आभार व्यक्त करती है, जिससे यह प्रकाशन संभव हुआ। इस पुस्तक में वर्णित सफलताओं के लिए हम अपने नेटवर्क के उन सभी स्वतंत्र थिंक टैंक्स का भी आभार व्यक्त करते हैं जिनकी दूरदृष्टी, नेतृत्व तथा नवाचार युक्त कार्य इस पुस्तक के मुख्य आकर्षण हैं। इस प्रकाशन का मूल उद्देश्य आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देकर निर्धनता उन्मूलन के लिए कार्यरत विश्व भर के नेतृत्वकर्ताओं के एक मजबूत नेटवर्क को प्रोत्साहित करना, उनके कार्यों को प्रकाशित करना और नवाचार युक्त विचारों को प्रसारित करना है।

एटलस नेटवर्क इसके अलावा चिप बिशप, हिलेरी गॉविंस और अन्य स्वतंत्र योगदान करने वालों का भी आभार व्यक्त करता है, जिनकी मदद से विषय अवलोकन के लिए सामग्री तैयार हो पायी।

विषय सूची

परिचय : निर्धनता को लेकर नया नज़रिया
मैट वार्नर 10

खंड 1: वाह्य घटकों वाली दुविधा 22

वाह्य घटकों की दुविधा से उबरना : क्या परोपकारी लोग विकासशील देशों को लाभ पहुंचा सकते हैं
मैट वार्नर 24

उत्पादक ज्ञान को प्रोत्साहन : ऐड सुधारकों का वाह्य घटकों वाली दुविधा से सामना
मैट वर्नर 33

खंड 2: थिंक टैंकों का प्रभाव और उनका माप 48

लक्ष्य निर्धारित करना : थिंक टैंक की सफलता का मूल्यांकन
मैट वार्नर 50

विस्तृत कार्य क्षेत्र का निर्धारणः थिंकटैंकों के नेतृत्व के लिए वैश्विक नेटवर्क
मैट वार्नर 54

खंड 3संपत्ति के अधिकार का विषय अवलोकन 60

सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग का विरोध
इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस,यूनाइटेड स्टेट 62

रंगभेद के शिकार लोगों के लिए स्वामित्व बहाल करना
फ्री मार्केट फाउंडेशन दक्षिण अफ्रीका 73

छोटे किसानों के भूमि के अधिकारों की बहाली
ईजी बिजनेस यूक्रेन 81

खंड 4: व्यापार और व्यवसायिक लाइसेंस की आवश्यकता का विषय अवलोकन 88

कम आय वाली जनसंख्या के लिए वैध बाजार को खोलनासेंटर फॉर डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज़ेज़ ग्रेट लेक्सबुरुंडी *90*

जेल से रिहाई के बाद आर्थिक अवसर
जॉर्जिया सेंटर फॉर ऑपर्च्युनिटीसंयुक्त राज्य अमेरिका *97*

समावेशी समृद्धि हासिल करना
सेंटर फॉर सिविल सोसायटी भारत *107*

खंड 5 निजीकरण का विषय अवलोकन 118

भरोसेमंद बिजली तक पहुंच का विस्तार
लेबनीज़ इंस्टीट्यूट फॉर मार्केट स्टडीज़ लेबनान *120*

सबके लिए शुद्ध पेयजल
एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू पेरू *127*

खंड 6 अनुचित कर के बोझ का विषय अवलोकन 138

महिलाओं के राह की बाधाओं को दूर करना
एडवोकाटा इंस्टिट्यूट श्रीलंका *140*

प्रतिगामी कर प्रणाली की वापसी
लिपा टैक्सपेयर्स एसोसिएशन, क्रोएशिया क्रोएशिया *145*

खंड 7 आर्थिक स्वतंत्रता के लेखा परीक्षण का विषय अवलोकन 152

संकट के दौर से उबरना
फाउंडेसियन लिबरटेड वाई प्रोग्रेसो, (एलवाईपी) अर्जेंटीना *155*

आज़ादी को पुनर्परिभाषित करना
सेंटरो डी डाइवुलजेसियन डेल कोनोसिमेंटो इकोनोमिको पैरा ला लिबरटेड (सीईडीआईसीई), वेनेजुएला..... *166*

आशा की किरण
इजिप्टियन सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीज़ (ईसीपीपीएस) इजिप्ट..... *178*

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें 188

एटलस नेटवर्क के बारे में 191

अधिक जानें..... 194

परिचय :
निर्धनता को लेकर नया नज़रिया

मैट वार्नर

सन् 1800 के दौर में संयुक्त राज्य अमेरिका के वानिकी विभाग ने जंगलों में लगने वाली आग को लेकर बेहद सख़्त नीति का अनुसरण करना शुरु किया। उनका मानना था कि प्राकृतिक संसाधनों के बेहतर देखभाल का मतलब प्रत्येक चीज को आग से जलने से बचाना है। हमने चूंकि सीखा है कि जंगल में लगने वाली छोटी-छोटी आग की घटनायें वास्तव में, बड़े और विनाशकारी अग्निकांडों से बचाव करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं क्योंकि इससे सूखी और पुरानी पैदावार को प्रबंधकीय तरीके से समाप्त किया जा सकता है। लेकिन वानिकी विभाग द्वारा आग की छोटी छोटी घटनाओं पर नियंत्रण लगाने जैसे कार्यों ने उनके वास्तविक उद्देश्यों के विपरीत परिणाम दिया। इससे जंगलों में बड़े अग्निकांड की घटनाओं के अधिक खतरे पैदा हो गये।।**[1]**

जब हस्तक्षेप के द्वारा बेहतर करने की बात आती है तो इस प्रकार के एक रेखीय प्रयासों का प्रतिरोध करना कठिन हो जाता है। यह वैसा ही है जैसे कि यह सोचना कि धन और विशेषज्ञता का एक स्थान से दूसरे स्थान पर हस्तांतरण कर निर्धनता को समाप्त किया जा सकता है। कुछ क्षेत्र शिक्षित और समृद्ध हैं। कुछ क्षेत्र शिक्षित और समृद्ध नहीं हैं। ऐसे में निर्धनता दूर करने के लिए एक क्षेत्र से लेकर दूसरे क्षेत्र को हस्तांतरित कर दीजिए। यह एक सादगी युक्त विचारधारा है और हमारे नैतिक दायित्यबोध को प्रभावित करती है। लेकिन यह मूर्खतापूर्ण ढंग से उस पारिस्थितिकीय तंत्र की जटीलता को कमतर कर आंकना है जो कालांतर में गरीबी को बढ़ाने का कारक ही बनती है।**[2]**

---

1. Ben Ramalingam, Aid on the Edge of Chaos, (Oxford: Oxford University Press, 2013), 207–10.

2. Note that for this volume the notion of ending poverty or reducing poverty refers to the achievement of sustained economic progress for

इस सोच के चलते ग़रीब क्षेत्रों के स्थाई गरीबी बने रहने के खतरे बढ़ जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे जंगल की छोटी आग से नई वृद्धि की संभावनाओं को विस्तार मिलता है। इसी तरह, मुक्त अर्थव्यवस्था समुदायों को सतत दीर्घकालीन विकास की ओर उन्मुख करती है। इस पुनरावृत्तीय प्रक्रिया से गुजरने के कारण वे अनर्थकारी घटनाओं के आसान शिकार नहीं बनते हैं।

इन जटिलताओं के मद्देनज़र, परिस्थितियों को विकट बनाये बिना बाहर से उनकी मदद कैसे की जाए, यह एक चुनौती होती है। हम उनकी मदद के लिए क्या कर सकते हैं?

हमारी भूमिका पर पुनर्विचार

मॉरिसिओ मिलर को गरीबी के बाबत उनके मौलिक पुनर्विचार वाली अवधारणा के लिए वर्ष 2012 में मैक ऑर्थर जीनियस ग्रांट प्रदान किया गया। इस अवधारणा के क्रियान्वयन के लिए उन्होंने 35 वर्ष तक ऑकलैंड व कैलिफ़ोर्निया में कम आय वर्ग के लोगों के लिए परंपरागत स्थानांतरण आधारित सहायता प्रारूप के तहत तब तक कार्य किया, जब तक उन्हें अपनी गलती का अहसास नहीं हो गया। उनके स्वयं के शब्दों में 'गरीबी के प्रति हममें से अधिकांश की सोच गलत है।[3]

अपनी हालिया पुस्तक में वे लिखते हैं, 'लोकोपकार की सरकारी व निजी संस्थाओं की बातें और योजनाएं अच्छी नजर आती हैं, लेकिन... वे कभी इस बात को स्वीकार ही नहीं करते हैं कि उनके शीर्ष से नीचे (टॉप-डाऊन) मॉडल वाले समाधान से निर्धनता दूर नहीं हो सकती है। और ना ही आर्थिक गतिशीलता का सृजन हो सकता है।[4]

मिलर के अनुसार, बतौर वाह्य घटक हम अतिरेक कर जाते हैं और यह हमारी बड़ी भूल होती है। हम इस भ्रम में रहते हैं कि अपने ज्ञान और संसाधनों के बूते हम दूसरों की दीर्घकालीन आर्थिक समस्याओं को दूर कर पाएंगे। और इसलिए अच्छी नीयत के बावजूद हम उनके मामलों में नेताओं की बहुत अधिक भूमिका मानने लगते हैं।

मिलर के अनुसार मानवीय गरिमा को अधिक गंभीरता से न लेने की प्रवृत्ति ही हमारी विफलता का मूल कारण है। ग़रीब लोगों को अपना पीड़ित या अपनी ज़िम्मेदारी मानना

---

populations of people and is distinct from and not to be conflated with the notion of temporary poverty relief.

3. Mauricio Miller, The Alternative: Most of What You Think About Poverty Is Wrong, (Lulu Publishing Services, 2017), 56.

4. Mauricio Miller, The Alternative: Most of What You Think About Poverty Is Wrong, (Lulu Publishing Services, 2017), 56.

और रक्षा के लिए खुद पर निर्भर मानना हमारी विफलता है। उनका मुख्य संदेश है कि ये लोग हमारे समान हैं और अपना जीवन सुधारने के लिए नेतृत्व करने के अधिकारी भी वहीं हैं न कि उनकी मदद करने वाले बाहरी लोग।

मिलर के अनुसार स्वाग्रह कोई सिद्ध औषधि नहीं है। उन्होंने स्वयं व अपनी टीम की गरीबी उन्मूलन की सोच में व्यापक सुधार किया। बजाय कि अपने आश्रित को नि:शुल्क सेवा उपलब्ध कराने के, उन्होंने उन्हें व्यक्तिगत प्रयासों से आगे बढ़ने की राह दिखाई। उन्होंने स्वयं और कर्मचारियों का वहां हस्तक्षेप करने से रोका, जहां उन्हें लगा कि वे इस बारे में बेहतर जानते हैं। दरअसल, उन्होंने अपने स्टाफ के लिए एक नियम बना दिया था कि यदि उन्होंने कम आय वर्ग के मुवक्किलों की मदद की तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा।

मिलर ने गरीबी उन्मूलन के लिए सर्वोत्तम समाधान तलाशा, जो व्यक्ति विशेष के प्रति खास और संवेदनशील धारणा को बल देता है। जो कि सामाजिक-आर्थिक परिदृश्य की जटिलताओं और आदर्शों से इतर था। इसके मायने थे कि उनका ज्ञान और अवधारणाएं उन्हें सक्षम बना सकती है। उनके अपने जीवन मूल्य व निर्णय ही समृद्ध जीवन के लिए मार्गदर्शक बन सकते हैं। उन्हें सफलता के लिए बेहतर अवसर देने के लिए उनका सुझाव था कि हमें इस बात पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए कि गरीबी में रहने वाले लोगों की हम क्या मदद कर सकते हैं। साथ ही उनके व्यक्तिगत और आर्थिक अवसरों में क्रियान्वन एजेंसी की भूमिका को कितना सीमित कर सकते हैं।

ऑक्सफॉम विशेषज्ञ डंकन ग्रीन अपनी पुस्तक 'हाउ चेंज हैपन' में चयन करने के विकल्प वाले परिदृश्य में अनुकूल वातावरण हेतु व्यक्तिगत प्रयासों की संभावनाओं पर प्रकाश डालते हैं। वे इस बात पर बल देते हैं कि गरीबी में रहने वाले लोगों को स्वावलंबी बनाने के प्रयासों के केंद्र में उन्हीं के प्रयास हो न कि हमारे। [5]

एजेंसी के अधिकार, नेटवर्क और 'सकारात्मक विचलन'

निजी प्रयासों की सराहना करने वाले की सभी दृष्टिकोणों की आलोचना आमतौर पर यह कहकर होती है कि कोई भी व्यक्ति पूर्णतया अपने आप सफल नहीं हो सकता है। व्यक्ति कोई द्वीप नहीं है। इसलिये जो लोग ग़रीब है उनसे अपनी समस्याओं के स्वयं समाधान ढूंढने की उम्मीद गलत होगी। 'बूटस्ट्रैप मिथ' [6] - जिसके बारे में बहुत कुछ कहा और

5. Duncan Green, How Change Happens, (New York: Oxford University Press, 2016), 82.

6. For just one example, see http://ideas.time.com/2012/09/07/the-myth-of-bootstrapping/.

लिखा जा चुका है- उस विचार की आलोचना करता है जिसके अनुसार सभी निम्न आय वर्ग के लोगों को गरीबी के दुश्चक्र से बाहर निकलने के लिए अपने बूटस्ट्रैप (जूते के फीते को बांधने में सहायक चमड़े का टुकड़ा) को खुद खींचना होगा और अपनी समस्याओं का समाधान खुद करना होगा। नि:संदेह, एक समृद्ध समुदाय में सामाजिक नेटवर्क और सामाजिक पूंजी, निजी सफलता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसलिये, वास्तव में, गरीब लोगों की सहायता के दौरान इस तथ्य की अनदेखी करना गलती होगी।

हालांकि, मिलर ने निर्धनता उन्मूलन की प्रक्रिया में व्यक्तिगत प्रयासों और सामाजिक पूंजी की अलग अलग भूमिका के मिलन बिंदु के बीच बारीक फर्क को तलाशा है। उन्होंने पाया कि जब गरीब इलाकों में लोगों की मदद करते हैं तो फर्क इस बात पर निर्भर करता है कि वे किन पर भरोसा करते हैं तथा उनकी सामाजिक संरचना की प्रकृति क्या है। मिलर ने महसूस किया कि वे और उसकी टीम ने वास्तव में कम आय वर्ग के लोगों के बीच सामाजिक जुड़ाव के घटक को कमतर आंका और सामाजिक सेवा एजेंसी और बाह्य पेशेवर विशेषज्ञों की भूमिका को अधिमान दिया। यही वजह है कि यह निर्भरता की दृष्टि कारगर साबित नहीं हो रही थी तथा बेहतर विकल्पों को क्षति पहुंचा रही थी।

दरअसल, उन्होंने जो नई दृष्टि अपनायी, उसके अग्रदूत जैरी व मानिक्यू स्टेरनिन्स थे। उन्होंने नब्बे के दशक में इसका उपयोग तब किया जब वे वियतनाम में गैर-लाभकारी संस्था 'सेव द चिल्ड्रन' के तत्त्वावधान में कुपोषित शिशुओं की समस्या पर काम कर रहे थे। उन्होंने अपनी पुस्तक 'द पॉवर ऑफ पॉजिटिव डिवियंस : हाउ अनलाइकली इनोवेटर्स सॉल्व द वर्ल्ड्स टफेस्ट प्रॉब्लम्स' में स्टेरनिन्स ने स्पष्ट किया कि सामाजिक समस्याओं पर काम करते वक्त सबसे बड़ी विसंगति यह है कि हम यह नहीं स्वीकारते कि स्थानीय स्तर पर समस्या के समाधान के विकल्प विद्यमान हैं।**[7]**

वियतनाम में, स्टेरनिन्स ने यह खोजबीन करने का निर्णय किया कि कम आय वर्ग के कुछ परिवारों के शिशुओं में कुपोषण की समस्या मौजूद नहीं थी जबकि वे भी संसाधनों की उतनी ही किल्लत झेल रहे थे, जितने कि उनके पड़ोसी। उन्होंने स्वस्थ परिवारों की विशिष्ट आदतों का अवलोकन किया और पाया कि वे अपने शिशुओं को नियमित रूप से उन चीजों का सेवन करा रहे थे जो आमतौर पर प्रचलित नहीं थे।

महत्वपूर्ण बात यह है कि स्टेरनिन्स ने खुद को एक नये विशेषज्ञ के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया और न ही उस पद्धति को 'श्रेष्ठ उपाय' बताते हुए वहां की बाकी जनता को भी उस पद्धति को अपनाने का पाठ पढ़ाया। ग्रीन परंपरागत इस पद्धति के विराम के महत्व पर

7. Richard Pascale, Jerry Sternin, and Monique Sternin, The Power of Positive Deviance: How Unlikely Innovators Solve the World's Toughest Problems, (Cambridge: Harvard University Press, 2010).

जोर देते हुए चेताते हैं कि, यदि वाह्य विशेषज्ञों के द्वारा इसकी जांच कर उसके परिणामों को टूलकिट के तौर पर तैयार किया जाता है तो इस पद्धति का बहुत थोड़ा सा पहलू ही बाहर आ सकेगा। लेकिन जब समुदाय द्वारा स्वयं इसकी खोज की जाएगी तो उनमें व्यवहारिक परिवर्तन शुरु होगा। इस प्रक्रिया को स्टेरनिन्स ने सामाजिक प्रमाण की संज्ञा दी। [8]

इस पड़ताल को अमलीजामा पहनाने के लिए स्टेरनिन्स ने स्वाभाविक उपायों के तौर पर कुपोषण की समस्या से जूझते परिवारों को स्वस्थ परिवारों के साथ भोजन तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया। ऐसा करके उन्होंने सामाजिक संबंधों में प्रगाढ़ता को बढ़ावा दिया। इन प्रयासों की सार्थक परिणति सामने आई। इसके चलते 22 लाख लोगों की जनसंख्या में कुपोषण के मामले में 65 से 80 प्रतिशत की महत्वपूर्ण गिरावट आई। इसी तरह वियतनामी परिवारों ने अपनी कई समस्याओं का समाधान तलाशा। इस तरह सिस्टम के भीतर किसी ने कहीं से एक व्यवहारिक समाधान ढूंढ निकाला। उस समाधान की उपयुक्तता ने इसकी प्राकृतिक प्रतिकृति को बढ़ावा दिया।

क्रमिक विकास, स्थानीय ज्ञान और आर्थिक आज़ादी

आपको यह क्रमिक विकास के जैसा तो प्रतीत नहीं हो रहा, जी हां। अर्थव्यवस्थाओं और सामाजिक नेटवर्क में अध्ययन के लिए स्कॉलरों ने क्रमिक विकास की अवधारणाओं का सहारा लिया। वास्तव में ऑक्सफोर्ड के अर्थ शास्त्री एरिक बेनहॉकर की व्याख्या के अनुसार धन- जो कि किसी भी गरीबी उन्मूलन रणनीति का लक्ष्य होता है- अवश्यंभावी रूप से क्रमिक विकास की प्रक्रिया के प्रतिफल के रूप में हासिल होना चाहिए। [9]

निम्न आय वाले क्षेत्रों में आर्थिक प्रगति के लिए आवश्यक क्रमिक विकास की प्रक्रिया की राह में असहयोग और हेराफेरी के प्रयासों या केंद्रीयकृत तरीके से बनावट आदि जैसी बाधाएं हैं। क्रमिक विकासपरक चिंतक डेनियल डेनेट के मुताबिक, क्रमिक विकास खोजने की वह प्रणाली (एल्गोरिद्म) है जो संभावनाओं की सूखी घांस की ढेर में से अच्छे प्रकार की सूई को ढूंढ निकालती है। [10] एक स्वस्थ बाजार की तरह क्रमिक विकास के प्रारूप को कोई डिजाइनर तैयार नहीं करता है। ऐसे में प्रगति के लिए अपनायी जाने वाली प्रक्रिया

8. Duncan Green, How Change Happens, (Oxford University Press, 2016), 25.

9. Eric Beinhocker, The Origins of Wealth: The Radical Remaking of Economics, (New York: Random House Business, 2007), 19, 318.

10. Beinhocker, The Origins of Wealth, 14.

एक ऐसी अनियोजित व प्रायोगिक प्रक्रिया बन जाती है, जिसमें बड़ी संख्या में व्यक्ति आपस में जुड़े रहते हैं।

वाह्य हस्तक्षेप वाली दुविधा का समाधान

ऐसे लोग जो गरीबी से प्रभावित इलाकों में आर्थिक आज़ादी को बढ़ावा देने की वकालत करते हैं, उनके कार्यों का सत्यापन मिलर, ग्रीन और स्टरनीन जैसे विचारकों के कार्यों के आधार पर किया जा सकता है, जिनके अनुसार व्यक्तिगत एजेंसी से विकेंद्रीकरण को बढ़ावा मिलता है और यहां तक कि सीमित सरकार वाली व्यवस्था को भी मजबूती प्राप्त होती है। यह स्पष्ट नहीं है कि वे इस कार्य को उसी नज़रिये से देखते हैं या नहीं लेकिन इतना अवश्य स्पष्ट है कि विचारशील और अनुभवी सहायकों, गरीबी और आर्थिक विकास मामलों के विशेषज्ञों के बीच बाहरी लोगों को यह चेताने पर सहमति बनती जा रही है कि वे लोगों पर विशेषकर ऐसे लोगों पर अपनी राय व विचार थोपने की कोशिश न करें जिनको हमारे कारण परेशानियों में पड़ने की संभावना अधिक हो। यह सोच वाह्य घटकों की भूमिका की दुविधा को ही उजागर करती है, जो यह बताती है कि वाह्य हस्तक्षेप करके हम ऐसी गलती न करें, जो भला करने के बजाय उनका नुकसान कर दे।

एटलस नेटवर्क एक ऐसी सर्वमान्य सहमति को विकसित होता देखना चाहता है, जिससे इस भ्रम के उन्मूलन हेतु उदार सिद्धांतों का निरूपण हो सके, जो वैचारिक विविधता को उच्चता प्रदान करते हुए—'विशिष्टता से विकास [11] को स्थापित करे। इन सिद्धांतों का उल्लेख इस प्रस्तावना और उनका विस्तार I और II खंडों में इस पुस्तक में उल्लेखित हैं। इन सिद्धांतों की क्रियाविधि का अनुपयोग का विवरण खंड III से खंड VII है, जिसमें विभिन्न देशों की केस स्टडी विस्तृत विवरण शामिल है, जिसमें अमेरिका भी शामिल है।' हमें विश्वास है कि यह पुस्तक 'वाह्य हस्तक्षेप की दुविधा' का संभव व सारभूत तथा प्रोत्साहक घटनाक्रम के साथ विश्वव्यापी गरीबी उन्मूलन में सहायक भूमिका निभाएगी। ये आधारभूत सिद्धांत हैं :

पहला सिद्धांत # यह सुनिश्चित हो कि वाह्य घटकों की स्थानीय परिवर्तन में नेतृत्वकारी भूमिका न हो और इस बात को स्वीकृति दे कि जब बात व्यक्तिगत एजेंसी और विकल्प की हो तो सरकारें, यहां तक कि स्थानीय सरकारों का व्यवहार भी बाहरियों के जैसा ही हो।

11. https://www.odi.org/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/events-documents/5149.pdf.

दरअसल, इस बात की प्रबल संभावना होती है कि वाह्य हस्तक्षेप का बहुत थोड़ा सा प्रभाव भी स्थानीय समाधान के क्रमिक विकास को विकृत कर दे। इसी कारणवश, वर्ष 2005 में 161 देशों के व्यापक सहायता समूहों ने 'पेरिस डिक्लेरेशन ऑन ऐड इफेक्टिवनेस' नामक समझौते के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय सहायता के लिए दिए जाने वाले डॉलर्स पर रोक लगाने का प्रयास किया था। **[12]**

बहरहाल, बावजूद अच्छी सोच के समझौता विफल रहा क्योंकि दान देने वाले और दान लेने वाले देशों की सरकारों ने अपने राजनीतिक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए विकास के लक्ष्यों को जटिल बना दिया। सरकारें, यहां तक कि स्थानीय सरकारों ने भी वाह्य हस्तक्षेपकारी भूमिका में आर्थिक परिवेश को बाधित करना जारी रखा।

एक अमेरिकी-नाइजेरियन पत्रकार डायो ओलोपाडे, जो यह बेहतर ढंग से जानती हैं कि ऐसी मदद से किस प्रकार इस क्षेत्र का नुकसान हुआ, अपनी पुस्तक 'दि ब्राइट कंटिनेंट : ब्रेकिंग रूल्स एंड मेकिंग चेंज इन मॉर्डन अफ्रीका', में लिखती है 'विश्व में लंबे समय से सबसे बड़ी समस्या यह रही है कि अफ्रीका के विकास हेतु सरकारों और औपचारिक संस्थानों के मध्य पारस्परिक क्रिया को प्राथमिकता मिली है, जबकि उदयीमान, विश्वसनीय और आर्थिक दृष्टि से महत्वपूर्ण पारंपरिक क्रिया व्यक्ति विशेष और विकेंद्रीयकृत समूहों के मध्य रही।' **[13]**

ओलोपाडे के अवलोकन को यदि क्रमिक विकास और संपत्ति के संदर्भ में बेनहॉकर द्वारा किये गए कार्यों के साथ मिलाकर देखें तो एक नए दृष्टिकोण की आवश्यकता का पता चलता है जो कि परिवर्तन के वाहक के तौर पर सरकार पर कम से कम निर्भरता वाली मान्यता पर आधारित है। स्थानीय अर्थव्यवस्था के क्रमिक विकास की प्रक्रिया में विदेशी सरकारों से प्रभावित स्थानीय सरकार निराशाजनक तौर पर विध्वंसकारी बाहरियों सा व्यवहार करती हैं।

दूसरा सिद्धांत # संस्थागत बदलावों को हासिल करने के लिए स्थानीय स्वतंत्र थिंकटैंक्स के दृष्टिकोणों का समर्थन करना

व्यवस्था के स्तर पर बदलाव के लिए गैरसरकारी नेतृत्व की हमारी तलाश के दौरान लगातार इस बात को मान्यता मिल रही है कि स्थानीय थिंकटैंक्स इस कार्य में बड़ी भूमिका

12. See https://www.oecd.org/dac/effectiveness/parisdeclarationandaccraagendaforaction.htm.

13. Lydia Polgreen, "Home Improvement," New York Times, August 11, 2014, https://www.nytimes.com/2014/04/13/books/review/the-bright-continent-by-dayo-olopade.html.

निभा सकते हैं। वर्ष 2017 में हेवलेट फाउंडेशन के थिंकटैंक के सहयोग से प्रकाशित शोधपत्र में स्थानीय नेतृत्व के जरिये नीति परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध गैर-लाभकारी संगठन किवयू इंटरनेशनल के संस्थापक गुय लॉज और विल पैकस्टन मानते हैं कि स्थानीय थिंक टैंक जब वैश्विक रणनीति बनाकर प्रासंगिक और दीर्घकालीन बदलाव लाने में भूमिका निभाते हैं तो उनके कार्यों का न्यायसंगत मूल्यांकन नहीं हो पाता है।[14]

एटलस नेटवर्क में हमारे अवलोकन में पाया गया कि पिछले बीस वर्षों में स्थानीय स्वतंत्र थिंक टैंक पूरे विश्व में प्रभावकारी भूमिका में रहे हैं। इस दौरान न केवल उनकी संख्या में वृद्धि हुई है बल्कि स्थानीय समस्याओं को पहचानने और उनके समाधानों के नियोजन में उनकी भूमिका का महत्व भी बढ़ा है। कम आय वर्ग के लोगों के लिए आर्थिक अवसरों को सृजित करने में भी थिंकटैक्स का विशेष प्रभाव रहा है।

दक्षिण अफ्रीका में भूमि के वर्गीकरण (लैंड टाइटलिंग) के विषयावलोकन के दौरान जोहान्सबर्ग में मुख्यालय वाले स्थानीय थिंकटैंक फ्री मार्केट फाउंडेशन के कार्यों को रेखांकित करने का उदाहरण लिया जा सकता है। रंगभेद की समाप्ति के बाद सरकारी भवनों के स्वामित्व के स्थानांतरण वाले कानून का समर्थन करने के दौरान थिंकटैंक से जुड़े कार्यकर्ताओं ने पाया कि अनुमति होने के बावजूद इसके लिए पात्र कुछ लोग ही इस अवसर का लाभ प्राप्त कर रहे थे। इसके तुरंत बाद फ्री मार्केट फाउंडेशन ने कम आय वर्ग वाले क्षेत्रों में रहने वाले किरायेदारों को वकीलों के जरिये मुफ्त कानूनी सहायता उपलब्ध कराया, लेकिन आवेदकों की संस्था फिर भी कम ही थी।

यह प्रयास विफल रहा। इसका कारण लोगों में सरकार और बाहरी लोगों (बड़े शहरों के वकीलों) के प्रति अविश्वास था। यह योजना इतनी अच्छी थी कि लोगों को इसपर विश्वास ही नहीं हो रहा था। लेकिन जब फ्री मार्केट फाउंडेशन के कार्यकर्ताओं ने इस कार्य के लिए स्थानीय वकीलों की सेवाएं लीं और स्थानीय कर्मचारियों के साथ काम किया तो संपत्ति के स्वामित्व और संपत्ति के अधिकार की मांग में स्थानीय स्तर पर काफी वृद्धि हुई।

तीसरा सिद्धांत # आर्थिक आज़ादी या व्यक्तिगत एजेंसी में संस्थागत वृद्धि को प्राथमिकता।

तीसरा सिद्धांत प्रणाली के स्तर पर आवश्यक बदलावों को लेकर है; वे बदलाव जो 'व्यक्तिगत और विकेंद्रिकृत समूहों' की स्वतंत्रता में वृद्धि करता है ताकि समस्या के संभावित समाधान तलाशने की उनकी प्रवृत्ति में निरंतर विकास हो सके। शोध कार्यों से यह बात सामने आई है कि सांस्कृतिक और आर्थिक आज़ादी आर्थिक समृद्धि हासिल

14. Guy Lodge and Will Paxton, "Innovation in Think Tanks: Policy Influence and Change in Developing Countries," RSA, 2017.

करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, लेकिन सफलता का सर्वाधिक मजबूती से आंकलन आर्थिक आज़ादी के माध्यम से ही संभव है। **[15]**

आप एमिएबल मेनीकिरजा के बुरुंडी के उन अनुभवों के बारे में पढ़ सकते हैं, जहां का औपचारिक बाजार निम्न आय वर्ग के कारोबारियों की पहुंच में नहीं था, जिसकी वजह बेहद ज्यादा पंजीकरण फीस थी जो कि प्रवेश के लिए बड़ी बाधा थी। कारोबारी पंजीकरण फीस बाजार में प्रतिभागियों पर तीन कृत्रिम प्रकार के खर्चे आरोपित करती थी।

एक, तय फीस की सीमा पहले से ही बहुत अधिक थी जो छोटे छोटे कारोबारियों को कानूनी रुप से व्यापार करने से रोकती थी। दूसरा, कारोबार को पंजीकृत करने की प्रक्रिया काफी जटिल थी और इसके लिए कई सरकारी अधिकारियों की अनुमति जरूरी होती थी। इससे प्रक्रिया में अनावश्यक विलंब होता तथा करों की ऊंची दरों के कारण कम आर्य वर्ग के कुछ ही लोग इसे हासिल कर पाते। अंतत: इन सरकारी बाधाओं के कारण रिश्वतखोरी जैसे भ्रष्टाचार के अवसर पैदा हुए।

भारत का एक मामला लेते हैं, जिसमें एक मध्यम दर्जे के उद्यमी ने थिंकटैंक सेंटर फॉर सिविल सोसायटी के कार्यकर्ताओं को बताया कि यदि वे नियमों के अनुरूप अपने कारोबार को पंजीकृत कराना चाहें तो इसकी योग्यता हासिल करने के लिए उन्हें सबसे पहले मनमाने ढंग से तय की गई एक धनराशि को बैंक में अलग से जमा करके रखना होगा और लाइसेंस पास कराने के लिए रिश्वत के रूप में मोटी रकम नौकरशाहों को देनी होगी। यही वजह है कि इस अनावश्यक रकम चुकाने की बाध्यता के चलते अनेक उत्साही उद्यमी कानून सम्मत बाजार से बाहर हो जाते हैं।

कई अन्य प्रकार की भ्रामक नीतियां भी सरकारी एजेंटों के लिए अवैध कमाई का जरिया बनती है, जिससे स्थानीय कारोबार में अनावश्यक हस्तक्षेप उत्पन्न होता है और यहां तक कि बिना किसी कानूनी प्रावधानों के व्यवसायों को बर्बाद भी कर देता है।

यूनाइटेड स्टेट में इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस के एक शोध में बताया गया है कि किस प्राकर मझौले दर्जे के उद्यमियों को नागरिक संपत्ति जब्ती कानून के तहत पुलिस को नकदी और अन्य संपत्ति जब्त करने का अधिकार देता है, वह भी बिना किसी अपराध के आरोप के। अपराध साबित करने की बात तो छोड़ दीजिए। ये शक्तियां आर्थिक आज़ादी और अवसरों को बेइंतिहा तरीके से सीमित करती है, जिसका कम आय वर्ग की जनसंख्या पर प्रतिकूल असर पड़ता है जो एकल उद्यम की विकास दर को कम करता है और वे लक्ष्यों को पाने से वंचित रह जाते हैं।

15. Claudia R. Williamson and Rachel Mathers, "Economic Freedom, Culture, and Growth," Working Paper, Mercatus Center at George Mason University, 2009.

इस उदाहरण से और इस किताब में शामिल इसके जैसे अन्य विषय अवलोकनों से यही निष्कर्ष निकलता है कि किसी भी गरीबी उन्मूलन रणनीति के केंद्र में आर्थिक स्वतंत्रता महत्वपूर्ण घटक है। किसी भी रणनीति की सफलता के लिए जरूरी है कि वास्तविक सांस्कृतिक संदर्भ का अनुपालन हो, जो बाह्य घटकों के हस्तक्षेप के चलते हासिल नहीं किया जा सकता।

सारांश यह है कि 'वाह्य घटकों की दुविधा' वाली समस्या के समाधान के लिए एटलस नेटवर्क निम्नलिखित सिद्धांतों पर सहमति बनाने का आह्वान करता हैः

- सुनिश्चित करें कि वाह्य घटक स्थानीय स्तर पर बदलाव का नेतृत्व न करें और इस बात को स्वीकार करें कि जब एकल एजेंसी और विकल्प वाले मसलों पर हस्तक्षेप की बात आती है तो सरकारें, विशेषकर स्थानीय सरकारें बाहरियों के जैसे व्यवहार करती हैं।
- संस्थागत परिवर्तन के लक्ष्य को हासिल करने के स्थानीय थिंकटैंकों के उद्देश्यों का समर्थन हो
- एकल एजेंसी अथवा आर्थिक आज़ादी में संस्थागतत वृद्धि को प्राथमिकता दें

मजबूत बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए मुख्य चुनौती यह है कि बाह्य भूमिका को दरकिनार कर पूरे विश्व में ऐसे प्रोजेक्टों को बढ़ावा देना, जिनमें आर्थिक स्वतंत्रता को बल मिले। इस कार्य का नेतृत्व उत्कृष्ट कार्य प्रदर्शन वाले थिंकटैंक करें तथा स्थानीय दृष्टि व रणनीति वाले प्रोजेक्टों को उनकी संप्रभुता में हस्तक्षेप किये बिना प्रोत्साहित किया जाए।

हमारा दृष्टिकोण

सकारात्मक दृष्टि से बदलाव की राह का दृष्टिकोण कम आय वर्ग वाली आबादी की सफलता सुनिश्चित करता है। यह एटलस नेटवर्क दृष्टिकोण से अवगत कराते हुए नवाचार के जरिये वैश्विक नेटवर्क के रूप में स्वतंत्र थिंक टैंक की सफलता का मार्ग प्रशस्त करता है। स्टेरनिंस की तरह, हम ऐसे अवसर सृजित करते हैं कि विशेषज्ञ समूह के सहयोगियों के साथ मित्र समूह के रूप में कार्य को अंतिम दे सकें। जो कि नये विचार और प्रवाह के नये स्तर की ओर ले जाते हैं। पुनरावलोकन की प्रक्रिया में इन नये विचारों से अप्रत्याशित लाभ की स्थितियां बनती हैं। लेकिन ये साथ ही सरलीकरण की रणनीति का लक्ष्य भी है।

हमारे प्रशिक्षक द्वारा हमारे साथ प्रतिस्पर्धा करने और साथ में सफलता का जश्न मनाने का मॉडल जो परस्पर सहयोग को मजबूत करने वाले प्रशिक्षण, प्रोजेक्ट की ग्रांट, नवाचार पुरस्कार व नेटवर्किंग कार्यक्रम के जरिये सामाजिक परिवर्तन के लिए ऊर्जा और संसाधन

जुटाने का कार्य प्रशासन करता है। हम इस प्रकार से कार्य इसलिए करते हैं क्योंकि यह कार्य करने का श्रेष्ठ तरीका है। वाह्य हस्तक्षेप की दुविधा को समाप्त कराने का यह अबतक का आजमाया हुआ श्रेष्ठ तरीका है जो प्रभावी ढंग से काम करता है। इतने सारे विचारशील विद्वानों, अध्येताओं, उसे अमली जामा पहनाने वालों और सभी क्षेत्रों के विशेषज्ञों को हमारी रणनीति को परोक्ष अथवा अपरोक्ष रूप से विभिन्न शाखाओं में लागू कराता देखना काफी उत्साहित करने वाला है।**[16]**

हमारा नया प्रकाशन, 'पावर्टी एंड फ्रीडम' इस समस्या के कारगर समाधान हेतु हमारे सफल नये प्रयासों के प्रसार का एक और उदाहरण है। इसमें चयनित कुछ केस स्टडीज एटलस नेटवर्क्स के ग्लोबल निवेश से थिंक टैंक की सफलता का आशुचिता (स्नैपशॉट) है। हर केस में थिंक टैंक के नेतृत्वकारियों के जरिये परिवर्तन की दृष्टि निकलती दिखती है। इसमें उनके लक्ष्य हैं, रणनीतियां उनकी हैं और नवाचार भी उनका ही है। यहां यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इनमें से किसी भी केस में हम मुख्य ग्रांट देने वाले डोनर का नहीं है। मिलर के जैसे, हमने वहीं निवेश किया है, जहां पहले से ही गंभीर प्रयास लक्ष्य की ओर उन्मुख रहे हैं।

हमारी दूर रहो की सोच के ये मायने कदापि नहीं हैं कि जवाबदेही कमतर किया जाये। जहां तक प्रोजेक्ट की योजना की गुणवत्ता का सवाल है तो हम उच्च मानकों को प्राथमिकता देते हैं और स्पष्ट आकलन बेहतर परिणाम सुनिश्चित करता है। हम दृष्टि और रणनीति में बदलाव की संस्तुति नहीं करते, बल्कि हम प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं ताकि जवाबदेही के मूल्यांकन तथा सफलता की गारंटी सुनिश्चित की जा सके।**[17]**

आप देखेंगे कि इस संदर्भ में प्रोजेक्ट के चयन में विषयों, रणनीति तथा लक्ष्यों में महत्वपूर्ण विविधतता रही है। इस विविधता के बावजूद वे सभी इस मायने में समान रहे कि वे उपरोक्त वर्णित तीनों सिद्धांतों से सामंजस्य स्थापित करते हैं। जैसे कि एटलस नेटवर्क की भूमिका सीमित दायरे में आउट साइडर वाली रही है जो कि वैयक्तिक आज़ादी को बढावा देती हैं जिनका नेतृत्व परिवर्तन के लिए स्थानीय दृष्टिकोण के साथ आगे बढ़ता है।

हमने ये उदाहरण देखे, साथ ही हमारे नेटवर्क में शामिल सैकड़ों थिंक टैंक सामाजिक परिवर्तन की हमारी रणनीति के केंद्र में 'आउट साइडर के भ्रम' के समाधान के साथ गरीबी उन्मूलन के अभियान का आधार रहे। यह एक रणनीति रही है कि दोनों क्लासिकल उदार

16. To provide just a few examples, see the work of Dan Honig, Nina Munk, Lant Pritchett, Michael Woolcock, and Pablo Yanguas.

17. Matt Warner, "Calling Your Shots: Measuring Think Tank Success," January 3, 2018, https://www.atlasnetwork.org/news/article/calling-your-shots-in-2018-measuring-success-in-the-nonprofit-sector.

सिद्धांतों के साथ सामंजस्य बनायें और यह सुनिश्चित करें कि नवीनतम मेधा, बहुआयामी खोज के जरिये संपदा व गरीबी के बीच प्रभावी लोकहितैषी निष्कर्ष सामने आयें।

हमें विश्वास है कि ये केस स्टडीज पूरे नेटवर्क में सामाजिक परिवर्तन के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए नये विचार देंगी। साथ ही थिंक टैंक और आर्थिक विकास विशेषज्ञों के सामंजस्य से लोकहितैषी नये मानकों की स्थापना को संबल देगी, जिससे गरीबी उन्मूलन के लक्ष्यों को हासिल करने की रणनीति युनाइटेड स्टेट्स और शेष विश्व में सफल होगी।

खंड 1:

वाह्य घटकों वाली दुविधा

परंपरागत सहायता मॉडल द्वारा आर्थिक विकास के लक्ष्यों को हासिल करने में विफलता का एक कारण स्थानीय ज्ञान पर अत्यधिक मात्रा में वाह्य ज्ञान थोपना रहा है। यदि सहायता और लोक कल्याण का उद्देश्य गरीब इलाकों की मदद कर उत्थान करना है तो वाह्य घटकों को उन तरीकों पर विचार करना ही होगा जिसके कारण उनके प्रयास से अच्छे के बजाय नुकसान हो जाता है। बड़े मददगार समुदायों ने बहुत पहले से ही स्थानीय ज्ञान के मोल को स्वीकार कर लिया था और इस समुदाय ने ऐसे कई कदम उठाये हैं, जो सद्इच्छा के साथ सहायता योजना और स्थानीय ज्ञान को एक साथ जोड़ने में सहायक हुए हैं। हालांकि, सरकार से सरकार को या सरकार से एन.जी.ओ. को सहायता करने की प्रक्रिया में निहित सत्ता की ताकत की गति के चलते बाह्य मूल्यों के हस्तक्षेप से बचाने और स्थानीय समूहों को प्राथमिकता देने का कार्य लगभग असंभव जैसा हो जाता है।

पुस्तक का यह भाग उन गहरे कारणों को तलाशता है कि क्यों स्थानीय ज्ञान महत्वपूर्ण है, सिस्टम के स्तर पर भी और व्यक्तिगत स्तर पर समृद्धि के मार्ग पर आगे बढ़ने के लिए। साथ ही यह भी कि स्थानीय थिंक टैंक क्यों विदेशी व स्वदेशी सरकारों के मुकाबले आउट साइडर के भ्रम को दूर करने के लिए सहायता समूहों के साथ तारतम्य स्थापित करने के कार्य में बेहतर स्थिति में होते हैं। इस सेक्शन के लेख विविधता के साथ रेखांकित करते हैं कि महत्वपूर्ण सहायता और आर्थिक विकास विचारक, जो स्थानीय ज्ञान के मुद्दे पर कड़ा संघर्ष करते हैं, वे इन प्रश्नों के जवाब तलाशने के लिए एक दृष्टि देते हैं कि बतौर आउट साइडर, हम मदद के लिए क्या कर सकते हैं?

इन लेखों के प्रारूप AtlasNetwork.org. पर उपलब्ध हैं।

वाह्य घटकों की दुविधा से उबरना : क्या परोपकारी लोग विकासशील देशों को लाभ पहुंचा सकते हैं

मैट वार्नर

कार्यकारी सारांश

आर्थिक विकास सहायता का आज का शीर्ष से पाद (टॉप डाउन) मॉडल अपरिहार्य रूप से दोषपूर्ण है। दरअसल, आर्थिक विकास के लिए एक विशिष्ट प्रकृति के समाधान की आवश्यकता होती है जो कि वाह्य घटकों द्वारा किये जाने वाले नियोजन एवं प्रबंधन के प्रयासों से संभव नहीं है। इसके बजाय बाजार के विकास के पक्ष में संस्थागत वातावरण परिवर्तन में स्थानीय स्तर पर विकसित समाधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, जिससे गरीब तबके के अधिकारों का संरक्षण करते हुए विश्वव्यापी गरीबी उन्मूलन के त्वरित प्रयासों का बेहतर अवसर हासिल हो सकता है।

वाह्य घटकों के लिए यह एक गंभीर दुविधा वाला प्रश्न है कि क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे बिना हस्तक्षेप किये मदद की जा सके? एटलस नेटवर्क ने सफलतापूर्वक एक नई रणनीति बनायी है, जिसमें लोक कल्याण के संसाधनों को स्थानीय शोध और स्वतंत्र बाजार केंद्रित थिंक टैंक की कार्यप्रणाली के जरिये संस्थागत मजबूती से विश्व के गरीबों का तेज विकास संभव हो सकेगा। वैश्विक सूची में इन प्रयासों से मानक स्थापित करके तथा विश्व बैंक द्वारा प्रकाशित कारोबार करने के तौर-तरीकों की रिपोर्ट में इन थिंक टैंक की उल्लेखनीय सफलता एवं महत्वपूर्ण परिणामों का उल्लेख है।

एलेक्स जॉर्जेस ने हैती में नवीकरणीय ऊर्जा कंपनी ईएनईआरएसए की सह-स्थापना की ताकि लोगों को केरोसीन लैंपों की बजाए विद्युत उर्जा से संचालित होने वाले लैंपों के इस्तेमाल की ओर ले जाया जा सके। वर्ष 2007 में आए भूकंप के बाद सौर्य ऊर्जा से मोबाइल उपकरणों, राहत कार्य में जुटे लोगों और अपने घरों के पुनर्निर्माण में जुटे लोगों को त्वरित और सुविधाजनक तरीके से ऊर्जा प्रदान की जा सकी। उसका कारोबार बढ़िया

चल रहा था और नई मांग की पूर्ति करने में सक्षम था। लेकिन मानवीय सहायता के रूप में विदेशी सोलर पैनलों की पूर्ति स्थानीय बाजारों में की गई, जिसका परिणाम यह हुआ कि ईएनईआरएसए बंद होने के कगार पर तथा जार्ज दिवालिया होने की स्थिति में जा पहुंचे।

नि:संदेह, मुफ्त की आपूर्ति हमेशा बुरी नहीं होती है, विशेषकर संकट के तुरंत बाद। लेकिन संवेदनशील अर्थव्यवस्थाओं में मानवीय सहायता की अनिश्चितता की प्रकृति मुश्किलों से हासिल आर्थिक तरक्की को पराभव की ओर ले जा सकती है। दरअसल, आपातकालीन सहायता का लाभ अल्पकालिक ही होता है, लेकिन दीर्घकालिक विकास कार्यक्रमों में इनकी भूमिका नहीं होती। आज इस सहायता का जो अस्पष्ट स्थाई मॉडल कार्यरत है, उसके बारे में विशेषज्ञों की राय है कि वह लाभ के बजाय नुकसान ज्यादा करता है। अच्छी खबर यह है कि अब अच्छा विकल्प मौजूद है, लेकिन इसके लिए पूर्व रूप से नई लोक कल्याणकारी रणनीति की जरूरत है।

मदद काम नहीं कर रही

ऑक्सफोर्ड प्रशिक्षित अर्थशास्त्री दमबिसा मोयो, जो जांबिया में पली-बढ़ी हैं, अपनी पुस्तक 'डेड एड : वाय ऐड इज़ नॉट वर्किंग एंड हाउ देयर इज़ ए बेटर वे फॉर अफ्रीका' में लिखती हैं, 'दान दाता, विकास एजेंसियां और नीति-नियंताओं ने अधिकांशत: मुखर सचेतक संकेतों की अनदेखी की है। यह जानते हुए कि सहायता मॉडल कारगर नहीं है और इसकी शैली काम नहीं कर रही है, फिर भी एड आधारित मॉडल की वकालत की है।' वह लिखती हैं कि शोध दर शोध यह साबित हुआ है कि वास्तविक लक्ष्यों को पाने में ऐड रणनीति कारगर नहीं है। संभव है संकट में मदद कुछ हद तक काम आये। वह निष्कर्ष देती है कि 'यह भ्रम है कि सहायता की नीति व्यवस्थागत गरीबी को दूर करने में सक्षम है।'

कीनिया में ब्रिटेन के इंटरनेशनल डेवलेपमेंट विभाग के प्रमुख सिमोन ब्लैंड ने पत्रकार नीना मुंक से कहा 'मैं चाहता हूं कि आपक किसी गांव में प्रत्येक व्यक्ति पर पर्याप्त धन खर्च करें तो आप उनका जीवन बदल सकते हैं... लेकिन समस्या यह है कि जब आप चले जाते हैं, तब क्या होता है?' ब्लैंड ने संकटकाल में ऐड पर निर्भर समुदायों की विचित्र स्थिति को बेहद करीब से देखा है। यह मदद न केवल अस्थिरता की समस्या को बढ़ावा देती है बल्कि आत्मनिर्भर विकास की गति को अवरुद्ध कर लक्ष्य से देरी उत्पन्न करती है जो कि दीर्घकालीन विकास और स्वतंत्रता के लिए जरूरी होता है।

वेनिटी फेयर मैगज़ीन की संपादक रही मुंक ने प्रसिद्ध विकास विशेषज्ञ और अधिक से अधिक ऐड के समर्थक जेफ्री साच्स के साथ छह वर्ष का लंबा समय बिताया। मुंक ने इस प्रोजेक्ट की शुरुआत इस मकसद से की थी कि उनकी रिपोर्टिंग जैफ्री के 120 मिलियन डॉलर के मिलेनियम विलेज प्रोजेक्ट के प्रति जागरूकता पैदा कर सकेगी। यह एक ऐसी

योजना थी, जिसका लक्ष्य गरीब लोगों को तीव्र आर्थिक विकास के मार्ग पर उन्मुख करने का था। आखिर में उन्होंने एक स्पष्टवादी मूल्यांकन 'दि आइडलिस्ट : जेफ्री साच्स एंड दि क्वेस्ट टू एंड पॉवर्टी' शीर्षक से प्रकाशित किया। इसमें उन्होंने विस्तार से बताया कि कैसे उनके दृष्टिकोण का आर्थिक विकास पर घातक असर पड़ा।

वह लिखती हैं 'जेफ्री साच्स' का अवलोकन जमीनी हकीकत में आवश्यक रूप से सीमित था; समय के दबाव, भाषा, संस्कृति, शिक्षा, पृष्ठभूमि, पूर्व संकल्पना व दीर्घकालीन लक्ष्यों के नजरिये से। उन्होंने आगे कहा 'इसके बावजूद साच्स चाहते थे कि हम उन पर विश्वास करें, बिना किसी सवाल के हम गरीबी उन्मूलन के नजरिये को स्वीकारे, जैसे कि हम किसी सामूहिक जादुई सोच से जुड़ रहे हों।'

उन्होंने अपने प्रत्यक्ष अवलोकन में इस 'जादुई सोच' की कीमत का अवलोकन किया, जो यह विश्वास दिलाता था कि सीमित ज्ञान वाला एक बाहरी व्यक्ति दूसरे लोगों की आर्थिक समस्याओं का हल निकाल सकता था। इस योजना के निष्कर्ष के तौर पर यह देखने को मिला कि नई फसल में बड़ा निवेश करने के बाद भी उस नई फसल को ग्राहक नहीं मिले, नव स्थापित ट्रेड सेंटर को कारोबारी नहीं मिले, नयी नौकरियाँ टिकाऊ साबित नहीं हुईं। यहां तक कि जिन प्रयासों के परिणाम सकारात्मक थे, वे आगे मिलने वाली सहायता के बिना जारी न रह सके। इस तरह परिणाम विपरीत रहे ओर साच्स की विकास रणनीति की सीमाओं को उजागर किया।

अधिकांश योजनाकार इन समस्याओं से अच्छे तरीके से वाक़िफ़ रहे हैं लेकिन पिछले एक दशक से वे इनसे उबरने के लिए कार्यक्रम की रूपरेखा को ही बेहतर बनाने के प्रयास में लगे रहे। विभिन्न तरीकों से विकास के लक्ष्य हासिल करने के उनके प्रथम सिरे नहीं चढ़े, वजह यह कि वे गैर-स्थानिक हस्तक्षेप के प्रभाव को कम नहीं कर पाये। यही वजह है कि वे जरूरतमंदों की समृद्धि के लक्ष्य हासिल करने से वंचित रहे।

संस्थागत विषय

संपन्नता हासिल करने के लिए संपत्ति का अधिकार, कानून का राज, स्वतंत्र बाजार आदि जैसी संस्थाओं की सबसे अधिक जररूत होती है। कई दशक से अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं और सरकारों ने कुछ मामलों में इस तरह की व्यवस्थाओं से जुड़े सुधार ऊपर से नीचे तक किये हैं, जो ट्रेड, ऐड और ऋण से जुड़े थे, लेकिन अक्सर उनके दुखांत सामने आये।

हमने मुश्किल अनुभवों से पाया है कि संपत्ति का अधिकार जैसी व्यवस्था यदि आयातित मॉडल पर आधारित होती है तो वह टिकाऊ नहीं होती है। दरअसल, इसका विकास भीतर से होना चाहिए, स्थानीय स्तर पर विकसित हो, दोनों पक्षों की सहमति हो और उससे भी अधिक जरूरी है कि यह उस विशिष्ट सांस्कृतिक मेकैनिज्म्स के साधनों को तलाशा जाये जो अनौपचारिक मानकों को एक औपचारिक सिस्टम से सहजता से बेहतर ढंग से संचालित करे।

जैसा कि पहले कहा गया है कि दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद की समाप्ति के बाद भूमि स्वामित्व का विस्तार हुआ। ऐसे ही सरकारी मकानों के स्वामित्व हासिल करने के प्रयास तेज हुए जब एक गैर-सरकारी संगठन की फ्री मार्केट फाउंडेशन ने रचनात्मक भूमिका निभाई। यह संगठन गरीबों को स्वामित्व अधिकार दिलाने के लिए जाना जाता है। सामाजिक सुधारों के इसके प्रयासों की बदौलत सामुदायिक स्तर पर सुधार के कार्यों के लिए प्रयास शुरु हुए जिसमें लोगों ने स्वइच्छा से भाग लेना शुरु किया। इस दृष्टिकोण ने संपत्ति के अधिकार वाली संस्था को मजबूत बनाने में सफलता हासिल की क्योंकि मूल रूप से इसे उन लोगों द्वारा बढ़ावा दिया गया जिन्होंने इससे लाभ प्राप्त किया था।

'वाई नेशंस फेल' पुस्तक में लेखक डारोन एसेमोग्लू और जेम्स राबिन्सन ने संस्थागत अधिकारों के महत्व की बात स्वीकारी, मगर इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण बात की ओर ध्यान दिलाया कि 'दो समाज एक जैसे संस्थान नहीं बना सकते।' सफल संस्थानों में कई प्रकार की समानता हो सकती हैं, लेकिन उनकी संरचना और इस संरचना को पाने की प्रक्रिया निश्चित रूप से विशेषीकृत स्वभाव के अनुरूप होती है। यह योजना निश्चित रूप से असफल होगी, यदि इसका निर्माण बाहरी दिमाग और संगठन द्वारा किया जाएगा।

विदेशी सरकार : पूर्ण रूप से बाहरी

इस असहज करने वाले सत्य को स्वीकार करना ही होगा, हालांकि, प्रेरणा और नियत में अंतर संभव है। आज के बौद्धिक वर्ग में इस बात को लेकर अभिमान हो सकता है कि आर्थिक विकास का इतिहास विश्व के अमीर और गरीब देशों के बीच के लंबे और परेशान करने वाले पैतृकता वाली भावना पर निर्भर है। दरअसल, ऐड देने के वर्तमान दर्शन पर

उपनिवेशवादी अतीत की छाया रही है। अपनी पुस्तक में एसेमाल्यू और राबिन्सन ने वर्णन किया है कि अतीत में सत्ताधीशों की निर्दयता और आरोपों की प्रतिछाया आज की सरकारों के कुशासन के रूप में सामने आती है। ऐसे में विकास के लिए मदद की प्रेरणा महज दिखावा है। आत्मकथ्य लेखक एडम होचस्चाइल्ड बताते हैं कि कैसे बेल्जियम का क्रूर राजा लियोपोल्ड-II, जो 19वीं सदी में कांगों पर निर्लज्ज शासन के लिए जाना जाता है और उसने मानवीय दुखों की पूर्णत: अवहेलना की। उसने दुनिया के सर्वोत्तम खोजकर्ताओं की भर्ती यह कहते हुए की कि उसका उद्देश्य केवल परोपकार पर आधारित है। उसने गुलामों के व्यापार को समाप्त करने का प्रण लिया जिससे कि उनके कानूनी संस्थाओं में सुधार किया जा सके और उनकी भर्ती सिर्फ निष्पक्ष मध्यस्थता के द्वारा हो सके।

पक्षपात की यही विरासत आज तकनीकी दक्षता और केंद्रीयकृत योजनाओं के समाधान के रूप में सामने आती है। यह बाहरी लोगों को इस दोषपूर्ण आधार पर सहमत कर लेता है कि उन्हें गरीबों की समस्याओं का समाधान करना चाहिए और वे ऐसा कर सकते हैं।

अपनी हालिया पुस्तक '*दि टायरनी ऑफ एक्सपर्ट्स : इकोनोमिस्ट्स, डिक्टेटर एंड दि फॉरगटन राइट्स ऑफ दि पूअर*' में न्यूयार्क यूनिवर्सिटी में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर और इसके डेवलेपमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट के सह-निदेशक विलियम इस्टरले, राज्यों में निहित अधिकारवादी दुराग्रहों की छाया को अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक विकास के इतिहास के साथ देखते हैं। वे चेताते हैं कि उपदेशात्मकता के बजाय सभी विकास से जुड़ी चर्चाओं को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। ऐसे में परोपकारी नजरिया स्पष्ट सोच में बाधक होता है।

यह काफी महत्वपूर्ण विषय हैं क्योंकि दांव बहुत बड़ा है। अर्थशास्त्री क्रिस कॉयन पुस्तक– '*इट्इंग बैड बाइ इट्इंग गुड : व्हाय ह्यूमेनटेरियन एक्शन फेल्स*' के लेखक हैं। उन्होंने पाया है कि 'समय के साथ-साथ मानवीय सहायता के कार्यक्रम सरकारों के व्यापक सैन्य और विदेश नीति के उद्देश्यों के साथ तेजी से जुड़े हैं।' इसके जरिये ये भ्रम बनाने का प्रयास किया जाता है कि अच्छी नीयत से की जाने वाली विदेशी कल्याणकारी मदद आर्थिक विकास में सहायक होती है।

कॉयन का शोध इस बात की पुष्टि करता है कि बाहरी तत्वों के अभिमान के चलते समस्या पैदा होती है। यह शोध श्रमसाध्य रूप से दर्शाता है कि कैसे राज्य के नेतृत्व वाले दृष्टिकोण का वर्चस्व व तेजी से विस्तार करके जटिल आर्थिक, कानूनी और राजनीतिक प्रणालियों की उपेक्षा या अवमूल्यन करके संस्थागत संगठनों व संस्थानों की प्रभावशीलता को कम किया जाता है। दुर्भाग्यपूर्ण ढंग से इसके परिणाम स्वरूप न केवल आर्थिक विकास असफल होता है, बल्कि भू-राजनीतिक सिस्टम हितों के टकराव और भ्रष्टाचार के लिए अधिक संवेदनशील हो जाता है।

ईस्टरले की तरह, कॉयेन एक परोपकारी विकल्प की पेशकश नहीं करते हैं मगर किताब के समापन अध्याय में वह लिखते हैं कि आर्थिक आज़ादी के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने से ज्यादा महत्वपूर्ण लाभ मिलेंगे बजाय की विदेशी सहायता के। दरअसल, यह अवलोकन ईस्टरले के उन विचारों की प्रतिध्वनि ही है जिसमें गरीबों के आर्थिक अधिकारों की पुर्नस्थापना पर जोर दिया गया है। किंतु बाहरी होने के नाते यह हमें उसी दुविधा में छोड़ भी देता है। ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है कि यदि बाह्य हस्तक्षेप स्वयं समस्या का हिस्सा है तो हम दुनिया के गरीबों की मदद कैसे कर सकते हैं?

दरअसल, बाहरी हस्तक्षेप की दुविधा को जान-बूझकर नजरअंदाज किया जाता है। विदेशी सरकारें लगातार विकास से जुड़े प्रोजेक्टों पर बड़ी धनराशि खर्च करती हैं। इस वाह्य घटक की दुविधा का सामना करने के स्थान पर उसकी अनदेखी करने से हम उसके समाधान तलाशने की बजाए विचित्र स्थिति में पहुंच जाते हैं।

अल्पकालिक बनाम दीर्घकालीन समाधान

वर्ष 2017 का संदर्भ लें, आर्थिक विकास के क्षेत्र में जो एक महत्वपूर्ण बहस बिल गेट्स और विकास विशेषज्ञ क्रिस बलटमैन के बीच सामने आई कि गरीबों के कल्याण के लिए उन्हें चिकन दिया जाये कि नकदी। नि:संदेह दोनों ही का मकसद कल्याण करना रहा है, लेकिन दोनों ही में से कोई स्वयंसिद्ध नही है जो समृद्धि लाने का दावा कर सके। साथ ही दोनों तरीके, गरीब लोगों पर शासन करने वाली संस्था की रूपरेखा कैसी हो इस अहम समस्या को पूर्णरुप से टालने का काम करते हैं।

शोधों का निष्कर्ष है कि जिस भी देश में गरीब लोगों को आर्थिक अधिकार प्रदत्त है उस देश में शरण प्राप्त कर लोग फले फूले ही हैं। जैसे कि हावर्ड के विकास विशेषज्ञ लैंट प्रिटचैट इसकी व्याख्या करते है— 'लोग गरीब नहीं होते हैं, लोग गरीब स्थानों पर रहते हैं।' अब आप चाहे किसी को चिकन दे या नकदी इससे बहुत अधिक फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि उस देश में उत्पादक होना मुश्किल है जहां उद्यमिता की राह में तमाम प्रकार की बाधाएं हो और कानूनी तौर पर आर्थिक अधिकार बहुत कम हों।

जब तक हम व्यक्ति के आर्थिक अधिकारों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक आर्थिक उन्नति की कोई भी दृष्टि सफल नहीं हो सकती। जैसा कि वर्ष 2015 के नोबेल पुरस्कार विजेता एंगस डीटन 'दि ग्रेट इस्केप : हेल्थ, वेल्थ, एंड दि ओरिजन ऑफ इनइक्वीलिटी', में व्याख्या करते हैं, जब परिस्थितियां विकास के अनुकूल हों, एड की जरूरत नहीं पड़ती। जब विकास के लिए स्थानीय परिस्थितियां प्रतिकूल हों, तब मदद उपयोगी नहीं हो सकती। यह स्थितियों को स्थायी बनाने की दृष्टि से हानिकारिक ही साबित होती हैं।

वास्तव में, हमें गैर-महत्वपूर्ण कदमों को नकारने में बेहद सावधानी बरतनी चाहिए। अब चाहे व्यक्ति और परिवार को चिकन देने का मसला हो या फिर नकदी देना। इसी बीच हमें बड़ी समस्या पर ध्यान केंद्रित करना है, जिसके समाधान से दूरगामी प्रभावों को हासिल किया जा सके। कोयने राजनैतिक सिद्धांतवादी और नैतिक दार्शनकि माइकल वॉल्जर का हवाला देते हैं, जिन्होंने लिखा है कि, 'निःसंदेह किसी को भूख से मरने से बचाने के लिए सबसे अधिक जरूरत उसे तत्काल भोजन कराना होता है। राहत की जरूरत मरम्मत से पहले होती है, लेकिन इसके बावजूद मरम्मती के अपने खतरे भी हैं, हमें विकास के दीर्घकालीन लक्ष्यों को ध्यान में रखना चाहिए ताकि संकट बारम्बार और आम बात न हो जाये। बाहरी तत्वों के हस्तक्षेप से बचाव करते हुए आप चुनौती को स्वीकार कर सकते हैं। मूलत: विश्व के गरीबों की मदद के लिए भिन्न मौलिक सोच की जरूरत होती है। जैसा कि पता चला है कि ऐसी सोच पहले से ही उभर रही है।

बाहरी तत्त्वों के लिए नई कार्यनीति

एटलस नेटवर्क 96 देशों में 480 स्वतंत्र थिंक टैंक की सहायता करता है। इनमें से प्रत्येक थिंक टैंक सुधार के अपने अपने तरीके के एजेंडे के साथ सभी लोगों के आर्थिक कल्याण के लिए स्वतंत्र समाज और आर्थिक अधिकारों के सिद्धांतों के साथ काम करते हैं।

ये संगठन उस खोयी हुई कड़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जो स्वतंत्र आर्थिक अधिकारों के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करते हुए लोगों को स्थानीय स्तर पर उपलब्ध समाधान का प्रयोग करते हुए वर्तमान को सुधारते हैं और कल के लिए मजबूत संस्थानों की नींव रखते हैं।

वे लोक कल्याणकारी अवसरों का प्रतिनिधित्व करते हैं, गरीबी उन्मूलन की नई कार्यनीति अपनाते हैं और वाह्य घटकों की दुविधा से मुक्त होने का प्रयास करते हैं तथा समाज में बुद्धिमत्ता तथा सावधानी बरतते हुए विविध विशेषज्ञों को तैयार करते हैं।

छोटे सुधार, बड़ा प्रभाव

उद्यमशीलता और आर्थिक विशेषज्ञ विलियम बॉमोल, कार्ल शरम तथा राबर्ट लिटन ने अपनी पुस्तक–'गुड कैपिटलिज्म, बैड कैपिटलिज्म' में विकास के लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए आर्थिक स्वतंत्रता पर बल दिया है, खासकर उन देशों में जहां गरीबी की दर ऊंची है। बहुत से देशों की राजनीतिक हकीकत को दृष्टिगत रखते हुए भी वे सुधारों के जरिये "सीमांत नीतिज्ञता" (मौलिकता पर बल) से युक्त महत्वपूर्ण परिणाम हासिल कर सकते हैं।

यहां सवाल उठना स्वाभाविक है कि हम सीमांत नीतियों को कैसे पहचानेंगे? इसका जवाब निम्नलिखित चार प्रश्नों के सकारात्मक उत्तर देकर हासिल किया जा सकता हैः

1. क्या व्यापार को शुरू करना, बढ़ाना और बंद करना सुगम है?
2. क्या उत्पादक व्यवहार के पुरस्कार को अनुभव करना सरल (जैसे कानून का राज, संपर्क की आज़ादी, संपत्ति का अधिकार, सरल कर प्रणाली) है?
3. क्या अनुत्पादक व्यवहार का प्रतिफल अनुभव करना (धोखाधड़ी, चोरी और रेंट सिकिंग) कठिन है?
4. क्या प्रतिस्पर्धा के माध्यम के अलावा किसी अन्य प्रकार से दूसरे प्रतिस्पर्धियों पर अंकुश लगा पाना कठिन है (कारोबार व निवेश की बाधाएं)?

ये वे नीतियां हैं जो उदाहरण स्वरूप, इकोनोमिक फ्रीडम ऑफ दि वर्ल्ड रिपोर्ट और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट द्वारा मापी जाती हैं। इन नीतियों में परिवर्तन के बारे में बॉमोल आदि ने बाद में लिखा, 'ये छोटे मामले नहीं हैं।' वे आगे कहते हैं, 'इनमें से कुछ या ये सभी कदम त्वरित परिणाम के निर्धारक हो सकते हैं।' वे डूइंग बिजनेस रिपोर्ट का हवाला देते हैं, 'जहां ये दस्तावेज पंजीकृत व्यवसायों की संख्या में तेजी लाते हैं और व्यावसायिक निवेश में वृद्धि करते हैं, जिन्होंने अपने यहां कारोबार को पंजीकृत कराने की प्रणाली को सुव्यवस्थित किया है।

अलग तरीके से आर्थिक विकास

आर्थिक विकास की नई रणनीति में इस बात को मानती है कि वाह्य तत्व प्रभावपूर्ण ढंग से स्थानीय समाधान नहीं दे सकते। ज्ञान, क्षमता और आर्थिक आज़ादी की राह की बाधाओं को हटाकर आर्थिक आज़ादी के अधिकारों की पुर्नस्थापना करने की आकांक्षा स्थानीय स्वतंत्र थिंकटैंकों को इस कार्य के लिए श्रेष्ठ विकल्प बनाती है।

नई रणनीति विभिन्न देशों में आर्थिक आज़ादी के मार्ग में आने वाली उन बाधाओं को बेहद व्यावहारिक ढंग से हटाने के तौर तरीकों को आत्मसात करती है जो उद्यमियों और लोगों को उत्पादक होने से रोकती हैं उद्यमशीलता और उत्पादकता को गति देती है। ऐसे सुधार काफी महत्वपूर्ण साबित होते हैं। अपनी हालिया पुस्तक के उपसंहार वाले हिस्से में ईस्टरले स्पष्ट करते हैं कि वे भविष्य के प्रति आशावादी हैं क्योंकि आर्थिक आज़ादी में क्रमबद्ध सकारात्मक परिवर्तन विश्व के गरीबों के जीवन में धनात्मक परिवर्तन लायेगा।

इसके अलावा, नई रणनीति इस कार्य में वाह्य घटकों की भूमिका को भी मान्यता देती है। परोपकारी लोग दुनियाभर में स्थानीय शोध और एडवोकेसी परियोजनाओं को बढ़ावा देने का कार्य कर सकते हैं। वे स्वतंत्र संगठनों को सहायता कोष प्रदान कर सकते हैं जो

सुधारों के लिए प्रतिबद्ध हो और आर्थिक विकास के लिए जरूरी संस्थाओं को मजबूती प्रदान कर सके। मौजूदा संसाधनों के बीच, विश्वभर के थिंक टैंक नियमित रूप से महत्वपूर्ण सुधारों को हासिल कर रहे हैं और हर सुधार का मापे जा सकने वाला सकारात्मक प्रभाव गरीबों के जीवन पर देखा गया है।

अधिक सहायता प्राप्त कर वे और अधिक सफलता हासिल कर सकते हैं।

वर्तमान में प्राप्त होने वाली सहायता से हम वे लक्ष्य कभी हासिल नहीं कर सकते हैं जो सही मायनों में हम विश्व में गरीबी दूर करने के लिए चाहते हैं। इस लक्ष्य के करीब पहुंचने का श्रेष्ठ मौका एक ऐसी रणनीति बनाने से प्राप्त होगा जो अंर्तमन से इस बात को स्वीकार करे कि गरीबी के चंगुल से बाहर निकलने के लिए जिस विशेषज्ञता, विषय ज्ञान और नेतृत्व की जरूरत है वह स्थानीय लोग ही प्रदान कर सकते हैं।

उत्पादक ज्ञान को प्रोत्साहन : ऐड सुधारकों का वाह्य घटकों वाली दुविधा से सामना

मैट वर्नर

कार्यकारी सारांश

विशेषज्ञों और सहायता मुहिम से जुड़े लोगों में अब सहमति बनने लगी है कि अंतर्राष्ट्रीय सहायता को और अधिक प्रभावी व पारदर्शी बनाने, फिजूलखर्ची, भ्रष्टाचार और नुकसानदायक होने के आरोपों से बचाने के लिए इसके तौर-तरीकों में व्यापक बदलावों की जरूरत है।

एक नई विचारधारा का विस्तार हो रहा है जो व्यापक शोध के बाद सहायता और वाह्य घटकों व स्थानीय समुदाय के संबंधों पर पुनर्विचार की जरूरत बता रही है। इसके बावजूद, सुधार की गति- ऐड एजेंसियों और दुनिया भर के विकासशील देशों के सरकारी बाबूशाही, जिसके साथ वे भागीदारी करते हैं- को चुनौती देने के उलट, उनके साथ संबंध सुधारने के ईर्द गिर्द केंद्रित नजर आती है।

जटिल शोध की वैकल्पिक व्याख्या विकासशील देशों में सहायता एजेंसियों और सरकारों की आर्थिक भूमिका को न्यूनतम करने और व्यक्ति की आर्थिक आज़ादी को अधिकतम करने का सुझाव देती है ताकि वे विकास के जरिये समृद्धि के विश्वसनीय मार्ग की ओर अग्रसर हो सके।

परिचय

अंतर्राष्ट्रीय सहायता कार्यक्रमों के शीर्ष से नीचे की ओर (टॉप-डाऊन) वाले विदेशी तौर तरीकों व इनके सरल व रेखीय रणनीति पर अत्यधिक निर्भर रहने कारण लंबे समय से आलोचना की जाती रही है जबकि इसके विपरीत राष्ट्रों का विकास काफी जटिल तरीके से होता है।

शुरुआत, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित विकास अर्थशास्त्री पी.टी. बॉयर की 1971 में प्रकाशित पुस्तक 'डिसेंट ऑन डेवलेपमेंट' में नामचीन बुद्धिजीवियों और विशेषज्ञों ने सहायता उद्योग की भारी-भरकम योजनाओं से गरीबों की मदद करने की कोशिशों को चुनौती दी है। नोबेल पुरस्कार प्राप्त अर्थशास्त्री एलिनॉर ओस्ट्रम सहायता एजेंसियों के योगदान को खारिज करते हैं, उनकी शिकायत है कि शुरुआत में भले ही वे सही बात करते हों, मगर उनकी समस्या को लेकर गहरी समझ नहीं होती।

इसकी और अधिक निंदा तब हुई जब दि अफ्रीका इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर रिचर्ड डॉडन ने एक बार कहा कि आधुनिक सहायता एजेंसियाँ स्थानीय लोगों और उनकी संस्कृति की उतनी परवाह भी नहीं करती हैं जितना कि औपनिवेश काल में उनके पूर्ववर्ती किया करते थे। और तो और, वर्ष 2013 में 'दि ग्रेट इस्केप : हेल्थ, वेल्थ, एंड दि ओरिजन्स ऑफ इनइक्वलिटी' किताब लिखने व वर्ष 2015 में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले एंगस डीटन का निष्कर्ष था कि सहायता एजेंसियां जहां काम करती हैं, उन समाजों का भला करने के बजाय ज्यादा नुकसान करती हैं।

उत्साहपूर्वक ढंग से, आज की मुख्यधारा के अनेक शिक्षाविदों व यहां तक कि कुछ ऐड प्रदाता भी आलोचनाओं से सहानुभूति जताते हुए उत्साहवर्द्धक तरीके से इस प्रक्रिया में सुधार की मांग पर जोर देते हैं। हालांकि, सहायता कार्यक्रमों की विफलता से सीखे गए सुधार के सबक उनके प्रदर्शन में लंबे समय तक देखने को नहीं मिले।

इसके विपरीत, यह नजर आता है कि सहायता एजेंसियों की केंद्रीय भूमिका निभाने और राष्ट्रीय सरकारों के विकास परिचालन की प्रतिबद्धता उसी घातक दंभ का नया संस्करण पेश करती है, जो आज सहायता की वकालत करने वालों के पूर्ववर्तियों ने किया था। ऐसे में प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि गरीबों के जीवन में समृद्धि लाने के प्रयासों में उनकी अंतर्दृष्टि का बेहतर इस्तेमाल कैसे कर सकते हैं?

सहायता की प्रभावहीनता से निबटना

वर्ष 2003 में शुरू हुए, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनोमिक को-आपरेशन एंड डेवलपमेंट (ओईसीडी) ने सहायता की प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों का नेतृत्व किया, खासकर

ऐतिहासिक परंपराओं में पारदर्शिता और लक्षित उद्देश्यों की पूर्ति की बाधाओं पर ध्यान देते हुए। अबतक 160 से अधिक देशों, जिनमें दान देने वाले और सहायता पाने वाले दोनों शामिल हैं, ने इन प्रयासों का समर्थन किया और नये सिद्धांतों के संग्रह पर एक राय बनी जिसे समय समय पर परिष्कृत किया जाना था। हाल का सबसे नया संस्करण निम्नलिखित चार विषयों को समाहित करता हैः

1. विकासशील देशों द्वारा विकास की प्राथमिकताओं का स्वामित्व: विकास की साझेदारी तभी कामयाब हो सकती हैं जब कि उसका नेतृत्व विकासशील देश करें और ऐसी सोच के अनुरूप क्रियान्वयन हो जो देश विशेष की ज़रूरतों व परिस्थितियों के अनुकूल हो।
2. परिणामों पर ध्यान : हमारे निवेश व प्रयास गरीबी खत्म करने व लंबे समय तक गैर-बराबरी को कम करने वाले हों। विकासशील देशों में विकास को स्थायित्व मिले व उनकी क्षमताओं को विस्तार मिले। जिनका साम्य विकासशील देश की प्राथमिकताओं और नीतियों से हो।
3. समावेशी विकास के लिए साझेदारी : विकास के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए साझेदारी में विश्वास, खुलापन, एक-दूसरे का सम्मान व सीखने की स्थितियां जरूरी हैं। साथ ही सभी नेतृत्वकारियों को विकास के विभिन्न और पूरक लक्ष्यों की पहचान होनी चाहिए।
4. पारदर्शिता व एक दूसरे के प्रति जवाबदेही : बेहतर परिणाम हासिल करने के लिए जरूरी है कि पारस्परिक जवाबदेही और लाभार्थियों के प्रति जिम्मेदारी के साथ बेहतर परिणामों के लिए सम्मानित नागरिकों, संगठनों, घटकों तथा अंशधारकों के साथ सहयोग किया जाये। पारदर्शी कार्यप्रणाली जवाबदेही के आधार को विस्तार देती है।

इन सिद्धांतों के पालन से तात्पर्य सहायता प्राप्त करने वाले देशों के उपर सहायता प्रदान करने वाले देशों के प्रभाव को कम करना है, जिससे ये देश अपनी विशिष्ट और संलिष्ट ज़रूरतों के पूर्ति में अपने ज्ञान का उपयोग कर पायें। इससे चीजों को बेहतर ढंग से करने की उम्मीद बनती है, पिछली ग़लतियों से सीखते हैं और बेहतर परिणामों के लिए बेहतर मानकों का उपयोग करते हैं।

दुभार्ग्यपूर्ण है कि बदलाव की गति निराशाजनक है। वर्ष 2016 में ओईसीडी के लक्ष्यों की प्रगति के अवलोकन के लिए जिम्मेदार संगठन 'दि ग्लोबल पार्टनरशिप फॉर इफेक्टिव डेवलपमेंट कोऑपरेशन' की रिपोर्ट में मिश्रित परिणाम प्राप्त हुए और इस रिपोर्ट में ख़ुशियाँ मनाने के लिए बहुत कम कारण थे। रिपोर्ट की भाषा के काफी उत्साहवर्द्धक होने के बावजूद यह उन चुनौतियों को लगातार और अपरिहार्य तौर पर रेखांकित करता है जो बाहरियों के द्वारा बिना हस्तक्षेप के मदद करने के प्रयास के लिए जरूरी है। उदाहरण के

लिए, प्रतिकूल प्रथाओं के उन्मूलन के लिए होने वाली प्रगति जैसे कि सशर्त समर्थन (सहायता में निहित अंतर्विरोध, जो सहायता करने वाले देशों के हितों की पूर्ति करते हैं, भले ही वे स्थानीय लोगों की प्राथमिकताओं को अनदेखा करें) के चलते लक्ष्यों के मानक नीचे ही रह जाते हैं।

एक तरफ जहां ओईसीडी द्वारा निर्धारित सिद्धांत समाधान के महत्व के बारे में अंतर्दृष्टि देते हैं, कुछ विशेषज्ञ सवाल उठा रहे हैं कि क्या हम सही मायनों में समस्या की जटिलता को ही समझ पाये हैं।

सहायता और गतिशीलता

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में परंपरागत सहायता क्यों काम नहीं करती, इस बाबत एक नई सहायक दृष्टि की व्याख्या बेन रामलिंगम ने अपनी 2013 में प्रकाशित पुस्तक, 'एड ऑन दि ऐज ऑफ केआस : रिथिंकिंग इंटरनेशनल को-ऑपरेशन इन ए कॉम्पलेक्स वर्ल्ड' में की है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहायता वाले दृष्टिकोण की तुलना जंगल की आग बुझाने की भ्रमित नीतियों से की है जो 19वीं सदी में राष्ट्रीय पार्कों पर प्रयोग की गई। उन्होंने व्याख्या की कि 'आग नियंत्रण नीतियों ने जंगलों को नहीं बचाया बल्कि उन्हें निरंतर बड़े खतरे में धकेल दिया'। इसके चलते आग बुझाने के लिए हस्तक्षेप ने जंगलों की सुरक्षा के प्राकृतिक स्वास्थ्य प्रणाली में बाधा डाल दी। इसके चलते जो चेतावनी के रूप में सहज ज्ञान मिला 'छोटी आग को रोकना बड़ी आग के लिए रास्ता बना देता है'।

पर्यावरणीय व्यवस्था की तरह ही अर्थशास्त्र के लिए भी जटिल तकनीकी सोच जरूरी है, यानी कि एक रेखीय रणनीति के चलते आर्थिक परिणामों के मार्ग में असफलता हासिल हो सकती है, क्योंकि असंख्य अन्य कारक योजना के परिणामों को प्रभावित करते हैं।

ये कारक केवल संख्या में ही बहुतायत नहीं है, ये एक दूसरे पर निर्भर भी हैं। ये एक-दूसरे को किस तरह प्रभावित करते हैं उसके बारे में परंपरागत तौर-तरीके अपनाकर ठीक से भविष्यवाणी कर पाना कठिन है। ऐसे में परिवर्ती कारकों को अलग करके व जांचने के बाद ही कोई भविष्यवाणी की जा सकती है। इसके परिणाम स्वरूप सीधी-सपाट रणनीतियों के जरिये होने वाला हस्तक्षेप, अब चाहे यह साक्ष्यों द्वारा समर्थित हो, जटिल प्रणालियों के चलते लक्ष्य उलझन में फंस जाते हैं।

जटिलता का विज्ञान

विरोधाभासों की गतिशीलता से प्रेरित एक नई दिशा में शोध करने के लिए, जटिलता विज्ञान के बैनर के तहत प्रयास किया गया कि हम कैसे बेहतर विकास कर सकते हैं। एक

मामले में इस दृष्टिकोण का श्रेय 1974 में नोबेल पुरस्कार विजेता फ्रेड्रिक वान हायेक को जाता है। अपनी पुस्तक 'दि प्रिटेंस ऑफ नॉलेज' में उन्होंने विज्ञानवेत्ता बिरादरी से आग्रह किया कि वैज्ञानिक साधनों का उपयोग करते वक्त जटिल समस्याओं के निराकरण में साधनों की सीमाएं समझें। साथ ही प्रयास करें कि इन सीमाओं से ऊपर उठें। इसके लिए जरूरी है कि वैज्ञानिक साधनों को उत्कृष्ट बनाकर दक्ष कर्मियों के जरिये जटिलता दूर करें।

वैज्ञानिक सोच वाले विचारकों के लिए यह तनाव नया नहीं है। वर्ष 2015 में न्यूयार्क टाइम्स की बेस्ट सेलिंग किताब 'सुपर फॉरकास्टिंग : दि आर्ट एंड साइंस ऑफ प्रिडिक्शन' में लेखक फिलिप ई. टेटलॉक और डॉन गार्डनर लिखते हैं 'सदियों से वैज्ञानिक मानते रहे हैं कि विकसित होते ज्ञान में भविष्य बनाने की बड़ी संभावना होगी क्योंकि वास्तविकता एक घड़ी के समान है। एक बड़ी और जटिल घड़ी, लेकिन आज भी वह घड़ी है और अधिकांश वैज्ञानिकों ने यंत्र के भीतरी हिस्से के बारे में जाना, कैसे गियर साथ घूमते हैं, कैसे वजन और स्प्रिंग काम करते हैं। वे बेहतर ढंग से इसकी कार्यप्रणाली के समीकरणों को निर्धारित कर पाते हैं और बता सकते हैं कि यह क्या करेगा।

टेटलॉक और गार्डनर ने व्याख्या की कि कैसे मौसम विज्ञानी एडवर्ड लॉरेंज ने 1970 से पहले बताया कि 'वातावरण सरीख अरैखिक सिस्टम में एक छोटा-सा परिवर्तन (या गलती) शुरुआती दौर में विपुल समानुपातिक रूप में तेजी से फैल सकता है।' वहीं आर्थिक विकास के लिए, इसके मायने हैं कि कम शक्ति वाली व साधारण कार्यनीति नेतृत्व के बजाय समृद्धि को तबाह करने वाली होगी। टेटलॉक और गार्डनर ने घड़ी की तुलना के बजाय जटिल वास्तविकता के समाधान के लिए बादल का अनुकूल उदाहरण दिया। यद्यपि, बादलों के बारे में हम जानते हों, लेकिन फिर भी असमर्थ हैं। उदाहरण के लिए यह बनाने में कि उसका आकार कैसा होगा।

वे निष्कर्ष देते हैं 'पहले से आकलन न कर पाना और पूर्वानुमान जटिल रूप में विस्तारपूर्वक गुथे सिस्टम में विद्यमान होती है, जो हमारे शरीर, हमारे समाज और ब्रह्माण्ड को बनाते हैं। किसी भविष्य का आकलन इस बात पर निर्भर करता है कि हम क्या कल्पित कर रहे हैं, भविष्य में कितनी दूर और किन परिस्थितियों में भविष्य का आकलन न कर पाने और आकलन कर पाने के बीच की रेखा की प्रतिध्वनि अस्थिरता के रूप में आती है। इसे रामालिंगम रेत के डिब्बे के रूप में दर्शाते हैं और बताते हैं कि हमें इससे खेलना चाहिए, यदि हम बेहतर आर्थिक विकास चाहते हैं।'

व्यवहार में इसके मायने हैं कि एक जटिल व्यवस्था के विश्लेषण में हमें एकमात्र समाधान से परहेज करना चाहिए, जिसे रामलिंगम सर्वोत्तम कार्यपद्धति बताते हैं। वे सहायता एजेंसियों से कहते हैं कि पहले वे स्वयं को दुविधा के विकार से मुक्त करें, नई सोच अपनाएं और स्वयं समाधान थोपने के बजाय विशिष्ट संदर्भ में हल तलाशें। जब ये समाधान तलाश लें तो

उन्हें साधारण तरीके से क्रियान्वित न करें। इसके बजाय सहायता क्रियान्वयन में ध्यान रखा जाये कि नये प्रयासों की प्रकृति विकास की गति को विस्तार देने वाली हो और नेटवर्क में समाधान प्रभाव का प्रसार हो।

एक जटिल सिस्टम में समाधान तलाशने का ज्ञान बताता है कि नियम विरुद्ध वाह्य तत्त्व कैसे सिस्टम संचालन को प्रभावित कर रहे हैं। उनके द्वारा प्रस्तुत परिणामों से स्पष्ट होता है कि ज्ञान दूसरे अवयवों के साथ सिस्टम में संयुक्त रूप से विद्यमान रहता है, जो उन्हें पहचानने, मूल्यांकन और नवाचार अपनाने की इजाजत देता है। अवलोकित बाह्य ज्ञान का स्पष्ट होना तथा सिस्टम के अंतर्गत चयनित ज्ञान का उपयोग भी महत्वपूर्ण है। वास्तव में वैश्विक स्तर पर वस्तुओं, सेवाओं और विचारों का आदान-प्रदान भी मानवीय समृद्धि का महत्वपूर्ण उत्प्रेरक है। महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि कौन इसे ग्रहण करने वाला और कौन इन विचारों को व्यक्ति विशेष के लाभ के लिए अमल में लाने वाला है? बाहरी हस्तक्षेपक या व्यक्ति विशेष स्वयं?

जटिल सिस्टम में उत्पादक ज्ञान

अर्थशास्त्री रिकॉर्डो हॉसमैन और उनके सह-लेखक 'दि एटलस ऑफ इकोनोमिक कॉम्प्लेक्सिटी : मैपिंग पाथ्स टू प्रॉस्पेरिटी' में इस ज्ञान को उत्पादक ज्ञान के रूप में दर्शाते हैं। यह ज्ञान एक जटिल सिस्टम में समाधान तलाशने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हॉसमैन के अनुसार यह ज्ञान बेचने योग्य आर्थिक गतिविधियों का उत्पादन करता है। इस ज्ञान का वितरण व्यापक रूप से व्यक्तियों में होता है और एक गतिशील प्रक्रिया के जरिये उन व्यक्तियों को तलाशा जाता है जो एक-दूसरे से विभिन्न संदर्भों में जुड़े रहते हैं; मसलन बाजार में अपने लिए स्वयं फैसला लेना।

नि:संदेह, 'डिस्ट्रीब्यूटेड' शब्द का भ्रामक अभिप्राय है, जिससे बोध होता है कि किसी वाह्य व्यक्ति द्वारा वितरण के कार्य को अंजाम दिया गया है। दरअसल, ऐसा महत्वपूर्ण ज्ञान व्यक्ति में पहले ही मौजूद है जो उसने विभिन्न अनुभवों व अनुभूतियों से हासिल किया है। इसके अतिरिक्त यह ज्ञान उसमें अंतर्निहित है, जिसका अभिप्राय है कि संभव है कि उसे इसका भान न हो, वह इसका उपयोग करने में सक्षम न हो। यह भी संभव है कि यह न पहचान सके कि विकल्पों के मूल्यांकन में निर्णय कैसे लिया जाये। और अंत में सबसे महत्वपूर्ण यह कि उत्पादक ज्ञान का प्रयोग वाह्य घटकों के द्वारा किसी और की ओर से नहीं किया जा सकता है।

रामालिंगम से इतर, ऐसे लोग जो सहायता एजेंसियों की कार्यप्रणाली में सुधार चाहते हैं ताकि जटिल स्थितियों में वे बेहतर ढंग से प्रबंधन कर सकें, हॉसमैन उत्पादन अंतर को पाने के लिए देशों की क्षमता में सुधार की उम्मीद रखते हैं। वे लिखते हैं 'नीतिगत संदेश

अधिकांश देशों के लिए स्पष्ट है कि वे ऐसा वातावरण बनायें जहां उत्पादन गतिविधियों में विविधता का विकास हो सके। साथ ही उन गतिविधियों पर खास ध्यान दें जो तुलनात्मक रूप से अधिक जटिल है और अधिक अवसर उत्पन्न करती है।'

हॉसमैन और उनके सह-लेखकों ने वैश्विक व्यापार के आंकड़ों का उपयोग करते हुए एक आर्थिक जटिलता सूचकांक तैयार किया। इसकी मदद से वे परोक्ष रूप से किसी देश के उत्पादक ज्ञान का आकलन उस देश द्वारा दूसरे देश को निर्यात किये जाने वाले उत्पाद की जटिलता का तुलनात्मक रूप से मूल्यांकन कर के करते हैं। वे दावा करते हैं कि आर्थिक जटिलता आय व विकास के स्तर पर लंबे समय तक चलती है। अंर्तदृष्टि के साथ क्या करना चाहिए, इसके प्रति मार्गदर्शन के लिए उन्होंने 'कॉम्प्लेक्सिटी आउटलुक इंडेक्स' भी विकसित किया है जो किसी देश द्वारा बनाये जा सकने वाले संभावित उत्पादों का मूल्यांकन वस्तु की जटिलता और देश की उत्पादक क्षमता के आधार पर करता है। इसके साथ ही, हॉसमैन व साथियों का दावा है कि उनके मानक भविष्य के प्रगति का आकलन करते हैं जो कि किसी भी अन्य विकास साहित्य के परीक्षित आंकड़ों से ज्यादा बेहतर हैं।

यद्यपि हॉसमैन और उनके सह-लेखक अपने उपकरणों के इस्तेमाल के संबंध में ऐड एजेंसियों की कोई भूमिका निर्धारित नहीं करते हैं लेकिन वे अपनी सूचियों के विस्तृत उपयोग पर बल देते हैं जो उस व्यक्ति द्वारा उपयोग की जाती है, जिसने आर्थिक विकास में निवेश किया है। इसमें वे फर्म भी शामिल हैं जो स्थानांतरण के लिये प्रयासरत हैं या विविधता लाने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यापक आमंत्रण के बावजूद, कार्रवाई के लिए उनके अधिकांश सुझाव राष्ट्रीय सरकारों के दायरे में आते हैं। उम्मीद की जाती है कि उनके काम का प्रभाव विकासशील देशों में औद्योगिक नीति का विस्तार के तौर पर देखने को नहीं मिलेगा।

एक अंतिम कार्य जो विकासशील देश अपने देश की सरकार से कराना चाहते हैं वह यह है कि विजेता और हारने वाले का चयन बाजार में ही किया जाए अर्थात बाजार आधारित प्रक्रिया के द्वारा ही किया जाए। विकास अर्थशास्त्री विलियम ईस्टर के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से संबंधित शोध में निर्यात की सफलता में 'पॉवर लॉ' का खुलासा किया गया है जिसका आंकलन है कि कुछ घटनाओं में सामान्य वितरण की तुलना में बड़े परिणाम संभव हैं। परिणामस्वरूप, किसी एक विजेता के चुने जाने की संभावना क्षीण हो जाती है। दरअसल, ये सफलता को परिभाषित करने के लिए उपयोग की जाने वाली सीमा है। खासकर, विकासशील देशों के लिए, जिसके मायने हैं कि ऐसे जुए के लिए दांव अधिक ऊंचे हैं।

प्रभावी राहत के लिए सरकारों में सुधार

हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के मैट एंड्रयूज, लैंट प्रिटचेट और माइकल जे.वी. वूलकॉक ने 2017 में प्रकाशित 'बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी : एविडेंस, एनालिसिस, एक्शन' पुस्तक, ओईसीडी के दूसरे सिद्धांत पर केंद्रित क्षमता विकास पर ध्यान केंद्रित करने के लिए दोनों तरह के तर्क प्रस्तुत करती है। यह धुरे की कील की तरह आर्थिक विकास में सफलता के साथ-साथ सरकारी नौकरशाहों के लिए एक सुधार गाइड भी है। उनके लिए यह आर्थिक विकास की कुंजी है।

लेखक का तर्क है कि जब तक विकासशील देशों की सरकारें अधिक परिष्कृत और सक्षम नहीं बनती, तब तक लोक सहायता के लिए बने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन में वे सफल नहीं हो सकती। दरअसल, उनकी तय रणनीति का एक केंद्रीय और प्रेरक सिद्धांत यह स्वीकार कर रहा है कि संस्थानों को केवल विदेशों से प्रत्यारोपित नहीं किया जा सकता है। इसकी तुलना वे नकल करने से करते हैं। वजह यह कि वह एक जटिल सिस्टम का हिस्सा हैं, संस्थानों को स्थानीय संदर्भ में विकसित किया जाना चाहिए। इस संदर्भ में कि वे वास्तविक ज़रूरतों का प्रतिनिधित्व कर सकें। साथ ही वे स्थानीय संस्कृति व प्रथाओं की छाप लिये हों।

सरकारों की क्षमता में सुधार में मदद करने के लिए इन लेखकों ने नौकरशाहों के लिए एक कार्यक्रम तैयार किया है, जिसे वे प्रॉब्लम्स ड्रिवेन इट्रेटिव एडॉप्शन (पीडीआईए) कहते हैं। दरअसल, जटिलता विज्ञान की अंतर्दृष्टि में निहित है, पीडीआईए सरकारी टीमों को नौकरशाहों की क्षमता बढ़ाने हेतु अपने विशिष्ट रास्ते खोजने के लिए अभ्यास की एक श्रृंखला उपलब्ध कराती है। इस प्रक्रिया में उठाये जाने वाले कदमों का यहां उल्लेख जरूरी है क्योंकि वे जटिल प्रणालियों के समाधान के व्यापक लक्षणों की प्रतिध्वनि प्रकट करते हैं:

- स्थानीय नेतृत्व द्वारा नामित और प्राथमिकता के अनुरूप विशिष्ट समस्या पर ध्यान केंद्रित करना, विशेषकर स्थानीय संदर्भ में।
- प्रेरक समस्याओं को पहचानना।
- नये विचारों के साथ सक्रिय व जारी प्रयोगात्मक पुनरावृत्तियों को नये विचारों के साथ बढ़ावा देना। इन पुनरावृत्तियों से सबक लेने के लिए समाधानों को उभरने की अनुमति देना।
- निर्णय लेने के लिए एक अनुकूल वातावरण स्थापित करें जो प्रयोग और सकारात्मक विचलन को प्रोत्साहित करे।
- अत्यधिक विविध कौशल समूह के साथ सुनिश्चित करना कि सुधार व्यावहारिक, वैध और प्रासंगिक हों।

ध्यान देने वाली बात ये है कि इनमें से प्रत्येक बिंदु इस मार्ग में ऐसे प्रयुक्त किये जाते हैं जिससे बाजार की आर्थिकी के मुख्य सिद्धांत स्पष्ट होते हैं। ये एक जटिल सिस्टम में सफल आर्थिक विकास का मार्ग उन्मुख करने में सहायक हैं। उदाहरण के लिए 'स्थानीय सूत्रधारों की प्राथमिकता', जिसकी पहचान करते हुए विचारक हायक 'समय और स्थान का ज्ञान' के रूप में परिभाषित करते हैं। ये वह ज्ञान है जो व्यक्ति की प्राथमिकताओं और परिस्थितियों को लेकर होता है। इसे केंद्रीयकृत नहीं किया जा सकता है और दूसरों के द्वारा उत्पादकता के लिए हासिल नहीं किया जा सकता। यह हॉसमैन के उत्पादक ज्ञान के अनुरूप ही है।

प्रेरक समस्याओं की महत्वपूर्ण भूमिका की पहचान करते हुए अर्थशास्त्र की अंतर्दृष्टि को ही प्रतिबिंबित किया जाता है,जो प्रोत्साहन को संबल देता है। खासकर प्रिसिंपल एजेंट की समस्या को देखते हुए अनेक ऐड वर्कर का मार्गदर्शन का प्रयास करना चाहिए। व्यापक संदर्भों में, यह समस्या उन जटिलताओं को उजागर करती है, जो तब उत्पन्न होती हैं, जब कोई व्यक्ति किसी दूसरे के स्थान पर कार्य कर रहा होता है। यही वजह है कि सहायता के मामले में वाह्य भूमिका के चलते नुकसान होता है।

'पुनरावृत्तीय परिवर्तन' से परिणाम अप्रत्याशित होते हैं, लेकिन उत्पादक विकास की राह दिखाते हैं। इस सीखने और परिवर्तन की प्रक्रिया से पुराने मॉडल के खात्मे से सबंधित नया समाधान मिल सकता है। रचनात्मक विध्वंस के माध्यम से उद्यमशीलता परिवर्तन जोसेफ शुम्पेटर की अवधारणा के अनुरूप ही है। एक रेखीय आधारित विकास के प्रयास जटिल सिस्टम में केंद्रीयकृत प्रयास के चलते अप्रत्याशित लेकिन संभावित परिणाम देते हैं।

'बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी' में निर्णय लेने के लिए अधिकृत परिवेश बनाने में एक महत्वपूर्ण प्रेरणा यह है कि विकेंद्रीकृत निर्णय लेने की आवश्यक अंतर्दृष्टि से प्रगतिशील समाधान प्राप्त किये जा सकते हैं। इसी प्रकार बाजार की उत्पादक दक्षता भी विकेंद्रीयकृत संपत्ति अधिकारों में निहित है, निर्णय उन्हीं के द्वारा बेहतर लिये जाते हैं जो लागत वहन करने और निर्णयों का लाभ उठाने में सक्षम होते हैं। इस मार्ग में सभी निर्णय दुविधा से प्रभावित होते हैं। विकासशील अर्थव्यवस्था में केंद्रीय प्राधिकरण जटिल प्रणाली से युक्त व्यापारिक दुविधाओं को नहीं समझ सकते है।

अन्ततः जटिल समस्याओं की पहचान करने वाले विविध प्रकार के लोग जो विशेषज्ञता की मानसिक योग्यता रखते हैं, घातांक लाभ हासिल करने में सक्षम होते हैं। इसके अतिरिक्त, एक जटिल सिस्टम में किसी के द्वारा जीवंतता, वैधता और प्रासंगिकता कैसे हासिल हो इसका निर्धारण तीसरे पक्ष के द्वारा उसके व्यक्तिगत निर्णय से होता है। ये किसी भी पहल या उत्पाद की सफलता का समर्थन करने या समर्थन करने में विफल होते हैं। इस तरह की उपभोक्ता संप्रभुता इस बात का कतई संकेत नहीं है कि तीसरा पक्ष सर्वज्ञाता या पूरी तरह तर्कसंगत है। इसके साधारण मायने हैं कि सफलता कई स्वतंत्र कर्ताओं के कार्यों पर

निर्भर है और जब एकजुट होते हैं तो विशिष्ट योगदान के रूप में विकसित अर्थव्यवस्था का समर्थन करते हैं।

यह देखना उत्साहवर्द्धक है कि मुख्यधारा के विशेषज्ञ भी अब यह मानने लगे हैं कि आर्थिक विकास से संबंधित प्रश्नों का जवाब मूल आर्थिक विचारों में ही निहित है। हालांकि, इस बात की संभावना नहीं है फिर भी यदि स्थानीय सरकारें, अपने नौकरशाहों को उभरते समाधानों के लिए विदेशी अनुभवों का लाभ उठाने को प्रेरित करें तो विकास की कमी की समस्या का प्रभावी समाधान संभव है। दरअसल, राज्य की क्षमता को अपने स्वयं के मापकों के आधार पर, लेखकों ने अधिकांश विकासशील देशों की सफलता की संभावना सीमित रखी हैं। इस सदी के केवल आठ देश ही ऐसे हैं जो मजबूत सामर्थ्य की अपनी परिभाषा के अनुसार सही रास्ते पर बढ़ रहे हैं।

बौद्धिक योगदानों के बावजूद, जिस चौहद्दी के भीतर इन विचारकों द्वारा कार्य किया जाता है, वह बेहद ही सीमित है। अनमने तरीके से यह मान लिया जाता है कि विकास का समाधान विदेशी तकनीक ज्ञान से ही संभव है और उन विदेशियों और स्थानीय सरकारों के साथ तालमेल से उन स्थानों के लिए भी समाधान निकाल लिया जायेगा, जहां विकास सबसे ज्यादा जरूरी है। संभव है कि महत्वाकांक्षाएं कुछ कम हों, हालांकि उनकी सार्वजनिक नीति का विश्लेषण इस बात का संकेत दे सकता है कि हॉसमैन द्वारा उल्लेखित उत्पादक ज्ञान को, जटिल विज्ञान को अंतर्दृष्टि के जरिये अनलॉक करके उपयोगी बनाया जा सकता है।

सावर्जनिक नीति और राज्य की क्षमता

विभिन्न सार्वजनिक नीतियों को आगे बढ़ाने के संदर्भ में राज्य की क्षमताओं को देखते हुए एंड्रयूज व अन्य ने सरल और जटिल में अंतर करके समस्याओं के समाधान के लिए चार श्रेणियों का प्रयोग किया है। ये बेहतर ढंग से लागू करने तथा व्यवस्था को बनाये रखने के नौकरशाहों की क्षमता का प्रतिनिधित्व करते हैं:

- क्या नीतिगत लेनदेन गहन है?
- क्या इसके लिए ढेर सारे विवेकसम्मत निर्णय लेने की जरूरत होती है?
- क्या यह जनता की सेवा करता है या उन पर दायित्व का बोझ डालता है?
- क्या यह ज्ञात या अज्ञात तकनीक पर आधारित है?

क्या आपकी गतिविधि...	क्या आपकी गतिविधि सफल परिणाम दे रहा है...
गहन लेनदेन वाली है?	काम करने के लिए ज्यादा एजेंटों की जरूरत है या कम
स्थानीय स्वनिर्णयगत?	क्या अंतिम श्रेष्ठता के लिए एजेंटों से अनुबंधन करने की जरूरत है ताकि वैश्विक गुणवत्ता का श्रेष्ठता संभव हो? क्या तीसरे पक्ष के लिए ये गुणवत्ता हासिल करना कठिन है?
सेवा या अनुबंध का अधिरोपण है	क्या लोग सीधे आपके के संपर्क में हैं? क्या सफलता में एजेंट की भूमिका होती है या नहीं?
सुपरिचित तकनीक पर आधारित है	क्या वहां कोई सर्वमान्य हैंडबुक या कोई मार्गदर्शक ज्ञान की ईकाई है,जो आपको निर्देशित करे कि आपको क्या करना है या इसके लिए किसी नवाचार की जरूरत है? (केवल मात्र संदर्भ नहीं)

चित्र 5.1 की पुनर्संरचना : बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी (ऑक्सफोर्ड प्रेस, 2017) के पृष्ठ संख्या 108 पर एक गतिविधि के लिए आवश्यक सक्षमता को वर्गीकृत करने के लिए प्राप्त चार मुख्य विश्लेषणात्मक प्रश्न ।

'*बिल्डिंग स्टेट कैपेबिलिटी*' के माध्यम से लेखक का उद्देश्य दुनिया भर में राष्ट्रीय और स्थानीय सरकारों की जटिल नीतियों के बेहतर ढंग से क्रियान्वयन में मदद करना है। ये जटिलताएं कारोबार की गहनता, बुद्धिमत्ता व विवेकसम्मत निर्णय लेने में नौकरशाह एजेंटों की भूमिका, जनता पर अप्रिय दायित्व थोपने की प्रवृत्ति और नवाचार की सफलता के लिए नौकरशाही की प्रेरक भूमिका से संबंधित हैं।

नि:संदेह, वे चुने हुए कार्यों की कठिन प्रवृत्ति को देखते हैं। वे स्वीकार करते हैं कि 'सही मायनों में उन कार्यों के बारे में गंभीर चर्चा होनी चाहिए जिनके क्रियान्वयन में सरकार वास्तविक भूमिका निभा सकती है।' विशेषरूप से तब जब निजी संगठनों और दूसरे सिविल सोसायटी के प्रतिनिधि इस कार्य को बेहतर ढंग से कर सकते हैं। यह अवलोकन सरकार को सीमित भूमिका में देखता है। लेकिन वे यह सुझाव भी देते हैं कि राज्यों की क्षमता में सुधार होने पर भविष्य में इन कामों में सरकार को भी शामिल किया जा सकता है।

यहां सवाल पैदा होता है कि यदि जब दुनिया में राज्य अपनी क्षमता के लिए संघर्षरत हैं, तो क्यों न ऐसी सार्वजनिक नीतियों को प्रोत्साहित किया जाये, जो सफलता के लिए सरकार

पर कम निर्भर हों। इसका मतलब यह है कि उन नीतियों का समर्थन करना जो हर जगह दखल रखने वाले सरकार के प्रतिनिधियों पर कम निर्भर हो, नागरिकों पर बोझ कम हो। संक्षेप में कहें तो ऐसी नीतियाँ जो उनके निर्वहन के लिए जिम्मेदार लोगों की बुनियादी कार्यनिर्वाह-क्षमता पर निर्भर करती हैं।

ऐसा प्रतीत होता है कि ये इस तरह की नीतियां हैं जो जटिलता विज्ञान की अंतर्दृष्टि के लिए प्रशंसा प्रदर्शित करने में अग्रणी हैं। नि:संदेह उन्हीं लोगों के पास महत्वपूर्ण समाधान तलाशने का उत्पादक ज्ञान होता है जो कि इन कार्यक्रमों का लाभ हासिल करने वाले होते हैं। निष्कर्ष यह है तु उत्पादक परिवर्तन और विकास के लिए जरूरी निर्णयों में व्यक्ति विशेष की निर्णायक भूमिका के लिए नीतियों को लचीला बनाया जाना चाहिए।

सार्वजनिक नीति और आर्थिक आज़ादी

नोबेल पुरस्कार विजेता अमर्त्य सेन की वर्ष 1999 में प्रकाशित पुस्तक 'डेवलेपमेंट एज फ्रीडम' में इन दो विचारों के बीच के अगंभीर संबंधों का विवरण दिया गया है। वे लिखते हैं कि 'स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का उपयोग अवश्यंभावी परिवर्तन के विश्लेषण के मूल्यांकन और अपेक्षित तीव्र विकास के लिए विस्तृत व भविष्य में होने वाले तीव्र परिवर्तन में स्वतंत्रता की भूमिका का विश्लेषण करने की दोहरी भूमिका में होता है।'

नि:संदेह, जटिल प्रणालियों के भीतर स्वतंत्रता समाधानों के लिए उर्वरा भूमि तैयार करती है। यदि सरकारों व सहायता एजेंसियों का आर्थिक विकास पर सकारात्मक प्रभाव दृष्टिगोचर होता है तो उसका मूल्यांकन स्वतंत्रता के संदर्भ में देखा जाना चाहिए। अमर्त्य सेन व्याख्या करते हैं कि बाजार के संचालन से जुड़ी विभिन्न सामाजिक संस्थाएं मसलन प्रशासन, विधायिका, राजनीतिक दल, गैर-सरकारी संगठन, न्यायपालिका, मीडिया और समुदाय के संचालन से जुड़ी विभिन्न सामाजिक संस्थाएं, जो अपने प्रभाव से विकास की प्रक्रिया में योगदान देती हैं, व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ाने व संरक्षण देने वाली होती हैं।

फ्रेजर इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ दि वर्ल्ड रिपोर्ट हो या वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, बड़ी संख्या में मौजूद ऐसी जगहों का उल्लेख करती है, जहां ऐसी नीतियों की बहुलता है, जिसमें इन देशों में व्यक्तिगत आर्थिक पसंद और सरकार के कार्यक्षेत्र की संभावना और कार्यप्रणाली को आंका जाता है। दोनों ही रिपोर्ट व्यापार को सरल व कम लागत वाला बनाने वाली नीतियों के प्रभाव को दर्शाती हैं। साथ ही सीमाओं के आर-पार के कारोबार को सहज व सस्ता बनाने, संपत्ति के पंजीकरण के अलावा निर्माण परमिट हासिल करने को सस्ता व सरल बनाती हैं। क्रमश: दोनों रिपोर्ट अपेक्षाकृत छोटी सरकारों को अनावश्यक नियमों से परहेज के लिए प्रेरित करती हैं।

नि:संदेह, अच्छी नीतियां, यहां तक कि इनमें से कुछ वैश्विक सूची में शामिल हैं, समर्थ और सक्षम सरकारों द्वारा समर्थित मजबूत संस्थानों की जरूरत होती है। सवाल यह है कि सरकारों द्वारा इन चीजों को करने की संभावना कितनी होती है। जैसा कि एंड्रयूज और अन्य परामर्श देते हैं कि हम बहस तो करते हैं, लेकिन वे अपने उन कामों तक ही सीमित हैं, जो कि वास्तव में जरूरी हैं।

इस मामले में भी, वाह्य घटक भारी गलती कर बैठते हैं जब वे आर्थिक लक्ष्यों को हासिल करने के लिए दूसरों की मदद करते हैं। वे तब भी गलती करते हैं जब दूसरी सरकारों से अपनी संस्थाओं को मजबूत करने में मदद लेते हैं। अमेरिकी जर्नल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड सोशियोलॉजी में प्रकाशित एक लेख में पीटर बोएत्के, क्रिस्टोफर कॉइन और पीटर लेसन 'चिपचिपा' जैसा शब्द प्रयोग करते हैं, यह बताने के लिए कि कैसे संस्थान सफलतापूर्वक अपने देश में डटे रहते हैं। उनके विश्लेषण में लसलसा या चिपचिपा का क्या अभिप्राय है, वे निष्कर्ष देते हैं कि जब स्थानीय कर्ता सुधार की प्रक्रिया का नेतृत्व करते हैं तो संभावनाएं सर्वोत्तम होती हैं।

यही वजह है, थिंक टैंक यदि सबके लिए आर्थिक विकल्पों के विस्तार पर ध्यान केंद्रित कर रहे तो मकसद प्रभावी परिवर्तन के लिए सर्वोत्तम अवसर उपलब्ध कराना है। दरअसल, यह नागरिक उद्यमशीलता है जो यह निर्धारित करती है कि किन सुधारों की आवश्यकता है। इनमें से किसे हकीकत बनाना संभव है। साथ ही स्थानीय संदर्भ में प्रासंगिकता व स्थिरता को किस तरह हासिल किया जा सकता है।

जटिल प्रणाली में उत्पादक ज्ञान उजागर करना

दि इकोनिमक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड रिपोर्ट और डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में बड़ी संख्या में सुधार के मायने ये हैं कि हम अधिक से अधिक खुद को गरीबी की दलदल से बाहर निकाल सकते हैं। उदाहरण के लिए भारत में सेंटर फॉर सोसायटी मोदी सरकार को इस बात पर सहमत कराने में सफल रही है कि नये कारोबार शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की अनिवार्यता को समाप्त किया जाये। यह एक ऐसी नीति है जो गरीबों पर गैर-अनुपातिक रूप में बोझ डालती है। एंड्रयूज व सहयोगियों के अनुसार एक जटिल परिदृश्य नौकरशाही की क्षमता को बेतहाशा बढ़ाती है। इसका समाप्त होना आर्थिक विकास की एक जीत है।

नि:संदेह, इस तरह के परिवर्तन जटिल विज्ञान में अंतर्दृष्टि देते हैं। आर्थिक विकास के लिए जो ज्ञान जरूरी है वह गरीबी में रह रहे उन लोगों के पास है, जो कि इस बात का आकलन करने में सक्षम स्थिति में है कि उनके पास नया व्यवसाय शुरू करने के जोखिम के लिए पर्याप्त पूंजी है। नि:संदेह यह आगे की राह तय करने का बेहतर तरीका है कि सहायता एजेंसियों को अनुकूल बनने दें, या नौकरशाहों को अधिक सक्षम बनने दें, या फिर देश की

सरकार को विजेताओं या हारने वालों को चुनने के लिए बाजार का प्रयोग करने दें। दरअसल, ये उपक्रम गरीबी कम करने वाले अग्रदूतों की आर्थिक प्राथमिकता के विस्तार के लिए कुछ नहीं करते बल्कि गरीब लोगों को खुद ही करना होता हैं।

बतौर बाहरी, हम स्वतंत्रत शोध का समर्थन करके अपना दायित्व निभा सकते हैं और स्थानीय बौद्धिक नेतृत्व द्वारा संचालित थिंक टैंक का समर्थन कर सकते हैं जो जानते हैं कि उनके देश के भविष्य की आर्थिक सफलता सभी लोगों के लिए अवसरों के विस्तार से तभी संभव है, जबकि उनकी सरकारें उनके नाम पर कम से कम आर्थिक नियोजन करे। नि:संदेह यह ओईसीडी सिद्धांतों की भावना के ही अनुरूप है, जो स्थानीय स्तर पर समाधान की बात करता है तथा उन्हें उनके नैसर्गिक निष्कर्ष की ओर ले जाता है।

एंड्रयूज, रामालिंगम और हॉसमैन से जुड़ी टीम ने आर्थिक जटिलताओं के प्रति हमारी सोच विकसित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है और फिर भी उस बढ़े ज्ञान का उपयोग करने के लिए उनकी उम्मीदें केंद्रीयकृत निर्णय लेने वाली सहायता एजेंसियों तथा राष्ट्रीय सरकार पर टिकी हैं। एक जटिल सिस्टम में अंतर्दृष्टि के समाधान को गंभीरता से लेने की जरूरत है, ताकि व्यक्ति विशेष स्वतंत्र रूप से गतिशील प्रक्रिया युक्त समाधान तलाश सके। यह केंद्रीयकृत व्यवस्था के ऊपर से नीचे तक के भागीदारों से ज्यादा उम्मीद जगाने वाली है। फिर भी बड़ी विचारधारा का प्रतिनिधित्व करने वाली इस अंतर्दृष्टि को कम करके ही आंका जाता है। नि:संदेह यह एक अवसर है विश्व में दूसरों की मदद करने का नजरिया बदलने का, क्योंकि विकासशील अर्थव्यवस्था में उत्पादक ज्ञान को व्यापक रूप से बांटा जाता है। हमारी पहली प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना होना चाहिए कि इस हम उत्पादक ज्ञान के उपयोग में हस्तक्षेप या बाधा तो नहीं डाल रहे हैं।

हॉसमैन अपने लेखन के दौरान इस बात को बेहतर ढंग से प्रस्तुत करते हैं। वे लिखते हैं, 'आधुनिकता का रहस्य यह कि हम सामूहिक रूप से ज्ञान के भंडार का उपयोग करते हैं, जबकि हम से प्रत्येक के पास इसका कुछ ही अंश होता है।' तब महत्वपूर्ण यह है कि हमें बाहरी लोगों तथा सरकारों को ज्ञान को केंद्रीयकृत करने से रोकना है और इसे उजागर करना है। दरअसल, हम दूसरों की आर्थिक समस्याओं को हल करने के प्रयासों का विरोध करते हैं, उतना ही हम स्थितियों में सुधार करते हैं। रामलिंगम ने हमें प्रोत्साहन के लिए यह सूत्र वाक्य दिया है, 'भले ही वैश्विक कल्याण का एक संकुचित, सरल, यंत्रवत् न्यूनतावादी रूप में परोपकारवाद हमारी विरासत हो, लेकिन आवश्यक नहीं कि यही हमारा मुकद्दर हो।'

खंड 2:

थिंक टैंकों का प्रभाव और उनका माप

‘वाह्य घटकों की दुविधा’ के प्रकाश में, स्थानीय थिंक टैंकों के द्वारा सामाजिक परिवर्तन को हासिल करने के लिए स्थानीय नेतृत्व का समर्थन करने के कार्य का अल्प मूल्यांकन किया जाता है। पिछले दो दशकों की स्थिति पर ध्यान दें तो स्थानीय थिंक टैंकों की संख्या और विशेषज्ञता दोनों में वृद्धि हुई है। उदाहरण के लिए, देखें तो आज स्वतंत्र भागीदारों के रूप में एटलस नेटवर्क की सूची में 95 देशों के 480 से अधिक थिंक टैंक्स हैं। वे संगठन स्थानीय ज्ञान और स्थानीय प्राथमिकताओं के आधार पर स्थानीय परिवर्तन के लिए अनूठी दृष्टि प्रदान करते हैं। ऐसे में यह तय करना कठिन है कि क्या और कौन समर्थन योग्य है।

भलाई के कार्यों को करने के दौरान कई लोग उन कार्यों के प्रभाव और उनके मापन जैसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर उधेड़बुन में रहते हैं। यही वह क्षेत्र है, जिसे वाह्य घटक प्रभावित करते हैं और जवाबदेही के नाम पर सफलता के संभव मार्गों को बाधित कर सकते हैं। हालांकि, समन्वय स्थापित किया जा सकता है। कई सिद्ध तरीके हैं जैसे कि दानदाता दिये जाने वाले दान को लेकर अधिक न्यायसंगत हो सकता है, उच्चस्तरीय जवाबदेही तय कर सकता है और इन सबके बीच परिवर्तन के लिए स्थानीय दृष्टिकोण और रणनीति में हस्तक्षेप से बचा बी रह सकता है। यह खंड कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाओं और सहायक शोध का परिचय देता है, जिनके अनुपालन का एटलस नेटवर्क समर्थन करता है। यह खंड एटलस नेटवर्क की रणनीति के पीछे के सिद्धांतों का उल्लेख करते हुए वर्तमान और संभावित अनुदानों के नेटवर्क में नवाचार और महत्वाकांक्षा का भी विवरण देता है।

इस खंड के लेखों के संस्करण AtlasNetwork.org पर उपलब्ध हैं।

लक्ष्य निर्धारित करना : थिंक टैंक की सफलता का मूल्यांकन

मैट वार्नर

मैं अपने पिताजी के साथ पूल (बिलियर्ड्स) खेलकर बड़ा हुआ हूं। हमने 'नो स्लोप' खेला, जिसका मतलब है कि आपको क्यू बॉल को मारने से पहले अपने शॉट को बताना पड़ता था। यदि आप अपनी गेंद को इस तरह से डालते हैं, जैसा आपने इरादा नहीं किया है, तो आपको इसे बाहर निकालना होगा, इसे वापस टेबल पर रखना होगा, और अपनी बारी खोनी होगी।

नि:संदेह इस सिद्धांत की शक्ति का प्रदर्शन उसी प्रकार से किया जाता है जैसे हम लोग बेबे रूथ जैसे खिलाड़ियों के सधे खेल की सफलता से प्रफुल्लित होते हैं। कहानी यह है कि एक मैच में, 'स्वात के सुल्तान' ने आउटफील्ड से बाउंडरी की तरफ इशारा किया ताकि वह चाहरदीवारी के बाहर स्विंग करने के अपने इरादे को पूरा कर सकें। ज़ाहिर है, जब वह एक रन हिट करता था, जैसा कि वह संकेत देता था कि वह एक हिटर के रूप में अपने कौशल को हकीकत में बदल देता है।

विशिष्ट परिणाम प्राप्त करने के लिए किसी के इरादे की सार्वजनिक रूप से घोषणा करके उसे क्रियान्वत करने की इच्छा तेजी से सफल गैर-लाभकारी नेताओं के लिए एक महत्वपूर्ण अभ्यास बन रही है।

वर्ष 2016 में अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक लिबर्टाड वाई प्रोग्रेसो (एलवाईपी) ने लैपटॉप और टैबलेट जैसी गैजेट्स पर अन्यायपूर्ण ढंग से कर लगाने के विरोध में जन-जागरण अभियान चलाने की घोषणा की। इस मुहिम में एलवाईपी टीम ने एटलस नेटवर्क के साथ अपनी रणनीति साझा की और उस विश्वास की तार्किक व्याख्या की, जिसके चलते उन्हें लगता था कि कर की बढ़ी हुई दर वापस हो जायेगी। इस तरह से 'उनके शॉट को कॉल करना' यानी निर्धारित लक्ष्य के बारे में बात करने से हमारे लिए उनके काम का अनुदान के साथ समर्थन करने का फैसला करना आसान हो गया। बिना किसी शक और सुबहा के हम यह जान सकेंगे कि हमारा निवेश काम आया या नही।

एलवाईपी द्वारा इस कार्य के लिए अपेक्षाकृत छोटी समय सीमा तय की गई थी। हमे पता था कि उन्हें आश्वस्त होकर उनके काम का श्रेय दिया जा सकता था।

2017 की गर्मियों तक, शोध और समर्थन (एडवोकेसी) के कठिन अभियान के बाद जो निष्कर्ष निकल कर सामने आया वह एक शक्तिशाली था। अर्जेंटीना में बढ़े टैरिफ को निरस्त करना पड़ा। मुझे विश्वास है कि एलवाईपी के कार्य ने ईच्छित परिणाम हासिल किये। उनके नेतृत्व ने जिस प्रकार का विश्वास दिखाया था और जिस प्रकार एक निश्चित लक्ष्य के प्रति जवाबदेही दर्शायी थी, मैं इस सारे कार्य का श्रेय उसे ही देता हूं।

दरअसल 'कॉलिंग योर शॉट' का सिद्धांत, लक्षित वर्ग में अपनी विश्वसनीयता बढ़ाने तक ही सीमित नहीं है। जब इसे पूरी तरह आत्मसात किया जाता है तो इससे संगठन की रणनीतियों को क्रियान्वित करने की राह आसान होती है। एक बार जब टीम द्वारा विशिष्ट लक्ष्य निर्धारित कर लिया जाता है और घोषणा कर दी जाती है, तो इस दिशा में होने वाली गतिविधियों पर ध्यान अधिक केंद्रित और अनुशासित हो जाता है और चीजें और अधिक स्पष्ट हो जाती हैं।

दरअसल, कार्यनीति पर होने वाली बहस, लोकप्रिय, परिचित और सुरक्षित कार्यों जैसे दिशाहीन निष्कर्षों के प्रति संवेदनशीलता कम करती है। इसके चलते पुरानी गलतियों का दोहराव मुश्किल हो जाता है। इस प्रक्रिया को हार्वर्ड की टीम 'तुल्यकारी नकल' की संज्ञा देती है, जिसमें में हम सफल मित्र समूहों की नकल करके सफल होना चाहते है। मेरे अवलोकन में इसका कारण वह गलती होगी, जिसमें भ्रम है कि वास्तविक सफलता क्या है। दरअसल, एक सफल संगठन बनाने के तरीके तलाशने के बजाय लक्ष्य यह हो जाता है कि संगठन कैसे सफल दिखे। एक समय में भले ही इसका अंतर सूक्ष्म हो, लेकिन वास्तव में इसके परिणाम गहरे होते हैं।

बोस्टन में आयोजित कार्यशाला में भाग लेने के दौरान मुझसे नॉन प्रॉफिट गुरु डैन पल्लोटा ने अपने शुरुआती दिनों में उस कहानी का जिक्र किया, जिसमें एड्स अनुसंधान हेतु धन जुटाने के लिए सफल आयोजन किये गये। कुछ अप्रत्याशित सफलताओं के बाद, डैन पल्लोटा ने सफलता की गति को बरकरार रखने के लिए कार्यक्रमों के लिए नये शहरों की सूची और आगामी कार्यक्रमों की तारीखों की घोषणा करने का फैसला किया। इस फैसले से उनकी टीम उलझन में थी क्योंकि उन शहरों में कार्यक्रम के आयोजन के लिए उनके पास कोई संसाधन नहीं था। पल्लोटा ने सिर्फ इतना ही कहा कि हम 'हम बेहतर करेंगे!' और, निश्चित रूप से, उन्होंने वास्तव में प्रयास किये और उसको हकीकत बनाया।

मैं इस बात की सलाह नहीं दे रहा हूं कि गैर-लाभकारी संगठनों के नेता हवाई बातें करने की आदत डालें। लेकिन यह कहानी एक महत्वपूर्ण संकेत अवश्य देती है कि हमें किस तरह के नेता चाहिए। क्या हम स्वयं को एक सार्वजनिक लक्ष्य के प्रति जवाबदेह बनाने के

लिए तैयार हैं? क्या हम तब भी महत्वाकांक्षी होने को तैयार हैं जबकि हम यह नहीं जानते कि सफलता कैसे प्राप्त करेंगे?

यदि हम लक्ष्य हासिल न कर पाये तो क्या होगा? बेशक यह संभव है। लेकिन मेरा मानना है कि अगर हम उच्च लक्ष्य रखते हैं और परिणाम कुछ कम भी रह जाए, फिर भी हमारे पास मौजूदा चीजों से अधिक ही होगा। अगर हम दृढ़निश्चय हो जायें और निर्धारित लक्ष्यों की सफलता के लिए प्रतिबद्ध हैं, तो हमारी असफलताएं हमें अलग तरीके से करने की एक बेहतर दृष्टि प्रदान करेगी। इस प्रकार हम सफल लक्ष्य प्राप्ति के लिए और भी मजबूत मार्ग प्रशस्त करेंगे। मैंने यह भी देखा है कि जब तक हम अपनी प्रगति के बारे में पारदर्शी रहते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि असफलता के जवाब में हम नई योजनाओं के लिए अपनी प्रतिबद्धता को जाहिर कर रहे हैं, तो जिन्होंने हमारा समर्थन किया है, उनका विश्वास बना रहेगा।

'अपने लक्ष्य को भेदने के लिए साहस दिखाना महत्वपूर्ण है।' गैर-लाभकारी क्षेत्र में, जब भी हम अपने सेक्टर का नाम लेते हैं हमारे जेहन में अत्यधिक केंद्रीयकृत प्रवृत्तियां ताजी हो जाती हैं। दरअसल, लाभ का मापदंड न होने के कारण सफलता मापने का हमारे पास कोई प्राकृतिक पैमाना नहीं है। ऐसे में मार्जिन के अभाव में नवाचार और असफलता ही इसके दो विकल्प हैं। इसके बजाय, हमें नवाचार के लिए अपने मानक बनाने होंगे। हम जो पहले से ही आराम से करना जानते हैं उससे आगे पहुंचकर और फिर परिणामों के एक विशिष्ट समूह के लिए खुद को सार्वजनिक रूप से जवाबदेह ठहराते हुए, हम नवाचार और सफलता के लिए एक मार्जिन बनाते हैं जो हमारे आगे के मार्ग को स्पष्ट करता है।

अन्य गैर लाभाकारी संगठनों के लिए सेवा संगठन के तौर पर एटलस नेटवर्क सदैव उन बातों पर अमल करना चाहता है जिसका उपदेश यह दूसरों को देता है। तो हमने अपने लिए किस लक्ष्य को निर्धारित किया है? हमारा लक्ष्य है कि हम दुनिया भर से 10 लाख लोगों को गरीबी से बाहर

एक सेवा संगठन के रूप में, अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं के लिए एटलस नेटवर्क हमेशा जो कहता है वह करता है। अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए क्या कर रहे हैं? पहले, हम दुनियाभर में 1,000,000 लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में योगदान देना चाहते हैं।

हमने इसे अपना लक्ष्य बनाया है। क्या यह महत्वाकांक्षी है? हां।

क्या हम जानते हैं कि यह कैसे करना है? नहीं, लेकिन हमारे पास एक योजना है।

पिछले दो वर्षों में हमने इस लक्ष्य को प्राप्त करने के तरीके के बारे में बहुत कुछ अप्रत्याशित सीखा है। हमने अपने गैर-लाभकारी क्षेत्र में सबसे अधिक आशाजनक परियोजनाओं के लिए प्रति वर्ष 5 मिलियन डॉलर का पुरस्कार देने वाली एक मजबूत और

अत्यधिक चयनात्मक अनुदान प्रक्रिया का निर्माण किया है, जो विशिष्ट परिणामों की गणना कर अपने लक्ष्य को पूरा करने के लिए प्रयास करते हैं। उन अनुदानों का एक हिस्सा परियोजनाओं में जाता है, जैसे कि अर्जेंटीना में टैरिफ निरसन, जो लोगों के लिए रोजाना आर्थिक विकल्पों का विस्तार करना चाहता है।

हर साल, हम और अधिक करने की योजना बनाते हैं। कृपया इसे हमारी जवाबदेही मानें। हम यह निश्चित रूप से नहीं जानते हैं कि हम सफल होंगे, लेकिन, बेबे रूथ की तरह, हमें विश्वास है कि हम यह कर सकते हैं। हम इसे आगे ले जाने के लिए हर तरह से खुद को व्यवस्थित कर रहे हैं।

यदि आप एक गैर-लाभकारी संगठन नेता के रूप में इस वर्ष बड़ी सफलता हासिल करना चाहते है तो हम जानना चाहेंगे कि आपने इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए क्या रणनीति बनाई है ताकि हम आपका हौसला बढ़ा सकें और वैश्विक समृद्धि की बाधाओं को दूर करने का प्रयास कर सकें।

विस्तृत कार्य क्षेत्र का निर्धारणः थिंकटैंकों के नेतृत्व के लिए वैश्विक नेटवर्क

मैट वार्नर

कार्यकारी सारांश

सवाल है कि लाभ के मकसद के बिना, क्या गैर-लाभकारी नेता लाभ के लिए काम करने वाले अपने समकक्षों की तुलना में नवाचारी और सफल हो सकते हैं? अनुभव से पता चलता है, एक प्रकार की प्रेरणा है जो लाभ के लिए मुहिम को आगे बढ़ाती है, और यह गैर-लाभकारी नेताओं के व्यवहार को प्रभावित करने के साथ-साथ परिणामों में सुधार की ओर भी आगे बढ़ा सकती है। इसे सामाजिक तुलना के नाम से जाना जाता है और शोध से पता चलता है कि यह प्रेरणा पैसे से भी अधिक शक्तिशाली हो सकता है।

पहली बार जब मैंने अपनी पत्नी के साथ ग्रेट फॉल्स का दौरा किया, तो वाशिंगटन, डी.सी. के ठीक उत्तर में पोटोमैक नदी पर एक राष्ट्रीय उद्यान था, हम इसके बारे में कुछ नहीं जानते थे। हमने मैरीलैंड नदी के किनारे किनारे जाने का निर्णय किया और जंगल में जल प्रपात की ओर संकेत करते संकेतकों के साथ चलना शुरू कर दिया।

तकरीबन 100 गज की दूरी के बाद, हम एक छोटे झरनों की खूबसूरत शृंखला से रूबरू हुए, वे उस फुटब्रिज के नीचे से गुजरते थे, जहां हम खड़े थे। वहां पानी तेजी और तेज आवाज के साथ बह रहा था। फ्लोरिडा में बढ़ते हुए हमने पाया था कि वहां सपाट ऊंचाई के साथ कुछ झरने थे, जिसने हम दोनों को प्रभावित किया।

वहां चंद तस्वीरें लेने के उपरांत, हमें आश्चर्य हुआ कि आगे बढ़ने के निशान गायब हैं। दरअसल, वहां लोग दोनों दिशाओं से आ रहे थे, इसलिए हमने नीचे की तरफ रास्ते पर चलते रहने का फैसला किया। एक मिनट से भी कम समय बाद हमने जल बहाव की आवाज को महसूस किया। पानी के बहाव में विस्तार आवाज कम हुई और मंथन करता नजर आया। शीघ्र ही इसका विस्तार देखने में आया।

सही मायनों में जल प्रपात वास्तव में अद्वितीय थे। काफी ऊंचाई से जल प्रवाह के सौंदर्य से हम आश्चर्यचकित थे। हमें यह सोचकर अपनी अज्ञानता पर हंसी आई कि हमने कुछ ही मिनट पहले जो देखा था, वह बामुश्किल इसका 1/100 वां हिस्सा था जो अब हमारे सामने मुख्य आकर्षण था।

सवाल उठता है कि आखिर क्या निर्धारित करता है कि झरने महान हैं? हम शुरू में क्यों बहुत छोटे फॉल्स से संतुष्ट थे? यदि आप इस संबंध में विचार करें, तो यह वही बात है जो निर्धारित करती है कि क्या गैर-लाभकारी परिणाम महान हैं या नहीं। यह उनकी तुलना के बाबत है।

तुलना की ताकत

कह सकते हैं कि तुलना कुछ कुछ सार्वभौमिक, यहां तक क मानव व्यवहार के केंद्र में है। सामाजिक मनोवैज्ञानिक लियोन फेस्टिंगर को संभवतः संज्ञानात्मक विसंगति के जनक के रूप में जाना जाता है। संज्ञानात्मक विसंगति अर्थात एक ही समय में दो परस्पर विरोधी विश्वास रखने की प्रथा। मगर 1950 के दशक में फिस्टिंगर के शुरुआती कार्य को उन्होंने सामाजिक तुलना सिद्धांत कहा था : हमें इस अंतर्दृष्टि से परिचित करना कि एक सामाजिक प्राणी के रूप में हमारे आत्म-मूल्यांकन दूसरों की राय से बहुत प्रभावित होते हैं।

दशकों बीत जाने के बाद शोधकर्ताओं ने फिस्टिंगर के इस सिद्धांत के मूल विचार को मान्यता दी है। उदाहरण के लिए, वर्ष 2014 में, तीन अलग-अलग अध्ययनों में शिक्षाविदों ने पाया कि सामाजिक तुलना का प्रभाव इतना शक्तिशाली है कि जब लोग खुद के महारत-आधारित लक्ष्यों का उपयोग मूल्यांकन के लिए निर्धारित करते हैं, तो मूलत: वे तुलना-आधारित सूचना से खासे प्रभावित होते हैं।

यहां एक सर्वविदित उदाहरण है। अपने कॉलेज में अपनी पहली भौतिकी प्रश्नोत्तरी में 75 प्रतिशत अंक हासिल करने की कल्पना करें, लेकिन संतुष्टि-सी नहीं होती, निराशा का भाव। आप कैसा अनुभव करोगे? यदि आपको विषय में दक्षता हासिल है, तो शायद आप स्वयं के प्रदर्शन से निराश और असंतुष्ट महसूस करेंगे। लेकिन वहीं दूसरी ओर कल्पना कीजिए कि आप कक्षा में आते हैं और जानकारी मिलती है कि कुल 40 छात्रों की कक्षा में आपके नंबर सबसे ज्यादा हैं। अब आप कैसा महसूस करते हैं? प्रफुल्लित? गर्वति? आखिर क्या बदल गया? इस नजरिये में बदलाव की वजह ही सामाजिक तुलनात्मक जानकारी का अत्यधिक प्रभाव का होना है।

सामाजिक तुलना के कुछ अन्य आश्चर्यजनक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। उदाहरण के लिए, यह बताती है कि प्रायोगिक रूप में कुछ लोग कम पैसे को प्राथमिकता देते हैं अगर

उनकी आय उनके साथियों से अधिक है। निष्कर्ष यही है कि वे सापेक्ष आय हीन भाव के अभाव में अधिक से अधिक धन छोड़ देंगे।

यह हमें यह पुनर्विचार के लिए प्रेरित करता है कि लाभ के उद्देश्य के प्रति वर्चस्व का भाव हमें सफलता का एहसास कराता है। बेशक, धन और लाभ दूसरों से तुलना करने के लिए सबसे उपयोगी उपायों का प्रतिनिधित्व करते हैं, लेकिन जब यह धन प्रेरणा के लिए प्रेरित कर सकता है, तो यह एक लक्ष्य के बजाय एक साधन के रूप में अधिक कार्य करता है।

नि:संदेह, यह गैर-लाभकारी नेताओं के लिए अच्छी खबर है क्योंकि इसके मायने हैं कि एक फर्म के रिटर्न के बीच सामान्य अंतर और दूसरे का दो गैर-लाभकारी नेताओं की उपलब्धियों के बीच मामूली अंतर के अनुरूप है। युक्ति उस अंतर को निर्धारित करने की कोशिश करने वाले गैर-लाभकारी समस्या को अलग करने के लिए है और इसके बजाय हम इस बात पर विचार करें कि अपने क्षेत्र में सामाजिक तुलना जानकारी की मात्रा, प्रासंगिकता और प्रभाव को कैसे बढ़ा सकते हैं।

अलाभकारी सफलता में सामाजिक तुलना की भूमिका

यह स्पष्ट है कि तुलना के घटित होने के क्रम में, गैर-लाभकारी नेताओं को समकक्षों की आवश्यकता होती है। यह कम ही जाना जाता है कि सामाजिक मनोविज्ञान हमें उन साथियों के प्रकार के बारे में सिखा सकता है, जिन्हें हमें तलाशना चाहते हैं। खास किस्म का वातावरण सामाजिक तुलना-आधारित जानकारी की गुणवत्ता बढ़ाने में सहायक होता है। महत्वाकांक्षी गैर-लाभकारी नेता के लिए, उन अंतर्दृष्टि को सीखना और लागू करना मध्यम सफलता को बनाए रखने और उत्कृष्टता के नए मानकों को तराशने के बीच का अंतर हो सकता है।

रिचर्ड डुराना स्लोवाकिया में एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक के प्रमुख हैं। कोपेनहेगन में एटलस नेटवर्क के यूरोप लिबर्टी फोरम में चार गहन दिन बिताने के बाद, उन्होंने मुझसे कहा, 'मैं इन आयोजनों को मानसिक रूप से उद्वेलित करने वाला (माइंडक्वेक) कहता हूं। इस अभियान में प्रतिभाशाली विचारकों से मिलना, मेरी नसों में नई प्रेरणा और ऊर्जा के प्रवाह को तीव्र करता है।'

रिचर्ड डुराना का रचनात्मक शब्द, 'माइंडक्वेक,' स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि जब आप प्रबुद्ध लोगों से एक साथ मिलते हैं तो क्या संभव हो सकता है। लेकिन अकस्मात लाभ नहीं है। मिशिगन विश्वविद्यालय और नोट्रे डेम विश्वविद्यालय के शोधकर्ता बताते हैं कि तीन ऐसे आयाम हैं, जो साथियों के बीच प्रतिस्पर्धी शक्ति के स्तर को प्रभावित करने वाले, प्रासंगिकता, समानता और निकटता के रूप में दर्शाये गये हैं। यहां यह विचारणीय है कि उनकी सफलता में तुलना के बिंदु कितने प्रासंगिक हैं? वे एक-दूसरे से कैसे समान हैं? वे

व्यक्तिगत रूप में अपने रिश्ते में कितने करीब हैं? मेरे विचार से कई थिंक टैंक नेता सहज रूप से उन आयामों पर जोर देते हैं, जब वे एटलस नेटवर्क के कार्यक्रमों के अनुभव को दर्शाते हैं।

मिशिगन में एक थिंक टैंक के अध्यक्ष हैं जो लेहमैन। लेहमैन और उनका संगठन व्यापक रूप से इस तरह के काम के सफल उदाहरण के रूप में सराहे जाते हैं। यदि आप जो उनकी सफलता रहस्य पूछते हैं तो इसके मूल में ऐसे साथियों की तलाश करने की कार्यप्रणाली है, जो तुलना के प्रासंगिक आयामों का प्रतिनिधित्व करते हैं। विशेष रूप से, वह बताते हैं, 'मेरे लिए सुधार करने का सबसे असरदार तरीका उन लोगों को खुद के साथ जोड़ना है, जो किसी भी चीज़ में मुझसे बेहतर हैं। आमतौर पर यह सीईओ की अदला बदली के दौरान होता है।'

फाउंडेशन फॉर गवर्नमेंट अकाउंटेबिलिटी के संस्थापक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी टेरेन ब्रैगडन ऐसी समानता के लाभों को तब प्रबलित किया जब उन्होंने मुझे यह कहने के लिए लिखा, 'एटलस नेटवर्क का सीईओ शिखर सम्मेलन मेरे लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। मैं इससे सीखता हूं, प्रेरित होता हूं, और अपने समकक्षों द्वारा चुनौती पाता हूं। वे जो मेरी दुनिया को समझते हैं जैसे कोई और नहीं समझ सकता।' एक अन्य थिंक टैंक नेता, लंदन स्थित मार्क लिटलवुड, आर्थिक मामलों के संस्थान के जनरल डायेरक्टर हैं। उन्होंने नेटवर्किंग के माध्यम से निकटता पैदा करने के महत्व को रेखांकित किया, जब उन्होंने एटलस नेटवर्क के कार्यक्रम में अपने समय का आकलन करते हुए कहा, 'मैं कभी भी धरती पर किसी भी ऐसे कार्यक्रम में नहीं आया हूं जिस पर मैंने अपने समकक्षों के बीच तमाम महत्वपूर्ण व्यक्तित्वों और पेशेवर लोगों से व्यक्तिगत और पेशेवराना मित्रता स्थापित की है।'

अपने समकक्षों को चुनना

प्रासंगिकता, समानता, और निकटता ये तीन आयाम ऐसे हैं जो गैर-लाभकारी नेताओं के लिए एक अवसर का आकलन करते हैं कि उनके सहकर्मी उनकी सफलता को कितना प्रेरित करते हैं। सौभाग्य से, असंतोषजनक आकलन घातक नहीं होता है।

अपनी पुस्तक 'चूजिंग द राइट पॉन्ड : ह्यूमन बिहेवियर एंड द क्वेस्ट फॉर स्टेटस' में अर्थशास्त्री रॉबर्ट फ्रैंक का आकलन है कि इस बात का चयन करने में हम काफी हद तक सक्षम होते हैं कि हमें अपनी तुलना किससे करनी है। हमारे पास हमारे 'तालाब' (पांड) को चुनने की हमारी मुहिम को प्रभावित करने की क्षमता है कि हमारी सफलता की गति धीमी हो या हमें और भी अधिक प्राप्त करने के लिए प्रेरित करे। हम सभी ने 'बड़ी मछली, छोटे तालाब' की अभिव्यक्ति को किसी ऐसे व्यक्ति के वर्णन करने के लिए सुना है, जो साथियों

के व्यापक समूह में उतना ऊंचा कद हासिल नहीं कर सकता जितना कि उसे उसके घर में प्राप्त है।

अंत में, कोई भी 'बड़ी मछली, छोटे तालाब' सिंड्रोम का शिकार नहीं होना चाहता, यह मानना कि आप पहले से ही सबसे अच्छे हैं आप केवल इसलिए हो सकते हैं क्योंकि आप बड़े तालाबों में मछली की तुलना करने से बचते हैं। उस गलती से बचने के लिए तीन आयामों का उपयोग करते हुए, गैर-लाभकारी नेता खुद से पूछ सकते हैं :-

- अगर मैं अब भी इससे अधिक हासिल करने के लिए प्रतिबद्ध हूं, तो मैं ऐसे साथियों को चुन सकता हूं जो एक प्रेरक तुलना के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं और जिनसे मैं सबसे अधिक सीख सकता हूं?
- क्या मेरे सहकर्मी उतने सक्षम हैं जिससे कि तुलना करते हुए वास्तव में मुझे उनसे आगे निकलने की कोशिश करने के लिए प्रेरणा प्राप्त हो?
- मैं उन साथियों के साथ सार्थक, व्यक्तिगत संबंध विकसित करने के लिए क्या कर रहा हूं, और क्या मैं उनके करीब जाने के लिए आवश्यक समय का निवेश करने को तैयार हूं?

एटलस नेटवर्क का कोच, कम्पीट, सेलिब्रेट मॉडल

सामाजिक तुलना की दृष्टि से, थिंकटैंकों का वैश्विक नेटवर्क महत्वाकांक्षी गैर-लाभकारी नेताओं को एक दूसरे से जोड़ने के एक अप्रत्याशित संसाधन का प्रतिनिधित्व करता है। लेकिन ये व्यक्तिगत आयाम ही तुलना के स्तर को बढ़ाने का एकमात्र उत्तोलक (लीवर) नहीं हैं। एटलस नेटवर्क जैसे संगठन भी उन उत्पादक व्यवहारों को बढ़ावा देने की स्थिति में हैं, जिन्हें शोधकर्ता 'परिस्थितिजन्य' कारक कहते हैं। ये प्रोत्साहन संरचनाएं वैसी ही हैं जैसे कि शून्य-राशि (ज़ीरो सम गेम) का खेल और मानक डायनामिक्स से निकटता। इनमें रैंकिंग के माध्यम से प्रदर्शन में अंतर पर एक बिंदु निर्धारित किया जाता है; बढ़ी हुई प्रतियोगिता, एक घटनाक्रम, जो समकक्षों के संकरे मंडली के रूप में होती है, एक दूसरे से आगे निकलने की कोशिश करने के लिए बनाई जाती है; और सामाजिक श्रेणी की दोष रेखाएं, जहां स्व-पहचान के रूप प्रतिस्पर्धा के लिए नारा लगाते हैं (जैसे, अमेरिकी बनाम यूरोपीय)।

एटलस नेटवर्क द्वारा विकसित कोच, कम्पीट, सेलिब्रेट! माडल नवाचार विस्तार व नेटवर्क में शोध से हासिल अंतर्दृष्टि के संयोजन पर आधारित है। लाभ मार्जिन की अनुपस्थिति में, हमें लगता है कि जिन अंतर्दृष्टि को एक साथ लिया गया है, वे सामाजिक प्रभावों की अपेक्षा कर सकने वाले शक्तिशाली प्रभावों को पूरा करने के लिए सबसे कारगर रणनीति का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इसके अतिरिक्त, हम प्रशिक्षण, नेटवर्किंग, प्रतियोगिताओं और पुरस्कारों के लिए समकक्ष समूहों को हर वर्ष बुलाते हैं। प्रत्येक वर्ष, हम अफ्रीका, एशिया, यूरोप और लैटिन अमेरिका में क्षेत्रीय लिबर्टी फ़ोरम और साथ ही हमारे वैश्विक लिबर्टी फ़ोरम और फ्रीडम डिनर की मेजबानी भी करते हैं, जिनमें से प्रत्येक सामाजिक तुलना और नवाचार प्रसार की सभी प्रमुख अंतर्दृष्टियां हमारी रणनीति में एकीकृत होती है।

प्रशिक्षण पाठ्यक्रम को लगातार अपडेट करने का हमारा आधार अवार्ड विजेता परियोजनाओं का विषयावलोकन होता है ताकि सहकर्मी नई महत्वाकांक्षाओं के लिए प्रोत्साहित हों और उन्हे प्रेरित करने के लिए सफलता की नवीनतम कहानियों से उनका जुड़ाव रहे। हम विभिन्न संगठनों में नए सहकर्मी समूह बनाने और दुनिया भर में नई व्यक्तिगत दोस्ती स्थापित करने के लिए नए क्षेत्रों में सीईओ का मेल मिलाप भी कराते हैं।

हमारे मॉडल को सत्यापित करने के तरीकों में एक तरीका वार्षिक टेम्पलटन फ्रीडम अवार्ड के लिए छह फाइनलिस्ट परियोजनाओं की गुणवत्ता में वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि की तुलना करना भी है। प्रत्येक वर्ष, इस तरह के काम में 'अच्छा' होने का मतलब है कि नेटवर्क के व्यापक परिभाषा के रूप में आवेदकों और फाइनलिस्ट्स की क्षमता को आगे बढ़ाते हैं, उत्कृष्टता के नए मानकों को समृद्ध किया जाता है। हम प्रत्येक वर्ष अपने उत्साह को बरकरार रखते हैं क्योंकि हम ध्यान से समीक्षा करते हैं, और हमारे भागीदारों की अप्रत्याशित उपलब्धियों से प्रेरित होते हैं, जो अतीत के स्थापित उच्च मानकों को लगातार आगे बढ़ाते हैं।

ये तो महज शुरुआत है

हमारा अतीत का अनुभव यह स्पष्ट करता है कि गैर-लाभकारी नेता लाभकारी नेताओं के समान ही प्रगतिशील और परिणाम-उन्मुख होने में सक्षम हैं। हमारे नेटवर्क से जुड़े साझेदारों और परोपकारी लोगों के लिए सामाजिक तुलना की शक्ति को एक साथ अंगीकार करना ही मुख्य है। यही हमारे कार्यक्षेत्र के लिये लाभ आधारित मापकों का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे शक्तिशाली रणनीतिक विकल्प है। यह रणनीति काम कर रही है। यह देखना अप्रत्याशित है कि हम कितनी तेज़ी से प्रगति कर रहे हैं और, जैसा कि मैं स्वयं के उस छोटे संस्करण से कहना चाहूंगा कि यह तो झरने का बस पहला सेट है, बस आप प्रतीक्षा कीजिए और देखिये आगे क्या आने वाला है।

खंड 3

संपत्ति के अधिकार का विषय अवलोकन

सुरक्षित संपत्ति के अधिकारों के बिना गरीबी से जूझ रहे लोगों की न केवल आर्थिक उपलब्धियाँ हासिल करने के अवसर सीमित हो जाते हैं बल्कि वे राजनीतिक, मानवीय और नागरिक आदि अधिकारों भी वंचित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए वर्ष 2010 में ट्यूनीशिया के एक विनम्र सब्जी विक्रेता मोहम्मद बुअजीज, जो वर्षों से स्थानीय सरकारी अधिकारियों द्वारा रिश्वत मांगने की वजह से परेशान थे, ने सार्वजनिक रूप से विरोध जताते हुए खुद को आग लगा ली। उनके अंतिम शब्द थे, 'आप मुझसे कैसे उम्मीद करते हैं कि मैं ऐसे हालत में जीवन यापन कर सकूं?'

नि:संदेह मोहम्मद की तरह, निम्न आय अर्जित करने वाले तमाम लोग असुरक्षित संपत्ति के अधिकारों से पीड़ित हैं। उनके घरों या जमीन पर औपचारिक स्वामित्व की कमी हो सकती है, या उनके माल और पैसे भी बिना किसी कारण के आसानी से सरकारी जब्ती के जद में आ सकते हैं। यह समस्या अमीर और गरीब दोनों देशों में हो सकती है। केवल उन्हीं देशों में जहां संपत्ति का स्वामित्व अधिकार सुरक्षित है और कानून के शासन का पालन करने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है, हम पायेंगे कि वहां अधिक लोग आर्थिक सफलता प्राप्त करने के लिए को स्वतंत्र होंगे।

इस खंड में केस स्टडी के संस्करण AtlasNetwork.org पर उपलब्ध हैं।

सरकारी शक्तियों के दुरुपयोग का विरोध

इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस,
यूनाइटेड स्टेट

परिचय

इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस (आई.जे.) संयुक्त राज्य अमेरिका में वर्जीनिया के अर्लिंग्टन स्थित एक गैर-लाभकारी जन-हित कानूनी फर्म है। यह खुद को अपनी वेबसाइट पर 'एक नेशनल लॉ फर्म जो सरकारी शक्तियों के आकार और दायरे को सीमित करने और यह सुनिश्चित कराने के लिए कार्यरत है कि सभी अमेरिकियों को समाज के स्वतंत्र और जिम्मेदार सदस्यों के रूप में अपने स्वयं के भाग्य को नियंत्रित करने का अधिकार हो'

इस संगठन की स्थापना विलियम एच. 'चिप' मेलर और क्लिंट बोलिक ने 1991 में की थी और यह 100 से अधिक कर्मचारियों के संगठन के रूप में विकसित हुआ है। आई.जे. वाशिंगटन, डीसी के पास अपने मुख्यालय से संचालित होता है, और पूरे देश में छह अन्य स्थानों पर भी कार्यालय संचालित करता है। आज, फर्म का नेतृत्व स्कॉट बुलॉक द्वारा किया जाता है, जो इसकी स्थापना के समय इस संगठन में शामिल हुए थे। इनके साथ में मेलर ने निदेशक मंडल के अध्यक्ष के रूप में कार्य किया। बुलॉक ने पिट्सबर्ग विश्वविद्यालय से कानून की डिग्री और ग्रोव सिटी कॉलेज से अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री प्राप्त की है।

आई.जे. ने चार'स्वतंत्रता के स्तंभों:' आर्थिक स्वतंत्रता, स्कूल चयन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और संपत्ति के अधिकारों के आसपास अपने काम को वर्गीकृत किया है। यह संगठन केस जीतने के मामलों1 में 70 प्रतिशत की सफलता दर का दावा भी करता है। आमतौर पर आई.जे. छोटे-व्यवसाय संचालकों, स्कूल जाने वाले बच्चों के माता-पिता और संपत्ति के मालिकों आदि के व्यक्तिगत मामलों का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्ष 2006 में आरंभ होकर, आई.जे. ने रणनीतिक अनुसंधान कार्यक्रम की शुरुआत की। यह एक ऐसा डिजाइन किया गया विभाग था, जो संगठन द्वारा लड़े जाने वाले मुकदमों का समर्थन करने के लिए मौलिक और दृढ़ सामाजिक विज्ञान अनुसंधान प्रदान करता है।

डिक कारपेंटर और लिसा कनेप्पर बतौर निदेशक, रणनीतिक अनुसंधान कार्यक्रम का नेतृत्व करते हैं। कारपेंटर, सामाजिक विज्ञान अनुसंधान और शिक्षा (उच्च शिक्षा और के-12) वाली पृष्ठभूमि से है। उन्होंने कोलोराडो विश्वविद्यालय से डॉक्टरेट की उपाधि हासिल की है। स्ट्रैटेजिक रिसर्च प्रोग्राम में शामिल होने से पहले, कनेप्पर आई.जे. में संचार निदेशक थी। वह ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी की स्नातक हैं, जहां उन्होंने अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में पढ़ाई की है। इसके अतिरिक्त वहां रणनीतिक अनुसंधान कार्यक्रम टीम में एक वरिष्ठ शोध विश्लेषक, दो शोध विश्लेषक और एक शोध संपादक सहित कुल छह सदस्य कार्यरत हैं जिनमें से पांच ने पूर्व में भी आई.जे. के मुख्यालय में काम किया है।

प्रोजेक्ट का विवरण

1990 के दशक में आई.जे. ने अपने कार्यक्षेत्र से संबंधित मुकदमों की शुरुआत की। ये मुकदमें सरकार द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग कर निजी भूमि या अन्य संपत्तियों का सार्वजनिक उपयोग के नाम पर कब्जा करने के मामलों से जुड़े थे। आई.जे. ने इन मामलों में संपत्ति के मालिकों का प्रतिनिधित्व किया, जिनकी ज़मीन सरकार द्वारा निजी उपयोग के लिए ली जा रही थी। इसके लिए सरकार की तरफ से दलील दी जा रही थी कि ऐसा करने के पीछे उद्देश्य सार्वजनिक हित था (जैसे क्षेत्र का पुनर्विकास, उस क्षेत्र के लिए नौकरियाँ आकर्षित करना, कर आधार बढ़ाना, आदि)। उन मामलों पर मीडिया का ध्यान आकर्षित हुआ, जिसके फलस्वरूप देशभर के संपत्ति मालिकों ने बड़ी संख्या में आई.जे. को फोन कर स्वयं के सत्ता प्रतिष्ठान की शक्तियों के दुरुपयोग के पीड़ित होने की बात बताई।

जनमत निर्माण आई.जे. की रणनीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ऐसा इसलिए क्योंकि अन्य लोगों की भांति न्यायाधीश भी जनता से जुड़े मुद्दों पर गंभीर दृष्टि बनाये रखते हैं। आई.जे. के जनहित अभियान का महत्वपूर्ण हिस्सा है स्वतंत्रता-अनुकूल नीतियों के पक्ष में अधिक से अधिक जनमत का निर्माण करना। इस अभियान के क्रम में आई.जे. जानता है कि ऐसे विशिष्ट व्यक्तियों की कहानियों को आम लोगों तक पहुंचाना उपयोगी होगा, जो सरकारी संस्थानों की घातक नीतियों से प्रभावित होते हैं और जिन्हें संस्था तार्किक परिणति तक पहुंचाती है। लोगों के ऐसे मुद्दों से भावनात्मक रूप से जुड़ने की संभावना अधिक होती है।[18] जब इन मुद्दों का कोई मानवीय चेहरा होता है। और आई.जे. को अपने मुवक्किलों से ऐसे प्राकृतिक विषय उपलब्ध हो जाते हैं।

आई.जे. की टीम को इस बात का अहसास था कि व्यक्तिगत अन्याय की कहानियों को आवश्यकता अनुरूप कवरेज नहीं मिलेगी। जैसा कि केनेपर व्याख्या करती हैं, 'हमें पता था कि इस विषय को चर्चा में लाने के लिए इसे एक राष्ट्रीय समस्या के तौर पर प्रदर्शित करना बेहद जरूरी था।' हालांकि सिर्फ कह देने भर से ऐसा नहीं होता, हमें इसके लिए एक प्रमाणिक आंकड़े की जरूरत थी यद्यपि हमारे पास प्रतिदिन ढेरों फोन कॉल्स आते थे।

तब मेलर ने डाना बर्लिनर से विमर्श किया जो उन दिनों फर्म के सीनियर ऑटार्नी थे। आज बर्लिनर संस्था में सीनियर वाइस प्रेजिडेंट हैं और मुकदमों से जुड़े विभाग के निदेशक हैं। बर्लिनर और उनकी छोटी टीम ने एक वर्ष से अधिक समय तक ऐसे मामलों की खोजबीन की और देशभर से अखबारों की खबरें और कोर्ट के रिकॉर्ड जुटाये। इसकी परिणति 'पब्लिक पॉवर, प्राइवेट गेन' नाम से एक प्रकाशन के तौर पर हुई जो अप्रैल 2003 में प्रकाशित होने के बाद मील का पत्थर साबित हुई। इसमें पांच साल के दौरान के ऐसे दस हजार से अधिक मामलों का दस्तावेजीकरण किया गया था, जिसमें निजी संपत्ति को सत्ता की शक्ति के दुरुपयोग के कारण खतरा उत्पन्न हुआ था।

इस चौंकाने वाले आंकड़े ने एक बड़ी न्यूज स्टोरी के रूप में सीबीएस न्यूज कार्यक्रम में साठ मिनट के लिए जगह बनायी। इस मामले के व्यापक खुलासे के बाद नेप्पर का विश्वास था कि इससे इस बात की संभावना बढ़ जाती है कि आई. जे. के अब तब के सबसे चर्चित मामलों में से एक केलो वर्सेस सिटी ऑफ न्यू लंदन, यू.एस. सुप्रीम कोर्ट पहुंच जायेगा। अदालत ने वर्ष 2005 में आई.जे के क्लाइंट व सुसेटे केलो के खिलाफ फैसला सुनाया, मगर न्यायाधीश ओ कॉनर ने पब्लिक पावर, प्राइवेट गेन का उद्धरण दिया जो आई.जे. ने यह साबित करने के लिए तैयार किया था कि देश में कोई भी संपत्ति सुरक्षित नहीं है।

इस मामले के दो आशा की किरणें नजर आयीं। पहली, इसने राष्ट्रीय स्तर पर एक आक्रोश को जन्म दिया और विशिष्ट अधिकार क्षेत्र के बारे अप्रत्याशित रूप से जागरूकता पैदा की। दूसरे, अदालत ने सर्वसम्मति से यह सुझाव दिया कि राज्य सरकारें अपने स्तर पर अपने राज्यों में कानून के जरिये विशिष्ट कार्यक्षेत्र पर शिकंजा कस सकती हैं। इसके बाद आई.जे. ने देश के राज्य कानूनों में सुधार के लिए प्रतिबद्ध प्रमुख गठबंधन का नेतृत्व करने का सफलता पूर्वक प्रयास आरंभ कर दिया।

आई.जे. ने व्यक्तियों को भावनात्मक रूप से जोड़ने के लिए प्रभावित करने वाली कहानियों से जोड़ते हुए राष्ट्रव्यापी आंकड़े जुटाकर विशिष्ट अधिकार की तरफ लोगों का ध्यान खींचा। ऐसे में अलग-थलग पड़े मामलों को विसंगति के रूप खारिज नहीं किया जा सकता था। दरअसल, इससे जुड़े आंकड़ों को वास्तविक मुवक्किलों के जरिये मानवीय चेहरा दिया गया, जिससे आई.जे. के लक्षित वर्ग ने इसे गंभीरता से लिया और इस मुहिम से जुड़ते गए।

मेलोर ने अनुभव किया कि यह एक सफलता हासिल करने का संयोजन था और इसे आई.जे. के भीतर इसे संस्थागत रूप में शामिल किया जाये। उन्होंने वर्ष 2006 में रणनीतिक शोध कार्यक्रम बनाया। यह संज्ञान लेते हुए कि संचार की सभी अनुसंधान उत्पादों के विकास में केंद्रीय भूमिका होगी, उन्होंने लिसा कनेप्पर से संचार निदेशक की भूमिका को छोड़ कर रणनीतिक शोध कार्यक्रम की लीडरशिप टीम का हिस्सा बनने का आग्रह किया। आई.जे. ने फिर कनेप्पर के साथ काम करने के लिए डिक कारपेंटर की भर्ती की।

अनुसंधान टीम की पहली परियोजना आर्थिक स्वतंत्रता पर केंद्रित थी। उसके कुछ समय बाद, उन्होंने अपना ध्यान संपत्ति के अधिकार के मुद्दे की ओर लगाया। दरअसल, नागरिक संपत्ति जब्ती के मामले तब कानून प्रवर्तन और कानूनी समुदायों के बाहर काफी हद तक अनजाने थे। आई.जे. निम्नलिखित तरीके से ने नागरिक संपत्ति जब्ती को वर्णित किया :-

> *एक ऐसा मेकैनिज्म, जिसके माध्यम से कानून प्रवर्तन एजेंसियां संपत्ति को केवल किसी अपराध से जुड़े होने के संदेह के आधार पर ही जब्त कर सकती हैं और अपने कब्जे मे रख सकती हैं। आपराधिक ज़ब्ती में संपत्ति को केवल आपराधिक दोष सिद्ध होने के बाद ही ज़ब्त किया जाता है, जबकि इसके उलट नागरिक ज़ब्ती में कानून प्रवर्तन को ऐसे निर्दोष लोगों की संपत्ति ज़ब्त करने की भी अनुमति प्राप्त है जिन लोगों पर कभी भी औपचारिक रूप से किसी अपराध का आरोप भी नहीं लगा। दोषी सिद्ध होना तो दूर की तो बात रही।*

इसी दौरान, आई.जे. ने नागरिक परिसंपत्ति ज़ब्ती के मुद्दे को उठाना शुरू कर दिया। एक मामले में एक संक्षिप्त विवरण दाखिल किया तो दूसरे पर मुकदमा चलाया। बुलॉक न्यू जर्सी के एक पूर्व हाकिम (शेरिफ) के कार ज़ब्ती के मामले का मुकदमा हार गए, लेकिन उन्होंने न्यू जर्सी स्थित मिलविले के कैरोल थॉमस की कहानी सुनाकर इस मामले की रूपरेखा भी बनाई थी, जिसके किशोर बेटे को ड्रग रखने के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया था, जब वह बिना अनुमति के कार चला रहा था। बुलॉक उनकी कार को वापस लाने में तो कामयाब रहे, लेकिन ज़ब्ती की प्रणालीगत पद्धति जारी रही। हालांकि अनुभव ने उन्हें संपत्ति की ज़ब्ती कानूनों के कारण होने वाली मुख्य समस्याओं से स्पष्ट तौर पर वाक़िफ करा दिया थाः पुलिस को शक्तियों का दुरुपयोग करने पर वित्तीय फायदा होता था और संपत्ति के मालिकों को अपनी संपत्ति वापस लेने के लिए उसे साबित करने करना का उल्टा बोझ पड़ता था।

दरअसल, संपत्ति मालिकों को बुनियादी उचित प्रक्रिया व अधिकारों से अनिवार्य रूप से वंचित रखा जाता है और उन्हें तब तक दोषी माना जाता है जब तक कि वे अपनी बेगुनाही साबित नहीं करते देते। आई.जे. को मालूम था कि उनका लक्ष्य नागरिक संपत्ति ज़ब्ती

कानून को समाप्त देखना और आपराधिक संपत्ति ज़ब्ती से प्राप्त होने वाले राजस्व को एक तटस्थ निधि में स्थानांतरित कराने की व्यवस्था कराना है। ऐसा करने से पुलिस को अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने के लिए प्रोत्साहन का अभाव हो जाता।

वर्ष 2007 में, कारपेंटर और कनेप्पर ने सीनियर अटर्नी बुलॉक से मुलाकात की। इस मुलाकात का उद्देश्य इस सवाल का जवाब तलाशना था कि आई.जे. को भविष्य में संपत्ति ज़ब्ती के प्रयासों के खिलाफ किस प्रकार की संस्था की स्थापना करनी चाहिए, समस्या की हद का वर्णन कैसे करना चाहिए और नागरिक संपत्ति ज़ब्ती को किस प्रकार प्रकाश में लाना चाहिए? टीम समाचार पत्रों में प्रकाशित होने वाले संपत्ति ज़ब्ती के व्यक्तिगत मामलों का ही हवाला दे सकी, लेकिन विस्तृत आंकड़ों के बिना, यह तर्क करना कठिन था कि यह एक प्रणालीगत समस्या थी।

इस विषय से संबंधित दस्तावेज़ों का पुर्नअध्ययन करने के बाद दल ने इस बात का परीक्षण किया कि क्या विभिन्न राज्यों में नागरिक संपत्ति जब्ती से जुड़े कानूनों में विविधता का संबंध दुरुपयोग के मामलों से है। शीघ्र ही यह साफ हो गया कि कई राज्यों द्वारा इससे संबंधित रिकॉर्ड न रखने से इस बाबत डाटा जुटाना कठिन होगा। जिन राज्यों के लिये इस तरह की जानकारी जुटानी जरूरी थी, वहां भी इसकी अनदेखी की गई।

इस विषय पर प्रकाशित सामग्री की समीक्षा के दौरान टीम ने तीन बाहरी शोधकर्ताओं को तलाशा, जिनमें : मैरिएन विलियम्स, जेफरसन होलकॉम, और टोमिस्लाव कोवंदज़िक शामिल थे। इन सभी के पास डॉक्टरेट की डिग्री थी और सभी ने इस विषय से जुड़ी सामग्री प्रकाशित की थी। उन्होंने सुझाव दिया कि टीम न्यायोचित बंटवारे के मुद्दे पर भी ध्यान दे, एक ऐसी परंपरा शुरू हो, जिसके तहत राज्य संघीय सरकार की ओर उन्मुख हो सकते हैं ताकि संपत्ति जब्त करने के लिए संयुक्त रूप से कानूनी प्रक्रिया को अपनाया जा सके या इस बाबत काम किया जा सके। निजी संपत्ति को मजबूत सुरक्षा देने वाले राज्यों में पुलिस विभाग इससे जुड़ी खामियों को दूर कर सकता है, जो कि संपत्ति जब्ती से हासिल राजस्व 80 प्रतिशत तक बचा सकते हैं।

राज्यों द्वारा सभी समान-साझा गतिविधियां न्याय विभाग के केंद्रीय डेटाबेस में दर्ज की जाती हैं: इस खुलासे ने केवल प्रारंभिक शोध प्रश्न में सुधार किया, जिस को लेकर आई.जे. ने आगे बढ़ाने की योजना बनाई थी, बल्कि साथ ही इसने आंकड़ों से संबंधित समस्या को भी हल कर दिया।

रणनीतिक शोध कार्यक्रम टीम, जिसमें बाहरी शोधकर्ता भी शामिल थे, ने राज्यों और न्याय विभाग से उपलब्ध सभी आंकड़ों को अगले तीन वर्षों के लिए एकत्र किया। इसके लिये जहां जरूरत पड़ी सूचना की स्वतंत्रता का प्रयोग किया गया। इस प्रयास से दस हजार से

अधिक महत्वपूर्ण दस्तावेज़ हासिल हुए, इन सभी को आई.जे. की टीम द्वारा स्प्रेडशीट में कोड देने और व्यवस्थित करने की जरूरत थी।

इस टीम ने मार्च 2010 में विस्तृत आंकड़ों के साथ पहली राष्ट्रीय रिपोर्ट 'पॉलिसिंग फ़ॉर प्रॉफ़िट' प्रकाशित की कि कैसे सरकारी एजेंसियों के लिये नागरिक संपत्ति ज़ब्ती सामान्य और लाभकारी हो सकती है। उदाहरण के लिए, रिपोर्ट से खुलासा हुआ कि 2008 में पहली बार न्याय विभाग ने नागरिक संपत्ति जब्ती से 1 बिलियन डॉलर से अधिक की धनराशि आर्जित की। इसके अतिरिक्त इस बात की भी पुष्टि हुई कि कड़े कानूनों वाले राज्यों में समान रूप से साझाकरण से एजेंसियों को प्रोत्साहन मिला और संघीय सरकार लगातार सहयोग के लिए उन्मुख हुई।

दरअसल, यह रिपोर्ट तत्काल बहुत अधिक ध्यान आकर्षण करने में सफल नहीं रहा। इसका कारण लोगों में इस मुद्दे को लेकर जानकारी का अभाव था। इसके अतिरिक्त, कारपेन्टर ने यह समझाया कि 'राष्ट्रीय रिपोर्ट से यह सब कुछ नहीं हो सकता है और न्यायाधीश और रिपोर्टर अपने राज्य विशेष की समस्या का संदर्भ देना चाहते हैं।' इसलिए, आई.जे. की कानूनी टीमों ने जब नए मुवक्किलों को पाया और मुकदमा दायर करना शुरू किया, तो रणनीतिक अनुसंधान कार्यक्रम टीम राष्ट्रीय अध्ययन के पूरक के लिए विशिष्ट राज्य आधारित रिपोर्ट तैयार करने में व्यस्त हो गई।

कारपेंटर ने बताया कि 'मगर राष्ट्रीय (रिपोर्ट) इतनी महत्वपूर्ण थी; किसी ने समस्या को परिभाषित करने में समय ही नहीं लगाया। और इसलिए (राष्ट्रीय रिपोर्ट) में स्पष्ट किया गया कि एक वहां एक गंभीर समस्या थी।' उन्होंने आगे बताया कि 'और फिर राज्य रिपोर्टों में पुष्टि हुई कि, जिन स्थानों पर हमारा अभियोग चल रहा था, वहां भी यह एक समस्या थी। अब न्यायाधीश यह नहीं कह सकते थे कि ठीक है, यह राष्ट्रीय स्तर पर एक मुद्दा हो सकता है, लेकिन हमारे राज्य में ऐसी स्थिति नहीं है।'

कनेप्पर बताते हैं, ऐसी परिस्थितियों में दृढ़ता सार्थक परिणाम देती है। मीडिया ने ध्यान देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा, 'दरअसल, हमारे पास हर राज्य से जुड़ी कानूनी जानकारी थी, साथ ही हमारे पास संघीय डेटा था, इसने हर राज्य को समाचार के लिये जरूरी मुद्दा उपलब्ध कराया।' इसने राष्ट्रीय पत्रकारों को भी पड़ताल करने के लिए पूरी कहानी दी।

अगस्त 2013 में न्यू यॉर्कर मैगज़ीन की स्टाफ लेखिका साराह स्टिलमैन ने नागरिक संपत्ति ज़ब्ती के बारे में एक दमदार और विस्तृत लेख प्रकाशित किया। इसमें आई.जे. के विधायी वकील ली मैकग्राथ का बयान प्रकाशित किया गया। वाशिंगटन पोस्ट के माइकल सल्लाह, जब मियामी हेराल्ड के लिए काम करते थे (तब से वह वापस आ चुके हैं), तब उन्होंने संपत्ति जब्ती के विशिष्ट मामलों को कवर किया था, इसलिए वे इस मुद्दे से परिचित थे। 'पोलिसिंग फॉर प्रॉफ़िट' पढ़ने के बाद, वह इसके बारें में और अधिक जानने के लिए

आई.जे. की टीम के पास पहुंचे। बाद में उन्होंने सह-लेखकों के साथ इस मामले को प्रकाशित किया। सितंबर, 2014 में शुरू होने वाली पोस्ट में व्यापक रूप से परिसंपत्ति के अधिग्रहण पर आधरित छह भागों वाली ऋंखला प्रकाशित हुई। पोस्ट की ऋंखला का सारांश निम्न निष्कर्ष देता है :-

> *हाल ही के वर्षों में, हज़ारों लोगों का अपराध बताये बिना पुलिस द्वारा उनकी नकदी जब्त की गई है। पोस्ट ज़ब्ती के पीछे पुलिस की कार्य-संस्कृति देखती है। साथ ही उन लोगों का संघर्ष भी देखती है जो अपने पैसे वापस पाने के लिए सरकार से लड़ने के लिए मजबूर थे।*

मई, 2015 में, पत्रकार कोनोर फ्रेडर्सडॉर्फ ने द अटलांटिक के लिए एक लेख लिखा था, जिसका शीर्षक था, 'द इन्जस्टिस ऑफ सिविल एसेट फॉर्फिचर', जो सीधे सीधे लाभ के लिए पुलिसिंग से जुड़ा था। इसमें आई.जे. को एक प्रमुख स्रोत के रूप में उद्धृत किया गया था।

मीडिया कवरेज का यह धारदार प्रयास देशभर में इस मुद्दे को फैलाने में निर्णायक बिंदु साबित हुआ। 'हम इधर उधर पत्रकारों के साथ फोन पर सिर्फ महज दस मिनट खर्च नहीं कर रहे थे', कारपेन्टर ने बताया। 'हम पत्रकारों के साथ घंटों की बैठक और डेटा के माध्यम से लेखन और उन्हें इस समस्या की गंभीरता को समझने में मदद कर रहे थे।'

दरअसल, इस मुद्दे को विस्तार देकर और वकीलों को बौद्धिक अस्त्र-शस्त्र प्रदान करके, रणनीतिक अनुसंधान कार्यक्रम टीम ने अभियोग को न्याय और सुधार प्राप्त करने के लिए एक अधिक प्रभावी साधन बना दिया था। उदाहरण के लिए, आई.जे. ने जॉर्जिया में एक निर्णय अपने पक्ष में किया, जिसमें राज्य एजेंसियों को रिपोर्टिंग कानूनों का पालन करना आवश्यक था।

सरकार के सभी स्तरों पर सुधार प्रयासों को गति देने में टीम ने मदद की। जनवरी 2015 में, अमेरिकी अटॉर्नी जनरल एरिक होल्डर ने घोषणा की कि न्याय विभाग अपने कुछ नागरिक संपत्ति जब्ती प्रथाओं, विशेषकर एक समान बंटवारे वाली प्रथा पर अंकुश लगाएगा। आई. जे. ने इस नीति परिवर्तन के निहितार्थों का आकलन करने के लिए न्याय विभाग के डेटाबेस का अध्ययन किया और पाया कि इससे अधिकांश वर्तमान बरामदगियां अप्रभावित रहेंगी। इस प्रकार की आलोचना के जवाब में, न्याय विभाग ने पात्रता के लिए सख्त परिभाषाएं प्रदान करने के लिए अतिरिक्त दिशा-निर्देश जारी किए, लेकिन सरकार के अधिकारों के दुरुपयोग को और सीमित करने के अपने प्रयासों में आई.जे. सतर्कता का पालन कर रहा था।

आई.जे. ने 'पुलिसिंग फॉर प्रॉफिट' का दूसरा संस्करण नवंबर, 2015 में जारी किया, और साथ ही नए मामलों को लेने और शोध की नयी दिशाओं पर काम करना जारी रखा। उदाहरण के लिए, मिशिगन में संस्था के एक मुवक्किल ने देखा कि बैंक में जमा उसकी सभी व्यापारिक पूंजी को ज़ब्त कर लिया गया है क्योंकि खाते में जमा राशि लगातार सीमा रेखा से नीचे जा रही थी, जो कि संघीय रिपोर्टिंग की आवश्यक थी। जब जान-बूझकर रिपोर्टिंग से बचने के लिए ऐसा प्रयास किया जाता है, तो इस अभ्यास को 'स्ट्रक्चरिंग' कहा जाता है और संघीय एजेंटों को आपकी गतिविधियों पर संदेह हो सकता है। हालांकि, आई. जे. के ग्राहक जान-बूझकर स्ट्रक्चरिंग नहीं कर रहे थे, जो कि सरकारी अधिकारियों को एक सामान्य से जांच से पता चल सकता था। जवाब में, आई.जे. ने एक नई रिपोर्ट, 'सीज़ फर्स्ट, आस्क क्वेश्चन लेटर' जारी कर नए घटनाक्रमों के लिए समयबद्ध तरीके से जवाब देने के लिए चल रही प्रतिबद्धता का प्रदर्शन किया।

प्रमुख दृष्टिकोण

स्ट्रेटेजिक रिसर्च प्रोग्राम टीम का मॉडल मुद्दों को आगे बढ़ाने और उन प्रमुख अवधारणाओं को स्पष्ट करने में कारगर साबित हुआ है जो आई.जे के मुकदमों वाले प्रयासों के लिए प्रासंगिक थे। विशेष संचार और कानूनी लक्ष्यों को पूरा करने के लिए शोध डिजाइन करके, गुणवत्ता के साथ समझौता किए बिना रणनीतिक अनुसंधान कार्यक्रम टीम निर्णय लेने के लिए अपने ढांचे को परिभाषित करने में सक्षम है।

सहकारिता के बारे में

कॉरपेन्टर शोध विकास प्रक्रिया को एक सहयोगी के रूप में वर्णित करते हैं। क्नेप्पर रणनीतिक शोध कार्यक्रम टीम के भीतर, शुरुआती संपादन और प्रॉडक्शन को नेतृत्व प्रदान करती हैं। कॉरपेन्टर का आंकलन है कि रणनीतिक शोध कार्यक्रम टीम के अलावा, प्रकाशन से छह सप्ताह पूर्व मसौदा अनुसंधान आई.जे. की संचार टीम के साथ साझा किया जाता है। अनुसंधान पद्धति की संपूर्णता औपचारिक रूप से मेज पर कभी नहीं होती है, लेकिन संचार टीम शोध निष्कर्षों को समझाने के लिए अतिरिक्त विचार प्रदान करती है कि कौन से घटनाक्रम बेहतर ढंग से समस्या का चित्रण करते हैं, और कौन सी भाषा आई. जे. के दर्शकों के लिए सरल व स्पष्ट रूप से सार्थक संदेश देगी। अखिरकार यह फीडबैक अंतिम सामग्री को प्रभावित करता है।

दरअसल, अधिकांश शोधकार्य अभियोग (मुकदमेबाजी) से संबंधित है, इसलिए रणनीतिक शोध कार्यक्रम टीम आई.जे. के वकीलों के साथ महत्वपूर्ण तर्कों पर विचार-विमर्श करने, प्रतिवादों का पूर्वानुमान लगाने और न्यायाधीशों, पत्रकारों और जन सामान्य

के बीच एक मुद्दे से संबंधित ज्ञान में संभावित अंतराल का आकलन करने हेतु काम करती है।

आई.जे. की टीमें इकाइयों के रूप में कार्य करती हैं जिसे वे व्यसायिक इकाईयां कहते हैं। इनमें रणनीतिक शोध, अभियोग, कानून निर्माण, संचार और सामाजिक सक्रियता शामिल हैं। क्नेप्पर ने विशिष्ट मुद्दों या परियोजनाओं को आगे बढ़ाने के लिए व्यावसायिक इकाइयों में लचीलापन और सहयोगी प्रक्रिया का उल्लेख किया है। नि:संदेह बेहतर परिणामों के लिए इनपुट और समन्वय महत्वपूर्ण है, और आई.जे. प्रबंधन का मानना है कि प्रबंधकीय निरीक्षण पर यह कुछ हद तक ही निर्भर करता है। किसी संगठन द्वारा पहले ही सद्भाव से हासिल विश्वसनीयता की भी इसमें बड़ी भूमिका होती, जो आमतौर पर संगठन की कार्य संस्कृति की साख के रूप में उल्लेखित किया जाता है। 'यह केवल संस्था की उम्मीद ही नहीं है कि टीम के सभी लोग परियोजनाओं में बढ़ चढकर शामिल हों और अपनी मदद प्रस्तुत करें, बल्कि लोग वास्तव में खुद भी ऐसा चाहते हैं।' क्नेप्पर ने कहा 'मुझे लगता है कि उन्होंने हमें काम करते देखा है और वे जानते हैं कि जब हम एक साथ काम कर रहे होते हैं तो परिणाम सबसे प्रभावी होते हैं।' उन्होंने कहा कि आई.जे. अत्यधिक पदों के अनुक्रम (हायरार्की) के तरीके से संचालित नहीं होता है। कार्य संस्कृति का उदाहरण ऊपर से शुरू होता है, और भर्ती (हायरिंग प्रक्रिया) के माध्यम से उस संस्कृति की गुणवत्ता को सावधानीपूर्वक जारी रखा जाता है।

लक्षित दर्शक वर्ग की पहचान

आई.जे. के लक्षित दर्शक वर्ग को परिभाषित करते हुए क्नेप्पर कहते हैं कि वे सभी औसत अमेरिकी जो थोड़े बहुत भी जागरुक हैं, व्यापक रूप से हमारे दर्शक हैं। आई.जे. की एक एक्टिविज्म वाली शाखा भी है, और रणनीतिक शोध कार्यक्रम टीम सभी सक्रिय नागरिकों को सहजता से शामिल करना चाहती है। कॉरपेन्टर बताते हैं कि आंतरिक तौर पर संस्था के लोग इसे 'मॉम टेस्ट' कहते हैं। यदि आप समस्या का समाधान बताते हैं और समाधान आपकी मां की समझ में नहीं आता, तो आपको उसपर और अधिक काम करने की जरूरत है। जटिल शब्दों वाली भाषा या अति अकादमिक लेखन को जर्नल के लिए सुरक्षित रखा जाना चाहिए, न कि लोकप्रिय या पेशेवर दर्शक वर्ग के लिए।

सरकारी डेटा हासिल करने पर

कॉरपेन्टर सुझाव देते हैं कि सभी पब्लिक पॉलिसी संस्थाओं में टीम के एक व्यक्ति को सूचना की स्वतंत्रता कानून या अपने देश में मौजूद ऐसे समकक्ष कानून का विशेषज्ञ होना चाहिए। उन्होंने कहा कि यह न केवल सरकारी जानकारी प्राप्त करने के प्रयासों को बढ़ावा

देता है, बल्कि न्यायाधीशों और अन्य सरकारी एजेंसियों के साथ विश्वसनीयता को भी सुनिश्चित करता है, विशेषकर सहयोग में कमी या विद्वेष की स्थिति में।

संदेश तैयार करने के बारे में

कारपेन्टर ने कहा कि सरकार में शामिल लोगों पर व्यक्ति केंद्रित आलोचना का प्रभाव प्रतिकूल भी हो सकता है। इससे गलत निष्कर्ष निकल सकता है कि केवल उक्त जिम्मेदारी का निर्वहन करने वाले लोगों को बदलने से समस्या का समाधान हो जाएगा। उनका कहना है कि ऐसा करने की बजाय आई.जे. का संदेश कानूनों को बदलने, प्रेरणा परिवर्तन, व्यवहार को बदलने पर ध्यान केंद्रित करना है।

क्नेप्पर इस महत्व पर बल देते हैं कि संदेश में वास्तविक लोगों की कहानियों को शामिल किया जाये। अधिकांश दर्शकों के साथ जुड़ने की अधिक संभावना तब होती है जब वे एक विशिष्ट पीड़ित की पहचान कर सकते हैं, जो अकेले आंकड़ों की तुलना में मजबूत भावनात्मक प्रतिक्रिया को बढ़ावा देता है। उन कहानियों को तस्वीरों और आंकड़ों के साथ शोध रिपोर्टों में शामिल किया जाना चाहिए ताकि यह स्पष्ट हो सके कि घटना से संबंधित यह इकलौता मामला नहीं है। यह एक शक्तिशाली संयोजन है। दोनों सफलता के लिए महत्वपूर्ण हैं और एक-दूसरे को बढ़ावा देते हैं।

मापन पर

एक संगठन के रूप में आई.जे. मुकदमों को जीतने पर ध्यान केंद्रित करता है, लेकिन यह अनुकूल समझौतों और वांछनीय विधायी सुधार भी चाहता है। संचार विभाग मीडिया कवरेज की सावधानीपूर्वक निगरानी करता है, और रणनीतिक शोध कार्यक्रम टीम ने विशेष रूप से मीडिया कवरेज को देखना शुरू कर दिया है, जो उनके शोध पर संदर्भ या निर्भर करता है। वे न्यायाधीशों द्वारा सुनाए जाने वाले फैसलों पर भी निगाह रखते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि उनके शोधों की उसमें कोई सार्थक भूमिका थी या नहीं। रणनीतिक शोध कार्यक्रम टीम का एक अन्य लक्ष्य अपने चुने हुए केंद्रित क्षेत्रों में अधिक शोध को प्रेरित करना है, और इसे प्राप्त करने के लिए उनकी रणनीति का हिस्सा पत्रिकाओं में अपने शोध के अकादमिक संस्करण प्रकाशित करना है।

प्रश्न जिनपर चर्चा की जा सकती है

- क्या इंस्टीट्यूट फॉर जस्टिस (आई.जे.) के अनुसंधान और संचार के बीच संबंध सर्वोत्तम हैं? इसमें आप किस प्रकार की लाभ या हानि देखते हैं?

- आई.जे. अनुसंधान परियोजनाओं में कई बार वर्षों तक समय लगाता है। शोध रिपोर्टों को मीडिया के समक्ष प्रस्तुत करने में भी यह लंबा समय लगाता है। आपका संगठन इस तरह से संसाधनों के आवंटन के बारे में निर्णय कैसे लेता है? समझौते का समन्वय कैसे किया जाता है? क्या समन्वय संतुलन कर्मचारियों के आकार और बजट के आधार पर परिवर्तित होता है?
- आई.जे. लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अदालतों में अभियोग का सहारा लेता है और कालांतर में उन विषयों पर शोध को विकसित करता है जो रणनीतिक रूप से उन मुकदमों की प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हैं। आप शोध के विषयों का चयन कैसे करते हैं? यदि आपका संगठन मुकदमों की प्रक्रिया में नहीं भी पड़ता है, तो आप संबंधित निर्णय लेने में मदद करने के लिए वांछनीय परिणामों का आकलन कैसे करते हैं?
- अपने कार्यालय में अधिकतम परिणामों को अनुकूलित करने के लिए आप सहयोग के साथ पदानुक्रम को कैसे संतुलित करते हैं? क्या आप अपनी संगठनात्मक संस्कृति के बारे में सोचते हैं जब आप नयी नियुक्ति करते हैं?
- क्या आप उन व्यक्तिगत कहानियों के बारे में बता सकते हैं जो आपके संगठन से जुड़े मुद्दों से प्रभावित लोगों के बारे में बताती हैं। क्या यह शोध और संचार के लिए आपके संगठन के मॉडल का हिस्सा है?

रंगभेद के शिकार लोगों के लिए स्वामित्व बहाल करना

फ्री मार्केट फाउंडेशन
दक्षिण अफ्रीका

परिचय

एक दक्षिण अफ्रीकी थिंक टैंक हैं फ्री मार्केट फाउंडेशन यानी एफ.एम.एफ., जिसकी स्थापना वर्ष 1975 में मानवाधिकार और लोकतंत्र को बढ़ावा देने की हिमायत के लिए की गई थी। इस उद्देश्य के तहत खुले समाज के परंपरागत उदारवादी सिद्धांतों, कानून के राज, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और आर्थिक आज़ादी को मौलिक अवयव के तौर शामिल किया गया था। एफ.एम.एफ. के संस्थापकों में से एक लियोन लूव दक्षिण अफ्रीकी बौद्धिक उद्यमी हैं और हमेशा से संपत्ति के अधिकार के लिए एक्टिविज़्म करते रहे हैं। दरअसल, जोहानिसबर्ग की एक लॉ फर्म में काम करते समय हासिल अनुभवों से संपत्ति के अधिकारों में उनकी रुचि उत्पन्न हुई। लूव के अनुसार, 'मैंने हर दिन अपने ऑफिस के बाहर फुटपाथ पर एक बुज़ुर्ग अश्वेत महिला को फल बेचते देखा, जिससे कभी-कभी मैं भी फल खरीदा करता था। एक दिन मैंने देखा कि पुलिस ने उसके फलों की टोकरी को गली में फेंक दिया और उसे पकड़ने के लिए उसका पीछा चारों कोनों में किया। फिर उसे पकड़कर गिरफ्तार किया गया और उसे पुलिस वैन में डाल दिया गया। वे उसे जोहानिसबर्ग केंद्रीय पुलिस स्टेशन ले गए। वहां मैंने कई दिन उसे रिहा करने के लिए व्यतीत किये।'

दरअसल, यह घटनाक्रम एफ.एम.एफ. की स्थापना तथा खया लैम (मेरा घर) भूमि सुधार परियोजना की भावना और प्रेरणा का उल्लेख करता है। सही मायनों में ये दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद से बचे लोगों को फ्रीहोल्ड भूमि स्वामित्व लौटाने की पहल है। एफ.एम.एफ. के सह-निदेशक टेम्बा नोलशंगु बताते हैं, 'मुझे अभी भी याद है एक समय ऐसा था जब अश्वेत दक्षिण अफ्रीकी जमीन के मालिक होने की कल्पना भी नहीं कर सकते थे।'

वर्ष 1913 में लागू किए गए, मूल निवासी भूमि अधिनियम ने काले लोगों को भूमि खरीदने या मालिक होने से प्रतिबंधित कर दिया। उन्हें गोरे लोगों के स्वामित्व वाली भूमि पर किराये पर भी किसानी करने से रोक दिया गया था। वर्ष 1990 के दशक में रंगभेद सुधारों के बाद इन दमनकारी प्रतिबंधों को समाप्त करके सरकारी संपत्ति के किरायेदारों के लिए अपने घरों के रूप में पूर्ण स्वामित्व प्राप्त करने का अवसर संभव हुआ।

हालांकि, नया कानून उस बदलाव को हासिल करने के लिए पर्याप्त नहीं था, जिसका नोलशंगु उल्लेख करते हैं। स्वामित्व हस्तांतरण के अधिकांश उम्मीदवार आज भी इस बात से या तो अनभिज्ञ हैं या उन्हें इस बात पर विश्वास नहीं है। एफ.एम.एफ. ने इस खाई को पाटने और अधिक से अधिक उम्मीदवारों के स्वामित्व के अधिकारों को सुरक्षित कराने हेतु खया लैम परियोजना शुरू की।

आज, एफ.एम.एफ. का नेतृत्व कार्यकारी निदेशक लुओ और सह-निदेशकों यूस्टेस डेवी, टेम्बा नोलशंगु व जेसन उरबैच द्वारा किया जा रहा है और इसके अलावा दस पूर्णकालिक व तीन अंशकालिक कर्मचारी संस्थान में कार्यरत हैं। संस्था का परिचालन का वर्षिक बजट 650,000 अमेरिकी डॉलर है। इसके सलाहकार मंडल में जाने-माने अर्थशास्त्री दीपक लाल और इज़रैल किर्ज़नर शामिल हैं।

परियोजना का विवरण

खया लैम भूमि सुधार परियोजना का उद्देश्य उन दक्षिण अफ्रीकी लोगों का स्वामित्व सुरक्षित करना था, जिन्हें अधिकारों से वंचित किया गया था। एफ.एम.एफ. का अनुमान है कि ऐसे उम्मीदवारों की संभावित संख्या सत्तर लाख के करीब है। एफ.एम.एफ. टीम जानती थी कि कानूनी अधिकारों को हकीकत में बदलने के लिए छोटे पैमाने पर भूमि स्वामित्व के नये मॉडल को प्रयोग करने की जरूरत है, जिसके परिणामों से दूसरों को प्रेरित करते हुए इसकी प्रतिकृति पूरे देश में लागू करना संभव हो पायेगा।

एफ.एम.एफ. टीम ने पायलट प्रोजेक्ट के जरिये नगरपालिका के स्वामित्व वाले 3,000 किराये के घरों को फ्रीहोल्ड टाइटल में परिवर्तित कराने का प्रारंभिक लक्ष्य रखा। उनका मानना है कि इससे न केवल प्रभावित समुदायों में आर्थिक विकास को गति मिलेगी, बल्कि सरकार के नेताओं को दक्षिण अफ्रीका के सभी सात मिलियन सरकारी-स्वामित्व वाले किराये के घरों के स्वामित्व हस्तांतरण नीति का विस्तार करने के लिए भी प्रेरित किया जाएगा।

एफ.एम.एफ. टीम ने पायलट प्रोजेक्ट के लिए फ्री स्टेट प्रांत के नगवाथे नगरपालिका क्षेत्र को चुना। नगवाथे में लगभग 17,000 उम्मीदवार संपत्तियां शामिल हैं। यह नगरपालिका

परिषद के तहत आने वाला क्षेत्र है जिसका नेतृत्व एक बहुमत वाली पार्टी करती है। यह पार्टी अपनी स्थापना के समय से ही लोगों को भूमि स्वामित्व देने की समर्थक रही है।

संस्था की टीम को नगवाथे में पेरी फेल्डमैन नामक एक सेवानिवृत्त किसान के बारे में पता चला, जिन्हें बाद में खया लैम परियोजना का प्रबंधक बना दिया गया। फेल्डमैन ने स्थानीय अधिकारियों से परिचय कराया और लूव ने योजना का स्थानीय समुदाय के लिए प्रत्याशित आर्थिक लाभ बताते हुए, एफ.एम.एफ. योजना पेश करने के लिए नगरपालिका परिषद के साथ एक बैठक के लिए अनुरोध किया। परिषद ने मतदान किया और योजना को मंजूरी दे दी। योजना में यह प्रावधान भी शामिल था कि परिषद 'उन पूर्व में थोपी शर्तों को लागू नहीं करेगी, जो अश्वेत निवासियों के द्वारा अपनी भूमि के मनचाहे इस्तेमाल को प्रतिबंधित कर सकती हैं।'

नोलशंगु के अनुसार, यह प्रावधान महत्वपूर्ण था, क्योंकि 'एक मुक्त बाजार में, स्वैच्छिक विनिमय, व्यक्तिगत पसंद और निजी संपत्ति होनी चाहिए। जब सरकार इन सिद्धांतों को अनुल्लंघनीय स्वीकार करेगी, तभी दक्षिण अफ्रीका एक शांतिपूर्ण, सामाजिक आर्थिक क्रांति का एहसास कर सकेगा और जिसके फलस्वरूप बड़ी संख्या में लोगों का आर्थिक उत्थान होगा।'

महत्वपूर्ण बात यह है कि परिषद न केवल इस अभियान में सहायक थी, बल्कि, एफ.एम. एम परियोजना के समन्वयक गेल डे के अनुसार, 'परिषद ने औपचारिकताओं और लालफीताशाही से निपटने और उसे कम करके तुरंत अधिकार प्रदान करने का वादा किया।' इस प्रशासनिक बोझ में आई कमी और एफ.एम.एफ. के द्वारा वकीलों के साथ किये गए समझौते के कारण परियोजना की कीमत उस समय औसत लागत प्रति स्वामित्व 348 डॉलर से कम होकर 122 डॉलर कराने में सफलता मिली। नगवाथे में उम्मीदवार घरों के लिए औसत संपत्ति मूल्य 8,000 अमेरिकी डॉलर थी, जो कि यह एक आकर्षक मूल्य प्रस्ताव का प्रतिनिधित्व करता है।

एक अन्य एफ.एम.एफ. प्रतिनिधि, जेनेट म्पोंडो ने तब काउंसिल के साथ मिलकर नगवाथे में एक कार्यालय स्थापित किया। उन्होंने एक भूमि सुधार संपर्क अधिकारी के रूप में संभावित लाभार्थियों के साथ सीधे काम करने के पहल की। उसने उनके स्वामित्व आवेदनों के लिए दस्तावेज तैयार करने में मदद की।

नगवाथे में कार्यालय की स्थापना करना एक महत्वपूर्ण कदम था। एफ.एम.एफ. टीम ने स्थानीय रिश्तों और विश्वास के निर्माण के महत्व को जल्दी ही जान लिया। जेनेट म्पोंडो ने कार्यालय समय को बनाए रखा, लेकिन निवासियों के विचारों को बेहतर ढंग से समझने के लिए समुदाय में काम करने में अपना अधिकांश समय बिताया। इससे एफ.एम.एफ.

टीम को स्थानीय चिंताओं के बारे में तेजी से समझने और उसके अनुरूप समायोजित करने में मदद मिली।

उदाहरण के लिए, स्थानीय निवासियों ने उन वकीलों पर भरोसा नहीं किया जिन्हें एफ.एम. एफ. टीम ने शुरू में उन्हें सेवा देने के लिए काम पर रखा था, क्योंकि वे शहर के बाहर से थे, और उन्हें बाहरियों और स्थानीय निवासियों के सर्वोत्तम हितों के लिए प्रतिबद्ध नहीं होने के तौर पर देखा जा रहा था। उनके स्थान पर, एफ.एम.एफ. ने स्थानीय वकीलों को काम पर रखा, जो स्थानीय लोगों के दृष्टिकोणों को समझते थे और उनके निवासियों के साथ पहले से ही संबंध थे।

टीम की भूमिका की इसलिये भी खूब प्रशंसा हुई क्योंकि उन्होंने मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर पहुंच बनायी, विशेष रूप से स्वामित्व के लाभों को समझाने के लिए। कुछ लोगों के लिए संपत्ति रखने का अवसर सहज रूप से आकर्षक था। वहीं दूसरे इसके लाभ को स्पष्ट रूप से नहीं देख पा रहे थे और उन्हें प्रशासनिक अड़चनों की चिंता के साथ जुड़े लागतों को लेकर भी संदेह भी था।

इन चुनौतियों से मुकाबले के लिए एफ.एम.एफ. टीम ने एक बहुस्तरीय मार्केटिंग रणनीति विकसित की। इसके लिए सबसे पहले घर-घर दस्तक दी गई, उम्मीदवार निवासियों से खुद का परिचय कराया गया और स्वामित्व के आर्थिक लाभों की व्याख्या की गई। जेनेट म्पोंडो को स्थानीय रेडियो स्टेशन पर एक साप्ताहिक स्लॉट भी दिया गया ताकि स्थानीय निवासियों को स्वामित्व के लाभों के बारे में बताया जा सके और स्वामित्व प्रदान कराने के कार्य के लिए नए डोनर फंड्स जुटाए जा सकें।

दूसरे, उन्होंने ऐसे सूचनात्मक कार्यक्रमों के आयोजन किये, जिसमें स्वामित्व के लाभ के बारे में जानकारी दी गई। इसमें उनकी कई जिज्ञासाओं का निराकरण किया गया कि जैसे संपत्ति के बेचने का अवसर, सुधार के लिए प्रोत्साहन और क्रेडिट बाजारों तक पहुंचने की क्षमता आदि। उन आयोजनों में स्थानीय निवासियों को सवाल पूछने का मौका प्रदान किया जैसे कि, क्या उनके बच्चे वास्तव में उनकी संपत्ति प्राप्त करने में सक्षम होंगे?

तीसरा, उन्होंने ऐसे कार्यक्रमों का आयोजन किया, जिनमें बड़े डोनर व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होकर अपने द्वारा प्रायोजित स्वामित्व दस्तावेज नए गृहस्वामियों को प्रदान कर सकें। उदाहरण के लिए, फर्स्ट नेशनल बैंक के प्रतिनिधियों ने टुमहोल टाउनशिप में स्कूल के हॉल में 200 सफल आवेदकों को स्वामित्व से संबंधित दस्तावेज प्रदान किये गए। दूसरी ओर एफ.एम.एफ. ने प्रोजेक्ट को प्रायोजित करने वाले डोनर को स्वामित्व हस्तांतरण कार्य का गवाह बनने और उन लोगों के बारे में जानने के लिए आमंत्रित किया जिन्हें उनके दान के कारण लाभ हासिल हुआ। उदाहरण के लिए, एफ.एम.एफ. ने मारिया मोथुपी के लिए एक स्वामित्व हस्तांतरण समारोह आयोजित किया, जो उस समय 99 वर्ष

की थी। नि:संदेह मोथुपी के लिए, उनके नए स्वामित्व के लाभ स्पष्ट थे, अब उसके पास अपनी तीसरी पीढ़ी हेतु छोड़ने के लिए कुछ होगा। मोथुपी ने यह कहा भी कि वह संपत्ति में सुधार करने के लिए कुछ निवेश करेगी। जैसे कि नोलशंगु उल्लेख करते हैं, 'कई अश्वेत दक्षिण अफ्रीकियों के लिए (भूमि स्वामित्व) एक उपचारात्मक प्रक्रिया है।'

समारोह में डोनर टर्शिया कुक भी शामिल हुई और मोथुपी के साथ जश्न में भागीदारी की। कुक ने कहा कि उसने अपने भाई को जन्मदिन के उपहार के रूप में आर्थिक सहायता दी और इस निर्णय के लिए उसे खुशी है। बाद में उन्होंने जनवरी, 2016 में मोथुपी के लिए 100 वें जन्मदिन की पार्टी आयोजित की, जिसमें एफ.एम.एफ. की टीम भी उपस्थित थी।

एफ.एम.एफ. की टीम ने प्रचार सामग्रियों में मोथुपी की कहानी साझा की जिससे कुछ मीडिया का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। दरअसल, स्वामित्व दस्तावेज़ हस्तांतरण समारोह का उपयोग एक ओर डोनरों को प्रेरित करने के लिये किया गया तो वहीं दूसरी ओर पड़ोसियों और दोस्तों को इसे एक अवसर के रूप देखने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भी किया गया। इसके साथ ही एफ.एम.एफ. आवेदकों की संख्या में तेजी लाने और अपनी फंडिंग का विस्तार करने में भी सक्षम हुआ।

चौथा, यह कि टीम ने लोकप्रिय सरकारी नेताओं मसलन फ्री स्टेट प्रीमियर ऐस मैगाशुले और नगवाथे के कार्यकारी मेयर जॉय मोचेला का खुला समर्थन भी हासिल किया। उन नेताओं की उपस्थिति ने मीडिया को स्वामित्व दस्तावेज समारोह में आकर्षित करने में मदद की, जहां रिपोर्टर परियोजना से लाभान्वित होने वाले व्यक्तियों और उनके परिवारों से मिल सकते थे। मीडिया में प्रकाशित उन कहानियों ने लक्षित वर्ग को संलग्न करने और उन्हें इस के लिए सक्रिय करने में मदद की।

पांचवां, ऐसे आयोजनों की सहायता से एफ.एम.एफ. स्थानीय व्यवसायों, बैंकों और फर्मों तक पहुंच बनाने और अपने कार्यों के महत्व को समझाने में कामयाब हो गया। यहां तक कि कुछ फर्मों ने अपने कामगारों के लिए स्वामित्व दस्तावेजों को प्रायोजित करना प्रारंभ किया। चर्चाओं और मीडिया के ध्यान के माध्यम से, अन्य व्यवसायों के लोगों ने एफ.एम. एफ. को यह पूछने के लिए फोन करना शुरू किया कि वे इस अभियान से कैसे जुड़ सकते हैं।

उदाहरण के लिए, एक राष्ट्रव्यापी हार्डवेयर कंपनी ने नगवाथे में 54 स्वामित्व स्थानान्तरण दस्तावेजों को प्रायोजित किया है और हर उस क्षेत्र में स्वामित्व दिलाने का वादा किया है जहां यह स्टोर संचालित करता है। एक फल निर्यातक ने अपने सभी करीब सौ श्रमिकों को अपने घरों के स्वामित्व दस्तावेज प्राप्त करने में सहायता करने का वादा किया। जोहानिसबर्ग महानगरीय क्षेत्र में एक बड़ी इस्पात निर्माता कंपनी अपने पांच हजार श्रमिकों को अपने घरों के स्वामित्व दस्तावेज हासिल करने में मदद करने के व्यावहारिक पहलुओं

पर विचार किया। ये अवसर पायलट परियोजना से परे अन्य नगरपालिका क्षेत्रों में विस्तार के लिए मार्ग प्रशस्त करने में मदद कर रहे हैं।

वर्ष 2016 की शुरुआत तक, पायलट प्रोजेक्ट ने नगवाथे में 870 भूमि के स्वामित्व हासिल कराये थे जबकि तीन सौ प्रस्ताव विचाराधीन थे। अन्य क्षेत्रों में भी डोनरों ने स्वामित्व दस्तावेज के प्रायोजन में रुचि दिखाई। मुख्य रूप से केपटाउन क्षेत्र में 1,700 स्वामित्व दस्तावेज स्थानान्तरण के लिए योगदान और आश्वासन मिला।

एफ.एम.एफ. ने साबित किया कि प्रत्यक्ष परियोजना खर्चों के लिए प्रत्येक 100,000 यूएस डॉलर फंडिंग, दक्षिण अफ्रीकी में कम आय वाले लोगों के लिए पूंजी में तकरीबन 6.7 मिलियन यूएस डॉलर उत्पन्न करने में सक्षम है। यह शिक्षा खर्चों, नए व्यवसायों और संपत्ति में सुधार के साथ-साथ उत्तराधिकार और पुनर्वास के अवसरों के लिए ऋण के रूप में अवसर प्रदान करता है।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

भागीदारी पर

एफ.एम.एफ. ने अपने लक्षित वर्ग को जानने के महत्व की दृष्टि से इस परियोजना के माध्यम से एक गहरी समझ विकसित की। एफ.एम.एफ. की परियोजना के माध्यम से स्वामित्व प्राप्त करने के मौके पर नगवाथे के स्थानीय निवासी स्वत: शामिल नहीं हुए थे। वास्तव में, पात्र लोगों के विश्वास और उत्साह को अर्जित करने के लिए निरंतर प्रयास करने की आवश्यकता होती है। कुछ लोग नहीं मानते कि ऐसा अवसर वास्तविक हो सकता है। दूसरों को लाभ नहीं दिखता है, या लगता है कि यह प्रयास हकीकत में बदलने लायक नहीं है। यह दूसरों की मदद करने के बारे में एक व्यापक अंतर्दृष्टि को विकसित करता है: यहां उन लोगों के दृष्टिकोणों, इच्छाओं, और दुविधाओं को समझना महत्वपूर्ण है जिनकी आप मदद करना चाहते हैं। उनका ज्ञान उन निर्णयों के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक है, जो उन्हें करना चाहिए। कमोबेश उन फैसलों को स्वेच्छा से किया जाना चाहिए। एफ.एम.एफ. स्थानीय ज़रूरतों के लिए बेहतर ढंग से अपने प्रयासों को समायोजित करने में सक्षम था। स्थानीय वकीलों का उपयोग करके, वांछनीय निवासियों के बीच रोज काम करने के लिए प्रमुख कर्मचारियों को स्थानांतरित करना और स्थानीय निकायों के माध्यम से काम करके, एफ.एम.एफ. सफलता के लिए एक उपयोगी मॉडल की खोज करने के लिए एक बेहतर स्थिति में था।

शुरुआत करने के बारे में

एफ.एम.एफ की इस परियोजना के लिए अनुमानत: 7 मिलियन उम्मीदवार रहे। यह एक चुनौतीपूर्ण संख्या है। एक प्रबंधनीय पायलट परियोजना विकसित करके, एफ.एम.एफ. लचीलेपन के साथ अपने मॉडल का निर्माण करते समय व्यवहार्यता प्रदर्शित करने में सक्षम था। बड़े पैमाने पर एक परियोजना शुरू करना जोखिम भरा हो सकता है, विशेषरूप से अगर परियोजना को निष्पादित करने का अनुभव कार्यक्रम के डिजाइन में महत्वपूर्ण बदलावों का जरूरत बताता हो। इस बाबत अधिक जानकारी के लिए, एरिक रीज़ की पुस्तक 'द लीन स्टार्टअप' पढ़ें।

फंडिंग पर

दरअसल, एफ.एम.एफ. सभी उम्मीदवारों को भूमि के स्वामित्व के बारे में जानने और विचार करने का अवसर प्राप्त करता देखना चाहता है, लेकिन यह जानता है कि मौजूदा फंडिंग मॉडल पूर्ण पैमाने को पूरा करने में सक्षम नहीं होगा। इस वजह से यह महत्वपूर्ण है कि एफ.एम.एफ. स्वामित्व के लाभों को तलाशने और प्रदर्शित करना जारी रखे, विशेषकर उन लोगों के बीच जो खया लैम से लाभान्वित हुए हैं। यहां तक कि 122 यूएस डालर दक्षिण अफ्रीका में कई लोगों के लिए एक बड़ी राशि हो सकती है, इसलिए एफ.एम.एफ. को यह अपेक्षा करने के लिए पर्याप्त मूल्यांकन की उम्मीद है कि उम्मीदवार अपने स्वामित्व हस्तांतरण हेतु धन जुटाने के अपने तरीके खोजने लगेंगे। ये तरीके या तो बचत के होंगे या फिर उधार के माध्यम से जुटाये जाएंगे। इसके अतिरिक्त, नियोक्ता मॉडल, जिसके जरिये कंपनियां अपने कर्मचारियों के भूमि स्वामित्व को प्रायोजित करती हैं, से भी काफी उम्मीदे हैं। इससे आगामी चरणों के प्रोजेक्ट के लिए योजना बनाने से फंडिंग मॉडल में बदलाव आसान हो सकता है।

संदेशन पर

नि:संदेह अपने लक्षित वर्ग के बारे में स्पष्ट समझ रखना महत्वपूर्ण है। दक्षिण अफ्रीका में, कुछ प्रचलित आर्थिक शब्दों का भारी राजनीतिकरण किया गया है और ये विवादपूर्ण अर्थों से भरे हुए हैं। 'हमने एक बार भी पूंजीवाद के बारे में बात नहीं की थी; हमने उस समाज में स्वामित्व और संपत्ति के बारे में बात की' डेवी ने कहा। 'बस इतना ही'। अपने लक्षित वर्ग न कि अपने स्वयं के हितों पर ध्यान केंद्रित करके, एफ.एम.एफ. बेहतर तरीके से परियोजना के लाभों को व्यक्त करने में और परिणामों को हासिल करने में सक्षम रहा। एफ.एम.एफ. भी लगातार खुद को एक पक्षपात रहित संगठन के रूप में प्रस्तुत करता है जो ईमानदारी से रंगभेदी युग में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए प्रतिबद्ध है। नतीजतन, वे पक्षपातपूर्ण

विभाजन को पुल का काम करने और सहयोगियों की विविधता के साथ काम करने में सक्षम रहे हैं।

चर्चा योग्य प्रश्न

- लक्षित वर्ग के उन लोगों की सूची बनाएं जो आपके कार्यक्रमों में से एक को पूरा करने का इरादा रखते है। आपके सफल होने पर वे कौन से लाभों का अनुभव करेंगे? आप उन लाभों के बारे में अपने लक्षित वर्ग के साथ किस प्रकार संचार करेंगे ताकि वे स्वयं को उससे व आपके अभियान से जोड़ सकें। वह शब्दावली, जो स्वतंत्रता के विचारों से जुड़ी है आपके संदेश को प्रसारित करेगी या भ्रमित करेगी?
- अपने संगठन में एक नई या आगामी परियोजना की पहचान करें। आप अपने मॉडल के उन पहलुओं को अति-निवेश के बिना कैसे परखेंगे जो सफल नहीं हो सकते हैं?
- क्या आपके पास डोनरों और आपकी परियोजना के लाभार्थियों को मिलाने और एक-दूसरे से सीखने के लिए एक साथ लाने के अवसर हैं? आप एक यादगार अनुभव सुनिश्चित करने के लिए इस तरह के अवसर और मंथन के तरीके के लिए एक योजना का प्रारूप तैयार करें। क्या यह प्रयास मीडिया कवरेज के अवसर के रूप में भी काम कर सकता है?
- क्या आपके क्षेत्र में मौजूदा सार्वजनिक नीति के लाभों की वृद्धि में मदद करने के लिए कोई मौका है?

छोटे किसानों के भूमि के अधिकारों की बहाली

ईजी बिजनेस
यूक्रेन

परिचय

वर्ष 2014 में स्थापित किये गये ईजी बिजनेस का मिशन मुक्त बाजारों और प्रतिस्पर्धा के सिद्धांतों के आधार पर आर्थिक शोध और स्वतंत्र नीतियों वाली सिफ़ारिशें करके यूक्रेन के व्यापारिक वातावरण में सुधार करना है। ईजी बिजनेस की नीति का लक्ष्य भूमि सुधार, निवेश और व्यापार माहौल में सुधार, और यूक्रेनी स्टार्टअप्स के बीच नवाचार की सुविधा उपलब्ध कराना है।

यूक्रेनी सरकार ने जब भूमि सुधार के आग्रह को नजरअंदाज करने का मन बनाया, तो प्रगतिशील नेताओं ने ईजी बिजनेस का गठन किया, जो शोधकर्ताओं, याचिका दाखिल करने वालों और नागरिकों के लिए एक मंच उपलब्ध कराता है। इसका उद्देश्य संपत्ति मालिकों के लिए बाजार खोलना है ताकि वे स्वतंत्र रूप से खेती योग्य जमीन खरीदने और बेचने में सक्षम हो सकें जो पूर्व में प्रतिबंधित रहा है।

समूह के संस्थापक मूल रूप से सरकारी विनियामक टीम के सदस्य थे जहां उन्होंने सरकार से संपत्ति के अधिकार सुधार, विशेष रूप से कृषि भूमि की बिक्री पर लगी रोक को समाप्त करने को प्राथमिकता देने का आग्रह किया था। उनकी सिफारिशों को सरकार द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया जिसके बाद उन्होंने एक स्वयंसेवी संगठन के रुप में सबसे पहले ईज़ी बिजनेस का गठन किया और अंतत: अपनी लड़ाई अदालतों में ले गये।

इसी दौरान उन्होंने यूक्रेनी भूस्वामियों के उपयोग अनुकूल ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म शुरू किया ताकि वे अपने स्थानीय अधिकारियों पर दबाव बनाते हुए अपना अभियान शुरू कर सकें और साथ ही यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स या ईसीएचआर के जरिये सरकारों पर ऊपर से नीचे तक सुधार के लिए दबाव बना सकें।

‘न्यायालय महत्वपूर्ण सुधारों का समर्थन करने में बहुत मददगार साबित हो सकते हैं।’ ये कहना है ईज़ी बिजनेस के सीईओ एंड्रयू श्पाकोव का। ‘वे आमतौर पर स्वतंत्र और तटस्थ पार्टियों के रूप में देखे जाते हैं, जो समस्या के निष्पक्ष दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने में सक्षम हैं। हमारे मामले में, इसने उत्कृष्टता के साथ काम किया। जनता और राजनेताओं दोनों ने देखा कि मुक्त कृषि भूमि बाजार की आवश्यकता एक समूह की मांग मात्र नहीं है, लेकिन मान्यता प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय संस्था की प्रत्यक्ष आवश्यकता है जो संपत्ति के अधिकारों की रक्षा करती है। इस निर्णय से भूमि सुधार के कार्यान्वयन की वकालत करना आसान हो गया।’

ईज़ी बिजनेस की पहल ने यूक्रेन में भूमि बाजार कैसे खोले :

- एक नई मिसाल - ईज़ी बिजनेस के प्रयासों से यूरोपीय कोर्ट ऑफ ह्यूमन राइट्स ने अनुकूल निर्णय लिये, जिससे 7 मिलियन प्रभावित भूस्वामियों को उनके अधिकारों का दावा करने के लिए एक विश्वसनीय आधार मिला। थिंक टैंक का अनुमान है कि इस बाजार के उदारीकरण से दीर्घकाल में अर्थव्यवस्था में करीब 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निवेश हो सकता है। इसके अलावा यह भी अनुमान है कि प्रतिबंध किसी हद तक 500 मिलियन से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकता है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष वृद्धि की संभावना रखता है।
- भीतर से बदलाव - अदालत के इस फैसले के तुरंत बाद, यूक्रेनी संसद के 69 सदस्यों ने यूक्रेन के संवैधानिक न्यायालय के समक्ष एक मामला प्रस्तुत करते हुए यह स्वीकार किया कि प्रतिबंध यूक्रेनी संविधान का उल्लंघन करता है। यूक्रेन में न्याय मंत्रालय ने एक कामकाजी समूह भी बनाया, जिसमें ईज़ी बिजनेस को भी शामिल किया गया। इस समूह ने यूक्रेन में एक औपचारिक कृषि बाजार शुरू करने के लिए प्रभावी तंत्र विकसित करने का प्रारूप तैयार किया।
- सुधार आंदोलन के लिए पूरी ताकत - ईजी बिजनेस ने व्यापक शोध कार्य का प्रदर्शन किया, जमीन से जुड़े विशेषज्ञों का एक गठबंधन तैयार किया। पहले से ही अपने साथ ऑनलाइन मंच के माध्यम से जुड़े 500 से अधिक यूक्रेनी भूस्वामियों को सहायता प्रदान की है। जो एक प्रबुद्ध बौद्धिक विश्वास और जमीनी स्तर पर आंदोलन को गति दे रहा है।

परियोजना का विवरण

हेरिटेज फाउंडेशन के 2019 इंडेक्स ऑफ इकोनॉमिक फ्रीडम के अनुसार, यूक्रेन 44 यूरोपीय देशों में आर्थिक स्वतंत्रता सूची में अंतिम स्थान पर है। इनमें सबसे ज्यादा अतिक्रमण संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता का है। यूक्रेन में लगभग 7 मिलियन भूस्वामियों को कानूनी रूप से अपनी जमीन बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया है, जिससे यूक्रेन एकमात्र ऐसा लोकतांत्रिक राज्य है जहां लोगों को अपनी संपत्ति के स्वतंत्र रूप से निस्तारण से रोक दिया गया है।

इस देश में पंद्रह प्रतिशत आबादी के पास सत्तर प्रतिशत भूमि है, जिसमें से अधिकांश भूमि का उपयोग नहीं किया जाता है। वर्षों से देश में कृषि भूमि की बिक्री पर रोक का मुद्दा तबतक गर्म रहा जब तक कि हाल ही में क्यीव स्थित ईजी बिजनेस द्वारा ईसीएचआर में दाखिल मुकदमा सफल परिणति तक नहीं पहुंच गया।

अन्य नीतियों की तरह जो बनती तो अच्छे मकसद के लिए हैं, मगर अंततः व्यवस्था को नुकसान ही पहुंचाती हैं, यूक्रेन के कृषि बाजार पर प्रतिबंध भी अच्छे इरादों के साथ लागू किया गया था। पूर्व सोवियत कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत पीड़ितों के लिए भूमि को नये सिरे से बांटा गया था। नई सरकार ने ऐसे कानून बनाए जो नए भूमि मालिकों को बेचने के लिए दबाव से बचाने के तरीके के रूप में भूमि बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया। लेकिन वर्षों बाद, एक तथ्य यह उभरकर सामने आया कि बहुत से ऐसी ज़मीनों के मालिक हैं, जिन्हें वे बनाए नहीं रख सकते हैं, लेकिन कुछ और भी नहीं कर सकते। वे अपनी जमीन बेच भी नहीं सकते और वे अपनी संपत्ति का उपयोग व्यावसायिक उपक्रमों में समानान्तर रूप से भी नहीं कर सकते। इस तरह वे 'भूमिहीन' हो गए हैं।

एटलस नेटवर्क के अन्य साझेदारों ने भी यूक्रेन में इस मुद्दे पर कार्य किया है और यहां ईज़ी बिजनेस भूमि सुधार की दिशा में भरोसेमंद मार्ग प्रदान करने और खेतों के लिए एक मुक्त बाजार के विचार को लोकप्रिय बनाने में एक अग्रणी आवाज रही है। लगभग चार वर्षों में, समूह ने एक व्यापक नीति शोध कार्यक्रम और भूमि बाजार सुधार के लिए एक मार्गदर्शक कार्यक्रम विकसित किया। इसके अतिरिक्त विशेषज्ञों और आम यूक्रेनियों तक पहुंचने के लिए एक व्यापक संचार रणनीति को विस्तार दिया, जो इस मुद्दे के बारे में नहीं जानते थे।

इस समूह ने www.farmland.in.ua नामक एक वेबसाइट भी लॉन्च की, जो यूक्रेन के भूमि बिक्री प्रतिबंध की संवैधानिकता को चुनौती देने के लिए भूस्वामियों को ई.सी.एच.आर. में आवेदन करने में सहायता प्रदान करती थी। करीब 500 से अधिक आवेदन मंच के माध्यम से प्रस्तुत किए गए थे। जिनमें से दो को वास्तव में ई.सी.एच.आर. द्वारा स्वीकार किया गया, जहां ईज़ी बिजनेस फिर एक स्वतंत्र थिंक टैंक के रूप में तीसरा पक्ष बन गया, जो आर्थिक विशेषज्ञता और विधायी पृष्ठभूमि प्रदान करने में सहायक था।

मई 2018 में, दो यूक्रेनी भूस्वामियों ने यूक्रेन की सरकार के खिलाफ ई.सी.एच.आर. में अपना केस जीता। ई.सी.एच.आर. के फैसले के तुरंत बाद, यूक्रेनी संसद के 69 सदस्यों ने यूक्रेन के संवैधानिक न्यायालय को एक मामला प्रस्तुत किया, जिसमें कहा गया कि देश की तथाकथित कृषि भूमि की बिक्री पर रोक यूक्रेनी संविधान का उल्लंघन करती है।

ईज़ी बिजनेस का आकलन है कि यूक्रेन की भूमि बिक्री पर प्रतिबंध में सुधार से अर्थव्यवस्था में दीर्घकाल में 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर की वृद्धि हो सकती है। ईज़ी बिज़नेस का यह भी आकलन है कि प्रतिबंध किसी हद तक 500 मिलियन से 600 मिलियन अमेरिकी डॉलर तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को रोकता है और सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 10 बिलियन अमेरिकी डॉलर प्रति वर्ष वृद्धि की संभावना रखता है।

दरअसल, यूक्रेन में कृषि भूमि में बिक्री पर रोक के कारण सात मिलियन कृषि भूमि मालिक (जो यूक्रेन की कुल आबादी का 15 प्रतिशत है) और जिनके पास 28 मिलियन हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि है (जो यूक्रेन की कृषि योग्य कुल भूमि का 70 प्रतिशत है) वे स्वतंत्र रूप से अपनी भूखंडों की खरीद-फरोख्त नहीं कर सकते हैं। इस तरह मानवाधिकार उल्लंघन के मायने हैं कि यूक्रेन दुनिया भर में ऐसा लोकतांत्रिक देश है (वेनेजुएला, क्यूबा, ताजिकिस्तान और उत्तर कोरिया के साथ) जहां खेती की बिक्री पर रोक अभी भी मौजूद है।

इसे बदलने के लिए ईजी बिज़नेस को तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा :-

- स्थानीय अधिकारियों और भू स्वामियों के बीच इस बात को लेकर जागरूकता की कमी थी कि जमीन की खरीद-फरोख्त की आज़ादी से अर्थव्यवस्था और भू स्वामियों को कितना लाभ हो सकता है। यूक्रेन के केवल 18.8 फीसदी लोग ही सुधारों की बारीकियों से अवगत हैं।
- दरअसल, यूक्रेन में राजनीतिक दलों की लोकलुभावन नीति के तहत आक्रामक मीडिया अभियानों के कारण सुधारों के प्रति लोगों का रवैया एकपक्षी हो गया था। ईजी बिज़नेस अभियान की शुरुआत में केवल 32.4 प्रतिशत यूक्रेनियन ने ही भूमि सुधार का समर्थन किया।
- यूक्रेन में भूमि सुधार की दिशा में राजनीतिक समर्थन के अभाव में कृषि योग्य भूमि की स्वतंत्र खरीद बिक्री प्रतिबंध से मुक्त न हो पायी। इसकी मुख्य वजह लोकलुभावन वाद का प्रबल समर्थन ही रहा।

ईजी बिजनेस ने चुनौतियों के बावजूद सुधार और स्वतंत्रता के पक्ष में जनाधार जुटाने के लिए अनूठे उपायों का प्रयोग किया।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

जनाधार को आकार देना

'आम तौर पर, भूमि सुधार अभियान एक खास मामला था, जो मुक्त बाजार के लिए कम जन समर्थन और राजनेताओं की अनिच्छा के साथ जुड़ा था।' ईज़ी बिजनेस के सीईओ एंड्रयू श्पाकोव ने कहा, 'जनता ने सुधार में निहित लाभों को नहीं समझा और वे डरते थे कि कहीं विदेशी हित से जुड़े लोग सभी यूक्रेनी कृषि योग्य भूमि को न खरीद लें।' इस बीच, ज्यादातर राजनेताओं ने खुद को भूमि मामलों से हटा लिया क्योंकि उन्हें यह राजनीतिक रूप से नुकसानदायक लगा और इससे उनकी राजनैतिक छवि को नुकसान पहुंच सकता था।

उस समय आप क्या करेंगे, जब आप पहले से स्थापित गलत धारणाओं के खिलाफ काम कर रहे हों? ईजी बिज़नेस ने तथ्यों और आंकड़ों की बुनियाद पर नई आधार रेखा की स्थापना की।

भूमि सुधार प्रणालियों के लाभों को समझाने के लिए 60 देशों के विश्लेषण के साथ शोध आरंभ हुआ। ईजी बिज़नेस की टीम 'मिथक तोड़ने वाली' बन गई, जो मुक्त बाजारों के बारे में सच्चाई को उजागर कर रही थी। टीम ने बताया कि प्रतिबंध से हर रोज यूक्रेन को कितना नुकसान होता है। साथ ही यह भी बताया कि कैसे एक खुला बाजार यूक्रेन और उसके लोगों के लिए बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ उत्पन्न करेगा।

इस तरह नए शोध ने मीडिया में काफी ध्यान आकर्षित किया और सरकार के प्रभावशाली लोगों की सोच में बदलाव किया, लेकिन इसके बावजूद ईजी बिज़नेस को अभी भी आम जनता को समझाने के लिए एक लंबा रास्ता तय करना था। विशेष रूप से उन भूस्वामियों को समझाने के लिए जो सुधार से सबसे अधिक लाभान्वित होंगे। इसलिए इस समूह ने ईजी बिजनेस की अपील के लिए मुक्त विचारों वाले भू स्वामियों का समर्थन जुटाने के लिए एक नई पहल शुरू की।

फिर एक नई वेबसाइट farmland.in.ua के जरिये भूस्वामियों को ईसीएचआर के लिए अपील दायर करने की अनुमति दी गई। आखिरकार ईज़ी बिज़नेस को अदालत में अपील करने वाले पांच सौ से अधिक भू स्वामियों के आवेदनों का आधार मिल गया, जिसके परिणामस्वरूप सामूहिक मुकदमा दायर किया गया। इस तरह ईज़ी बिज़नेस आर्थिक और विधायी विशेषज्ञता की पृष्ठभूमि प्रदान वाली तीसरी पार्टी बन गई। कुल मिलाकर, इन प्रयासों ने नए अवसरों की एक सीमा को नया विस्तार दिया तथा शक्तियों का संतुलन संभव बनाया।

गठबंधन पर

परिवर्तनकारी नीतियों से बदलाव सहयोगियों के बिना संभव नहीं हो सकता। दुर्भाग्य से, शुरुआत में ईजी बिजनेस के लिए उन सहयोगियों को ढूंढ़ना मुश्किल था, जिन्होंने यूक्रेन के लिए मुक्त-बाज़ार फ़ार्मलैंड मॉडल का खुलकर समर्थन करते थे। वे भाग्यशाली थे, उन्होंने उन साझेदारों को जुटा लिया, जिन्होंने यूक्रेन में कृषि योग्य भूमि को बिक्री के लिये खोलने के विचार का समर्थन किया।

ईजी बिजनेस के सीईओ एंड्रयू श्पाकोव बताते हैं 'कालांतर में हमने अपने सभी भागीदारों के बीच एक खुले फार्मलैंड बाजार के विचार को बढ़ावा दिया। इस दृष्टिकोण ने अंततः समेकित रूप में कई सहयोगियों को सुधार की वकालत का समर्थन करने के लिए तैयार किया।'

ईजी बिजनेस संगठन भी इस मुहिम के लिए साथी एटलस नेटवर्क विशेषज्ञों का साथ मिलने की वजह से भाग्यशाली था, और यह अन्य भागीदारों को साथ जुटाने में सक्षम था, जिसमें सेंटर ऑफ इकॉनॉमिक स्ट्रेटेजी, इकॉनोमिचना प्रावदा, यूक्रेनियन इकोनॉमिक फ्रीडम्स फ़ाउंडेशन और अन्यों को इस अभियान के प्रसार में मदद के लिए शामिल किया गया था। ये साझेदार, यूक्रेन की संवैधानिक अदालत में प्रतिबंध को गैरकानूनी बताते हुए एक जनहित शिकायत दायर कर उसे समाप्त करने की मुहिम को विश्वसनीय आवाज़ प्रदान करने में सक्षम थे।

कहानी कहने की कला पर

ईज़ी बिज़नेस के लिए, इस अभियान को सफल बनाने के लिए न केवल अन्य अनुसंधान संगठनों और कानूनी संगठनों के समर्थन और साझेदारी की आवश्यकता थी, बल्कि ज़मीन के मालिकों की सहायता की भी आवश्यकता थी।

दरअसल, यह बहुत से लोगों के लिए ज्ञात नहीं था कि यूक्रेन की भूमि की बिक्री प्रतिबंधों का उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। ईजी बिज़नेस ने सुधार के कारकों को गति पैदा करने के लिए प्रभावित लोगों की कहानियों को साझा किया।

समूह के farmland.in.ua ऑनलाइन पोर्टल ने उन भूस्वामियों की पहचान करने में मदद की, जो लड़ाई में शामिल होना चाहते थे।

उनमें से दो भू स्वामी सोफिया ज़ेलेंचुक और विक्टर त्सेत्युरा थे। ईज़ी बिजनेस के ऑनलाइन पोर्टल का उपयोग कर वे यूक्रेनी सरकार के खिलाफ मामले में दो वादी बन गए। अंतत: वे जीत गए।

ईज़ी बिजनेस ने उस 79 वर्षीय विक्टर की कहानी बताई, जिसने वर्ष 2008 में सरकार से अपनी संपत्ति के प्रमाणपत्र प्राप्त किए। अब वृद्धावस्था में विक्टर खेती का काम नहीं कर सकते हैं और इसे बेचना चाहेंगे ताकि वह आराम से रिटायर हो सके। मगर खेती की बिक्री पर यूक्रेन में लगे प्रतिबंध ने उन्हें ऐसी संपत्ति पर बने रहने के लिए मजबूर कर दिया था जो वहन नहीं कर सकते थे। इस तरह विक्टर की कहानी को बढ़ाकर ईजी बिज़नेस ने लोगों को उस अव्यवहारिक भूमि नीति का शिकार बताया। उन्होंने विक्टर के लिए सुधार आंदोलन में एक सक्रिय भागीदार बनने के लिए एक मौका भी प्रदान किया। उन्होंने समूह के सार्वजनिक शैक्षिक कार्यक्रमों में भाग लिया और आंदोलन के दौरान फोन पर ईजी बिजनेस टीम के सदस्यों के साथ अक्सर बातचीत की। यहां तक कि विक्टर राजनेताओं, कार्यकर्ताओं और विशेषज्ञों के साथ एक पैनल चर्चा में भाग लेने के लिए क्यीव भी आए। सोशल मीडिया पर विक्टर की कहानी वाले ईज़ी बिज़नेस के वीडियो को एक लाख से अधिक बार देखा गया था।

निःसंदेह ईज़ी बिजनेस के प्रयासों के बिना, यूक्रेन में भूस्वामियों को अभी भी उन प्रतिबंधों को हटने की कोई उम्मीद नहीं रही होगी जो उन्हें स्वतंत्र रूप से कृषि योग्य भूमि खरीदने-बेचने से रोकते हैं।

चर्चा में शामिल प्रश्न

- क्या आपके देश में ऐसे कानून हैं जो संपत्ति के अधिकारों के स्वतंत्र उपयोग को रोकते है? वे क्या हैं और कौन लोग उनसे ज्यादा प्रभावित हैं?
- क्या आप सोचते हैं कि आपका थिंट टैंक सरकार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई में भाग लेता है? यदि नहीं तो क्यों? क्या कुछ ऐसे गठबंधन सहयोगी हैं जो इस काम में आपके लिए मददगार साबित हो सकते हैं?
- आप उन लोगों तक कैसे पहुंच बना सकते हैं, जिनको आपके द्वारा किये जाने वाले सुधार वकालत के कार्यों के कारण लाभ प्राप्त हो सकता है। आप उनकी कहानी को प्रभावी ढंग से कैसे बता सकते हैं?
- आप यह केस कैसे बना सकते हैं कि जब सरकारी प्रतिबंधों और उनके दुरुपयोग से अपनी और अपनी आजीविका की रक्षा करने की बात आती है तो संपत्ति के अधिकार भी नागरिक और मानवाधिकारों के समान ही महत्वपूर्ण साबित हैं।

खंड 4:

व्यापार और व्यवसायिक लाइसेंस की आवश्यकता का विषय अवलोकन

औपचारिक बाजार में भागीदारी की योग्यता समृद्धि की कुंजी है। औपचारिक बाजार में भागीदारी औपचारिक संस्थागत सुरक्षा प्रदान करती है। उदाहरण के लिए, जब आप एक औपचारिक बाजार में काम करते हैं तो विवादों के अदालत में शांतिपूर्वक निस्तारण की संभावना होती है। साथ ही ऋण और अन्य वित्तीय साधनों तक पहुंच काफी बढ़ जाती है। भविष्य की योजना तब अधिक संभव होती है जब विश्वास और संस्थान स्थिरता और पूर्वानुमेयता प्रदान करते हैं।

विडंबना यह है कि कई स्थानों पर, औपचारिक बाजार में शामिल होने के मार्ग में बाधाएं स्वीकार करने की सीमा से अधिक हैं। दरअसल, न केवल महंगी सरकारी लाइसेंस फीस बहुत सामान्य व्यवसायों को बाजार में पंजीकृत करने से रोकती है, बल्कि यह भ्रष्ट नौकरशाहों को भी रिश्वत देने के अवसरों को बढ़ावा देती है। इस तरह से कानूनी बाजार में प्रवेश करने की लागत बढ़ जाती है। साथ ही साथ, कई स्थानों पर एक लाइसेंस को मंजूरी देने के लिए तमाम सरकारी एजेंसियों की संख्या भ्रम और देरी उत्पन्न करती है, जिसके चलते बहुत कम आय वाले उद्यमियों की वास्तविक लागत अक्सर बहुत अधिक हो जाती है। खास लोगों के हित के तहत अक्सर प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए लाइसेंसिंग का उपयोग किया जा सकता है। कम आय वाले प्रवेशकों की कीमत पर अच्छी तरह से स्थापित प्रतियोगियों को सुरक्षा प्रदान की जाती है। केवल जब हम उन बाधाओं को समाप्त या सरल बनायेंगे, तभी प्रतिभावान, कम आय वाली जनसंख्या के पास समृद्धि को हासिल करने का एक वास्तविक मौका उपलब्ध होगा।

इस खंड में केस स्टडी के वर्जन AtlasNetwork.org पर उपलब्ध हैं।

कम आय वाली जनसंख्या के लिए वैध बाजार को खोलनासेंटर

फॉर डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज़ेज़ ग्रेट लेक्स बुरुंडी

परिचय

बुरुंडी विश्व बैंक द्वारा जारी किये जाने वाले व्यापार करने की सुगमता रिपोर्ट में सबसे कम रैंक वाले देशों में शुमार है। विश्व बैंक व्यापार करने की सुगमता के आधार पर देशों को रैंक प्रदान करता है। राजनीतिक अस्थिरता और एक भ्रष्ट व अत्यंत केंद्रीकृत सरकार ने उन सभी लोगों के लिए आर्थिक माहौल को मुश्किल बना दिया है जो शासक वर्ग से संबद्ध या वफादार नहीं हैं।

सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंटरप्राइज़ेज़ ग्रेट लेक्स या सीडीई-ग्रेट लेक्स, मुक्त समाज और मुक्त बाजार के सिद्धांतों के आधार पर बुरुंडी, रवांडा और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो में समृद्धि और अवसरों से युक्त बाजार के राह की बाधाओं को कम करने के लिए संघर्ष करता है।

विशेष रूप से, सेंटर फॉर डेवलपमेंट एंटरप्राइज़ेज़ ग्रेट लेक्स ने व्यवसाय को वैध बनने के लिए आवश्यक लाइसेंस की कीमत को अप्रत्याशित रूप से कम करने के लिए लड़ाई लड़ी, जो कई व्यापार करने वालों के लिए एक दुर्गम बाधा थी। समूह ने देश की अगली पीढ़ी के उद्यमियों को प्रशिक्षित और शिक्षित करने के लिए कई कार्यक्रम भी तैयार किये हैं, जो बुरुंडी की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित करने और लोगों का जीवन स्तर ऊपर उठाने में मदद करेंगे।

इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए, सीडीई- ग्रेट लेक ने अपना 'बिरशोबोका परियोजना' प्रोजेक्ट लॉन्च किया। 'बिरशोबोका' शब्द बुरुंडी का एक स्थानीय किरुंदी शब्द है जिसका अर्थ है 'यह संभव है।' इस परियोजना के माध्यम से सीडीई ग्रेट लेक अगली पीढ़ी के

बुरुंडियन सामाजिक उद्यमियों को प्रशिक्षित कर रहा है और उनकी सफलता के लिए देश के कानूनों और आर्थिक वातावरण को न्यायसंगत बनाने के लिए लड़ रहा है।

सीडीई- ग्रेट लेक ने बुरुंडी में व्यवसाय विकास के लिए परिदृश्य कैसे बदला :

- सीडीई-ग्रेट लेक्स के प्रयासों ने बुरुंडी सरकार को लाइसेंस की लागत में कटौती करने के लिए सहमत किया। सरकार ने लाइसेंस फीस मूल्य के एक-चौथाई यानी 78 यूएस डॉलर से 22 यूएस डॉलर (यानी 140,000 फ्रैंक से 40,000 फ्रैंक,बुरुंडियन मुद्रा) कर दी।
- सीडीई-ग्रेट लेक्स ने 1,500 से अधिक उद्यमियों को, उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से मुकाबले के लिए प्रशिक्षित और शिक्षित किया है, जिससे उन्हें अपने नए व्यावसायिक उपक्रमों को सफलतापूर्वक संचालित करने में मदद मिले।
- बुरुंडी के लोगों का मानना है कि देश में आर्थिक सुधारों की संभावना है और संस्था के प्रयासों ने देश में उद्यमिता की नई लहर को उत्पन्न करने को प्रेरित किया है।

सीडीई-ग्रेट लेक्स की कहानी प्रेरक सबक :

- खुद मिसाल बने, लोगों में विश्वास जगायें कि परिवर्तन उनके स्वयं के जीवन में हो सकता है।
- सभी प्रमुख हितधारकों को एक साथ लाकर नीतिगत परिवर्तन की गुणवत्ता के आधार पर सभी पक्षों को शिक्षित करें।
- शोध और एक मजबूत मीडिया अभियान के साथ सत्तावाद के सामने भयमुक्त होकर मुखर अभिव्यक्ति दें, फिर गठबंधन निर्माण की ओर उन्मुख हों।

परियोजना का विवरण

बुरुंडी दुनिया के सबसे गरीब और भ्रष्ट देश दोनों है। अशांत और अति हस्तक्षेप वाली सरकार जीवन को अप्रत्याशित और उन्नति की गतिशीलता को चुनौती पूर्ण बना देती है। मुक्त बाजार की आवश्यकता बुरुंडी के लोगों को संभवतः दुनिया के अन्य देशों से कहीं अधिक है। इससे बुरुंडी के लोगों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगेगी।

बुरुंडी के लोगों को बताने की जरूरत है कि उनका भविष्य भी बेहतर हो सकता है। इसी आशा और संभावना की भावना को हकीकत में बदलने की दिशा में सीडीई-ग्रेट लेक्स ने

अपना महत्वाकांक्षी 'बिरशोबोका प्रोजेक्ट' लॉन्च किया है। सीडीई-ग्रेट लेक्स की चुनौती दमनकारी सत्तावादी सरकार वाले देश में इन सुधारों को क्रियान्वित करने की थी।

बुरुंडी समेत कई अफ्रीकी देशों में, कोई भी आर्थिक प्रतिस्पर्धा नजर नहीं आती है। इसकी वजह यह है कि केवल वही व्यवसाय मौजूद हैं जो एक भ्रष्ट सरकार के आशीर्वाद के साथ कारोबार करते हैं।

ये व्यवसायी अधिकारियों को रिश्वत देते हैं और बाजार में दबदबा बनाए रखते हैं, इससे कीमतें बढ़ती हैं और परिणामस्वरूप उपभोक्ताओं को नुकसान होता है और नागरिक एक मनमानी कीमतों वाले बाजार के बंधक बनकर रह जाते हैं। नि:संदेह एक बड़े एकाधिकार का बाजार नवाचार को प्रोत्साहन नहीं करता है, जिसके चलते मजदूरी की दर कम रहती है और बड़े कारोबार के मालिक अपने सरकारी सहयोगियों के साथ भारी मुनाफा अर्जित करते हैं।

वहीं दूसरी ओर, जिन देशों में बाजार खुला है और कानून का शासन लागू है, व्यापार की गतिशीलता बढ़ जाती है और अन्य देशों के लोग उन क्षेत्रों में आते हैं। यह दक्षिण अफ्रीका के मामले में सच था जब यह संपन्न हो रहा था, उप-सहारा अफ्रीका के तमाम लोग काम करने, खरीदारी करने और विश्वविद्यालय जाने के लिए दक्षिण अफ्रीका गए।

बुरुंडी दुनिया के सबसे गरीब और भ्रष्ट देशों में से एक है। अशांत और अति हस्तक्षेप वाली सरकार जीवन को अप्रत्याशित और उन्नति की गतिशीलता को चुनौतीपूर्ण बना देती है। शायद दुनिया में अन्य देशों की तुलना में बुरुंडी के लोगों में बेहतर भविष्य की उम्मीद जगाने के लिए मुक्त बाजार की अधिक आवश्यकता है।

बुरुंडी के लोगों को बताने की जरूरत है कि उनके लिए एक बेहतर भविष्य संभव है। इसी आशा और संभावना की भावना को हकीकत में बदलने की दिशा में सीडीई-ग्रेट लेक्स ने अपना महत्वाकांक्षी 'बिरशोबोका प्रोजेक्ट' लॉन्च किया। सीडीई-ग्रेट लेक्स की चुनौती दमनकारी सत्तावादी सरकार वाले देश में इन सुधारों को क्रियान्वित करने की थी।

'बिरशोबोका प्रोजेक्ट' को दो भागों में रखा गया है। पहले भाग में अच्छे व्यावसायिक व्यवहारों में संभावित उद्यमियों का चयन, प्रशिक्षण और सहायता करना शामिल है ताकि उनके व्यवसाय उनके समुदायों के भीतर पनप सकें। दूसरे भाग में डूइंग बिज़नेस रिपोर्ट के आधार पर मानकों में सुधार के उद्देश्य से रणनीतिक सुधार शामिल हैं, जिस सूची में बुरुंडी वर्तमान में 190 में से 186वें स्थान पर है। दरअसल, यह खराब रैंकिंग उस सख्त दस-चरण की प्रक्रिया के कारण है जो व्यवसाय शुरू करने के लिए आवश्यक है। परिणामस्वरूप, अनेक उद्यमी अनौपचारिक अर्थव्यवस्था की ओर अग्रसर होंगे। 'बिरशोबोका प्रोजेक्ट' बैंकिंग प्रथाओं को भी बदलना चाहती है ताकि बेहतर सुधार की प्रक्रिया को आसान बनाया जा सके।

सीडीई-ग्रेट लेक्स ने कई महत्वपूर्ण सुधारों को दिशा दी, जिससे बुरुंडी में व्यापार पंजीकरण तक अधिक लोगों की पहुंच संभव हो सकी। इसके चलते उस देश में जहां प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद 2017 में लगभग 320 यूएस डॉलर था, व्यवसाय को पंजीकृत करने का शुल्क 78 यूएस में डॉलर से घटकर 22 डॉलर तक रह गई। यही नहीं व्यवसाय पंजीकृत करने में लगने वाला समय कई महीनों से घटकर केवल एक दिन रह गया है। इससे पहले बैंकों द्वारा व्यापार ऋण के लिए 18 प्रतिशत की दर से ब्याज वसूला जाता था। साथ ही व्यापारिक बैंक खाते को खोलने के लिए 16 यूएस डॉलर का शुल्क चुकाना पड़ता था। लेकिन बिरशोबोका अभियान को धन्यवाद जिसके प्रयासों के कारण ब्याज दरों को घटाकर 10 प्रतिशत कर दिया गया है और आवश्यक शुल्क को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है।

इन तमाम सुधारों का थोड़े ही समय में जो प्रभाव पड़ा है वह पहले से ही सर्वविदित है। वर्ष 2017 से 2018 तक, नए व्यवसाय पंजीकरण की संख्या 49.84 प्रतिशत बढ़ी। जबकि वर्ष 2017 में, नए पंजीकृत मामलों की संख्या में केवल 5.34 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई थी।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

कठिन राजनीतिक परिस्थितियों में राह दिखाना

बुरुंडी में, एक मजबूत सत्तावादी सरकार ने सुधार की राह में तमाम बाधाएं खड़ी की थी। यही वजह है कि इसके 'बिरशोबोका प्रोजेक्ट' पर बुरुंडी के लोगों के साथ सीधे काम करने के साथ ही, सीडीई-ग्रेट लेक्स ने सत्ता के अंदरूनी सूत्रों को समझाने की कोशिश की कि क्यों वहां आर्थिक सुधार जरूरी हैं। उन्हें यह समझाने का प्रयास किया कि आर्थिक सुधारों की उनकी कोशिशों और सरकार की नीतियों का एक ही मकसद है बुरुंडी की मजबूत अर्थव्यवस्था।

'दरअसल, हम बुरुंडी में गरीबी के कारणों को लेकर होने वाली ग़लतफहमी के कारण सरकार के सदस्यों की धमकियों का सामना कर रहे हैं,' सीडीई-ग्रेट लेक्स के संस्थापक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी, एमीएबल मनीराकिज़ा ने यह स्वीकारा।

वास्तव में बुरुंडी में अधिकारी आर्थिकी के आंकड़े सार्वजनिक करने से डरते हैं। कहीं न कहीं उन्हें भय है डेटा का उपयोग वास्तविक रिपोर्ट को हकीकत को तोड़मरोड़ कर पेश करने में इस्तेमाल होगा। या फिर इनका उपयोग देश की छवि को धूमिल करने के लिए किया जाएगा। संयोग से, सीडीई-ग्रेट लेक्स ने उन सार्वजनिक सेवकों की पहचान की, जो सार्वजनिक रूप से आमने-सामने की चर्चा में भाग लेने के लिए तैयार थे। जिन्होंने संगठन के शोध के अनुकूल उत्तर दिया।

सीडीई-ग्रेट लेक्स की टीम ने इन आमने-सामने की बैठकों का लाभ उठाने के लिए दो प्रमुख संदेश तैयार किए। जिसमें अधिकारियों को समझाने का प्रयास किया गया कि व्यवसाय की स्वतंत्रता और व्यापार की कम लागत न केवल नैतिक विकल्प था, बल्कि सरकार के लिए समकालीन जरूरत भी थी।

पहले तर्क ने सांसदों को एहसास कराया गया कि उनके आर्थिक प्रतिबंधों ने देश में विदेशों से आने वाले व्यापारिक निवेश को रोक दिया। सीडीई-ग्रेट लेक्स के शोध और आंकड़ों से पता चला कि आर्थिक विकास पर कठोर नियंत्रण के कारण बुरुंडी में व्यवसायों को अन्यत्र जगह तलाशने या पुनर्स्थापित करने की जरूरत पड़ी। समूह ने एक खुली अर्थव्यवस्था के महत्व को समझाया। जिससे में यह समझ बनी कि अधिक स्वतंत्रता से अधिक व्यावसायिक निवेश को बल मिलता है जिससे अधिक समृद्ध अर्थव्यवस्था का मार्ग प्रशस्त होता है।

सीडीई-ग्रेट लेक्स का दूसरा तर्क पहले तर्क की बुनियाद पर आधारित है कि कम फीस और कम नियंत्रण से जो अनौपचारिक आर्थिक क्षेत्र विकसित होता है उसमें सरकार के लिए कर संग्रह का विस्तार होता है। थिंक टैंक यह दिखाने में सक्षम हुआ कि फीस और बाधाओं को कम करके, बुरुंडियन सरकार वास्तव में कर राजस्व में वृद्धि कर पाएगी।

गठबंधन की जरूरत

ऐसे देशों में जहां दमनकारी शासक सत्ता में बैठे हैं, बेहतर भविष्य के लिए संघर्ष करने का मतलब है अपने जीवन को जोखिम में डालना है। वर्ष 1960 के दशक में बेल्जियम से आज़ादी प्राप्त करने के बाद भी बुरुंडी का अतीत अशांत रहा है। वर्ष 1993 में देश के पहले लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित राष्ट्रपति की हत्या उनके सत्ता में आने के सिर्फ सौ दिनों के बाद ही कर दी गई थी। देश के वर्तमान राष्ट्रपति ने बुरुंडी की दो-अवधि की संवैधानिक सीमा को नज़रअंदाज़ किया और 2015 में तीसरे कार्यकाल का दावा किया। इस उद्दंड कदम ने हिंसक विद्रोह को उकसाया, जिसके दौरान सैकड़ों बुरुंडियन मारे गए। बुरुंडी सरकार बार-बार असंतुष्टों को चुप कराने के लिए हिंसा और भय का सहारा लेती है।

सीडीई-ग्रेट लेक्स नेताओं को एहसास था कि अकेले अपने बूते सुधार की इस लड़ाई को लड़ना आसान नहीं होगा। इसी मकसद से उन्होंने व्यापार प्रतिबंध हटाने के लिए सरकार पर दबाव बनाने वाले समूहों का व्यापक नेटवर्क तैयार करने के लिए कड़ी मेहनत की। उन्होंने जमीन से जुड़े ब्लॉगर्स के साथ ऑनलाइन रिश्तों को बढ़ावा दिया, प्रभावित करने वालों समूहों को विश्वास में लिया और बड़े माइक्रोफोनों वाले समूहों का साथ लिया। यहां तक कि सरकार में शामिल ऐसे लोगों को साथ जोड़ा जो खुलकर उनका समर्थन कर सकें। मनीराकिज़ा और उनकी टीम का विश्वास था कि वे अपने आंदोलन में जितनी अधिक आवाजें शामिल करेंगे उतने ही मजबूत होंगे।

'नि:संदेह एक निरंकुश शासन के सामने बुरुंडी में उत्पीड़न को सीमित करने के प्रयासों के बारे में बड़ा सोचना बहुत जरूरी है,' मनीराकिज़ा ने कहा। 'हम किस्मत वाले थे कि हम अपनी मुहिम के कारणों का समर्थन करने के लिए कुछ सिविल सोसायटी के नेताओं और बुरुंडियन संसद के विपक्षी सदस्यों को साथ जोड़ पाये। विभिन्न समूह बिरशोबोका अभियान को प्रभावी ढंग से चलाने में उपयोगी रहे हैं।'

उम्मीद की किरण जगाना

नि:संदेह जब लोगों ने दशकों की राजनैतिक अस्थिरता व गरीबी को बर्दाश्त किया हो तो ऐसी दुनिया की कल्पना करना मुश्किल है जहां स्वतंत्रता और समृद्धि की बयार बहे। दरअसल, उन्हें बेहतर भविष्य की संभावना के लिए मदद की जरूरत है। उन्हें एक पथप्रदर्शक मशाल की जरूरत थी, जो उन्हें नई राह दिखा सके।

सीडीई-ग्रेट लेक्स को मालूम था कि आशा को संदीप्त किया जा सकता है क्योंकि बुरुंडी के लोगों में कुछ करने और समृद्ध होने की तीव्र इच्छा है। दरअसल, प्रतिकूल माहौल के कारण तमाम बुरुंडियन की उद्यमशीलता की भावना निष्क्रिय हो गई है, क्योंकि उन्हें लगता था कि उनका खुद का व्यवसाय बनाना असंभव था।

बुरुंडियन स्वभाव से उद्यमशील होते हैं - उद्यमशीलता उनके रक्त में प्रवाहित होती है

लंबे समय तक उद्यमिता, नौकरी की कमजोर संभावनाओं के कारण स्वरोजगार का पर्याय बन गई थी। सीडीई-ग्रेट लेक्स इस नए अभिनव अभियान के जरिये उद्यमिता के लिए देश प्रेरक ऊर्जा का काम कर रहा है। बिरशोबोका अभियान का मुख्य लक्ष्य, व्यवसाय शुरू करने की लागत में भारी कमी के अलावा और लोगों को सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक उपकरण प्रदान करना व उस दबी हुई उद्यमशीलता को मुखर कर लक्ष्य को प्राप्त करना था।

'इन प्रयासों से अधिक महत्वपूर्ण वह उम्मीद थी जो हमने उन्हें दी थी।' मनिराकिजा ने कहा, 'हमने अथक परिश्रम किया और हमें विश्वास था कि हम इस व्यवस्था को बदल सकते हैं।'

प्रभाव उत्पन्न करना

सीडीई- ग्रेट लेक के 'बिरशोबोका अभियान' के कारण बुरुंडी में संभावनाएं वास्तविकता में बदल रही है।

समूह के प्रयासों का शुक्रिया जिसके कारण 1,500 से अधिक उद्यमियों को उनके सामने आने वाली विशिष्ट चुनौतियों से मुकाबले के लिए शिक्षित किया जा सका। वाणिज्य मंत्रालय ने स्टार्टअप लागत 140,000 फ्रैंक (करीब 78 यूएस डॉलर) से घटाकर 40,000 फ्रैंक (22 यूएस डॉलर) कर व्यवसायों के पंजीकरण के बोझ को कम किया। इसके साथ ही, बैंकों ने इस प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करके अपने ग्राहकों को बेहतर सेवा देने के तरीके तलाशे हैं और लोगों को फोन पर खाते शुरू करने की इजाज़त दी है, साथ ही उद्यमियों के लिए विशिष्ट खाते निर्धारित किए।

सीडीई-ग्रेट लेक्स के प्रयासों के लिए धन्यवाद, अब उद्यमियों के लिए व्यवसाय शुरूआत करना और अपने समुदायों में सकारात्मक योगदान देना आसान हो गया है।

चर्चा योग्य सवाल

- आपके देश में किसी व्यवसाय को पंजीकृत करने की क्या प्रक्रिया है? क्या प्रक्रिया को सरल बनाने और खासतौर पर कम आय वर्ग लोगों के लिए पंजीकरण अधिक किफायती बनाने के तरीके अपनाये गये हैं?
- आप अपने शोध और सिफारिशों को किस प्रकार प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे कि विभिन्न राजनेताओं को प्रभावित कर सकें? क्या ऐसे व्यावहारिक लाभ हैं जिन पर आप ध्यान केंद्रित कर सकते हैं?
- आप एक छोटे परिचालन बजट का अधिकतम लाभ कैसे उठा सकते हैं? क्या आप उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में रचनात्मक भूमिका निभा पाएंगे या गैर परंपरागत डोनर्स से लाभ ले सकते हैं?

जेल से रिहाई के बाद आर्थिक अवसर

जॉर्जिया सेंटर फॉर ऑपर्च्युनिटी
संयुक्त राज्य अमेरिका

परिचय

संयुक्त राज्य अमेरिका में जॉर्जिया सुधारात्मक पर्यवेक्षण के तहत प्रति व्यक्ति संख्या के अनुपात में सबसे आगे है। हर 13 में से लगभग एक जॉर्जियन वर्तमान में जेल जा चुका है। इस संकट से निपटने के लिए, जॉर्जिया सेंटर फॉर ऑपर्च्युनिटी (जीसीओ) ने अपने कैदी पुनर्वास पहल के माध्यम से जॉर्जिया में सार्वजनिक नीति में बदलाव के लिए निम्नलिखित कदम उठाये हैं :

1. संगठन ने अपने नव विकसित कार्य समूह में शामिल करने के लिए आपराधिक न्याय के विशेषज्ञों को साक्षात्कार के बाद भर्ती किया।
2. एक वर्ष तक वे कार्य समूह के साथ नीतिगत समाधानों को विकसित करने के लिए मिले। ये समाधान गैर राजनीतिक थे और व्यापक जनसमर्थन को आकर्षित करते थे ताकि मौके को अपराधियों के पुनर्वास नीति में बड़े बदलाव के अवसर में बदला जा सके।
3. संस्था के प्रयासों से दो ऐतिहासिक रिपोर्टों को लिखा और वितरित किया गया।
4. लेजिस्लेटर और काउंसिल ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफ़ॉर्म से यह सुनिश्चित करने के लिए संपर्क किया ताकि प्रस्तावित समाधान जल्दी से अमल में लाये जाएं।

टीम के अथक परिश्रम और इस कार्यक्रम की सफलता के कारण, जीसीओ 2017 टेम्पल्टन फ़्रीडम अवार्ड के लिए नामित छह फाइनलिस्ट में से एक था।

जॉर्जिया सेंटर फॉर ऑपर्च्युनिटी यानी जीसीओ अटलांटा, जॉर्जिया में स्थित एक स्वतंत्र और निष्पक्ष थिंक टैंक है। यह संगठन समुदाय-आधारित नीति समाधानों पर शोध और विकास करने के लिए समर्पित है। यह कम आय वर्ग वाले उन लोगों के लिए अवसर उत्पन्न करता है, जो सरकारी कार्यक्रमों की विसंगतियों से मानवीय मूल्य व उम्मीदें खो देते हैं।

जीसीओ की टीम नीति निर्माताओं और लोगों के लिए उन समाधानों को बढ़ावा देती है जो अभिनव सामाजिक उद्यमों को सार्थक परिणाम देने में मदद करती है। जीसीओ जन मानस से जुड़ी नीति को आकार देता है और स्थानीय समुदाय के प्रयासों को प्रोत्साहन देकर जॉर्जिया में अधिक से अधिक लोगों के लिए एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्थिर रोज़गार और एक स्वस्थ पारिवारिक जीवन प्रदान करने का प्रयास करता है। संस्था अपना ध्यान सामाजिक गतिशीलता की बाधाओं को तोड़ने पर केंद्रित करती है ताकि व्यक्ति व समुदाय को समृद्ध होने में मदद मिल सके।

वर्ष 1990 और 2011 के मध्य, जॉर्जिया की जेल में कैदियों की संख्या दोगुनी से अधिक लगभग 56,000 हो गई। इसके साथ ही कैदियों के सुधारों पर राज्य का व्यय सालाना 492 मिलियन डॉलर से एक बिलियन डॉलर से अधिक तक बढ़ गया। इस बड़े निवेश के बावजूद, जॉर्जिया में फिर से अपराध करने की दर (उनकी रिहाई के तीन साल के भीतर ही फिर से जेल में वापस आने वाले व्यक्तियों की संख्या) लगभग एक दशक तक अपरिवर्तित रही।

वर्ष 2009 में, अमेरिकी राज्यों पर प्यू सेंटर ने एक अध्ययन जारी किया जिसमें दिखाया गया था कि जॉर्जिया व्यस्कों के किसी न किसी सुधारक पर्यवेक्षण में शामिल होने की संख्या के मामले में देश में सबसे आगे है। यह संख्या प्रति 13 में से 1 व्यक्ति की है जबकि राष्ट्रीय स्तर पर यह संख्या 31 में 1 है। जब इन व्यक्तियों को रिहा किया जाता है, तो अधिकांश व्यस्क जेल के बाहर सफलता के लिए तैयार नहीं होते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर, जहां पूर्व कैदियों के लगभग 65 प्रतिशत को पुन: गिरफ्तार किया जाता है वहीं जॉर्जिया में, लगभग 30 प्रतिशत तीन साल के भीतर खुद को वापस जेल में पाएंगे।

सामाजिक अध्ययन बताते हैं कि समाज में सामान्य नागरिक जीवन की ओर लौटने वाले नागरिकों को स्थिर रोजगार, सुरक्षित और किफायती आवास और विश्वसनीय परिवहन की आवश्यकता होती है। लेकिन विडंबना यही है कि ये मूलभूत सुविधाएं उन्हें सुरक्षित उपलब्ध कराना सबसे अधिक चुनौती पूर्ण हैं।

रोजगार, आवास और परिवहन काफी हद तक परस्पर जुड़े हुए हैं, क्योंकि एक के बिना दूसरे का उपलब्ध होना कठिन है। उदाहरण के लिए, किसी व्यक्ति के लिए अपेक्षाकृत पास में रहने की जगह के बिना नौकरी कर पाना मुश्किल है; यह संदिग्ध है कि एक व्यक्ति आय के एक नियमित स्रोत के बिना किराए का भुगतान करना जारी रख सकता है; और परिवहन के विश्वसनीय साधनों के बिना काम करना या आवागमन करना चुनौतीपूर्ण है। यही वह कारण है जो पुन: प्रवेश करने वाले लोगों को जेल से बाहर निकलने के लिए डराता है।

फिर भी, यदि इन तीन प्रमुख आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है, तो पूर्व कैदियों को वापस सलाखों के पीछे जाने की संभावना बहुत कम हो जाती है।

इन्हीं चुनौतियों का समाधान करने के लिए वर्ष 2011 में जॉर्जिया जनरल एसेंबली ने आपराधिक न्याय सुधार पर विशेष काउंसिल बनाई। दो वर्ष के उपरांत काउंसिल ने जॉर्जिया की पुन: प्रवेश से जुड़ी सेवाओं की समीक्षा की। काउंसिल ने पाया कि जब प्रयास अच्छी दिशा में चल रहे तो राज्यव्यापी प्रयास बाल्कनीकरण और सफलता के मार्ग कई बाधाओं से बाधित हुए।

इन निष्कर्षों के संदर्भ में परिषद ने जॉर्जिया में कैदियों की पुन: जेल में वापसी रोकने के लिए एक कार्यक्रम विकसित किया, जिसने जॉर्जिया में कैदियों की पुनरावृत्ति में कमी लाने के लिए एक पांच साल के प्रयास की नींव रखी, जिसने जॉर्जिया को कैदियों की वापसी रोकने के प्रयासों में अग्रणी बनाया।

प्रोजेक्ट का कथा सार

जॉर्जिया में उच्च अपराध पुनरावृत्ति दर की कीमत राज्य के समुदायों और परिवारों, सार्वजनिक सुरक्षा और करदाताओं को महंगी पड़ती है। यह जानने के बाद कि राज्य इस क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है, जीसीओ ने सार्वजनिक सुरक्षा को बढ़ाने और कैदियों को समाज में फिर से बसाने में मदद करके इस ओर होने वाले खर्च पर नियंत्रण को प्राथमिकता दी।

जॉर्जिया के सुप्रीम कोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश के साथ एक बातचीत के बाद, टीम ने जेल वार्डन, कैदियों, पारगमन केंद्र के नेताओं और जॉर्जिया के सुधार विभाग के लिए राज्य क्षमादान बोर्ड और पैरोल और पुन: प्रवेश सेवा डिविजन के प्रमुखों से संवाद करना शुरू किया।

जुलाई, 2013 में, कई माह के शोध के उपरांत लगभग चार दर्जन साक्षात्कार और राज्य की चार जेलों में सुविधाओं का अवलोकन करने हेतु दौरा करने के लिए, संगठन ने अपना प्रिजनर रिएंट्री वर्किंग ग्रुप लॉन्च किया। इस समूह का निर्माण करते समय प्राथमिकता जॉर्जिया की सुधारात्मक प्रणाली में विशेषज्ञता के साथ लोगों को साथ जोड़ने की रही थी। साथ ही समुदाय में लौटने वाले कैदियों के लिए परिणामों में सुधार के लिए एक गंभीर पहल थी। राजनीतिक संबद्धता की परवाह किए बिना नौ कार्य समूहों के लिये सदस्यों का चयन किया गया; हालाँकि, समूह का अधिकांश हिस्सा वामपंथियों और सेंटरिस्टों से युक्त रहा।

प्रिजनर रिएंट्री के अनुभवों को सुधारने के लिए नीति और सेवा-संबंधी समाधान विकसित करने, फिर से अपराध की ओर उन्मुख होने के मामलों को कम करने और कैदियों के लिए सकारात्मक परिस्थितियों में सुधार करने जैसे कि नौकरी प्राप्ति और अवधारण, आवास स्थिरता, विनम्र और नशा मुक्त रहना और ऋण दायित्वों को पूरा करना आदि विकसित करने के कार्य के दौरान ग्रुप के सदस्यों ने अटलांटा में जीसीओ के कार्यालय में साल में एक बार मिलने के लिए सहमति व्यक्त की। कार्य समूह तब लेजिस्लेटर, राज्यपाल और राज्य के आपराधिक न्याय सुधार परिषद के लिए अपनी सिफ़ारिशें प्रस्तुत करेगा।

ग्रुप की पहली बैठक के दौरान, सदस्यों ने नीतिगत समाधानों के लिए कई व्यापक क्षेत्रों पर तेजी से निर्णय लिया। उन क्षेत्रों में शामिल हैं :-

- रोज़गार : रोज़गार के क्षेत्र में प्रवेश संबंधित बाधाओं को दूर करना और कैदियों की रिहाई बाद रोज़गार और करने प्राप्त करने और उसमें बने रहने के अवसरों में वृद्धि करना।
- रिएंट्री कोर्ट : ऐसे कोर्ट का निर्माण करना, जो कैदियों के साथ काम करने में माहिर हों क्योंकि वे समुदाय में पुन: प्रवेश कर रहे हैं।
- ट्रैन्सिशनल सेंटर : अधिक लोगों की सेवा करने के लिए जॉर्जिया के ट्रैन्सिशनल केंद्रों की क्षमता बढ़ाना और यह पता लगाना कि विशिष्ट केंद्र जो कानून तोड़ने वालों साथ काम करने के लिए बनाये गये हैं, वे इनकी पुन: अपराधों की ओर उन्मुख होने की प्रवृत्ति को किस हद तक रोक सकते हैं।

हालांकि, इन शीर्षकों का दायरा विस्तृत है, मगर वर्किंग ग्रुप ने विशिष्ट और सामान्य समझ के समाधानों के जरिये बड़ी क्षमताओं के साथ अपेक्षित बदलाव लाने का प्रयास किया है।

कार्य समूह के मार्ग निर्देशन के साथ, जीसीओ ने दो रिपोर्टें लिखीं : 'इनक्रिज़िंग एम्पलॉयमेंट ऑपरच्युनिटीज़ फॉर एक्स-ऑफेंडर्स', जो दिसंबर, 2013 में प्रकाशित हुई और 'ए हाई प्राइस टू पे', जो दिसंबर, 2014 में जारी की गई। इन रिपोर्टों ने कार्यबल में सुधार के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। जिसमें अपराध की दुनिया से बाहर आये लोगों के पुनर्वास के साथ साथ उन्हें फिर से अपराध की दुनिया में लौटने से रोकने के प्रयासों में ऋण की भूमिका कम करने पर विचार किया गया। प्रत्येक रिपोर्ट में नीति समाधान को नीति निर्माताओं, मीडिया और आम जनता के लिए प्रचारित किया गया और वर्ष 2014 में जॉर्जिया काउंसिल ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफ़ॉर्म को प्रस्तुत किया गया।

दरअसल,जीसीओ का प्रिज़नर्स रिएंट्री इनिशिएटिव पूर्व अपराधियों के अपने परिवार और समुदाय के साथ पुनर्वास और बहाली पर केंद्रित है। हाल ही में रिहा हुए व्यक्तियों के रोज़गार पाने और अपने प्रियजनों के साथ फिर से जुड़ने में मदद करने के उद्देश्य वाले इस

कार्यक्रम को राज्य की न्याय प्रणाली को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने का श्रेय दिया गया है।

वर्किंग ग्रुप की सिफारिशें, जिन्हें दो रिपोर्टों में संकलित किया गया था और जॉर्जिया काउंसिल ऑन क्रिमिनल जस्टिस रिफ़ॉर्म के लिए प्रस्तुत किया गया था, उन्हें गवर्नर को भेजी जाने वाली काउंसिल की अंतिम रिपोर्ट में शामिल किया गया। पिछले कई वर्षों में, लगभग सभी सिफारिशों को कानून के रूप में पारित किया गया और नीतिगत परिवर्तन लागू किए गए। इन विधायी और नीतिगत परिवर्तनों में शामिल हैं :-

'इनक्रिज़िंग एम्पलॉयमेंट ऑपर्च्युनिटीज़ फॉर एक्स-ऑफेंडर्स' रिपोर्ट के सुझाव जो कार्यान्वित हुए:-

- एसबी 365 को अप्रैल, 2014 में पारित किया गया: यह बताता है कि नशे के कारोबार से जुड़े रहे अपराधियों के ड्राइविंग लाइसेंस को स्वत: रूप से निलंबित करना तार्किक नहीं है जब तक कि वे एक गैर-ड्राइविंग-संबंधित अपराध करते हैं। साथ ही साथ एक आपराधिक रिकॉर्ड वाले व्यक्ति को काम पर रखने पर नियोक्ताओं की जवाबदेही तय करने के प्रति सुरक्षा प्रदान करता है।
- बॉक्स पर प्रतिबंध लगा फरवरी 2015 में : जॉर्जिया के गवर्नर नाथन डील द्वारा जारी एक कार्यकारी आदेश के माध्यम से आधिकारिक तौर पर 'बॉक्स पर प्रतिबंध लगाने' वाला दक्षिण में पहला राज्य बन गया। इस प्रयास ने राज्य में रोजगार के लिए आवेदनों पर स्थित चेक बॉक्स को हटा दिया, जो आवेदक को किसी भी आपराधिक रिकॉर्ड को उल्लेख करने के लिए बाध्य करता है।
- एचबी 328 पारित 2015 में : उन अपराधियों को पेशेवर लाइसेंस प्राप्त करने के लिए अनुमति देता है, जिन्होंने ड्रग कोर्ट कार्यक्रम पूरा कर लिया है।

रिपोर्ट 'ए हाई प्राइस टू पे' के सुझाव जो क्रायान्वित हुए :

- चाइल्ड सपोर्ट सर्विस, अदालतों के वरिष्ठ न्यायाधीश, परिवीक्षा और पैरोल के जरिये अब संदेश दिया जाता है कि कैसे आपराधिक न्याय प्रणाली में शामिल लोगों के द्वारा बच्चों के पालन पोषण के लिए आर्थिक सहयोग के कार्य को बेहतर ढंग से सुनिश्चित कराया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उन्हें नौकरी खोजने में मदद करनी है, ताकि वे अब समाज में बेहतर योगदान दे सकें।
- 2016 में एसबी 367 पारित : हाल ही में रिहा व्यक्तियों के लिए व्यावसायिक लाइसेंस के माध्यम से रोजगार हासिल करने की प्रक्रिया को आसान बनाया गया है। इसमें नशे से संबंधित अपराधों के उन दोषी व्यक्तियों को जो मोटर वाहन से जुड़े अपराधों में शामिल नहीं थे ड्राइविंग लाइसेंस फिर से जारी करना, पैतृक जवाबदेही न्यायालयों के लिए वित्त की उपलब्धता में वृद्धि कराना (नीचे अधिक जानकारी देखें), जो कैद की

अवधि को कम करते हैं और माता-पिता को अपने बच्चों का समर्थन करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। साथ ही नियोक्ताओं के लिए संरक्षण हेतु जवाबदेही को बढ़ाते हैं।

- मार्च, 2015 : चाइल्ड सपोर्ट सर्विसेज के डिवीजन ने अपनी नीति में संशोधन किया ताकि निलंबित ड्राइविंग लाइसेंस को फिर से जारी किया जा सके। ताकि बच्चों की सपोर्ट करने वालों की मदद करके उनके काम करने में आने वाली बाधाओं को दूर किया जा सके।

पैतृक जवाबदेही न्यायलयों का विस्तार

- जीसीओ के तत्वावधान में किए गए शोध के आधार पर, जॉर्जिया ने राज्य सिस्टम द्वारा संचालित पैतृक जवाबदेही न्यायालयों की प्रणाली का विस्तार करते हुए इनकी संख्या को 10 से 30 तक किया। जिनमें 19 और जल्द ही शामिल होने वाले हैं। नि:संदेह यह सुधार दीर्घकाल तक लोगों को काम करने में मदद का रास्ता तय करेगा, अन्यथा वे न्याय प्रणाली की जटिलता में फंस जाएंगे, दूसरी ओर ज्यादा से ज्यादा माता-पिताओं को अपने बच्चों के जीवन का हिस्सा बनने में भी मदद मिलेगी।

जीसीओ द्वारा सुझाए गए सुधार, जो अब राज्य के कानून और प्रशासनिक नीति का हिस्सा हैं, हज़ारों जॉर्जियाई लोगों को वर्ष पर्यंत मदद करेंगे। जो समाज में बदलाव के नजरिये से समुदाय में उनके पुन: प्रवेश के जरिये उन्हें आत्मनिर्भर बनाने में सहायक होंगे, जिसके मायने हैं कि परिवार में फिर जुड़ाव, कम अपराध और करदाताओं के कम डॉलर जेलों पर खर्च होंगे।

नि:संदेह जीसीओ द्वारा किए गए सुधार सकारात्मक रुझान ला रहे हैं। दरअसल, वर्ष 2012 के बाद से जॉर्जिया की जेलों में कैदियों की संख्या में 6 प्रतिशत की गिरावट आई है, जिससे करदाताओं के 264 मिलियन डॉलर की बचत संभव हुई और जेलों में अपराधियों के लौटने की संख्या में 11 प्रतिशत की गिरावट आई।

एटलस नेटवर्क के सीईओ ब्रैड लिप्स ने आपराधिक न्याय सुधार के लिए जीसीओ के अनूठे दृष्टिकोण की प्रशंसा की। लिप्स ने कहा, 'जीसीओ के कैदी रिएंट्री इनिशिएटिव कार्यक्रम निष्कर्ष देता है कि कैद से रिहा लोगों और उनके परिवारों के प्रति दया भाव को करदाताओं और सार्वजनिक सुरक्षा के हितों के साथ जोड़ा जा सकता है।' उन्होंने कहा 'यह एक अभिनव पहल है जो अनुकरण के योग्य है।'

इसके साथ ही जीसीओ की पहल 'हायरिंग वेल, डूइंग गुड' और 'जॉर्जिया वर्क्स' दो अन्य आयोजन हैं, जो जीसीओ के 'प्रिज़नर्स रेंट्री प्रोजेक्ट' की सफलता से अलग हैं।

जीसीओ के 'हायरिंग वेल, डूइंग गुड' आयोजन का उद्देश्य विभिन्न व्यवसायों और बेरोजगारों को अवसर देने वालों के बीच नई साझेदारी विकसित करना है, जिससे अधिक लोगों को काम करने का अवसर मिले।

यह आयोजन बिजनेस लीडर्स को भी उन लोगों के लिए रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए प्रेरित करता है, जो अपने जोड़ीदारों से सीखने और समस्या की सीमा को जानने का प्रयास कर रहे हैं। इन आयोजनों में कानूनी और देनदारी की समझ, एक आबादी विशेष को रोजगार दिये जाने पर कर में छूट की उपलब्धता, गैरलाभकारी संस्थाओं के साथ व्यवसायिक सहयोग और अन्य व्यवसायों के अनुभव आदि जैसे विषय शामिल हैं।

इन कार्यक्रमों में अटलांटा फाल्कन्स, उबर, जॉर्जिया-पेसिफिक, आर्थर एम ब्लैंक फाउंडेशन, गुडविल इंडस्ट्रीज और सीकेएस. पैकेजिंग का समर्थन हासिल किया गया। जीसीओ के 'हायरिंग वेल, डूइंग गुड इवेंट' कार्यक्रम में 125 से अधिक समुदायिक नेताओं ने भाग लिया । इसके साथ ही मोटे तौर पर 30 व्यवसायों ने समयानुक्रम में बेरोजगारों को काम देने के उद्देश्य से हस्ताक्षर किए।

जॉर्जिया वर्क्स! का उद्देश्य! लागत की दृष्टि से प्रभावी, व्यापक कार्यक्रम विकसित करना और उसे कार्यान्वित करना है। जो बेघर, नशे की लत के आदी लोगों और आपराधिक पुनरावृत्ति की श्रृंखला को तोड़ने के लिए काम करने वाले लोगों की जरूरतों को पूरा करता है

इस कार्यक्रम में के दौरान प्रतिभागियों को एक वर्ष के लिए अपने साथ रखा जाता है। इस दौरान वे न्यूनतम 7.4 डॉलर प्रति घंटे के हिसाब से कमाई भी कर सकते है और सप्ताह में 30 या उससे अधिक घंटे काम कर सकते हैं। वास्तव में यह कार्यक्रम को उन बाधाओं को दूर करने के लिए तैयार किया गया है जो नशे के दुश्चक्र से मुक्ति के प्रयास के दौरान बेरोजगार हैं। यह उन्हें व्यक्तिगत सहायता और जीवन निर्वहन के साधन और जीईडी कक्षाएं उपलब्ध कराता है।

सही मायनों में जॉर्जिया वर्क्स! कार्यक्रम में भाग लेने वालों की एक सामान्य जीवन की जरूरत को पूरा करने वाले उपायों मसलन ड्राइविंग लाइसेंस बनाने और बैंक खाता खोलने में सहायता करता है।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

गठबंधन का नजरिया

जीसीओ के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी रैंडी हिक्स इस परियोजना की सफलता का मुख्य श्रेय उन रणनीतिक साझेदारों को देते हैं, जिन्होंने परियोजना को पूरे राज्य में विकसित किया। न्यूयॉर्क सिटी में एटलस नेटवर्क के लिबर्टी फ़ोरम और फ़्रीडम डिनर में उन्होंने कहा, 'इन साझेदारियों का कई गुना व्यापक प्रभाव पड़ा क्योंकि उन्होंने हमें वास्तविक स्थिति के मुकाबले बहुत बड़ा दिखाने का प्रयास किया। सही मायनों में हमारे साथ एक प्रभावशाली गठबंधन था जिसने सुनिश्चित किया कि रोज़गार सृजन के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए सभी सिफारिशों का अनुपालन हो। वे उत्साही थे और इसके लिए काम करने को तत्पर थे।'

- लघु संस्थानों और कम बजट वाली परियोजनाओं को अपने नीतिगत समाधानों को विस्तारित करने के लिए सही भागीदारी खोजना बेहद आवश्यक है।

हितधारकों की विविधता

जीसीओ जॉर्जिया में वर्किंग ग्रुप को विकसित करके पुन: अपराध की ओर लौटने की प्रवृत्ति को विविध हितधारकों की मदद से रोकने में सक्षम था। यह मॉडल वास्तविक सुधार के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए शोध, नीति और क्रियान्वयन को कारगर बनाने के लिए प्रभावी रणनीति प्रदान करने में सक्षम था। हिक्स ने कहा, 'जैसा कि हमने राज्य के सहयोग से अभियान चलाया था (कार्यदल के सदस्यों को खोजने के लिए), हम उन लोगों की तलाश कर रहे थे जो इस बारे में ज्यादा जानते थे। हमें वैचारिक रूप से गठबंधन करने की आवश्यकता नहीं है। हमें बस यह जानने की आवश्यकता थी कि कुल मिलाकर वे क्या जानते हैं, इसलिए हमने उन्हें तलाशने ,उनकी चिंताओं और अनुभवों को सुनने के लिए समय लिया। इस तरह से हमें स्पष्ट समझ थी कि राज्य में जब कैदियों की पुन: अपराध की ओर उन्मुख होने की बात हो रही थी, तब उसके मूल में क्या था। '

- यूं तो वर्किंग ग्रुप के कई सदस्य संगठन के कतिपय नीतिगत मुद्दों पर जीसीओ से असहमत थे, इसके बावजूद वे अभी भी जेल के कैदियों की बड़ी संख्या और उनके पुन: अपराध की दुनिया में प्रवेश करने की समस्या के लिए बाजारीय समाधान तलाशने के लिए एक साथ काम करने को तैयार थे।
- वर्किंग ग्रुप के सदस्य अपने प्रभावी नेतृत्व के साथ उत्साही कार्यकर्ता के रूप में नीतिगत समाधानों की वकालत करने और बचाव के लिए तत्पर थे।

निर्धारित खाके से बाहर सोचना

निष्पक्ष थिंक टैंक के रूप में, जीसीओ ने कार्यदल के सदस्यों को जॉर्जिया के रिहा कैदियों की अपराधों की दुनिया में लौटने को कम करने के संभाव उपायों पर विचार के लिए बेबाकी से सोचने के लिए प्रोत्साहित किया। सरकारी आयोगों और अन्य समान निकायों के विपरीत, जीसीओ जैसे स्वतंत्र थिंक टैंक को सर्वोत्तम विचारों के लिए अधिक स्वतंत्रता दी जाती है ताकि वे पारंपरिक ज्ञान या वर्तमान राजनीतिक व्यवहार्यता से आवरण हटा सकें।

इसका परिणाम यह हुआ कि संगठन को खुले ढंग से सोचने की अनुमति देने से उन नीतिगत समाधानों को तलाशने का अवसर मिला, जिनके बारे में अब तक नहीं सोचा गया था या फिर अन्य संगठन जिसे निष्प्रभावी मानते रहे थें।

दृष्टिकोणों में संतुलन का प्रयास

कार्यदल के एक सदस्य ने परियोजना की शुरूआत में एक ऐसी नीति की वकालत की, जिसमें विभिन्न अपराधों के तहत गिरफ्तार किए गए आरोपितों की संख्या की एक सीमा तय करने या नस्लीय आधार पर कोटा तय करने की बात कही गई था। मगर समूह में राय बनी कि ऐसा करना राजनीतिक रूप से असंभव दृष्टिकोण है। इसके चलते नीति में बदलाव नहीं होगा।

जीसीओ द्वारा कैदियों के अपराध में पुन:प्रवेश की समस्या पर कार्य करने वाले समूह को विकसित करते समय यह जरूरी था कि समूह के लक्ष्यों को अग्रिम रूप से संप्रेषित किया जाये। यह जानते हुए कि इस नये विचार की नीति की सिफारिश को व्यवहार में लाना मुश्किल होगा, साथ ही इस तरह समूह को अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद नहीं मिलेगी, यह विचार आगे टाल दिया गया।

- जीसीओ ने वर्किंग ग्रुप की मासिक बैठकों के दौरान यह तय किया कि समूह वर्ग विशेष में प्रचलित शब्दों और कैदियों के फिर से अपराध की दुनिया में प्रवेश से जुड़े उलझावदार मुद्दों से दूर रहें। केवल इस बात पर ध्यान केंद्रित किया कि राज्य में बदलाव लाने के लिए क्या किया जाना चाहिए।

राजनीतिक दुविधा

जीसीओ को लेजिस्लेटिव प्रतिनिधियों और गवर्नर से प्रतिगामी संकेत मिले, जो वर्किंग ग्रुप के कुछ सुधारात्मक विचारों को स्वीकार नहीं करना चाहते थे। दरअसल, जॉर्जिया रोजकोषिय घाटे की स्थिति में चल रहा था और सज़ायाफ्ता लोगों को राज्यपोषित रोजगार देने से राज्य पर आर्थिक दबाव पड़ना लाजिमी था। इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए के

जीसीओ ने रणनीतिक साझेदारी की आवश्यकता महसूस की। इसके लिए आपराधिक न्याय सुधार पर राज्य के शीर्ष विशेषज्ञों से अपने कार्य समूह के निर्माण में मदद ली गई। इस तरह संपूर्ण नीतिगत समाधानों पर प्रभाव न्यूनतम था।

इस मुद्दे पर वर्ष 2013 में एक कार्यकारी समूह बनाने के बाद, जीसीओ ने विशेषज्ञों के दृष्टिकोणों को समाहित करते हुए दो ऐतिहासिक रिपोर्ट तैयार किया। इसके आगामी वर्षों में, संगठन की लगभग सभी सिफारिशों को कानूनी अमलीजामा पहनाया गया, जिससे समाज में पूर्व कैदियों के लिए बेहतर अवसरों को व्यापक बनाने में सहायता मिली।

चर्चा योग्य प्रश्न

- अपने देश में नीतिगत प्राथमिकताओं के विषय में मंथन कीजिए। सुधारात्मक प्रयास किस अन्याय को दूर करने में सहायक होंगे? इससे किस वर्ग को लाभ होगा?
- आप अपने मुख्य लक्ष्यों को लेकर आंतरिक रूप से कितने स्पष्ट हैं? क्या आप परिवर्तन के बारे में बड़ा सोचते हैं? अगले 12-18 महीनों में आप कौन से मील के पत्थर प्रगति की राह में स्थापित कर पायेंगे?
- आप दूसरों के साथ बदलाव के लिए काम करने के लिए सहभागिता कैसे बना सकते हैं?

समावेशी समृद्धि हासिल करना

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी
भारत

परिचय

भारत बदलाव के दौर से गुजर रहा देश है। वैश्विक स्तर पर इसने लंबी छलांग लगायी है और वर्ष 1991 में आर्थिक उदारीकरण के बाद इसकी जीडीपी वर्ष 2000 के बाद से तीन गुना हो गई है। वर्ष 2001 में, इसे ब्रिक्स समूह देशों (ब्राजील, रूस, भारत, चीन, दक्षिण अफ्रीका) की अर्थव्यवस्थाओं में से एक के रूप में प्रतिष्ठित किया गया, जो इसके बढ़ते आर्थिक विकास का प्रतीक है। ब्राजील, रूस, चीन और दक्षिण अफ्रीका सहित अपने ब्रिक्स साथियों के बीच प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पाद में सबसे ऊपर आने के दौरान- आईएमएफ़ का अनुमान है अगले कुछ वर्षों में इन सभी देशों की तुलना में भारत की जीडीपी 7 से 8 प्रतिशत की तेज दर से बढ़ेगी ।

जैसा कि देश एक शीर्ष स्तरीय अर्थव्यवस्था के रूप में बने रहने के लक्ष्य के प्रति प्रतिबद्ध है, वहीं बड़ी आबादी वाले इस देश में नागरिक संगठन कई तरह के कष्टों का सामना कर रहे हैं। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के रूप में उल्लेखित किये जाने वाले भारत के 1.3 बिलियन लोगों में से 800 मिलियन से अधिक लोग वोट करने के योग्य हैं और 2014 के आम चुनावों में उन्होंने 65 प्रतिशत से अधिक मतदान के साथ भागीदारी किया। यद्यपि मतदान का अधिकार स्वत: ही प्रतिनिधि सरकार या व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण गारंटी नहीं देता है। वास्तव में, देश में कई ऐसे सामाजिक मुद्दे उभरे हैं जो इस विविधताओं वाले देश के लक्ष्यों को हासिल करने की राह में चुनौती हैं।

एक कालखंड में उलझाव के चलते भारत अपने एक औपनिवेशिक अतीत से धीमी गति से मुक्त होती जाति व्यवस्था और एक समाजवादी ढांचे के अवशेषों के साथ संघर्ष करता है, जिसमें नौकरशाही की दखल वाली प्रणाली को 'लाइसेंस राज' कहा जाता है। अत्यधिक गरीबी, अशिक्षा और अन्य सामाजिक बुराइयों व बीमारियों से लाखों लोग मरते हैं, जिन्हें अक्सर आदिम कायदे-कानूनों द्वारा संरक्षित किया जाता है जो नीचे से शीर्ष की ओर होने

वाली प्रगति की राह को अवरुद्ध करते हैं। देश विविधतापूर्ण लोगों और उन्नतिशील विचारों के साथ काम कर रहा है, लेकिन भारत ने जो विकास की गति हासिल की है, उसे कायम रखने के लिए, उसे रचनात्मक सुधार की आवश्यकता है, जो देश को आगे बढ़ाने में सहायक हो।

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी, भारत के अग्रणी और विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त थिंक टैंक है, जिसका उद्देश्य सार्वजनिक नीति के जरिये सामाजिक परिवर्तन को बढ़ावा देना है, और जो अक्सर सामाजिक पायदान के सबसे निचले स्तर पर परिवर्तन को लक्षित करता है।

वर्ष 2017 में अपनी 20वीं वर्षगांठ का उत्सव मनाते सेंटर फॉर सिविल सोसायटी को नियमित रूप से दुनिया के सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक नीति अनुसंधान संगठनों में, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के थिंक टैंक और सिविल सोसायटी प्रोग्राम द्वारा स्थान दिया जाता है। सीसीएस अपने उद्देश्य के रूप में शिक्षा, आजीविका, व्यावसायिक माहौल और नीति प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित करते हुए विचारों को हकीकत में बदलने को कृतसंकल्प है। केंद्र के संस्थापक और अध्यक्ष पार्थ शाह संस्था के लक्ष्य को स्पष्ट करते हैं कि सीसीएस 'एक थिंक टैंक से अधिक है; यह एक काम करने वाला 'टैंक' है।'

अर्थशास्त्र में संयुक्त राज्य अमेरिका से डॉक्टरेट की उपाधि पाकर शाह ने पहली बार इस धारणा का अहसास किया कि स्वतंत्रता से परिपूर्ण समाज ही व्यक्तिगत उन्नति के साथ-साथ आर्थिक और सामाजिक प्रगति कर सकता है। इसी विचार ने उन्हें 1990 के दशक में कई थिंक टैंकों के साथ जोड़ा। मिशिगन विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर के रूप में अपने शैक्षणिक जीवन की शुरुआत करने के लंबे समय बाद तक, उन्होंने सामाजिक समस्याओं को दूर करने में अधिक सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रयास करना शुरू किया। वह अपने मूल देश भारत लौट आए और उन्होंने सीसीएस की स्थापना की, जहां वे तथ्य आधारित शोध पर अपना ध्यान केंद्रित करना जारी रखे हुए हैं।

नीतिगत प्रभाव के माध्यम से समाज में बदलाव लाने के लिए सेंटर फॉर सिविल सोसायटी प्रतिबद्ध है। संस्था का मानना है कि किसी मुद्दे पर सीधी कार्रवाई केवल लक्षणों को संबोधित करती है, जबकि नीतिगत परिवर्तन पर ध्यान केंद्रित करना सामाजिक मुद्दों के मूल को लक्षित करता है। संस्था की यह सोच पूर्णत: प्रशिक्षित पेशेवरों की टीम के साथ परिलक्षित होती है जो शाह के साथ मिलकर उससे हकीक़त बनाने में जुटी हुई है।

सीसीएस की रिसर्चर और डेवलपमेंट मैनेजर भक्ति पाटिल कहती हैं कि संस्था के लगभग 35 कर्मचारी सदस्य तीन श्रेणियों में वर्गीकृत हैं : जिसमें रिसर्च, एडवोकेसी (इसमें मीडिया, नीति निर्धारक और हिंदी भाषा की पहल शामिल हैं) और सीसीएस एकेडमी (जो राजनीतिक प्रक्रिया में विशेषीकृत प्रशिक्षण के साथ छात्रों, मीडिया और नीति निर्माताओं

को लक्षित करती है। और साथ ही नैतिक और डेटा-संचालित नीति समाधानों की आवश्यकता को प्राथमिकता देती है)।

इसके बावजूद यह सुनिश्चत नहीं है कि अच्छी तरह से प्रशिक्षित टीम के सदस्य, सुव्यवस्थित संचालन रणनीति और अभ्यास सफलता तय कर दे। भक्ति पाटिल बताती हैं कि समाज में एक स्थापित पूर्वाग्रह है कि 'बाज़ार अमीरों के लिए हैं और गरीबों को पीछे छोड़ते देते हैं।' इसी वजह से दिल-दिमाग को बदलने के लिए, सीसीएस ने संपर्कों का एक गहन बुनियादी ढांचा विकसित किया है और उन्हें लगातार गुणवत्तापूर्ण शोध निष्कर्ष प्रदान करता है। दरअसल, समय के साथ, इस दृष्टिकोण ने विश्वसनीयता हासिल की है, साथ ही नीति को प्रभावित करने के लिए महत्वपूर्ण अवसर भी प्रदान करता है।

शाह कहते हैं, पहुंच केवल बाधा का हिस्सा है, क्योंकि जब राजनीतिक इच्छा शक्ति बाजार आधारित सुधारों की ओर झुकने लगते हैं तो 'सरकार (क्रोनीइज्म) पक्षपातपूर्ण नीतियों, नियमन और सब्सिडी के उपयोग को वरियता देने लगती है।' यह सीसीएस के काम के लिए नई चुनौतियों पैदा करता है, लेकिन टीम इन कारकों को संबोधित करने से पीछे नहीं हटती।

सीसीएस टीम सामाजिक सीढ़ी के सबसे निचले पायदान (पिरामिड) को प्रभावित करने वाले सुधारों पर ध्यान केंद्रित करती है। यह बाज़ारों के प्रति सामाजिक पूर्वाग्रह को कम करता है, जबकि गरीबों के जीवन में अप्रत्याशित सुधार करने के लिए अपनी ताकत का प्रयोग करता है, जो देश के विकास में सहायक होता है।

प्रोजेक्ट का विवरण

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी ने कई वर्षों तक एटलस नेटवर्क के विभिन्न प्रशिक्षणों और कार्यक्रमों में भाग लिया है। शाह का मानना है कि इससे संगठन के विकास में मदद मिली है। लेवरेजिंग इंडायसेस फॉर फ्री एंटरप्राइज (लाइफ) प्रोग्राम के के साथ सीसीएस नेतृत्व ने अपने कार्यक्रम पोर्टफोलियो को और विस्तारित करने के अवसर के रूप में देखा। वास्तव में, कई मायनों में यह कार्यक्रम भारत में सीसीएस के सामने आने वाले परिवेश के अनुकूल था।

शाह ने अनुभव किया कि लाइफ के लॉन्च का समय आदर्श था, क्योंकि वर्ष 2014 में जो सरकार चुनी गई थी, वह अभी वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की शानदार रैंकिंग के बारे में बात करना शुरू कर रही थी। इस बदले हुए राजनैतिक माहौल ने सीसीएस को अपने विचारों और उससे प्रभाव पैदा करने का लाभ उठाने का जबरदस्त अवसर प्रदान किया।

सेंटर फॉर सिविल सोसायटी ने एक स्थापित संस्थान के रूप में सार्वजनिक नीति का काम करने के लिए प्रक्रियाओं का विकास किया ताकि राजनीतिक और सांस्कृतिक संदर्भ को इसके परिवेश में सिरे चढ़ाया जा सके । हालांकि 'लाइफ' की कार्यनीति को अंतिम रूप देते समय, टीम को अपनी कुछ रणनीतियों को संशोधित करना पड़ा। उदाहरण के लिए सीसीएस ने अक्सर व्यापार सुधार की पहल पर काम किया है, लेकिन इस तरह के प्रयास छोटे-छोटे भागों में रहे, क्योंकि वे आम तौर पर इससे बाहर अपने मुख्य क्षेत्रों शिक्षा और आजीविका पर केंद्रित रहे हैं। 'लाइफ ने एक छाते के नीचे इस काम को एकीकृत किया।' पाटिल ने कहा, 'इससे हमें अपनी रणनीति में सुधार करने में मदद मिली।'

हालांकि, 'लाइफ', सीसीएस के लिए अपने काम पर विचार करने का अभिनव तरीका था, लेकिन इसके कार्यों को स्थापित प्रक्रियाओं द्वारा निर्देशित किया गया था। सर्वप्रथम, इसमें उन प्रमुख समस्याओं को खोजने पर ध्यान केंद्रित किया गया जो बदलाव के लिए तैयार थीं। दूसरा, टीम ने यह पहचान की कि कौन से कारक उन मुद्दों को प्रभावित करते हैं और उन नियमों के आधार पर सुधार का मसौदा तैयार करने के लिए प्रमुख कर्मचारियों को मार्गदर्शन प्रदान किया। तीसरा, इसने लक्षित कार्यक्षेत्रों में शोध और विश्लेषण का ढांचा तैयार किया। अंतिम और चौथा, संचार समूह ने शोध के आसपास पक्ष समर्थन योजना का निर्माण किया।

योजना को विस्तार देते हुए, शोध दल ने उन क्षेत्रों की तलाश की, जहां भारत विशिष्ट परियोजनाओं के लक्ष्यों को हासिल करने में पिछड़ा था। तब उन्होंने अपनी आंतरिक क्षमताओं के आकलन के साथ उन क्षेत्रों को क्रॉस-रेफ़र (अन्योन्य संदर्भ) किया, साथ ही पहचाना की ये योग्यताएं किस में है, जो विषय का बेहतर ढंग से निस्तारण कर सके। वे खासकर इस बात का आकलन करते थे कि उनके संगठन में किस व्यक्ति ने संबंधित नीति क्षेत्रों में काम किया था। मायने यह कि जिनके पास कौशल था और जो एकाग्रता के साथ नए क्षेत्रों में स्थानांतरित हो सकते थे। बेहतर परिणामों के लिए केंद्रित क्षेत्रों में विभिन्न उपकेंद्र शामिल थे, जो व्यवसाय शुरू करने की आवश्यकताओं की बड़ी श्रेणियों और अनुबंधों को लागू करने के समय पर आधारित थे ।

टीम ने विशिष्ट विषयों पर 14 शोध पत्र तैयार किये। इसमें अनुबंध प्रवर्तन सुनिश्चित कराने के लिए आठ बिंदुओं वाली एक कार्ययोजना तैयार करने से लेकर जिन लोगों के चेक बाउंस होते हैं उन्हें दंडित करने के बाबत एक अंतर्राष्ट्रीय विश्लेषण भी शामिल था। सभी केंद्र और राज्य सरकारों को लक्षित करने के लिए बहु-आयामी पक्ष समर्थन की योजना के साथ कागजात भेजे गए थे। 'हमने मीडिया को भी गहरे तक जोड़ा है', पाटिल ने कहा 'सामग्री को उनके नीतिगत प्रशिक्षण में भी अनिवार्य रूप से एकीकृत किया गया था।'

व्यवसाय की शुरुआत (डूइंग बिजनेस, वर्ल्ड बैंक)

- प्रक्रियाओं की संख्या को दिल्ली में 11 से घटाकर 9 और मुंबई में 13 से 10 कर दें।
- व्यवसाय शुरु करने में लगने वाले दिनों की संख्या को 27 से घटाकर 22 (दिल्ली) और 30 से 25 (मुंबई) तक करें।
- भुगतान की गई न्यूनतम पूंजी आवश्यकता को निरस्त करने के माध्यम से शून्य करना। 2015 तक, आवश्यकता 111.2 प्रतिशत की थी।

अनुबंध प्रवर्तन

- दिनों की संख्या को 1,420 से घटाकर 500 दिन करें।

जैसे ही परियोजना आगे बढ़ी, सीसीएस ने सरकार को 2014 स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट लागू करने के लिए राजी करने का एक अतिरिक्त लक्ष्य तय किया। चयनित सूचकांक के दायरे से बाहर प्रतीत होते प्रयास को अन्य लक्ष्यों के लिए एक प्रॉक्सी के रूप में पहचाना गया था।

सर्वप्रथम स्कूलों को शुरू करने की प्रक्रिया को डीरेग्यूलेट करने के लिए आवश्यक कदमों का विश्लेषण करके शिक्षा के लिए संरचनात्मक बाधाओं पर काम करते हुए, सीसीएस ने निष्कर्ष निकाला कि यह एक व्यवसाय शुरू करने और व्यवहार्य नीति समाधान विकसित करने के लिए बाधाओं की पहचान करने की दिशा में समान कौशल पर ध्यान केंद्रित कर सकता है। स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसायों के रूप में औपचारिक रूप देने के अपने पिछले प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करते हुए, सीसीएस ने उन लोकप्रिय नौकरियों को अर्थव्यवस्था के एक मान्यता प्राप्त क्षेत्र के रूप में स्थापित करने पर भी ध्यान केंद्रित करने का निर्णय लिया।

संस्था के दृष्टिकोण की एक अनूठी विशेषता ,जिसने बड़े पैमाने पर समाज से विश्वसनीयता हासिल की है, प्रस्तावित नीति विचारों का परीक्षण करने के लिए पायलट कार्यक्रमों का उपयोग है। सीसीएस पहले स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट के पारित होने के कारण 2014 में स्ट्रीट वेंडर्स को व्यवसाय के रूप में कानूनी रूप से वैध बनाने में सफल रहा था। हालांकि, कुछ राज्यों ने देश की संघवादी नीति (फेडेरल डिस्क्रीट) का हवाला देते हुए एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है, जिससे स्ट्रीट वेंडिंग सेक्टर में लाखों लोगों को वैधता का लाभ मिलने में देरी हुई है। अपने लाइफ प्रोजेक्ट की एक पहल के रूप में, सीसीएस के वकीलों ने अदालत में केस दायर किया, और उस केस में जीत हासिल की, जो राज्यों को केंद्रीय अदालत के फैसले का पालन करने के लिए बाध्य करता है।

इसी तरह की संबंधित पहल में, सीसीएस ने बांस को एक पेड़ के बजाय घास के रूप में वर्गीकृत करने के लिए एक और कानूनी प्रक्रिया का पालन किया और सफल रहा।

साधारण सी बात प्रतीत होने वाला यह बदलाव नाटकीय रूप से व्यापार पर प्रभाव डालता है, विशेष रूप से गरीबों के संदर्भ में, क्योंकि पेड़ों की खेती, कटाई, बिक्री और व्यापार संरक्षित है। फिर से, सीसीएस के प्रयासों के परिणामस्वरूप वास्तविक परिवर्तन हुआ, जो व्यापक मौकों पर छोटे प्रयासों को आगे बढ़ाते हुए पिरामिड के निचले भाग में आर्थिक अवसरों को बढ़ाता है।

नि:संदेह यह परिणामी सूचकांक अंकों को लक्षित करने का एक गोलाकार तरीका था, लेकिन यह बदलाव के लिए मुख्य चालक नहीं था। 'जब हमने 'लाइफ' शुरू किया, तो हमने स्ट्रीट वेंडरों पर ध्यान केंद्रित नहीं किया क्योंकि यह सीधे सूचकांक पर लागू नहीं होता है,' पाटिल कहती हैं। 'लेकिन हमने परियोजना के मध्य में ही पटरी (और बांस) के विक्रेताओं के मुद्दे को एकीकृत करने का फैसला किया क्योंकि सूचकांक को स्थानांतरित करना हमारा अंतिम लक्ष्य नहीं है। हम दीर्घकाल के लिए व्यापार के माहौल में सुधार के एक बड़े पैमाने वाले दृष्टिकोण का अनुसरण कर रहे हैं।

इसके अतिरिक्त, पिरामिड के निचले हिस्से के उद्योगों पर ध्यान केंद्रित करने के निर्णय ने एक माध्यमिक उद्देश्य की सेवा की क्योंकि इससे सीसीएस की नीति समर्थन को मुख्यधारा में ले जाने में मदद मिली। भारत में, स्ट्रीट वेंडर सब जगह मिलते हैं, और ज्यादातर लोग उन्हें हर दिन देखते हैं। इसलिए इस विषय पर सीसीएस की नीति समर्थन को उनके अन्य कार्यों की तुलना में व्यापक वर्ग द्वारा समझा जा सकता है।

सामाजिक पिरामिड के निचले भाग में सामाजिक पूंजी के निर्माण के लिए, सीसीएस ने अपने शोध और रिपोर्टों के साथ नीति निर्माताओं और मंत्रालयों के प्रमुखों को लक्षित किया, अपनी दृढ़ता पर भरोसा किया और इस सफलता को चलाने के लिए नीति निर्माताओं के स्वयं के हितों पर ध्यान दिया। यह पूछे जाने पर कि सीसीएस ने सरकार में पहली बार कैसे संबंध स्थापित किए हैं, शाह हल्के फुल्के ढंग से कहते हैं, 'बार बार साथ साथ भोजन पर वार्ता करते हुए'। वह आगे व्याख्या करते हैं कि सीसीएस को मान्यता प्राप्त आवाज बनाने से पहले बहुत सारे दरवाजों को खटखटाने और चर्चा परिचर्चा करने की जरूरत पड़ी। सीसीएस कर्मचारियों के अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित करने, नए शोध अध्ययनों पर अपडेट भेजने, उभरते मुद्दों पर सलाह देने और मंत्रालय के सदस्यों से मिल कर अपने विचार साझा करने के लिए प्रयासरत रहे। ये कनेक्शन हमेशा अनुकूल परिणाम नहीं देते हैं, लेकिन सीसीएस की निरंतरता ने गहरी विश्वसनीयता प्रदान की है।

पहुंच के लगातार इस प्रकार के प्रयासों और उत्पादित शोध की गुणवत्ता के परिणामस्वरूप नीति निर्धारण में मदद करने के लिए निमंत्रण प्राप्त होने लगे। सरकार के डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग को आगे बढ़ाने के प्रयास के तहत विभिन्न अधिकारियों ने सीसीएस से उसकी राय मांगी है। इससे भी आगे बढ़कर 'लाइफ' की पहल के माध्यम से, सीसीएस ने राज्य सभा (संसद का उच्च सदन) के समक्ष अपना शोध प्रस्तुत किया, जिसके

परिणामस्वरूप कई सिफारिशें का पैनल द्वारा समर्थन किया गया। इसके अलावा उन्होंने भारतीय विधि आयोग के समक्ष अपने न्यायिक सुधार प्रस्तावों को भी प्रस्तुत किया, जिसमें अनुबंध प्रवर्तन के लिए अभियोग की प्रक्रिया को तेज करने का तर्क दिया गया था।

पुराने पड़ चुके और अप्रचलित कानूनों की एक लंबी सूची अभी भी केवल मनमाने ढंग से कानून की पुस्तकों में विद्यमान हैं, जो डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में भारत के निचले पायदान पर आने का एक कारण भी बनता है। सीसीएस ने इन असंगत कानूनों को एकीकृत करने के लिए एक पहल करने का निर्णय लिया और 'लाइफ' के बैनर के तहत एक अभियान की शुरूआत की, जिसे '100 कानूनों का निरस्तीकरण' नाम दिया गया। अब तक, उनमें से 23 को निरस्त कर दिया गया है। इसके बाद महाराष्ट्र में राज्य स्तर पर विशेष प्रयास किया गया, जहां 25 में से 19 प्रस्तावित कानूनों को निरस्त कर दिया गया।

इस उल्लेखनीय सफलता के अलावा, इस मुहिम ने गति पकड़ी, जिसके कारण सरकार ने 1,200 निरर्थक कानूनों को निरस्त कर दिया। 1,800 से अधिक ऐसे और कानूनों की पहचान की जा चुकी है जिनको समाप्त किया जाना है। सीसीएस ने अप्रासंगिक कानूनों पर ध्यान देने के लिए एक सोशल मीडिया अभियान भी शुरू किया, जिसमें '#LawsWithFlaws' हैशटैग का उपयोग करके जनता को उन कानूनों को खोजने की प्रक्रिया में शामिल किया गया, जिन्हें समाप्त किया जाना चाहिए। ट्विटर पर संवादात्मक चर्चा के मासिक सत्र के साथ इस दिशा में दूरगामी पहल करते हुए, वे 15,000 से अधिक विशिष्ट उपयोगकर्ताओं तक पहुँच चुके हैं।

नि:संदेह कानूनी अभियानों और सार्वजनिक सहभागिता की सफलता ने सीसीएस को और नया करने का मौका दिया। काफी बड़ा संगठन होने के बावजूद, सीसीएस को अपनी 'लाइफ' परियोजना के सभी क्षेत्रों में गति बनाए रखने की अपनी सीमाओं का एहसास हुआ। वे अपने डेटा संग्रह को समृद्ध करने के लिए अतिरिक्त इंटर्न ले आए और इस दिशा में विचार किया कि थिंक टैंक और सामाजिक भागीदारी के रूप में वे पहले से ही कानूनी शोध में सक्रिय हैं और अपनी परियोजनाओं को सफलता पूर्वक चलाने में मदद करने के लिए दूरगामी पहल करनी होगी।, 'अधिक सहयोगात्मक ढांचे की ओर बढ़ना और नई जमीन हासिल करना हमारी कार्रवाई की नई विशेषताएं थीं।' पाटिल कहती हैं 'लाइफ कार्यक्रम ने कमोबेश सहयोग के लिए हमारी आँखें खोली। यह पूरी तरह से नया नहीं था, लेकिन यह एक बहुत बड़ा अंग बन गया।

नए व अलग मुद्दों पर विशेषज्ञता रखने वाले व पहले से ही कार्यरत संगठनों के साथ काम करना सीएसए के लिए नया हो सकता है, लेकिन टीम आश्वस्त हो सकती है कि अपने स्वयं के संसाधनों को केंद्र में रखते हुए प्रगति जारी रह सकती है।

भारत के एक पैर अतीत में और एक पैर भविष्य में रखने की नीति के कारण देश नीतिगत सुधार को लेकर तनाव का सामना करता है। उदाहरण के लिए, क्रोनिइज़्म की जड़े इस देश में काफी गहरे तक पैठ जमा चुकी हैं। इसका कारण देश का लाइसेंस राज प्रणाली वाला इतिहास रहा है। इस प्रणाली ने 20 वीं शताब्दी के लगभग आधे समय तक भारत में औद्योगिक नीति को बढ़ावा देने का कार्य किया। अत्यधिक नियंत्रित माहौल के बारे में बताते हुए शाह कहते हैं कि 'पूर्वानुमेय ढंग से और समझ में आने लायक होने के कारण लोग शॉर्ट कट लेते हैं और प्रतिस्पर्धा को रोकने के लिए सरकार का उपयोग करते हैं।' भ्रष्टाचार के व्यापक होने के कारण इसके खिलाफ संघर्ष की स्थिति बदतर हुई है। इसने देश को बाजार-उन्मुख गतिविधियों के खिलाफ पूर्वाग्रहित कर दिया है। वैश्वीकरण की शुरुआत ने इस पूर्वाग्रह को कम करना शुरू किया है, हालांकि, लोग विमानन, दूरसंचार और बैंकिंग की परिवर्तनकारी शक्ति का अनुभव करते हैं, फिर भी प्रगति धीमी हो सकती है।

जाति व्यवस्था के तत्व देश की नीतिगत चर्चा में भी दिखाई देते हैं। कुछ का दावा है कि बाजार अमीरों के लिए हैं और गरीबों को नुकसान पहुंचाते हैं, शाह कहते हैं कि 'जब आप गरीबों को अधिक शक्ति देने की वकालत शुरू करते हैं, तो वही लोग जो शिकायत करते हैं कि कैसे बाजार गरीबों को वंचित करते हैं, वे कहते हैं कि गरीब अपने फैसले स्वयं लेने में सक्षम नहीं हैं।' इस संज्ञानात्मक असंगति को संबोधित करने के लिए धैर्य की आवश्यकता होती है।

भारतीय समाज की इन विसंगतियों ने सीसीएस की 'लाइफ' परियोजना बाधित की है, लेकिन उचित रूप से संबोधित किए जाने पर सीसीएस के सामने उत्पन्न चुनौतियां अक्सर दोगुने अवसर में तब्दील हो जाती हैं। संस्था आमतौर पर सुधार के साथ अपने आलोचकों के हितों को संरेखित करने के तरीकों की पहचान करके और यह प्रदर्शित करके कि उनके स्वयं के जीवन में सुधार होगा, प्रगति की जा सकती है, भले ही यह धीरे-धीरे हो। सौभाग्य से, धैर्य संस्था की एक विशेषता रही है जिसे आत्मसात करने के लिए सीसीएस अपनी स्थापना के बाद से ही बाध्य रहा है।

सीसीएस द्वारा 'लाइफ' प्रोजेक्ट आरंभ करने के बाद से भारत की ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में रैंकिंग बढ़ी है। अब सरकार ने व्यवसाय शुरू करने के लिए न्यूनतम पूंजी की आवश्यकताओं को समाप्त कर दिया है और अनुबंधों को लागू करने के लिए आवश्यक समय लगभग पैंसठ फीसदी तक कम हो गया है। साथ ही कारोबार शुरू करने के लिए आवश्यक प्रक्रियाओं और दिनों को कम कर दिया गया है। सीसीएस के इन प्रयासों को इन सफलताओं के साथ सीधा जोड़ने में मुश्किल होने के बावजूद, साक्ष्य बहुत ठोस है।

सीसीएस के नीति निर्माताओं के साथ के सीधे जुड़ाव ने एक ऐसा ठोस आधार प्रदान किया है, जिस पर उन्होंने 'लाइफ' परियोजना का निर्माण किया। इन प्रयासों ने अब फल देने भी

शुरु कर दिये हैं। भारत की औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने देश के व्यावसायिक परिवेश में सुधार के लिए सीसीएस के कई सुझावों को स्वीकार किया है। इसके अलावा व्यापार के पंजीकरण के लिए ऑनलाइन सुविधा शुरु करने के इसके प्रस्ताव को भी लागू कर लिया गया है। ये महज कुछ सफलताएं हैं जिसे सीसीएस ने कार्यक्रम के दौरान हासिल किये हैं और उम्मीद है कि यह गति जारी रहेगी।

भारत का डूइंग बिज़नेस आंकड़ा केवल नई दिल्ली और मुंबई में कानूनों और विनियमों पर आधारित है। इस कारण 'लाइफ' प्रोजेक्ट के तहत उनके प्रयासों की राह में बाधा उत्पन्न होती है। पाटिल कहती हैं कि भविष्य में उनकी योजना इस प्रोजेक्ट को देश के अन्य शहरों में विस्तारित करने और कई सफल पहलों को वहां लागू कराने की है। वहां सफलता को मापने का पैमाना विश्व बैंक का सूचकांक तो नहीं होगा लेकिन यह एक बैरोमीटर के रूप में काम करेगा। इसके अलावा, उन्होंने देश के संविधान दिवस पर 'रिपील ऑफ लॉज़ डे' लॉन्च करने के साथ ही एक जमीनी स्तर का अभियान शुरू किया है। यह नवंबर के अंत में मनाया जाता है, जिसमें नागरिकों और राजनेताओं को पिछले व्यापार सुधारों की सफलता से अवगत कराते हुए आगे के प्रयासों को जारी रखने की जरूरत बतायी जाती है।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

सीसीएस उन लोगों के लिए एक कठिन चुनौती साबित हुई है जो भारत को अपने स्थिर समाजवादी अतीत में फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रगति धीमी रही है, लेकिन संतुलित है। प्रभावी भूमिका प्राप्त करने के लिए, संगठन को न केवल शोध और संदेशन में मेहनत करनी पड़ी बल्कि उदासीन नेताओं और जनता के साथ ही साथ प्रतिरोधी दर्शकों के साथ जुड़ने के लिए मजबूत क्षमताओं का विकास करना पड़ा है। तकरीबन 1.3 बिलियन से अधिक लोगों के देश में, बहुत सी आवाज़ें शांत हो सकती हैं। कई लोग इसे एक अड़चन के रूप में देखेंगे, लेकिन सीसीएस में पार्थ शाह और उनकी टीम ने इसे एक चुनौती के रूप में देखा है। इसे जवाबदेही और अनुकूलन की क्षमता के लिए एक मजबूत क्षमता के साथ पूरा किया है।

दीर्घकालीन योजना के लिए विश्वसनीयता

सीसीएस ने लोककल्याण नीति के मुद्दों पर एक भरोसेमंद आवाज के रूप में एक अच्छी छवि बनाने में बहुत धैर्य का प्रदर्शन किया है। रिश्ते जो कि गैर-लाभकारी संगठनों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं, उन्हें बनाने में समय लगता है क्योंकि संगठन अल्पकालिक अस्तित्व के लिए शोध और फंड जुटाने पर निर्भर हैं। विश्वसनीय और प्रभावशाली नेटवर्क का निर्माण करना, हालांकि, संरचनात्मक नीति परिवर्तन को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण है। सीसीएस के कर्मचारियों ने नीति निर्माताओं और व्यावसायिक नेताओं से संपर्क करने, मिलने और

शिक्षित करने में अनगिनत घंटे बिताए। यह अन्य गतिविधियों की लागत पर संभव हुआ, लेकिन यह एक दीर्घकालिक योजना है और शाह और पाटिल दोनों विश्वसनीयता को अपनी सबसे बड़ी संपत्ति बताते हैं।

सीसीएस टीम ने स्ट्रीट वेंडर सुधार के अतिरिक्त लक्ष्य को आगे बढ़ाने का फैसला किया। भले ही यह डूइंग बिजनेस की किसी श्रेणियों से स्पष्ट रूप से जुड़ा नहीं था। इन प्रयासों का एक परिणाम लाखों उद्यमियों की स्वतंत्रता का विस्तार है, जो नि:संदेह औपचारिक सूचकांक स्कोर और रैंकिंग में देश के प्रदर्शन को प्रभावित करेगा। हालांकि, पहले से परिणाम ज्ञात नहीं थे, फिर भी ये गरीबी और कठिनाई को दूर करने के लिए सार्थक प्रयासों पर भरोसा करने के लिए एक मौलिक संकल्प को दर्शाते हैं।

साझेदारी की दृष्टि का विकास

नि:संदेह सीसीएस की प्रभावी सफलता के मूल में मानव पूंजी है। देश में मजबूत श्रम बाजार का लाभ उठाते हुए, सीसीएस ने अलग-अलग दक्षताओं को मिलाकर एक टीम बनाई है, जो नीतिगत मसलों के परिवर्तन को प्रभावित करने में सक्षम एक टीम का निर्माण करती है, जो एक दूसरे के संपूरक होकर विभिन्न कौशल प्रदर्शित करती हैं।

सी.सी.एस. के शोधकर्ताओं की अंतर्दृष्टि ने डूइंग बिजनेस रैंकिंग स्कोर में सुधार करने, वास्तविक रूप से सुधार के लिए बौद्धिक मामले का तैयार करने, व्यवसायों के लिए ई-फाइलिंग की ओर देश को उन्मुख करने और सफल उपक्रमों के लिए कुछ कानूनी मुद्दों आदि पर वास्तविक प्रगति करने में नेतृत्व किया। कानूनी टीम के निर्माण और वाद-विवाद के मामलों में नीचे के पिरामिड वाले उद्यमियों के लिए स्वतंत्रता में विस्तार और व्यापक और मनमाने कानूनों के निरस्त करने का नेतृत्व किया गया। शाह के अनुसार सीसीएस के मिशन को आगे बढ़ाने के लिए निदेशक मंडल को भी श्रेय दिया जाता है, क्योंकि वे व्यवसाय, शिक्षा और सरकार में सम्मानित स्थान रखते हैं। साथ ही सीसीएस की विश्वसनीयता को आगे बढ़ाते हैं।

सफलता हासिल करने के लिए प्रेरणा

दरअसल, सीसीएस की स्थापना मुक्त बाजारों तक पहुंच में सुधार के माध्यम से लोगों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए की गई थी। सीसीएस के अध्यक्ष पार्थ शाह कहते हैं, 'हम एक विचार-संचालित संगठन हैं।' यह टीम की क्षमताओं को विविध विषयों में परिवर्तित करने, उन्नतिशील दृष्टिकोण अपनाने और विशिष्ट नीतिगत मुद्दों के प्रति लकीर का फकीर नहीं होने के लिए असाधारण लचीलापन प्रदान करता है। सीसीएस ने नीतिगत विचारों को पायलट कार्यक्रमों के माध्यम से क्रियान्वित किया है ताकि यह पता चले कि उसके विचारों ने काम किया है और विशेष मुद्दों से निपटने के लिए बेहतर तरीके से सुसज्जित अन्य

संगठनों को सफल कार्यक्रम सौंप दिए हैं। यह दीर्घकालिक संरचनात्मक नीति परिवर्तनों को आगे बढ़ाने के लिए अल्पकालिक सफलता को जोखिम में डालने के लिए तैयार है।

चर्चा योग्य प्रश्न

- आपका संगठन क्या कभी सफलता से भ्रमित हुआ है? क्या आपके द्वारा शुरू की गई पहल या परियोजनाएं हैं जो ध्यानाकर्षण प्राप्त कर चुकी हैं लेकिन आपके कर्मचारियों को उनकी विशेषज्ञता के दायरे से बाहर की चीजों पर समय बिताने की आवश्यकता है? आपका संगठन इन परियोजनाओं को लंबे समय तक चालू रखने के लिए अधिक सुसज्जित अन्य संगठनों को कैसे सौंप सकता है?
- आपके देश के इतिहास के कौन से विशिष्ट तत्व बाजार-उन्मुख सुधार को मुश्किल बनाते हैं? आप उस चुनौती को अवसर में कैसे बदल सकते हैं?
- किसी संस्था के लिए एक प्रमुख प्रोजेक्ट को बीच में सुधार करना कितना मुश्किल है? किस तरह की जोखिम सहिष्णुता की आवश्यकता है? सीसीएस ने वेंडर सुधारों के लिए समर्थन को अपने 'लाइफ' प्रोजेक्ट में एकीकृत करने का निर्णय लिया, भले ही यह सीधे उनके लक्ष्य मानकों से बंधा हुआ न हो। आपको क्या लगता है उनके निर्णय के मूल में क्या था? क्या आपका संगठन भी इसी तरह कार्य करेगा?
- 'लाइफ' परियोजना ने सीसीएस को उस नीति क्षेत्र में क्षमताओं का निर्माण करने के लिए प्रेरित किया जहां यह पहले व्यवस्थित रूप से केंद्रित नहीं था। यह आपके संगठन को एक नई दिशा में आगे बढ़ने के लिए क्या संकेत दे सकता है? आप इस तरह की पहल के लिए सीमित संसाधनों को समर्पित करने या न करने का फैसला कैसे करेंगे?
- सत्ताधीश प्रशासन बदलते हैं और राजनीतिक दल विकसित होते हैं। आप राजनीतिक सुधारों में बदलाव की परवाह किए बिना संरचनात्मक सुधारों को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं? क्या आपके संगठन के वर्तमान कार्यक्रम छोटी या लंबी अवधि की नीति सफलता पर केंद्रित हैं?

खंड 5

निजीकरण का विषय अवलोकन

सरकारें संपत्ति के अधिकारों को हासिल करने, अनुबंधों को लागू करने और विवादों को निष्पक्ष और अनुमानित रूप से निपटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं। चूंकि ये कार्य इतने महत्वपूर्ण हैं, इसलिए उन्हें सरकारी क्षमता में सुधार के लिए किए जा रहे सभी प्रयासों के केंद्र में होना चाहिए। सरकारों की भूमिका को मुख्य कार्यों तक पुर्नकेंद्रित कर हम संस्थानों को बेहतर करने के लक्ष्य को हासिल कर सकते हैं। हम गैर-महत्वपूर्ण कार्यों में सरकार की भागीदारी कम करके उसके विकृत और दुर्बल प्रभाव को समाप्त या कम कर सकते हैं। कई मामलों में, सरकार ने विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं को प्रदान करने का प्रयास किया है, जो अत्यधिक लागत और कम गुणवत्ता के कारण निराशाजनक रूप से विफल हो गए हैं।

कतिपय मामलों में, सरकारी दखल का दुष्परिणाम यह होता है कि निजी सेवा प्रदाताओं को बाजार से बाहर करके उपभोक्ताओं को केवल सरकारी विकल्पों के भरोसे छोड़ दिया जाता है। अन्य मामलों में देखा गया है कि निजी सेवा प्रदाताओं को प्रतिस्पर्धा करने से प्रतिबंधित किया जाता है, जो कि साझा समृद्धि में योगदान देने वाले आर्थिक समाधानों का कोई विकल्प नहीं है। हम कुशल और सक्षम सरकारें चाहते हैं जो भ्रष्टाचार के प्रभावों को कम करती हो। इन उद्देश्यों को प्राप्त करने की प्रबल संभावना तभी होती है यदि सरकार के कार्यक्षेत्र को केवल उन्हीं कार्यों तक सीमित रखा जाये, जो वास्तव में एक स्वतंत्र और शांतिपूर्ण समाज के लिए जरूरी है।

इस खंड के केस स्टडी के वर्जन AtlasNetwork.org पर उपलब्ध हैं।

भरोसेमंद बिजली तक पहुंच का विस्तार

लेबनीज़ इंस्टीट्यूट फॉर मार्केट स्टडीज़
लेबनान

प्रस्तावना

वर्ष 1970 के दशक के बाद से लेबनान घंटों लंबी बिजली की कटौती से त्रस्त है। सरकार बिजली का एकमात्र अधिकार प्राप्त आपूर्ति कर्ता है जिसने नवाचार और प्रतिस्पर्धा बढ़ाकर उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली सेवा उपलब्ध कराने के कार्य का दम घोंट दिया है। लेबनानी इंस्टीट्यूट फॉर मार्केट स्टडीज को इस बात के लिए धन्यवाद कि लेबनान का बिजली बाजार अब निजी प्रतिस्पर्धा के लिए खुला है और लेबनान के लोग कम सरकारी अपव्यय और बेहतर बिजली की उपलब्धता हासिल कर रहे हैं।

लेबनानी इंस्टीट्यूट फ़ॉर मार्केट स्टडीज़ या लीम्स की स्थापना 2015 में आज़ादी के बाद देश के सबसे अंधेरे क्षणों के दौरान हुई थी। वह आज़ादी जिसे पाने के लिए लेबनान के संस्थापकों ने लड़ाई लड़ी थी वह अब नष्ट हो चुकी है क्योंकि सरकार बहुत बड़ी हो गई है और लोगों की स्वतंत्रता की स्वतंत्रता को कम कर दिया गया है। कुशासन के चलते वर्ष 2015 तक, सार्वजनिक ऋण सकल घरेलू उत्पाद का 148 प्रतिशत तक पहुंच गया। लेबनान के दूरदर्शी लोगों के एक दल ने सार्थक पहल की और एक संगठन बनाया, जो लेबनान में आर्थिक स्वतंत्रता को बहाल करने के लिए काम करेगा।

दरअसल, लीम्स की टीम लेबनान के लोगों को सशक्त बनाने और सार्वजनिक अधिकारियों, मीडिया और लोगों के साथ अनुसंधान, शिक्षा और विचार-विमर्श संबंधी चर्चाओं का उपयोग करके जन-स्वतंत्रता के लिए लड़ने का काम करती है।

आप कल्पना कीजिए एक ऐसे देश में रहने की, जहां यह संभव है कि आपके बहते नल से पानी आना अचानक बंद हो जाए, आप अपने कार्यालय के एलिवेटर में घंटों के लिए अटक जाएं, या आपका लाइफ सपोर्ट सिस्टम बंद हो जाए क्योंकि आपके पास पर्याप्त बिजली

की आपूर्ति नहीं है। अब कल्पना कीजिए कि यह समस्या इसलिए है क्योंकि जिस सरकार को आप फंड करते हैं वह सरकार बिजली की एकाधिकार प्राप्त आपूर्तिकर्ता है।

यह विकसित देशों के लोगों के लिए यह एक ऐसी अवधारणा है, जिसकी वे कल्पना भी नहीं कर सकते। लेकिन लेबनान के नागरिक इसे अपने जीवन की रोजमर्रा की वास्तविकता समझते हैं, क्योंकि औसत व्यक्ति दिन में औसतन 12 घंटे लगातार ब्लैकआउट का अनुभव करता है।

सरकार ने यह साबित कर दिया है कि वह लेबनान के लोगों को पर्याप्त रूप से बिजली प्रदान नहीं कर सकती है बल्कि ऐसा सिर्फ मुक्त बाजार, व्यवसाय और रचनात्मक शक्तियां जिन्हें मुक्त कर दिया गया है, कर सकते हैं। सौभाग्य से लेबनान के लोगों के लिए, लीम्स ने मूल शोध के साथ नए विचारों से शून्य को भरने और एक पूरी तरह से विकसित समाधानों के साथ कदम रखा, जो देश के बिजली बाजार को निजी कंपनियों के लिए खोल देगा और उपभोक्ताओं के लिए बेहतर बिजली सेवा उपलब्ध करेगा।

यहां बताया गया है कि कैसे लेबनान के बिजली बाजार का परिदृश्य बदला :

- 2014 में लीम्स ने सुधार के लिए एक खाका तैयार किया, जिसने लेबनान सरकार के शक्ति एकाधिकार को समाप्त करने के लिए आधार तैयार किया। यह सरकारी खर्चों में कटौती और सार्वजनिक बिजली के एकाधिकार को निजी प्रतिस्पर्धा से बदलने के लिए लीम्स का दृष्टिकोण था।
- अपने शोध के बाद लीम्स ने एक बड़े पैमाने पर जन जागरूकता अभियान चलाया। वर्ष 2016 में, लीम्स ने प्राइम-टाइम न्यूज़ और टॉक शो, 20 रेडियो कार्यक्रम, समाचारपत्रों में 42 साक्षात्कार और 50 ऑनलाइन लेखों पर 33 टेलीविज़न साक्षात्कारों के जरिये बदलाव के लिए मुहिम चलाई।
- इसके उपरांत लीम्स ने सांसदों और मंत्रियों के साथ 32 बैठकें करते हुए आग्रह अभियान चलाया। लीम्स के अधिकारियों ने अपनी योजनाओं और शोध को निर्धारित किया, साथ ही नीति-नियंताओं को बताया कि यह देश में बिजली का उत्पादन करने का एक बेहतर तरीका है।
- लेबनान की संसद ने 17 अप्रैल, 2019 को एक नई बिजली योजना की पुष्टि की, जो सरकार संचालित बिजली कंपनी की सब्सिडी में कटौती को अनुमति देती थी और निजी कंपनियों के लिए बिजली उत्पादन का रास्ता साफ करती थी।

प्रोजेक्ट विवरण

लेबनान के लिए बिजली आपूर्ति योजना 1906 में पेश की गई थी जब ओटोमन साम्राज्य ने बेल्जियम के निजी निवेशकों को बेरुत में पहली बिजली कंपनी खोलने की अनुमति दी थी। फिर इसे 1923 में एक फ्रांसीसी कंपनी और अंत में 1954 में सरकार को हस्तांतरित कर दिया गया। तब से सरकार लेबनान में बिजली का एकाधिकार प्राप्त सेवा प्रदाता रही है।

ब्लैकआउट की शुरुआत लेबनानी गृहयुद्ध (1975-1990) के दौरान हुई। युद्ध समाप्त होने के बाद, लेबनान में शांति तो वापस आ गई लेकिन विद्युत शक्ति नहीं लौटी।

चूंकि लेबनानी लोगों ने देश की सत्ता पर एकाधिकार स्थापित कर लिया था, इसलिए ब्लैकआउट संकट को हल करने के सभी प्रयास करदाताओं के अधिक डॉलर फेंकने पर केंद्रित थे। लेबनान की सरकार ने 2010 से बिजली पर 35 बिलियन डॉलर खर्च किए, फिर भी जनता बिजली कटौती के संकट से जूझती रही।

सही मायनों में बिजली की कमी एक व्यक्तिगत असुविधा से परे प्रभाव डालती थी। जैसा कि रायटर के लेखक एंगस मैकडॉवेल कहते हैं, 'लेबनान के बिजली संकट ने इसे वित्तीय बर्बादी के कगार पर ला खड़ा किया है, क्योंकि बिजली की कटौती से बाधित अर्थव्यवस्था और सब्सिडी के दबाव से आर्थिकी दुनिया के सबसे बड़े सार्वजनिक ऋण बोझों में से एक हो गई है।'

लेबनान प्रति वर्ष एक बिलियन डॉलर से अधिक बिजली सब्सिडी पर खर्च करता है, जो राष्ट्रीय ऋण के 40 प्रतिशत के बराबर है। यह एक बड़ी बात है, यह देखते हुए कि देश सार्वजनिक ऋण पर अपना आधा बजट खर्च कर रहा है। देश के बिजली स्रोत और सरकार की अस्थिरता के साथ संयुक्त रूप से यह भारी और अक्षम्य सरकारी खर्च, व्यापार निवेश की राह में एक बड़ी बाधा है। वास्तव में, देश की अर्थव्यवस्था हाल के वर्षों में सिर्फ 1-2 प्रतिशत बढ़ी है।

संकट वाली इस समस्या से जो समाधान दिला सके उसका मिलना चिरस्मरणीय कार्य था। वर्ष 2014-2016 तक लेबनान राष्ट्रपति विहिन था। राजनीतिक अस्थिरता के चलते कार्यवाहक नेतृत्व के कारण समस्या आज भी जस की तस है।

निजी तौर पर बिजली उत्पादन करना तकनीकी रूप से अवैध होने के बावजूद, लेबनान में लोग बिजली के लिए निजी जनरेटर की ओर रुख कर रहे हैं। वर्ष 2017 तक, निजी जनरेटर संचालकों ने ब्लैकआउट के दौरान 70 प्रतिशत घरों में सेवा की पेशकश की।

'मैं वर्तमान में सस्ते जनरेटर का उपयोग कर रहा हूं जो शोर, प्रदूषण करता है और बहुत कारगर नहीं हैं', ब्लैकआउट के दौरान बिजली आपूर्ति करने वाले उद्यमी अब्दुल्ला ने कहा। 'मैं अधिक कुशल बिजली संयंत्रों का निर्माण करना चाहता हूं। मैं सभी आपूर्ति को संभाल

सकता हूं, और मेरा पहले से ही एक अच्छा ग्राहक आधार है। ...एक बार कानूनी होने के बाद, मैं अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए बैंक से धन उधार ले सकता हूं या निवेशकों को आकर्षित कर सकता हूं, जो मैं अभी नहीं कर सकता।'

लेबनान में अब्दुल्ला जैसे सेवा प्रदाता बाजार की मांग का जवाब दे रहे हैं, लेकिन वे जो पेशकश कर सकते हैं वह सीमित हैं। छोटे पैमाने पर जनरेटर प्रदूषक होने के साथ ज्यादा ईंधन की खपत करते हैं और यह लोगों को पर्याप्त बिजली देने का स्थायी तरीका नहीं है।

ऐसे में लेबनान के लोगों के सामने विकट स्थिति में सार्थक बदलाव लाने के लिए लीम्स ने 'लेबनान में लाइट ऑन करें' समर्थक अभियान चलाया, जिसका लक्ष्य दोहरे सुधार लाना था : लेबनान में बिजली सब्सिडी में कटौती करना और निजी क्षेत्र को बिजली उत्पादन बाजार में प्रवेश करने की अनुमति दिलाना। इन सुधारों को प्राप्त करने के लिए, लीम्स ने पारंपरिक और सोशल मीडिया में निरंतर उपस्थिति के माध्यम से सार्वजनिक जागरूकता अभियान चलाया। संस्थान ने समर्थन प्राप्त करने के लिए राजनीतिक दलों से भी संपर्क साधा।

नि:संदेह सरकारी एकाधिकार को तोड़ना बहुत ही कठिन कार्य है और यह लीम्स के लिए एक आसान या त्वरित लड़ाई नहीं थी। वर्ष 2014 में, संगठन ने एक नीतिगत प्रस्ताव तैयार करके अपनी लड़ाई में पहला कदम उठाया, जो कालांतर सुधार का खाका बन गया। यह सरकारी खर्चों में कटौती और सार्वजनिक बिजली के एकाधिकार को निजी प्रतिस्पर्धा से बदलने के लिए लीम्स का दृष्टिकोण था।

वर्ष 2016 में एक प्रभावी मीडिया और सार्वजनिक जागरूकता अभियान के परिणामस्वरूप, जनमत ने निराशावाद को त्याग कर आशावाद की ओर बढ़ना शुरू कर दिया था। दरअसल, लीम्स ने लोगों को एक वैकल्पिक दृष्टि प्रदान की कि कैसे बिजली का उत्पादन किया जा सकता है।

लीम्स ने लोगों की सोच को बदलकर जन प्रतिनिधियों पर दबाव बनाकर, संसद सदस्यों और मंत्रियों के साथ निजी तौर पर और उनके सलाहकारों की मौजूदगी में बैठकें आयोजित करके जनभावनाओं से अवगत कराया। यह एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने सरकारी अधिकारियों को समझा दिया कि यथास्थिति काम नहीं कर रही है। साथ ही उन्हें इस बात के लिए विचार दिए हैं कि कैसे मुक्त बाजार सिद्धांतों को गले लगाकर समस्या को हल किया जा सकता है।

लीम्स की सार्थक मुहिम के चलते जब जनप्रतिनिधियों पर दबाव बनाया जा रहा था और इसके साथ ही सार्वजनिक अभियान चल रहा था, लेबनान बिजली कटौती के संकट से जूझ रहा था। लेबनान सरकार ने करदाताओं के खर्च पर कई नए बिजली संयंत्रों के निर्माण और दो अतिरिक्त 'पॉवरशिप' किराये पर लेकर सरकार द्वारा संचालित बिजली उत्पादन

को बढ़ाने की योजना बनाई। पावरशिप वे जहाज हैं जो फ्लोटिंग पावर प्लांट में परिवर्तित हो जाते हैं और लेबनानी बिजली उत्पादन के 25 प्रतिशत की भूमिका निभाते हैं। लीम्स ने इन योजनाओं का विरोध करने का निर्णय लिया, ताकि इस भारी खर्च योजना को अवरुद्ध करके एक बाजार-उन्मुख समाधान को बढ़ावा दिया जा सके।

नि:संदेह कोई भी योजना जो गंभीर सुधार के बिना वर्तमान स्थिति को बढ़ावा देती है वह विफल हो जाती है। लीम्स को पता था कि पावरशिप के खिलाफ लड़ाई में उनका सामना सबसे पहले नौकरशाही और अति-नियमन से होगा, ऐसे में विस्तृत अंतर्विभागीय समीक्षा पर जोर देकर योजना के क्रियान्वयन को धीमा कर दिया। लीम्स का अहसास था कि इस प्रक्रिया से योजना का खात्मा संभव है।

इसके उपरांत लीम्स ने शोधकार्य को प्रचारित करने पर अपना ध्यान केंद्रित किया, जिसके जरिये बिजली उत्पादन के बारे में एक बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य साझा किया गया : भूमि पर निर्मित निजी संयंत्र आधी लागत पर बिजली की आपूर्ति कर सकते हैं, जो तुर्की से अनुबंधित थे। लीम्स ने बताया कि लेबनान सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं है कि वह बिजली उत्पादन के लिए ईंधन खरीद सके, भले ही उपकरण मुफ्त में दिए जाएं, क्योंकि ऊर्जा मंत्रालय ने 2018 के लिए निर्धारित अपने बजट को पार कर लिया था।

दरअसल, 'पॉवरशिप' योजना न केवल अक्षम थीं और निजी भूमि-आधारित उत्पादन की तुलना में अधिक महंगी थी, बल्कि इसके साथ ही भारी पर्यावरणीय लागत भी चुकानी पड़ती थी। लीम्स ने ज़ौक मिकेल शहर के निवासियों की कहानियों को लोगों से साझा किया, जिन्होंने मौजूदा 'पॉवरशिप' से स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में सरकार को लंबे समय से शिकायत की थी। सरकार के प्रस्ताव के तहत ही 'पॉवरशिप' उस क्षेत्र में तैनात की गई होंगी, जिसने स्थानीय आबादी की पीड़ा को दोगुना किया होगा।

संदेश दिया गया कि यदि निजी कंपनियां बेहतर और सस्ती सेवा प्रदान कर सकती हैं, तो सरकार को बिजली उत्पादन को नियंत्रित नहीं करना चाहिए। इसकी बजाय प्रतिस्पर्धा करने के लिए बाजार खोलना चाहिए। लेबनान के लोगों के लिए यह एक बेहतर परिणाम है और लीम्स ने सुनिश्चित किया कि जनता ने इस सच्चाई को जोर से और स्पष्ट रूप से सुना।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

लीम्स साबित करता है कि बड़े नीतिगत संघर्ष सफलता हासिल करने में सफल होते हैं, खासकर यदि आप जिस समस्या का समाधान चाहते हैं, उसका आम जनता पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता हो। लीम्स की कहानी यह सिखाती है कि कैसे :-

- शोध के साथ नए विचारों देने से और समाधानों का एक पूर्ण विकसित स्वरूप मिलता है।
- अपनी वैकल्पिक दृष्टि से जनता को रूबरू करें और सार्वजनिक समर्थन का निर्माण करें।
- सरकारी अधिकारियों पर दबाव बनाने के लिए जन समर्थन और व्यवहार्य नीति विकल्पों का लाभ उठाएं।

लीम्स सरकार के बिजली के एकाधिकार के लिए आगे धन देने के खिलाफ बोलने के लिए तैयार था और दूसरों को अपनी आवाज उठाने के लिए सशक्त बनाया गया था। इससे खुले बाजारों के लिए आह्वान करना और इस मांग को नज़रअंदाज़ करना असंभव था। लीम्स के अनुसंधान के विस्तार में, लेबनान के राष्ट्रपति ने आर्थिक नुकसान, बिजली के नुकसान और नुकसान के अन्य कारण पर एक अध्ययन विकसित किया है और सरकार से व्यापक सुधारों को आगे बढ़ाने का आग्रह किया है।

सरकारी खर्चों के विपरीत निजी बिजली उत्पादन और बिक्री की वैधता के महत्व पर जोर देने के बाद, एक विकल्प की पेशकश की गई, जो करदाताओं को लगभग कुछ भी खर्च नहीं करते हुए देश की बिजली समस्या का समाधान करेगा।

प्रभावशीलता

लीम्स ने बिजली की स्वतंत्रता की लड़ाई में निर्णायक जीत हासिल की और उनकी सफलता बेहतर सेवाओं और नए सुधार के अवसरों की ओर अग्रसर है। अक्तूबर 2018 में, लीम्स की ऐडवोकेसी ने देश में बदतर हालात ही में एक असम्भव नई शक्ति को बाहर निकालने में मदद की। प्रगति अपने आयाम से जारी है। बदलाव की बयार में, लेबनान ने पहली निजी स्वामित्व वाली बिजली कंपनी के लिए अपने दरवाजे खोले, जिसमें लीम्स की टीम का बहुत मुखर समर्थन था और यह उनके लिए उत्सव था। फिर 17 अप्रैल, 2019 को, लेबनान की संसद ने एक नई बिजली योजना की पुष्टि की, सरकारी सब्सिडी वाली बिजली कंपनी की सब्सिडी हटाती है और निजी कंपनियों के लिए बिजली उत्पादन का रास्ता साफ करती है।

चर्चा हेतु प्रश्न

- सुधार में मदद करने वाले समूहों की व्यापक गठबंधन की पहचान करने और उन्हें संलग्न करने में समय लगाकर सुधार को पारित करने में लीम्स के प्रयासों को कैसे मदद या गति मिली है?

- अक्सर, एक थिंक टैंक को काम करने से जितना रोका जाता है, यह सुधारों को पारित कराने में उतना ही महत्वपूर्ण योगदाना देता है। खराब कानून या विनियमन को पारित होने से रोकने के लिए प्रभावी तरीके या समूह क्या नियोजित कर सकते हैं?
- वो कौन सा तरीका है जिससे कि छोटे लक्ष्यों को हासिल करने के दौरान थिंक टैंक समूह बड़े लक्ष्यों या सुधारों से न भटकें?

सबके लिए शुद्ध पेयजल

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू
पेरू

भूमिका

पेरू वैश्विक स्तर पर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने को तैयार है। अतीत में अमेरिका की सबसे पुरातन सभ्यताओं की भूमि पेरू 32वीं शताब्दी ईसा पूर्व अस्तित्व में आया था। लेटिन अमेरिकी देशों की हाल ही में बढ़ रही अर्थव्यवस्थाओं के बीच पेरू ने विशेष रूप से ध्यान आकर्षित किया है। भौगोलिक विविधता ने उसे प्राकृतिक संसाधनों की विशाल ऋंखला प्रदान की है, जिसमें खनन से ले कर मछली पकड़ने व कृषि उत्पादन तक शामिल हैं। लेकिन जो संसाधन उद्योगों को ऊर्जा प्रदान करते हैं वे सामाजिक तनाव का कारण भी बनते हैं।

पिछले दो दशकों में तेजी से बढ़ती आर्थिक वृद्धि ने देश की लगभग एक-तिहाई आबादी को देश की राजधानी लिमा की और आकर्षित किया है। हालांकि पेरू की दो-तिहाई आबादी का बड़ा हिस्सा अमेजन के वर्षा वनों से लेकर समुद्री तटों व पहाड़ों तक फैला हुआ है।

यह दूरदराज तक ग्रामीण व अविकसित क्षेत्रों में फैली आबादी सभी नागरिकों को देश की अर्थव्यवस्था से जोड़ने में बाधा उत्पन्न करती है। जहां एक और ग्रामीण समुदायों के बीच स्वच्छता, चिकित्सा, दूरसंचार व आधुनिक जीवनशैली के तत्त्वों को लाने का प्रयास है, वहीं यह देश विकास को संतुलित करने व सभी को समान अवसर प्रदान करने के लिए संघर्ष कर रहा है।

विकास के मार्ग में आने वाली संरचनात्मक व सांस्कृतिक बाधाओं के परिणामस्वरूप परस्पर विरोधी राजनीतिक आख्यान पैदा किये हैं। वर्ष 1990 में पेरू ने आर्थिक उदारीकरण को अपनाते हुए निवेश को बढ़ावा देकर देश की अर्थव्यवस्था के तकनीकी प्रबन्धन की और ध्यान लगाया। इस अवधि के दौरान देखी गई स्थिर मुद्रास्फ़ीति दर व

लगातार बढ़ती जीडीपी तथा व्यापारिक भागीदारी उल्लेखनीय है। कुछ राजनीतिक दलों ने तात्कालिक आर्थिक उत्कर्ष को देखते हुए उदारीकरण को और लचीला करने की मांग भी की जबकि अन्य दलों ने इससे उत्पन्न असमानता पर ध्यान केन्द्रित करते हुए पुनर्वितरण की योजनाओं को लागू करने के लिए दबाव बनाया जो कि दक्षिणी अमेरिकी शैली के समाजवाद के अनुरूप थीं। यह वैचारिक टकराव देश के भविष्य को काफी हद तक प्रभावित करेगा।

सन् 2012 में कुछ वकीलों, अर्थशास्त्रियों ओर व्यापारियों के एक छोटे से समूह ने मिलकर एक संगठन तैयार किया, जिसका नाम था - एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू। पूर्व में इसे कॉन्ट्रिबेंटिस पोर रेस्पेटो को नाम से जानते थे। इस संगठन ने टैक्स देने वाले पेरूवासियों के अधिकारों की वकालत करते हुए टैक्स के बदले गुणवत्तापूर्ण सेवाओं की मांग की। यह अत्यावश्यक मांग उस समय सामने आई जब पेरू विकास की राह पर था और केन्द्रीय सरकार का कोष भी वृद्धि की और अग्रसर था।

यथोचित विकास नीति को समझने के अभाव में अरबों डॉलर बर्बाद हो चुके थे। ऐसे में एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने इस विकराल समय में उठे साधारण से प्रश्न का उत्तर देने की पहल की, 'देश के विकास व सभी नागरिकों की भलाई हेतु अधिक से अधिक निवेश कैसे प्राप्त कर सकते हैं?'

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के प्रमुख शोधकर्ता 'जुआन जोसे गार्सिया' (जो आरम्भ से ही इस संस्थान के साथ थे) ने व्याख्या की, 'पेरू की इन समस्याओं की जड़ पेरू के दोषपूर्ण संस्थान हैं, जो अनुसंधान करने व समाधान करने के अवसर भी प्रदान करते हैं। 'गार्सिया' ने मुक्त बाजार के प्रति अपने जुनून का श्रेय उस अनुभव को दिया जो उसने किशोरावस्था में स्टॉक मार्किट में काम करते हुए और विश्वविद्यालय में पढ़ते हुए हासिल किया था। इस समय उन्होंने ऑस्ट्रियन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में जाना था। गार्सिया एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के चार पूर्णकालिक कर्मचारियों में से एक थे।

'अपने छोटे आकार के कारण संस्थान को लचीला व कुशल होना चाहिए जो कि एक संस्थान की कूटनीति की मांग है।' – यह विचार 'जोसे इग्नेसियो बटेटा ने प्रस्तुत किया जो दो साल पहले ही एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के अध्यक्ष बने थे। उनके पास अन्य गैर-लाभकारी संस्थानों में अग्रणी काम करने का अनुभव भी था। उन्होंने व्याख्या करते हुए कहा, 'एक तरफ हमें बुद्धिमता से संसाधनों का उपयोग करना होगा, तो दूसरी तरफ भविष्य की सफलता हेतु कुछ जोखिम भी उठाने होंगे।'

संस्था के मुताबिक समाधान के तौर पर एक अन्य मार्ग यह भी था कि अन्य गैर-लाभकारी संगठनो से कार्यकारी साझेदारी करना ताकि लेखांकन, मानव संसाधन, टैक्स व अन्य

कागजी कार्यवाही में सहयोग मिल सके। 'गार्सिया' ने लिखा, 'एक शोधकर्ता के रूप में, इन परिवर्तनों ने मुझे खुला समय प्रदान कर दिया। पहले मैं फेसबुक सन्देश बनाने में ही जुटा रहता था। अब मैं विशेष रूप से अपने शोध पर ध्यान केन्द्रित कर सकता हूं।'

अपनी संगठनात्मक कुशाग्रता के अतिरिक्त एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू अपनी अनूठी पहचान के लिए भी जाना जाता है। पेरू में यह करदाताओं का एकमात्र ऐसा संगठन है जो कि सरकारी एवं व्यावसायिक दोनो क्षेत्रों से स्वतंत्र है जिस कारण मीडिया में भी इसके कार्यों व योजनाओं के प्रति रुचि उत्पन्न हुई, जिसका रेडियो, टेलीविज़न प्रिंट मीडिया में और ऑनलाइन भी सैकड़ों बार उल्लेख किया गया। इस व्यापक प्रचार के चलते नीति-निर्माताओं द्वारा एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के नीति विकास विचारों को बल दिया गया और अपने पक्ष को प्रभावशाली ढंग से रखने पर उनका स्वागत किया गया।

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू का मूल लक्ष्य पेरू में मुक्त उद्यम को बढ़ावा देना है। उनके सारे शोध और विश्लेषण पेरू वासियों के जीवन को प्रभावित करने वाले सार्वजनिक और प्राइवेट क्षेत्र के परस्पर प्रभाव के गिर्द घूमते हैं। छोटी व लचीली होने के कारण टीम ने लक्ष्यपूर्ति हेतु विभिन्न साधनों जैसे मूल अनुसंधान, साझेदारी और यहां तक कि कार्टूनों का भी उपयोग किया।

परियोजना आख्यान

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने एटलस नेटवर्क को अपनी नीतियों का खुलासा करते हुए बताया कि उन्होंने लेवरेजिंग इंडाइसेस फॉर फ्री इंटरप्राइस (लाइफ) परियोजना के लिए रणनीतियां कैसे तैयार कीं। शोधकर्ताओं ने वर्तमान सरकार की योजनाओं को एवं वैश्विक सूचकांक में पेरू के दुर्बल क्षेत्रों को खंगाला। इसके अलावा विशेषज्ञों का आश्रय लेते हुए समाज के महत्वपूर्ण विषयों को सूचीबद्ध किया। इन सब को मिला-जुलाकर जो एक तत्त्व उभर कर सामने आया, वह था : 'बुनियादी ढांचा'। अत:एव उन्होंने सबके लिए एक बुनियादी ढांचे के आधार पर एक परियोजना का शुभारम्भ किया जिसका शीर्षक था – 'सबके लिए आधारभूत ढांचा', जिसका उद्देश्य छोटे-छोटे क्षेत्रों के साथ साथ दूरसंचार क्षेत्र व जल प्रबन्धन में बदलाव लाना था। इसे विश्व आर्थिक मंच की 'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक रिपोर्ट' के अनुसार चिन्हित सुधारों के लिए रूपांकित किया गया था।

आधारभूत ढांचा वह नींव है जिस पर अर्थव्यवस्था का निर्माण होता है और सरकार इसकी वृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पेरू में यह विशेष रूप से सत्य है क्योंकि यहां के अपरिभाषित संस्थानों ने बाजार आधारित लोकहित के प्रावधानों पर रोक लगा दी थी।

इससे एक दुविधा उत्पन्न हो गई क्योंकि विश्व आर्थिक मंच के अनुसार पेरू में व्यवसाय करने में सबसे बड़ी बाधा वहां का अक्षम अधिकारी वर्ग है। इसके अतिरिक्त अप्रयाप्त आधारभूत ढांचा तथा भ्रष्टाचार भी बड़ी समस्या है।

पिछले 20 वर्षों में 'लीमा' की जनसंख्या में 50 प्रतिशत की वृद्धि हुई, जिससे बुनियादी ढांचे के विकास की स्थिति और भी खराब हो गई तथा सार्वजनिक निवेश शहरी क्षेत्रों तक सीमित हो गया, जिसके कारण ग्रामीण क्षेत्र विकास की दौड़ से बाहर हो गए।

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू का लक्ष्य अन्तर्निहित पूंजी को मुक्त करके इस स्थिति को बदलना तथा निजी क्षेत्र को विकास को गति देने वाले समाधान के रूप में प्रस्तुत करना था। 'बटेटा' कहते हैं, 'हमने (पीपीपी) पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप योजना को स्थापित करने की कोशिश की है। यह दो संसारों के सम्मिलन की तरह था, जिसमें जनता से टैक्स द्वारा धन एकत्रित करके बाजार प्रक्रिया के माध्यम से जनता को अनेक सुविधाएं उपलब्ध करवाना था।'

इस परियोजना के निम्न लक्ष्य थे :-

- प्रमुख जिलों में सैल टावरों की स्थापना के लिए नागरिक संगठनों व स्थानीय सरकारों के विरोध को कम करना।
- जलाशयों को सुरक्षित करने के लिए सार्वजनिक स्वामित्व वाली कम्पनियों के स्थान पर पीपीपी कम्पनियों को बढ़ावा देने के लिए जनता को जागरूक करना।
- पीपीपी पुनर्निर्माण प्रक्रिया को बढ़ावा देने के लिए इस तथ्य को प्रतिस्थापित करना कि पीपीपी कम्पनियों की बुनियादी परियोजनाएं नैतिक मानकों के अनुरूप हैं।
- राजमार्ग पुनर्निर्माण में पारदर्शिता लाने वाली योजना तैयार करना क्योंकि यहां पर सबसे अधिक सार्वजनिक धन का उपयोग होता है।

पिछले दस वर्षों में मोबाइल फोन नेटवर्क की पहुंच 30 प्रतिशत से बढ़कर लगभग 100 प्रतिशत तक हो गई। विशेष तौर पर उन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां लोग इस डर से एंटिना का विरोध करते थे कि इसके स्थापन से कैंसर का रोग फैलता है। विस्तार की इस तेजी ने सबको आश्चर्य में डाल दिया है।

इस विस्तार में गुणवत्ता का अभाव है। यद्यपि देश के अधिकांश भाग में नेटवर्क की पहुंच तो है परन्तु धीमी गति व विश्वसनीयता का अभाव होने के कारण लोग इसका उतना लाभ नहीं उठा पाते। इस बिन्दु पर प्रकाश डालते हुए एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने एक रिपोर्ट में बताया कि जहां टोकियो में एक मिलियन लोगों के लिए 10,112 एंटिना हैं, वहीं लीमा में एक मिलियन लोगों के लिए 289 एंटिना स्थापित किए गए हैं।

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने दूरसंचार सुधारों को बढ़ाने के लिए एक अग्रगामी दृष्टिकोण अपनाया।

सबसे पहले उन्होंने कई अध्ययन प्रकाशित किए, जिनमें सरकार के अधिनियमों व नगरपालिका के उन कार्यों का वर्णन था जो सैल टावर की स्थापना में बाधा बनते हैं। उन्होंने 42 स्थानीय सरकारों के कार्यों का विश्लेषण किया और अपने निष्कर्षों को वेबसाइट पर एकत्रित कर उसे सोशल मीडिया अभियान के साथ जोड़ दिया।

दूसरे एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने दूरसंचार मंत्रालय के साथ साझेदारी करके दूरदराज के पहाड़ी क्षेत्रों का दौरा किया ताकि नेटवर्क का विस्तार किया जा सके तथा स्थानीय लोगों की भ्रान्तियों व भ्रमों को दूर किया जा सके। गार्सिया कहते हैं, 'पेरू में बहुत से लोग सैल टावर से डरते थे। उनका डर था कि उससे कैंसर रोग होगा व उनकी जमीनों की कीमत कम हो जाएगी।' इस अभियान के लिए एक नारा बनाया गया, 'अधिक एंटिना, बेहतर संचार'।

इन प्रयासों को सर्वव्यापी सराहना नहीं मिली। कई अन्तर्देशीय क्षेत्रों में रहने वाले तथा स्थानीय भाषा बोलने वाले पेरू वासियों ने एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कीं। कुछ शहरी क्षेत्रों ने तो अपने द्वार उनके लिए खोल दिए लेकिन कुछ ने तो टीमों को कस्बों से खदेड़ दिया। इसे याद करते हुए गार्सिया कहते हैं, 'यह सब बहुत डरावना था।' यह परियोजना तब तक क्रमिक प्रगति करती रही जब तक प्राकृतिक आपदा 'अल नीनो कोस्ट्रियो' ने पेरू को बर्बाद नहीं कर दिया।

वर्ष 2017 के आरम्भ में पेरू ने व्यापक बाढ़ व भूस्खलन का सामना किया, जिसमें 100 से अधिक लोग मारे गए। उसका पेरू की अर्थव्यवस्था पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा और नीति सुधार घुटनों के बल आ गए। परिणामस्वरूप एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू की परियोजनाएं पटरी से उतर गईं क्योंकि जनता का ध्यान दूसरी और चला गया था। लेकिन इसने एक अप्रत्याशित अवसर भी प्रदान किया। क्योंकि देश का अधिकतर बुनियादी ढांचा तूफान में नष्ट हो गया था इसलिए 'बटेटा' के अनुसार 'यह नीति-निर्माताओं के साथ पुनर्निर्माण की चर्चा का सुनहरा अवसर था।'

पेरू के 9 मिलियन लोगों के पास पेयजल की सुविधा नहीं थी। जल प्रबंधन सार्वजनिक कंपनियों द्वारा किया जाता था जो कि ग्रामीण सरकार के नेताओं द्वारा नियुक्त की जाती थीं। इन कंपनियों पर किसी प्रकार की बाजारी स्पर्धा का दबाव नहीं था अत: उनके खराब काम के कारण पेरूवासी पीड़ित थे। बटेटा ने बताया, 'भाई-भतीजावाद के कारण हम पानी का प्रबंधन निजी क्षेत्रों को सौंपने में असमर्थ रहे।'

आगामी शोध में एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने पाया कि व्यक्तिगत स्तर की प्रक्रिया को लक्षित करके जल प्रबंधन उद्योग में अपने पांव जमाए जा सकते हैं। उन्होंने

पानी की स्वच्छता को मुद्दा बनाया, जिसे स्थानीय सरकारों व सार्वजनिक कंपनियों द्वारा अक्सर अनदेखा किया जाता था।

प्राकृतिक आपदा 'अलनीनो कोस्टेरो' ने इस मुद्दे को और भी अधिक बल प्रदान किया क्योंकि जल संयंत्र अत्यधिक भर चुके थें और सार्वजनिक कंपनियों के पास इसको संभालने का कोई प्रबंध नहीं था। अवसर का लाभ उठाते हुए एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने पीपीपी को पानी के शोधन की अनुमति देने के अभियान का समर्थन शुरू किया। 'गार्सिया' के अनुसार, 'एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के शोध में हमने यह साबित किया कि बहुत से जलीय उपक्रम कर्जे में डूबे हुए थे।'

तात्कालिक आवश्यकता तथा अनुसंधान पर आधारित समर्थन ने केन्द्रीय सरकार को बाध्य किया कि वह जल कंपनियों को दिवालिएपन से निकालने के लिए विशेष प्रक्रिया अपनाएं तथा कोई ऐसा रास्ता निकाले जिससे निजी कंपनियों को जल प्रबंधन में बोली लगाने की अनुमति मिले। इसके परिचालन में समय लग सकता है लेकिन प्रक्रिया आरम्भ हो जानी चाहिए। एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू आशावादी है। बटेटा लिखते हैं, 'हमारी सबसे महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही कि हम नीति सुधारक प्राधिकारी बन गए थे।'

जलीय बुनियादी ढांचा व अन्य क्षेत्रों में एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू की धीमी प्रगति का कारण लोगों द्वारा पीपीपी का पक्ष न लेना भी था। जिस समय लाइफ परियोजना आरम्भ हुई उस समय ब्राजील में एक भ्रष्टाचार काण्ड सामने आया, जिससे पूरा लैटिन अमेरिका प्रभावित हुआ। ऑपरेशन कार वॉश नाम का यह घोटाला एक व्यापक भ्रष्टाचार योजना थी, जिसमें एक प्राइवेट निर्माण कम्पनी को ठेका देने के लिए सरेआम रिश्वत ली गई थी। इससे पीपीपी की प्रतिष्ठा को विश्व स्तर पर धक्का लगा था।

इस चुनौती को एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के लिए अप्रत्याशित थी। बटेटा लिखते हैं, 'आरम्भ में हम अनुभवहीन थे, हम अंदाजा ही न लगा सके कि पीपीपी भ्रष्टाचार के किस स्तर तक गिर सकती है।' अब उन्होंने अपनी योजनाओं के क्रियान्वन हेतु विशेष प्रयास व संसाधन प्रयोग किए। उनके इस प्रयास ने यह दिखाया कि एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू अपनी लाभकारी योजनाओं को दर्शाने के लिए एड़ी चोटी तक का जोर लगा सकती है।

पीपीपी के प्रवक्ता एवं पर्यवेक्षक होने के रूप में कार्य करने से एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने दोनों तरफ के दुराचार को कम किया तथा अपनी पहुंच व अनुसंधान के आधार पर सरकार को पीपीपी को सार्वजनिक वस्तुओं के मुक्त उद्यम की मंजूरी देने के लिए बाध्य किया। इसके साथ साथ अन्य व्यावसायिक समुदायों को भी जांच के घेरे में लाया गया व उनकी गतिविधियों पर नज़र रखी जाने लगी, जिससे भ्रष्टाचार के अवसर कम हो गए, पकड़े जाने व दण्डित होने की सम्भावनाएं बढ़ गईं। इस तरह एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस

डेल पेरू ने अपने आप को बुनियादी ढांचा तैयार करने वाले निजी संस्थानो के पक्ष में खड़े रहने के लिए तैनात किया जो कि लाइफ परियोजनाओं के लिए सीमाओं से परे जाकर भी कार्य कर सकती थी।

सरकार व व्यावसायिक क्षेत्र दोनों का एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के अनुसंधानों का उपयोग अपने लिए करने की चेष्टा उसकी उभरती स्थिति में बाधक बन रहा था। नीति-निर्धारक उनके शोध पर विश्वास करने और उसे नीति विकास प्रक्रिया में शामिल करने लगे। बेटेटा ने खुलासा किया, 'वे रिपोर्ट लिखने और कानून बनाने में हमारी मदद मांगने लगे। प्राइवेट कम्पनियाँ हमें साझीदार के रूप में देखने लगीं, वे भी हमें परामर्शदाता के रूप में रखना चाहतीं थीं।' प्रत्येक मामले में, एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू का सबसे विशिष्ट गुण – इसकी बौद्धिक स्वतंत्रता – खतरे में है।

संगठन ने इस चुनौती को भी चातुर्य से हल किया, सहकारी संस्थानों में संलग्न होने की रुचि दिखाने के साथ-साथ, स्वतंत्रता के महत्व से भी अवगत करवाया। इसने उनकी अन्य योग्यताओं को भी परिष्कृत किया जैसे कि संचार। इसने उन्हें उन चुनौतियों के लिए आकस्मिक रूप से तैयार रहने में मदद मिली जो गहरी पैंठी सांस्कृतिक संभावनाओं में उभर रही थीं ।

जबकि पेरू ने पिछले कुछ दशकों से काफी हद तक बाजार उन्मुख नीतियों को बनाए रखा है लेकिन राजनीतिज्ञों ने बाजार संस्थान विकसित करने में नगण्य भूमिका निभाई। इस विरोधाभास के कारण बौद्धिक मतभेद पैदा हो गया। पेरूवासी यद्यपि समाजवाद में विश्वास रखते थे तथापि उन्होंने बाजार के सुधारों का गुणात्मक लाभ उठाया। जबकि लोगों की यह धारणा थी कि बाजार पेरू के फूजीमोरी और चिली के पिनोशेत के सत्तावादी शासन का ही प्रतिबिम्ब है और उन्हीं की तरह निर्दयी व कठोर है।

नागरिक संगठनों की तरह ही बाज़ार सिद्धांतों के अंतर्गत धन में बढ़ोतरी व पहुंच के कारण सत्ता में वृद्धि होती है। बटेटा व गार्सिया को डर था कि देश पुन: अधोगति की और जा सकता है। वे वस्तुत: उस नई पीढ़ी से चिंतित थे जो अन्य समूहों की अपेक्षा समाजवादी मूल्यों को अधिक महत्व देती थी और 2021 के चुनाव में 3 से 4 मिलियन लोगों को मतदाता के रूप में प्रभावित करने की क्षमता रखती थी।

आंकड़ों पर आधारित कार्यवाही करने को उत्सुक बेटेटा ने कहा, 'हमें अपने विचारों को भावनात्मक और प्रेमपूर्म ढंग से प्रस्तुत करना चाहिए और एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने तुरंत इसे स्वीकार कर लिया। उन्होंने आरम्भ से ही शोध के आंकड़ों को सरल भाषा में प्रस्तुत करने को महत्व दिया। वास्तव में उनकी मजबूत पकड़ व विस्तृत पहुंच का एक परिभाषित तत्व यह भी रहा कि उन्होंने विचारों को कार्टून रूप में पेश कर उसे सरल व दृश्यमान रूप मे प्रस्तुत किया।

जनसांख्यिकी बदलाव के कारण मीडिया में भी परिवर्तन आया। इसलिए उन्होंने नवोदित पीढ़ी को लक्षित करते हुए ऐसे मीम्स तैयार किए जो उन्हें प्रभावित कर सकें। 'गार्सिया' लिखते हैं, 'मैं निजी तौर पर मूल्यांकन कर रहा हूं कि विचारों को सम्प्रेषित करने वाले साधन कैसे बनाए जाएं ताकि हम उस नवोदित पीढ़ी तक भी अपने विचार पहुंचा सकें जो समाचारपत्र नहीं पढ़ती।'

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने अपने आपको करदाताओं की प्रभावशाली समर्थक के रूप में प्रस्तुत किया। यद्यपि पेरू ने पिछले कई सालों में बड़ी-बड़ी चुनौतियों का सामना किया लेकिन 'वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक मंच' की रिपोर्ट के अनुसार पेरू ने विश्व स्तर पर अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। व्यक्तिगत आधारभूत ढांचे में अप्रत्याशित सुधार हुआ है जैसे कि मोबाइल व टेलीफोन के उपभोक्ताओं में वृद्धि व बिजली आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार।

दूरसंचार क्षेत्र में केन्द्रीय सरकार ने एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू की नीतियों का समर्थन किया, परिणामस्वरूप मंत्रालय ने समस्त देश में उनकी नीतियां पहुंचाने का काम किया। अब तक वे लगभग 30 प्रतिशत क्षेत्र तक पहुंच चुके हैं। अपने प्रभावों को और पुख्ता करने के लिए उन्होंने नागरिक समर्थक संगठनों से साझेदारी भी कर ली। सेलुलर नेटवर्क को विस्तृत करने हेतु उनकी दृढ़ता तथा पेरू के उद्योगों में नौकरशाही से उत्पन्न बाधाओं का विश्लेषण, मोबाइल धारकों की संख्या को बढ़ा रहा है।

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू का जल प्रबंधन में शोध व समर्थन तथा देश की पीपीपी के प्रति व्यवहार सम्बद्धता ने पेरू में इस चर्चा को और आगे बढ़ाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि सरकार ने 2016 में एक कानून पारित किया जो निजी कंपनियों को औपचारिक रूप से जल परियोजनाओं पर बोली लगाने की अनुमति देता है।

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने 'सबके लिए आधारभूत ढांचा' को ध्यान में रखते हुए लाइफ परियोजना आरम्भ की। वे देश के दूरदराज क्षेत्रों में भी समृद्धि लाने के लिए मुक्त उद्यम को मजबूती प्रदान करना चाहते थे। उन्हें खराब संचार परियोजनाओं का पुनर्निर्माण व परियोजना के बीच ही लक्ष्य बदलने जैसी अप्रत्याशित दुविधाओं का सामना करना पड़ा। लेकिन इस प्रक्रिया में भी संगठन ने अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखी और वह गुणात्मक अनुसंधान का मुख्य लक्ष्य ध्यान में रखते हुए तथा आपसी बातचीत के व्यवहार पूर्ण प्रयास करते हुए, जन नीतियों पर चर्चा का विश्वसनीय स्वर बन गया।

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने लाइफ परियोजना के द्वारा न केवल देश के अंतर्राष्ट्रीय रैंकिग में सुधार किया बल्कि इसने देश के युवा विशेषज्ञों को उभरने में भी मदद की। 'गार्सिया' के अनुसार, 'लाइफ परियोजना हमारी सफलता की प्रेरणा थी। इसके बिना हम कभी भी वह प्राप्त नहीं कर सकते थे जो हमारे प्राप्त किया।'

प्रमुख अन्तर्दृष्टि

सम्बन्ध बनाना

पेरू का सामाजिक व राजनीतिक वातावरण बाजार की किसी भी परिवर्तनकारी शक्ति को चुनौती प्रदान करता है। नि:सन्देह एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने दूसरों की स्थिति को समझने व विरोधियों के साथ रास्ता निकालने की पहल करने पर ध्यान केन्द्रित किया। इसके परिणामस्वरूप उसे नीति निर्माण हेतु लम्बी अवधि के आमंत्रण प्राप्त हुए।

त्वरित होना

सुनने में यह अविश्वसनीय लगता है कि एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू के पास मात्र चार पूर्णकालिक कर्मचारी थे। पर उन्होंने लक्ष्य प्राप्ति की भागीदारी बनाने में कमाल की आत्मीयता दिखाई। चाहे वह अन्य गैर-लाभकारी संस्थाओं के साथ रिकार्ड साझा करना हो या व्यापार संघ के साथ मिलकर वेबसाइट शुरू करना या फिर केन्द्रीय सरकारी मंत्रालय के साथ दूरदराज के क्षेत्रों की यात्रा करना या विश्व बैंक जैसी अंतर्राष्ट्रीय गैर-सरकारी संस्थाओं के साथ आपदा प्रक्रिया की चर्चा में शामिल होना। एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने एक सामान्य आधार खोजने तथा विभिन्न पक्षों के पारस्परिक लाभ की दिशा में काम करने में बहुमुखी प्रतिभा दिखाई।

अवसर हथियाना

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू से पहले उस देश में टैक्स देने वालों का समर्थन करने वाला कोई समूह नहीं था यदि होता भी तो उसकी सफलता संदेहास्पद थी। लेकिन एक समृद्ध समाज के दृष्टिकोण से लैस होकर एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू स्थापित हुई तथा प्राकृतिक आपदाओं तथा प्रस्तावित नीतियों से सम्बन्धित राजनीतिक घोटालों जैसी चुनौतियों का सामना किया। जब राजनीतिज्ञ यथास्थिति से संतुष्ट हुए तब एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने इसे नीति बदलाव के अवसर के रूप में देखा। यद्यपि यह बहुत मुश्किल था। किसी भी संगठन के लिए चुनौती भरे वातावरण में सीमित संसाधनों के साथ भी आशावादी बने रहना एक महान शक्ति है।

सिद्धांतों पर दृढ़ रहना

एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू करदाताओं की आवाज बनने के लिए तैयार हुई और वे अपनी उस दूर दृष्टि को सदैव समर्पित रहे। इसके बढ़ते हुए प्रभाव के हिस्सेदार बनने के लिए सरकार, वित्तीय संस्थान व व्यावसायिक घराने लालायित थे लेकिन एसोसिएशन डे

कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू अपने मूल उद्देश्य पर दृढ़ रही, जिससे इसकी प्रतिष्ठा भी बढ़ी व आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हुई।

लक्ष्य पर केन्द्रित रहना

प्रत्येक सफलता उसके शोध की गुणवत्ता पर निर्भर करती है। उन्होंने क्रियाकलापों को पुनर्गठित किया, व्यापक समूहों के साथ भागीदारी की, और बिल्कुल नए मुद्दों पर केन्द्रित हुए। लेकिन उन्होंने सदैव 'शोध की गुणवत्ता को बनाए रखा।' गार्सिया ने इस दृष्टिकोण की पुष्टि करते हुए कहा, हमने शोध में ठोस रहने का प्रयास किया ताकि हम आलोचनाओं का सामना कर सकें।

चर्चागत प्रश्न

- आपके संगठन ने किस नई चुनौती की सामना किया है? एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू को अपने अभियान के दौरान आंतरिक व वाह्य दोनों तरफ से झटकों का सामना करना पड़ा। आपके संस्थान ने इस तरह की स्थिति का सामना कब और कैसे किया? आप लड़े या भागे? किस वृत्ति की जीत हुई?
- क्या प्रशासनिक या नौकरशाही के मुद्दे आपके काम के विकास और पहुंच को बाधित करते हैं? एक सुदृढ़ भविष्य की कामना करते हुए आपका संगठन अल्पकालिक प्रदर्शन को बेहतर बनाने के लिए एक बाहरी समाधान कैसे पा सकता है?
- आपका तुलनात्मक फायदा क्या है? क्या कोई ऐसी चीज है जो आपका संगठन किसी और की तुलना में बेहतर करता है? या जो आप कभी भी करना बन्द नहीं करेंगे? यदि यह आपकी संगठनात्मक पहचान का एक अभिन्न हिस्सा है तो आप इसका अधिक से अधिक लाभ कैसे उठा सकते हैं?
- क्या आपका संगठन किसी ऐसे संगठन के साथ साझेदारी करने को तैयार होगा जो आपके साथ सहमत होने से ज्यादा असहमत हो सकता है? आप किन क्षेत्रों में इसे संभव होते हुए देख सकते हैं? यह कैसा प्रतीत होगा?
- एसोसिएशन डे कॉन्ट्रिबेंटिस डेल पेरू ने करदाताओं के लिए एक समर्थक के रूप में पहचान बना कर विश्वसनीयता प्राप्त की। जनमत हासिल करने के लिए आपका संगठन क्या सन्देश दे सकता है? क्या आपने कभी ऐसी कोशिश की है? उसका परिणाम क्या रहा या आपके अनुसार उसके क्या परिणाम हो सकते थे?

खंड 6

अनुचित कर के बोझ का विषय अवलोकन

सभी कर प्रशासकों को कराधान के मूलतत्त्वों का अवलोकन करना चाहिए। यह व्यापक होना चाहिए, इसके बोझ को समान रूप से बांटना चाहिए तथा यह किसी एक उद्योग या समूह की तरफदारी न करते हुए निष्पक्ष भी हो। अक्सर सरकारी नीतियां विशेष हितों के आग्रह पर बाजारों में हेरफेर करने व संकीर्ण परिणाम प्राप्त करने हेतु कर प्रणाली का उपयोग करना चाहती हैं।

इन प्रयासों के अनचाहे परिणाम प्राप्त होने का खतरा भी पैदा हो जाता है। जैसे कि अर्जेंटीना में कंप्यूटरों पर अतिरिक्त लगाने का उद्देश्य कुछ घरेलू कंपनियों को प्रतिस्पर्धा से बचाना था, लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि सभी लोगों को पड़ोसी देशों के मुकाबले लैपटॉप और टैबलेट पर दो-तीन गुणा अधिक दाम चुकाने पड़े। यह नीति सबकी कीमत पर कुछ को लाभ पहुंचाने में मदद करने लगी। इससे भी बदतर यह रहा कि इस उच्च कीमत की असमानता का प्रभाव सबसे अधिक निम्न आय वर्ग पर पड़ा।

कर निष्पक्षता को विचार में लाते समय बाजार को विकृत करने की नीति के अनापेक्षित परिणामों को भी ध्यान में रखना चाहिए। अधिकतर ये परिणाम निम्न आय वाली आबादी को प्रभावित करते हैं और आर्थिक अवसरों में उनकी पूर्ण भागीदारी को रोकते हैं।

इस अध्ययन के मूल संस्करण AtlasNetwork.org पर उपलब्ध हैं।

महिलाओं के राह की बाधाओं को दूर करना

एडवोकाटा इंस्टिट्यूट
श्रीलंका

भूमिका

कुछ समय पहले तक श्रीलंकाई सरकार ने महिलाओं के सैनेटरी उत्पादों पर 100 प्रतिशत से भी अधिक कर लगाया था, जिससे ये जरूरी वस्तुएं देश की अधिकांश महिलाओं की पहुंच से बाहर हो गईं। इस मुद्दे को लेकर चुप्पी और घिन के वातावरण में जब कोई भी आगे न आया तो एडवोकाटा इंस्टिट्यूट ने बहादुरी भरा कदम उठाया और बेजुबानों की जुबान बना। एडवोकाटा के इस काम से न केवल एक महत्वपूर्ण चर्चा आरम्भ हुई बल्कि सैनेटरी नैपकिन पर लगे उस अत्यधिक टैक्स को भी बहुत कम कर दिया गया, जिसने महिलाओं की अति आवश्यक वस्तु को उनकी पहुंच से दूर कर उनकी गरिमा को छीन लिया था।

एडवोकाटा इंस्टिट्यूट का श्रीलंका के संबंध में दृष्टिकोण यह है कि देश को अधिक मुक्त, खुला और समृद्ध होना चाहिए। संगठन के इस काम का उद्देश्य श्रीलंका में प्रत्येक व्यक्ति को कठिन परिश्रम करने और सफल होने के प्रचुर अवसर प्रदान करना है।

4.2 मिलियन महिलाओं वाले देश में केवल 30 प्रतिशत महिलाएं ही सैनेटरी नैपकिन का उपयोग करती हैं। बाकी की महिलाएं कपड़े और चिथड़ों का प्रयोग करती हैं जो स्वच्छता और स्वास्थ्य की दृष्टि से चिंता का विषय है। इस अन्याय का वर्षों तक किसी ने विरोध नहीं किया क्योंकि श्रीलंका में महिलाओं के मासिक चक्र को अशुद्ध व निषेध माना जाता है। मासिक धर्म के दौरान उन्हें स्कूलों व घरों में अवांछनीय समझा जाता है।

एडवोकाटा इंस्टिट्यूट ने श्रीलंका की चुप्पी वाली संस्कृति को माइक के द्वारा हटा दिया। जब तक सरकार करों पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं हुई तब तक अनुचित करों पर किए गए अभूतपूर्व शोध प्रसारित करना जारी रखा गया। एडवोकाटा इंस्टिट्यूट के प्रयासों की बदौलत श्रीलंका में महिलाओं के सैनेटरी उत्पादों पर से 30 प्रतिशत आयात शुल्क

समाप्त कर दिया गया। महिला उत्पादनों पर कुल कर पहले 101.2 प्रतिशत था जो लगभग 63 प्रतिशत तक कम हो गया। श्रीलंका के वित्तमंत्री मंगला समरवीरा ने थॉमसन रॉयटर्स फाउंडेशन को बताया कि वे सैनेटरी उत्पादों पर करों को और कम करना चाहते हैं।

एडवोकाटा इंस्टिट्यूट के कार्यों ने श्रीलंका में बदलावों को कैसे प्रभावित किया :-

- एडवोकाटा इंस्टिट्यूट इन उत्पादों पर 30 प्रतिशत आयात शुल्क समाप्त करके सैनेटरी नैपकिन को अधिक किफायती बनाने में सफल रहा।
- एडवोकाटा द्वारा किए गए शोध ने श्रीलंका में महिलाओं की कठिनाइयों को उजागर करते हुए इस मुद्दे पर प्रकाश डाला व बदलाव की आवश्यकता पर महत्वपूर्ण चर्चा छेड़ दी।

अधिवक्ताओं की कहानी यह दर्शाती है :-

- आर्थिक सुधारों की सुई आगे बढ़ाने से सांस्कृतिक कलंक के डर से प्रतीत होने वाली सीमाओं को दूर किया जा सकता हैं।
- बदलाव के लिए एक विश्वसनीय आवाज बनें।

एडवोकाटा की सफलता श्रीलंका में मुक्त बाजारों और महिलाओं के लिए एक जीत थी।

संयुक्त राष्ट्र के एक अध्ययन में पाया गया कि श्रीलंका के 60 प्रतिशत शिक्षकों का मानना है कि मासिक धर्म में रक्त अशुद्ध होता है। इस कारण 60 प्रतिशत लड़कियां मासिक चक्र के दौरान महीने में एक बार स्कूल से अनुपस्थित रहती हैं। महिलाओं को मासिक धर्म के दौरान अक्सर उनके घरों में मजबूर किया जाता है, कुछ बीमार हो जाती हैं और कुछ की मृत्यु हो जाती है। यह उनके साथ पृथकता व भेदभाव है।

संक्षेप में, महिलाओं से उनकी गरिमा छीन ली जाती है क्योंकि उनकी संस्कृति महिलाओं के प्राकृतिक मासिक धर्म से निपटना पसंद नहीं करती।

नारीत्व को लेकर आपत्तिजनक दृष्टिकोण न केवल श्रीलंकाई समाज में प्रचलित है बल्कि सरकार को महिला उत्पादों पर कर लगाने की अनुमति भी देता है।

एडवोकाटा इंस्टिट्यूट की शोध संचार प्रबन्धक 'अनुकी प्रेमचन्द्रा' के अनुसार, 'दक्षिण एशिया में महिलाओं को आमतौर पर सांस्कृतिक चुप्पी व द्वेष का सामना करना पड़ता है, (एक राष्ट्र के रूप में) हम उस स्थान से बहुत दूर हैं, जहां हम कभी थे। लेकिन हमें बहुत लम्बा रास्ता तय करना है।' एक महिला की भूमिका अभी भी व्यापक रूप में एक देखभाल करने वाली के रूप में आंकी जाती है। इन मान्यताओं को धता बताने वाली एक ऐसी

लड़ाई है जो हमें हर रोज लड़नी पड़ती है। यद्यपि श्रीलंका दुनिया का पहला देश था, जहां एक महिला प्रधानमंत्री नियुक्त की गई। तथापि महिलाओं को आमतौर पर नेतृत्व करने वाली या राजनीतिक भूमिका में कम देखा जाता है। सम्भवत: इसीलिए सैनेटरी नैपकिन जैसी आवश्यक वस्तु पर उच्च कर होने के बावजूद किसी ने इसको चुनौती नहीं दी जब तक की अधिवक्ता संस्थान ने इसके आंकड़ों पर प्रकाश नहीं डाला।

परियोजना विवरण

एडवोकाटा जानता था कि सैनेटरी नैपकिन तक महिलाओं की सीमित पहुंच हानिकारक है, लेकिन उन्हें यह भी पता होना चाहिए था कि यह महिलाओं क्यों और कैसे प्रभावित कर रहा है।

लड़ाई की संवेदनशीलता के कारण संगठन उन मानवीय कहानियों को बताने में असमर्थ रहा जो यह दर्शाती थीं कि मुद्दा कितना महत्वपूर्ण है। यूनिसेफ़ और अन्य समूहों की सहायता से उनके पास मासिक धर्म के प्रति लोगों का दृष्टिकोण व स्कूल न जा पाने वाली लड़कियों के आंकड़े उपलब्ध थे परन्तु उन्हें इसके बारे में और अधिक जानने की आवश्यकता थी।

अन्तत: अधिवक्ताओं ने यह जानने के लिए उपभोक्ता सर्वेक्षण करवाया कि कैसे सैनेटरी नैपकिन तक महिलाओं की सीमित पहुंच उनको प्रभावित कर रही है और उन्हें ज्ञात हुआ कि कम आय वर्ग की 50 प्रतिशत महिलाएं सैनेटरी नैपकिन का उपयोग ही नहीं करती।

सैनेटरी नैपकिन के विकल्प जैसे कपड़े व चिथड़े बहुत अस्वच्छ व असुरक्षित हैं। लेकिन सांस्कृतिक कलंक के कारण हमारे नीति-निर्माता इस बात से भी अनभिज्ञ हैं कि उनके आसपास की महिलाओं का प्रजनन स्वास्थ्य इन अस्वस्थ विकल्पों से कैसे दुष्प्रभावित हो रहा है। कपड़े-लत्ते की अस्वच्छता के कारण सर्वाइकल कैंसर हो सकता है जो श्रीलंका की महिलाओं में दूसरा बड़ा आम पाया जाने वाला कैंसर है। एचपीवी सूचना केन्द्र के अनुसार ताजा अनुमान बताते हैं कि हर साल 1,721 श्रीलंकाई महिलाओं में सर्वाइकल कैंसर का पता चलता है और 690 महिलाएं इस रोग से मर जाती हैं।

प्रेमचन्द्रा के अनुसार, 'ऐसी आवश्यक वस्तु पर लगाया जाने वाला भारी कर यह दर्शाता है कि वास्तविक दुनिया में महिलाओं की क्या स्थिति है। हम एक ऐसी संस्कृति में पले-बढ़े हैं जहां मासिक धर्म और स्त्रीत्व जैसे विषयों को स्वीकार करने की बजाय छिपाया जाता है। ऐसे में इस तरह के उच्च करों का बोझ लादना महिला की गरिमा के साथ अन्याय करना है।'

तथ्यों और जानकारी से ओत प्रोत एडवोकाटा यह बताने में सक्षम रहा कि क्यों स्त्रियों के उत्पादों पर लगाए जाने वाले करों में सुधार की आवश्यकता है।

श्रीलंका में महिलाओं का संस्कृति के नाम पर उत्पीड़न सिर्फ स्त्रियों के उत्पादों पर लगाए जाने वाले करों तक सीमित नहीं है इससे देश की अर्थव्यवस्था भी बुरी तरह प्रभावित होती है। इससे महिलाओं का विकास भी बाधित होता है। उदाहरण के तौर पर रात को 8 बजे के बाद महिलाओं को काम करने की मनाही है। महिलाओं की स्वतंत्रता और जीवनयापन के अधिकार को प्रतिबंधित करना श्रीलंका की आधी आबादी के लिए अविश्वसनीय रूप से हानिकारक है और एडवोकाटा महिलाओं की ही आवाज बनकर आगे आए।

एडवोकाटा इंस्टिट्यूट अपने कार्यों में इतना सक्षम इसलिए है क्योंकि इसकी संस्था की अधिकांश कर्मचारी महिलाएं हैं।

एडवोकाटा के निदेशक व सह संस्थापक 'डीन जयमाने ने कहा, 'मुझे लगता है कि हमारे कर्मचारियों में शामिल महिलाओं ने इस मुद्दे को लम्बे समय तक बनाए रखने में मदद की है।'

'संस्थान में कर्मचारियों की विविधता के परिणाम स्वरूप वे अलग प्रकार से सोच पाते हैं। उदाहरण के लिए डायपर पर उच्च करों से संबंधित शोध के चलते स्त्रियों के उत्पादों पर उच्च करों की समस्या सामने आई।'

जयमाने बताते हैं, 'लगभग दो साल पहले जब मैं पिता बना तो मैंने देखा कि श्रीलंका में डायपर अमेरिका की तुलना में अधिक महंगे थे। इतने महंगे कि माताओं की एक मंडली गोपनीय ढंग से डायपरों की तस्करी करती थी। जो शोधकर्ता इस दिशा में कार्यरत थे उन्होंने पाया कि डायपर पर 62 प्रतिशत कर था, इसी के चलते यह मालूम हुआ कि सैनिटरी नैपकिन पर 100 प्रतिशत कर था। हमने कुछ मीडिया संगठनों के साथ तथ्य साझा किए और वहीं से मुद्दे ने तूल पकड़ा।

प्रेमचन्द्रा जैसी कुशल महिला नेतृत्वकर्ता द्वारा महिलाओं के आर्थिक मुद्दे का समर्थन स्वाभाविक रूप से सही रहा। इससे एडवोकाटा को सुधारों की लड़ाई में अगुवाई मिली। जयमाने कहते हैं, 'इससे हमने यह सीखा कि यदि किसी मुद्दे के लिए संगठन के पास व्यक्तिगत प्रतिध्वनि हो तो सफलता की सम्भावना बहुत अधिक होती है।'

वे आगे कहते हैं, 'मुझे वास्तव में लगता है कि स्टाफ में विविधता होने से फर्क पड़ता है यह सोचने के नए ढंग व समस्याओं के विभिन्न समाधान खोजने में सहायक होता है।'

श्रीलंका में स्त्रियों के उत्पादों पर उच्चतम कराधान की खबर से मीडिया पर नाराजगी का तूफान उमड़ आया।

एडवोकाटा के अभियान के संदेशों को प्रसारित करने के लिए डिजिटल पहुंच बनाने और विकसित करने का प्रयास इस संस्थान के लिए नया क्षेत्र था। एक तो इस नए माध्यम का लाभ उठाने का समुचित ज्ञान इस टीम के पास नहीं था, दूसरी बड़ी चुनौती लक्षित दर्शकों को पहचानने की भी थी ताकि उनके प्रयास विफल न हों।

सोशल मीडिया इस लड़ाई में महत्वपूर्ण हो गया क्योंकि अनुसंधान पर आधारित अन्य पारंपरिक प्रयास फलदायी नहीं थे। लेकिन जब एडवोकाटा इस मुद्दे को लोगों तक ले गए तो उनकी धारणाएं ही बदल गईं। एक बार एडवोकाटा उन श्रोताओं को खींचने में कामयाब हो गए जो स्त्रियों के उत्पादों पर कर के बारे में सोचते थे तो उन्हें लगा कि अब वे श्रोताओं को चित्रों, संक्षिप्त संदेशों व वीडियो के माध्यम से आग में घी डाल सकते हैं और यह लोगों को खुद की वकालत करने के लिए प्रेरित करेगा।

उनकी रणनीति सफल रही। सार्वजनिक आक्रोश के कारण सरकार के अधिकारियों ने नीतिगत प्रभारी को मुद्दे की जांच करने के लिए कहा। अन्त में उन्होंने कर को समाप्त कर दिया।

एडवोकेटा इंस्टिट्यूट के सीओओ धननाथ फर्नैन्डो ने कहा, 'इस एकल सुधार के माध्यम से बाजार में व्यापार की स्वतंत्रता आएगी, जिससे महिलाओं की स्वच्छता सम्बन्धी सेवाओं व वस्तुओं की उपलब्धता में और सुधार होगा। महत्वपूर्ण यह है कि इससे महिलाओं में मासिक धर्म के प्रति स्वच्छता का भाव पैदा होगा, जो श्रीलंका की जनसंख्या का 52 प्रतिशत हिस्सा हैं।'

अधिवक्ताओं द्वारा सैनेटरी नैपकिन पर कर कम करने के लिए लड़ी गई लड़ाई इस देश की आर्थिक स्वतंत्रता में महत्वपूर्ण कदम है।

चर्चागत प्रश्न

- क्या आपके देश में अल्पसंख्यक आबादी है जो सरकार की गलत नीतियों का नुकसान भुगत रही हैं? आपके पास उनकी विश्वसनीय आवाज बनने के लिए क्या अवसर हैं?
- आप उस मुद्दे से सम्बन्धित एक आकर्षक संदेश कैसे तैयार करेंगे?
- आप कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि आपकी टीम में शामिल अलग-अलग क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से आपकी टीम को फायदा होगा?

प्रतिगामी कर प्रणाली की वापसी

लिपा टैक्सपेयर्स एसोसिएशन, क्रोएशिया
क्रोएशिया

भूमिका

'लिपा' क्रोएशिया में करदाताओं की प्रमुख आवाज़ है। यह प्रत्येक स्तर पर सरकार के प्रति उनके हितों का समर्थन करती है। क्रोएशिया में करों की दर यूरोपियन यूनियन के औसत से 50 प्रतिशत से भी अधिक है। थिंकटैंक लिपा का मुख्य ध्येय क्रोएशिया में करों के उच्च दर के लिए जिम्मेदार सरकारी नौकरशाहों की संख्या को कम कर, सरकारी तंत्र में पारदर्शिता लाकर तथा सार्वजनिक ऋण को घटा कर जनता पर से अधिक कर के बोझ को कम करना है।

यह तीसरा साल है जब एक युवा संगठन ने क्रोएशिया के नागरिक संवाद में जोरदार प्रभाव डाला है। इस संगठन ने सरकार के प्रति लोगों का दृष्टिकोण पूरी तरह से बदल दिया, वह भी उस धरती पर जहां स्वतंत्र और लोक केन्द्रित आवाजों को सदैव अनदेखा कर दिया जाता था।

परियोजना का विवरण

लिपा एक छोटी-सी दुकान है, जिसमें मात्र एक पूर्णकालिक कर्मचारी है और मामूली-सा बजट है। इसके बावजूद धैर्य और कुशलता के साथ इस संगठन ने क्रोएशिया के नए प्रॉपर्टी कर आलेख को खत्म करवा दिया। इस संगठन द्वारा संचालित जनता की प्रतिक्रिया इतनी उन्मुक्त व सशक्त थी कि 2017 में प्रधानमंत्री अन्द्रेज़ प्लेनकोविक को नया कानून लागू करने से पहले ही निरस्त करने के लिए बाध्य होना पड़ा। भारी टैक्सों के बोझ को लेकर जनता का रोष इतना उग्र था कि क्रोएशिया में किसी भी प्रकार का टैक्स वृद्धि कानून पास करवाना लगभग असम्भव हो गया।

लिपा के अभियान ने पूरा देश हिलाकर रख दिया। इसने सक्रियता और स्वतंत्रता की अवयक्त इच्छा के प्रति जागरूक किया, जिसे कईं वर्षों से सार्वजनिक रूप से व्यक्त नहीं किया गया था। 'लिपा' के स्वयंसेवकों ने प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध में अभियान चलाया और शानदार परिणाम प्राप्त किया।

- पहले 24 घण्टों में 'लिपा' ने याचिका के लिए 20,000 हस्ताक्षर एकत्रित कर लिए और दो सप्ताह में यह संख्या 50,000 तक पहुंच गई। जब अधिकारियों ने नागरिकों से एक फार्म में प्रॉपर्टी का ब्योरा मांगना आरम्भ किया तो यह संख्या 1,46,000 से भी अधिक हो गई जो कुल जनसंख्या का 3.5 प्रतिशत थी।
- 100 से अधिक समाचार घराने प्रॉपर्टी टैक्स निरस्त करने के अभियान में शामिल हो गए। अधिकारियों के लिए नागरिकों के इस जमीनी अभियान को अनदेखा करना असम्भव हो गया।
- 14 सितंबर, 2017 को क्रोएशियन सरकार ने पूरे देश में से प्रॉपर्टी टैक्स पूरी तरह निरस्त कर दिया। यद्यपि इसके बाद भी टैक्स लागू करने के कई प्रयास हुए तथापि जन तक विरोध के कारण नए टैक्सों को लागू करने में सरकार असमर्थ रही।

लिपा की इस अभूतपूर्व सफलता में अनेक सबक थे जो स्वदेश में अच्छा काम करने वाले मुक्त बाजार के समर्थक संगठनों को मार्गदर्शन दे सकते थे। संगठन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स अभियान को हराए जाने ने एक नई अन्तर्दृष्टि प्रदान की :-

- जन-आन्दोलन तैयार किये जाए।
- खराब टैक्स नीति के विरुद्ध लड़ने के लिए जनता की भावनाओं को उभारा जाए व वातावरण तैयार किया जाए।
- श्रोताओं को समझ में आने वाली भाषा में बात की जाए।

1991 में स्वतंत्र देश बनने के पश्चात क्रोएशिया ने धीरे-धीरे बाजारी सुधार देखना आरम्भ कर दिया था, पर यह आसान नहीं था। ।

साम्यवाद से अलग हो कर क्रोएशिया के स्त्री-पुरुष नवीन उदारवाद का उपयोग कर रहे थे, और प्रॉपर्टी में निवेश कर रहे थे। लगभग सभी आय वर्ग के 90 प्रतिशत क्रोएशियन किराये के घरों की बजाय अपनी जमीनों पर रह रहे थे। अपना घर होना निवेश का एक सशक्त साधन बन गया तथा परिपक्व जनता के लिए भविष्य को सुरक्षित करने का दीर्घकालीन साधन भी।

ये प्रॉपर्टी टैक्स इस व्यवस्था को तहस-नहस कर देता। लेकिन लिपा की बहादुर टीम इस विषाक्त नीति के विरुद्ध देश को एकजुट करने के लिए खड़ी हो गई। स्वतंत्र क्रोएशिया के इतिहास में पहली बार सभी नागरिकों की एक ही आवाज थी।

यद्यपि लिपा एक विशिष्ट टैक्स को खत्म करवाने के लिए जिम्मेवार थी, लेकिन उसकी असली सफलता देश को जोड़ना तथा आशा प्रदान करना था, जिससे वे साम्यवाद के खिलाफ आवाज उठा सकें तथा टैक्सों के विरुद्ध लड़ सकें।

क्रोएशिया जनसांख्यिकी संकटों से घिरा है। 1990 में अपनी जनसंख्या को शिखर पर 4.8 मिलियन देखने के पश्चात इस देश ने हर साल अपनी जनसंख्या को कम होते देखा है। जैसे कि क्रोएशियन अपना देश छोड़कर हरे भरे चारागाहों के लिए जर्मनी, आयरलैंड तथा अन्य यूरोपीय देशों में चले गए।

इसके अलावा मृत्यु दर भी जन्म दर से आगे निकल गई। आज क्रोएशिया की जनसंख्या 4.2 मिलियन है। वर्ष 2017 में लगभग 20,000 मौतें हुईं तथा 57,000 क्रोएशियन जर्मनी में जाकर बस गए।

क्यों? नुकसानदायक कर व कमजोर अर्थव्यवस्था। क्रोएशिया में सर्वोच्च व्यक्तिगत आयकर 40 प्रतिशत है और यह 2009 के 56 प्रतिशत के शिखर से नीचे आया है। आयकर आज भी एक महत्वपूर्ण समस्या है वह भी तब जब इसे 25 प्रतिशत सेल टैक्स के साथ जोड़ दिया जाता है। यहां बेरोजगारी की दर 13 प्रतिशत है, जिसमें 40 प्रतिशत युवा हैं जो इस देश में अपनी जड़ें जमाना चाहते हैं और सुनहरा भविष्य बनाना चाहते हैं पर ऐसा निकट भविष्य में होता दिखाई नहीं पड़ता।

वर्ष 2016 में नवीन कर सुधार ने एक झलक पेश की, कि कैसे अच्छे के लिए चीजों में बदलाव लाया जा सकता है। वर्ष 2016 के अन्त तक आते-आते क्रोएशियन संसद ने व्यक्तिगत व कार्पोरेट आयकर में भारी कटौती का बिल पेश किया तथा सरकार ने इसे पास भी कर दिया। यह एक अच्छी खबर थी परन्तु इसमें भी एक झमेला था। इस कटौती के साथ नई विधानसभा ने क्रोएशिया में एक ऐसा प्रॉपर्टी टैक्स लगा दिया जो देश का विनाश कर सकता था। यहां लगभग 90 प्रतिशत क्रोएशियन अपने घरों में रहते हैं, अर्थात अमीर-गरीब सबका दर्द समान था। पूर्व साम्यवादी राज्य में घर खरीदना पूरे देश भर में सबसे बड़ा निवेश था क्योंकि उस प्रणाली में आय बचाने के अन्य साधन बहुत कम थे।

'लिपा' संसद द्वारा की गई टैक्स कटौती का समर्थन कर रही थी, जानती थी कि इसका तत्काल असर होगा इसलिए उन्होंने एक अभिनव प्रयोग करते हुए तुरंत प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ हल्ला बोल दिया। जिस प्रॉपर्टी टैक्स को योजना अनुसार जनवरी 1, 2018 से लागू होना था, लेकिन मुद्दा प्रभावशाली होने के कारण संगठन ने संचार के सभी माध्यमों का प्रयोग करते हुए हर उम्र के क्रोएशियन तक अपनी पहुंच बना ली।

जनता को साथ लेकर प्रॉपर्टी टैक्स की लड़ाई में उतरने से पहले 'लिपा' ने प्रभावशाली अर्थशास्त्री 'वैल्मिर सौंजे' को क्रोएशिया के लोगों पर इस टैक्स से पड़ने वाले प्रभाव का

विश्लेषण प्रस्तुत करने को कहा। क्रोएशियन का क्या-क्या दाव पर लगा है, यह बात समझने में क्रोएशियन की मदद करने के लिए 'लिपा' ने संचार मुहिम आरम्भ कर दी।

तथ्यों से लैस होकर 'लिपा' ने यह मुहिम 18 अप्रैल, 2017 को क्रोएशिया के सारे प्रभावशाली मीडिया के समक्ष प्रेस विज्ञप्ति जारी करके आरम्भ की। प्रेस विज्ञप्ति जारी करने के अलावा टैक्स लागू करने के विरुद्ध ऑनलाइन याचिका दायर की गई। 24 घंटे के अंदर अंदर 20,000 से अधिक लोगों ने याचिका पर हस्ताक्षर कर दिए तथा योजना समाप्त होने तक एक सप्ताह में यह संख्या 50,000 तक जा पहुंची।

'लिपा' की इस सफलता और मुद्दे का प्रभावशाली रूप से उभरने का रहस्य, संगठन द्वारा अधिक से अधिक जानकारी जुटाना और उसे अभियान का रूप देकर अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना था। जानकारी का एक भी भाग व्यर्थ न जाने दिया जाता, उसे पुनः-पुनः, अलग-अलग ढंग से उपयोग में लाया जाता। उदाहरण के तौर पर मुहिम की सभी मीडिया कवरेज को फेसबुक के द्वारा बढ़ावा दिया जाता, जहां 'लिपा' के बढ़ते प्रभाव के कारण अनुसरण करने वालों की संख्या 15000 तक पहुंच गई थी।

ऐसा नहीं था कि 'लिपा' तक पहुंच रखने वाला प्रत्येक व्यक्ति सोशल मीडिया का प्रयोग करता था या समाचार केन्द्रों से जुड़ा हुआ था। इसलिए उन्होंने ईमेल एड्रेस इकट्ठे करने के लिए प्रॉपर्टी टैक्स के विरुद्ध याचिका दायर की। जैसे-जैसे हस्ताक्षर करने वालों की संख्या बढ़ती गई वैसे-वैसे ईमेल एड्रेस भी बढ़ते गए। इसका उपयोग 'लिपा' ने संपत्ति स्वामियों तक पहुंचने और उन्हें न्यूज़लेटर्स व अन्य सामग्रियां भेजने के लिये किया।

सरकार द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स लागू करने की योजना के बारे में यह मुहिम एक और नींव का पत्थर स्थापित करने के लिए जोर पकड़ रही थी। अभियान का सबसे महत्वपूर्ण दौर 2017 में आया जब स्थानीय सरकारों द्वारा क्रोएशियन नागरिकों को अपनी प्रॉपर्टी की जानकारी देने के फार्म भेज दिए गए। सरकार की इस चाल ने 1,00,000 और लोगों को इस मुहिम के साथ जोड़ दिया, जिससे सरकार पर और भी दबाव बनने लगा। क्रोएशिया के चार प्रमुख शहरों में संपत्ति स्वामियों द्वारा प्रदर्शन आरम्भ हो गए।

आखिरकार, 8 अगस्त को जनता के रोष को अनदेखा करना असम्भव हो गया। प्रधानमंत्री अन्द्रेज प्लेनकोविक ने नया प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने की शपथ ली। यह क्रोएशियन जनता की सांकेतिक जीत किन्तु 'लिपा' की महान विजय थी।

सफलता के सूत्र : डाटा के द्वारा प्रभाव मापन

- कुल 1,46,100 हस्ताक्षर एकत्रित किए गए, जिससे यह याचिका क्रोएशियन लोकतन्त्र की पहली सबसे सफल नागरिक - क्षेत्र की याचिका बन गई।

- 'लिपा' के आर्थिक प्रभाव विश्लेषण के अनुसार संगठन के द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स हटने पर प्रत्येक क्रोएशियन नागरिक 300 मिलियन कूना (50 मिलियन यू.एस. डॉलर) राज्य कोष में जमा करवाने की बजाय अपनी ही जेब में रखेंगे।
- 'लिपा' के अभियान ने राष्ट्रीय भावनाओं को टैक्स की और मोड़ दिया। प्रॉपर्टी टैक्स में हारने के बाद सरकार ने नए टैक्स लगाने की कोशिश की किन्तु लोगों के विरोध के कारण उन्हें उसे वापस लेना पड़ा। इसमें विशेष योगदान उन लोगों का रहा जिन्होंने याचिका पर हस्ताक्षर किए थे, उन्हें अभी तक संगठन के न्यूज़लेटर्स प्राप्त हो रहे थे। प्रॉपर्टी टैक्स अभियान के उपरान्त लिपा ने चार नए टैक्सों के विरुद्ध एक माह में ही 30,000 हस्ताक्षर एकत्रित कर लिये। इस तरह नए टैक्सों के सभी प्रस्ताव विफल हो गए।
- लिपा के प्रॉपर्टी टैक्स के विरुद्ध छह माह के अभियान में 100 राष्ट्रीय और स्थानीय मीडिया घरानों ने अभियान पर समाचार प्रकाशित व प्रसारित किए।
- लिपा के सदस्य प्रॉपर्टी टैक्स वापस लेने की आवश्यकता से सम्बन्धित वार्तालाप में 20 मुख्य टी.वी. चैनलों पर उपस्थित हुए।
- लिपा की वेबसाइट को इस दौरान 3,80,000 लोगों ने खंगाला।
- अभियान के दौरान लिपा के फेसबुक अकाउंट की पहुंच 900 प्रतिशत अधिक हो गई, जिसने 50 प्रतिशत अधिक अनुसरणियों को जोड़ा।
- 350 से अधिक लोग हस्ताक्षर अभियान चलाने हेतु स्वयंसेवक बने।

प्रमुख अन्तर्दृष्टि

संदेश तैयार करना

सरकार का विरोध करना आसान नहीं होता, विशेष तौर पर तब, जब आप उस टैक्स नीति को रोकना चाहें, जिसमें आप जनता को यह समझाने में भी असमर्थ हों कि यह टैक्स उन्हें कितना महंगा पड़ेगा।

जब क्रोएशियन सरकार ने नई प्रॉपर्टी टैक्स नीति तैयार की तो टैक्स की दर तय करने का अधिकार स्थानीय प्राधिकरण के उपर छोड़ दिया गया। इससे भी बढ़कर बात यह थी कि प्रॉपर्टी टैक्स की गणना एक जटिल प्रक्रिया बन गई थी जो अन्य चीजों के अतिरिक्त प्रॉपर्टी के आकार एवं उपयोग के आधार पर की जानी थी।

अन्त में, अभियान की सफलता का कारण संख्या नहीं अपितु लोगों की भावनात्मक अपील थी। एक सन्देश कि 'प्रॉपर्टी टैक्स हमें अपने ही घर में किरायेदार बना देगा।' एक लोक नारा बन गया और अधिकाधिक लोग इसके साथ गहराई से जुड़ गए।

यह क्यों मायने रखता है: *हमें जो साधन मिला हमने उसी का उपयोग किया। जब प्रॉपर्टी टैक्स विरुद्ध अभियान के लिए पर्याप्त डाटा उपलब्ध नहीं था, तब भी लिपा प्रॉपर्टी टैक्स से पड़ने वाले प्रभाव को लोगों तक पहुंचाने में कामयाब रही, इसके साथ ही सम्पत्ति में भारी निवेश करने वाले राष्ट्र में भावनात्मक अपील भी करती रही।*

साम्यवादी यूगोस्लाविया का एक हिस्सा रहे क्रोएशिया के हालिया अनुभव ने लोगों तथा उसकी अर्थव्यवस्था पर गहरा प्रभाव डाला तथा लिपा को नए प्रॉपर्टी टैक्स के विरुद्ध लड़ने के लिए शक्तिशाली मौका प्रदान किया।

एक स्थायी प्रभाव जो इस लड़ाई में विशेष रूप से प्रासंगिक था, क्रोएशिया में घर स्वामित्व पर साम्यवाद का व्यापक प्रभाव। कम्युनिस्ट शासन के दौरान मुद्रास्फीति के कारण, लोग धन बचाने हेतु घर खरीदने को मजबूर हुए; जिसने राष्ट्रीय मुद्रा के मूल्य में गिरावट के बावजूद अपना मूल्य नहीं खोया। आज जब घर के स्वामित्व के दर की बात होती है तो यूरोपियन संघ में रोमानिया और स्लोवाकिया के बाद क्रोएशिया का तीसरा स्थान आता है। देश में घर स्वामित्व की उच्च दर ने भी नागरिकों को प्रेरित करने हेतु लिपा की मदद की क्योंकि नई कर नीति सीधे उनके निवेश पर प्रभाव डाल रही थी, जिसका न केवल मौद्रिक मूल्य था अपितु एक मजबूत भावनात्मक लगाव भी था।

जनता को देखभाल के लिए प्रेरित करने पर

जब लिपा ने पहली बार सम्पत्ति कर की लड़ाई का विरोध किया तो उसे पता था कि यह लड़ाई बहुत कठिन होगी। एक तो यूरोपीय संघ आयोग ने इसे सरकार का सही निर्णय बताया था, दूसरे यदि संघीय कानून की जटिलताओं को छोड़ भी दें तो आम जनता को सम्पत्ति कर के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।

लिपा के अभियान से पहले क्रोशियाई नागरिक आमतौर पर नए कानूनों के प्रति बहुत संवेदनशील नहीं थे। वे सोचते थे कि यह किसी और की समस्या है, यह कराधान धनी लोगों को प्रभावित करेगा। इसलिए लिपा ने तथ्यों को उजागर किया। देश के सबसे आदरणीय अर्थशास्त्री के साथ यह प्रस्तुत करने के लिए साझेदारी की कि कैसे सभी क्रोएशियन इस सम्पत्ति कर से प्रभावित होंगे। इसे आम लोगों को समझाने के लिए सम्मोहक भाषा का प्रयोग किया गया कि हर नए कर का अर्थ है उनके परिवार पर खर्चने के लिए कम पैसा।

लिपा के कार्यकारी प्रबन्धक ज़ोरान लोव ने कहा, 'इसमें सबसे बड़ा सबक और सकारात्मक पक्ष यह भी था कि क्रोएशिया में उदार विषयों पर समर्थन प्राप्त करना सम्भव है। यदि अभियान को सही ढंग से चलाया जाए, दर्शकों को लक्षित करके ध्यानपूर्वक सन्देशों का चुनाव किया जाए और सही विषयों को चुन कर सही समय पर विभिन्न चैनलों के माध्यम से प्रसारित किया जाए।'

यह क्यों मायने रखता है : *जैसे ही नीति सुदृढ़ होती है हम यह महसूस करते हैं कि दूसरों का ध्यान आकर्षित करने हेतु हमें मुद्दे को भुनाना चाहिए। लिपा के मामले में भी यही हुआ। जब देश के अधिकांश लोगों को प्रभावित करने वाली नीति तैयार हो रही थी तब भी यह चुनौती बनी रही कि हम परवाह क्यों करें? जहां तक व्यक्तिगत संदेशों का सम्बन्ध है, सबसे पहले शुरुआत तथ्यों से करनी चाहिए। लिपा ने सम्पत्ति कर का आर्थिक प्रभाव दिखाने के लिए यही किया। पहले इसके प्रभाव को साधारण भाषा में ढाल कर सन्देश के रूप में आम जनता में इस नीति के खतरे को उजागर किया।*

चर्चागत प्रश्न

- लिपा टैक्सपेयर्स एसोसिएशन एक छोटा-सा संगठन है, लेकिन इसकी परवाह किए बिना यह सरकार को नया सम्पत्ति कर लागू करने से रोकने में सफल रही। अन्य विशेषज्ञ, समर्थन समूह या गैर-लाभकारी संगठन थोड़े से लोगों व मामूली से बजट के साथ अपने प्रयासों को बढ़ाकर अपने संगठन को कैसे विस्तार दे सकते हैं?
- सम्पत्ति कर के खिलाफ लिपा के अभियान की शक्ति के दो भाग थे— एक आर्थिक विश्लेषण, जो यह बताता था कि यह कर क्रोएशियाई लोगों पर कैसे बोझ डालेगा दूसरा संचार माध्यमों व विपणन का उपयोग कर लोगों को यह समझाना कि उनका क्या दांव पर लगा है। विशेषज्ञ, समर्थन समूह, तथा गैर-लाभकारी सस्थाएं उन लोगों तक सन्देश कैसे पहुंचाए जो इन विस्तृत विवरणों को समझ नहीं पाते?
- लिपा ने सभी संचार माध्यमों – रेडियो, टेलीविज़न, सोशल मीडिया तथा पत्राचार का उपयोग करके लोगों को बहुत जल्दी अपने साथ जोड़ लिया। सभी संगठनों के लिए यह नीति सर्वोत्तम नहीं हो सकती। विपणन और संचार की रणनीति बनाते समय अन्य संगठनों को अन्य बातों पर भी विचार करना चाहिए?
- सम्पत्ति कर की लड़ाई में लिपा की प्रारम्भिक चुनौती यह थी कि आम जनता नए करों के प्रभावों से अनजान थी इसलिए करों के खिलाफ लड़ाई में उसकी कोई रुचि भी न थी। विपणन अभियानों के अतिरिक्त अन्य विशेषज्ञ, समर्थन समूह व गैर-लाभकारी संस्थान उन नए लोगों को अपने साथ जोड़ने के लिए क्या कर सकते हैं जो अनभिज्ञ व अनिच्छुक हों ?

खंड 7

आर्थिक स्वतंत्रता के लेखा परीक्षण का विषय अवलोकन

वार्षिक इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट के प्रकाशक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के सहयोग से एटलस नेटवर्क 'आर्थिक स्वतंत्रता का लेखा परीक्षण' यानी इकोनोमिक फ्रीडम ऑडिट्स (ईएफएएस) का समर्थन करता है जो कि स्थानीय थिंकटैंक्स की अगुवाई में नीतिगत सुधारकों को आर्थिक स्वतंत्रता के लाभों से अवगत कराता है। प्रत्येक आर्थिक स्वतंत्रता का लेखा परीक्षण देश के भीतर स्थानीय और क्षेत्रीय प्राथमिकताओं की सहमति तथा सुधार के अवसरों पर चर्चा व समीक्षा के लिए हितधारकों के विविध समूहों को आमंत्रित करती है। इस खंड में तीन विषय अवलोकनों को शामिल किया गया है जो व्यावहारिक नीति सुधार संबंधी विचारों को पहचानने, हितधारकों के साथ काम करने तथा लागू करने की रणनीतियां विकसित करने की प्रक्रिया को चित्रित करते हैं।

इस खंड में केस स्टडीज़ के संस्करण AtlasNetwork.org पर उपलब्ध हैं।

आर्थिक स्वतंत्रता का लेखा परीक्षण क्या है?

आर्थिक स्वतंत्रता के लेखा परीक्षण मात्र रिपोर्ट या रैंकिंग से कहीं अधिक है। यह संस्थागत परिवर्तनों हेतु व्याख्यान और सुविज्ञा सहमति पहुंचाने के लिए विशेषज्ञों को एकत्रित करने का अवसर है। स्थानीय विशेषज्ञ अपने संबंधों व अनुभवों का उपयोग कर मीडिया, व्यवसायों, सरकारी अधिकारियों व शैक्षणिक समुदायों को एकत्रित कर संपरीक्षा (ऑडिट) को गति देते हैं। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय हितधारकों और स्थानीय विशेषज्ञों के बीच कई बैठकों के बाद, अंतिम रिपोर्ट का मसौदा तैयार किया जाता है और अगले चरणों की पहचान की जाती है।

एक प्रशिक्षित संयोजक विभिन्न समूहों के साथ काम करता है। वह संपरीक्षा (ऑडिट) के विशिष्ट लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए चर्चा छेड़ता है और प्रतिभागियों से प्रतिपुष्टि (फीडबैक) प्राप्त करता है। स्थानीय लोगों को शामिल करना स्वामित्व का भाव प्रकट करता है और सुनिश्चित करता है कि संपरीक्षा वास्तविकताओं को उजागर करें क्योंकि यह देश के लोगों द्वारा तैयार की गई है जो स्थितियों को बाहरी लोगों की तुलना में बेहतर समझते हैं। प्रत्येक वर्ग में गहराई से जाने पर, स्थानीय स्तर पर होने वाली वास्तविक चीजों से संबंधित स्टीक व समयबद्ध आंकड़ें उपलब्ध होते है।

रिपोर्ट लक्षित देश को निम्न श्रेणियों में रैंकिंग (पंक्तिबद्ध) करती है : सरकार का आकार, वैधानिक प्रणाली और संपत्ति का अधिकार, स्थिर मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार स्वतंत्रता तथा विनियमन। प्रत्येक श्रेणी के विभिन्न भाग होते हैं। इनमें से प्रत्येक को स्कोर (गणना) किया जाता है। रिपोर्ट में नीतिगत सिफारिशों को भी सूचीबद्ध किया जाता है, जिन्हें प्रत्येक श्रेणी में चर्चा के बाद चुना जाता है। ये चर्चाएं सफलता के प्रमुख पैमानों के बारे में निर्णय लेने हेतु विविधतापूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करती हैं और यह गहन प्रक्रिया इतनी समृद्धता प्रदान करती है जो वैश्विक ईएफडब्ल्यू रिपोर्ट में वर्णित प्राकृतिक बाधाओं से अधिक है।

अंतिम रिपोर्ट ईएफए प्रक्रिया का एकमात्र उत्पाद नहीं है। नीति परिवर्तन और निरंतर प्रगति इसके लक्ष्य हैं और रिपोर्ट के परिणाम लक्षित देश में आम जनता की राय को प्रभावित करने तथा प्रगतिशील नीति प्राथमिकताओं के प्रति मीडिया का ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रस्तुत किये जाते हैं। इस पूरी प्रक्रिया के दौरान मीडिया को जोड़ कर रखा जाता है। उसके द्वारा समाचार प्रसारण, साक्षात्कार, संपरीक्षा प्रक्रिया की पारदर्शी प्रस्तुति, एक संपरीक्षा के बाद बनी (पोस्ट ऑडिट) प्रेस रिलीज़ तथा विषय केंद्रित विस्तृत साक्षात्कार इत्यादि प्रसारित व प्रकाशित किये जाते हैं। और अंत में एक रिपोर्ट, जिसमें विस्तृत विश्लेषण व नीतिगत सिफारिशों को अंतिम रूप देकर जनता के सामने औपचारिक निष्कर्षों के रूप में प्रस्तुत किया जाता है।

संकट के दौर से उबरना

फाउंडेसियन लिबरटेड वाई प्रोग्रेसो, (एलवाईपी)
अर्जेंटीना

अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स, दक्षिण अमेरिका का सबसे अधिक दर्शनीय स्थल है। पर्यटक इसकी विचित्र सड़कों, पुराने यूरोपियन अनुभव और समृद्ध संस्कृति का आनंद लेते हैं। किंतु इनमें से कुछ पर्यटक जानते हैं कि देश संकट में है।

अर्जेंटीना के पेसो ने 2018 में अपना आधा मूल्य गंवा दिया था तथा अर्जेंटीनी इक्विटी और बांड्स ने अपना महत्वपूर्ण मूल्य खो दिया है। देश ने अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से 57 बिलियन डॉलर का सौदा करने के लिए लंबी-चौड़ी बातचीत की जो आई.एम.एफ. के इतिहास में सबसे बड़ी डील है। देश के केंद्रीय बैंक राजस्व, वित्त, मौद्रिक तथा विनिमय दर की स्थिति में फिर से विश्वास स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इन सुधारों की एक कीमत चुकानी होगी, जिसके लिए अर्जेंटीना के लोग तैयार नहीं हैं।

मजदूर वेतन वृद्धि पर लगाये गये अंकुश के विरोध में हड़ताल करते हैं और लोग प्रस्तुत किये गये मितव्ययता के उपायों का विरोध करते हैं। हाल ही के वर्षों में लोगों को देश द्वारा उठाये गये कदमों पर संशय पैदा हो गया था। उन्होंने 2015 में मौरिको मैक्री के राष्ट्रपति चुनने के पक्ष में आवाज उठाई जो कि एक व्यापारी दिग्गज थे और 1932 के बाद के पहले गैर-कट्टरवारी तथा गैर-सिद्धांतवादी राष्ट्रपति थे।

देश का क्या होगा यह अभी देखना बाकी है। लेकिन एक संगठन ऐसा है जो एक तरफ बैठकर इंतजार करने में संतुष्ट नहीं है। ब्यूनस आयर्स में स्थित एक लक्ष्य-उन्मुख, मुक्त बाजार विशेषज्ञ संगठन फाउंडेसियन लिबरटेड वाई प्रोग्रेसो (एलवाइपी) असंतुष्ट जनता को नीति सुधार लक्षित कार्यक्रमों से मंत्रमुग्ध कर रहा था।

हाल ही में, एलवाइपी ने आर्थिक स्वतंत्रता संपरीक्षा (ईएफए) आरंभ करने के लिए फ्रेज़र इंस्टीट्यूट और एटलस नेटवर्क के साथ साझेदारी की, जो किसी देश की गिरती अर्थव्यवस्था को ऊपर खींचने, मजबूती प्रदान करने व गहराई से मूल्यांकन करने में माहिर है। एलवाइपी की स्वदेशी प्रकृति की संपरीक्षा (ऑडिट) ने अर्जेंटीना पर सीधे प्रभाव डालने

वाली विभिन्न नीतियों को उदाहरण सहित प्रस्तुति किया। परिवर्तन पर बुरा प्रभाव डालने वाले तत्वों तथा अन्य ग़लतियों को पकड़ा। ईएफए के परिणाम देश के आर्थिक पक्ष को सुधारने के लिए रास्ता बनाने में रोडमैप का काम करेंगे। संपरीक्षा की सहायता से आरंभ में ही उभरने के लिए कुछ सफलताएं मिली हैं और एलवाइपी का अनुभव अन्य देशों के विशेषज्ञों को, उनके अपने देश को विकासहीनता से बचाने के लिए प्रेरित करेगा।

देश की पृष्ठभूमि

अर्जेंटीना की स्थिति की गंभीरता को समझने के लिए, यह आकलन करना सहायक होगा कि देश का भाग्य कितना गर्त हो चुका है।

अर्जेंटीना का भविष्य एक समय में बहुत उज्ज्वल था। 20वीं सदी के प्रारंभिक वर्षों में अर्जेंटीना दुनिया के सबसे अग्रणीय देशों में से एक था। अन्य तेजी से विकसित हो रहे देशों ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, न्यूजीलैंड तथा अमेरिका की भांति इसमें भी समृद्धि व आर्थिक विकास की उच्चतम संभावनाएं थीं। यहां तक कि बहुत से यूरोपियन प्रवासी इस बात पर चर्चा करते थे कि उन्हें न्यूयॉर्क जाना चाहिए या ब्यूनस आयर्स।

अब वे देश फ्रेजर इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक फ़्रीडम ऑफ़ वर्ल्ड (ईएफडब्ल्यू) रिपोर्ट में शीर्ष 20 स्थानों पर कायम हैं जबकि अर्जेंटीना लगभग निचले स्तर पर है। देश में प्रति व्यक्ति जीडीपी भी वैश्विक औसत से काफी कम है, जबकि पूर्व में यह वैश्विक औसत से 200 प्रतिशत से अधिक था। रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण के अनुसार अर्जेंटीना मध्य से निम्न स्तर के रैंक वाले देशों में से एक है।

एलवाइपी के बारे में

फाउंडेसियन लिबरटेड वाई प्रोग्रेसो (एलवाइपी) गैर लाभकारी थिंकटैंक है जो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में स्थित है। एलवाइपी अर्जेंटीना में भारी बदलाव के लिए संघर्षरत है। उसके लिए यह सार्वजनिक नीतियां तैयार करने का काम करता है, राष्ट्रीय राजनीतिक चर्चाओं में संलग्न होता है तथा नागरिक समूहों को सरकार का अर्थव्यवस्था में योगदान जैसे मुद्दों पर बहस करने के लिए प्रेरित करता है। एलवाइपी ऐसी नीतियों को तैयार करने मांग करता है और उनका समर्थन करता है जो न केवल अर्जेंटीना अपितु शेष लैटिन अमेरिका वासियों के जीवन में लंबे समय तक गुणात्मक सुधार ला सकें।

एलवाइपी का गठन तीन समान विचारधारा वाले विशेषज्ञों के विलय के माध्यम से किया गया था, जिन्होंने व्यक्तिगत अधिकारों का सम्मान, सीमित सरकारी दखल, निजी संपत्ति, मुक्त उद्यम तथा शांति जैसे मुद्दों का समर्थन करने हेतु एकजुट होने का निर्णय लिया था।

एलवाइपी की सक्रियता ने कई रूप धारण किये। वर्ष 2017 में अर्जेंटीना में लैपटॉप और टैबलेट पर उच्च टैरिफ के बारे में इसके वीडियो को 80,000 बार देखा गया तथा महत्वपूर्ण मीडिया कवरेज मिला। परिणामस्वरूप टैरिफ को निरस्त कर दिया गया। एलवाइपी ने टैरिफ उन्मूलन मुहिम में से एक रिपोर्ट प्रकाशित की, जिसका शीर्षक था 'उदार अर्जेंटीना', जिसमें अर्जेंटीना के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की स्थिति की समीक्षा की गई थी और व्यापार के क्षेत्र में उदारीकरण के लिए तर्क दिये गये थे। एलवाइपी ने अपने 'वार्षिक संस्थागत गुणवत्ता सूचकांक' (आईक्यूआई) को भी प्रकाशित किया, जिसमें देशों को उनके राजनीतिक संस्थानों के सामर्थ्य तथा भ्रष्टाचार के स्तर के आधार पर सूचीबद्ध व स्तरबद्ध किया गया (अर्जेंटीना 2018 के आईक्यूआई में 183 देशों में से 119वें स्थान पर था)।

अर्जेंटीना में यह अधोगति 1943 से आरंभ हुई, जब 'कर्नल जुआन पेरोन' सैन्य तख्तापलट के बाद सत्ता में आए। 'पेरोन' ने इतालवी फासीवाद और लैटिन अमेरिकी लोकलुभावन संरक्षणवादी नीतियों तथा आर्थिक राष्ट्रवाद का अनुसरण किया। 'पेरोनिज्म' पेरोन और उनके उत्तराधिकारियों की विचारधारा के रूप में जाना जाता है, जिसकी मुख्य विशेषताएं हैं—विशिष्ट समूह द्वारा नियंत्रीकरण, संगठित श्रम का केंद्रीयकरण, प्रत्यक्ष नियंत्रण तथा अर्थव्यवस्था का नियमीकरण। 1955 के तख्तापलट में 'पेरोन' हार गया किंतु उसने जो आंदोलन शुरू किया, वह लगातार विकसित व लोकप्रिय होता रहा।

अर्जेंटीना के इस लोकलुभावनवाद ने सामाजिक सेवाओं की उच्च मांग पैदा की तथा व्यापार के लाभों के प्रति संदेह व्यक्त किया। वर्ष 1960 के दशक में टैरिफ औसतन 84 प्रतिशत था, और सरकार द्वारा निर्यात पर कर लगाया गया जो सिमट कर राष्ट्रीय आय का मात्र 2 प्रतिशत रह गया। सरकारी खर्च जीडीपी का दोगुना हो गया। 1930 के दशक में जीडीपी का 10 प्रतिशत से कम रहने वाला सरकारी खर्चा सन् 2000 में 30 प्रतिशत 2015 में 45 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2003 से 2015 के बीच सार्वजनिक कर्मचारियों की संख्या में 77 प्रतिशत की वृद्धि हुई।

लोकलुभावन नीतियां बहुत आकर्षक लगती हैं क्योंकि ये दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति का उदार वादा करती हैं। उदाहरण के लिए, एक विधवा महिला को न केवल पेंशन देना बल्कि उसके मृतक पति के हिस्से का पेंशन भी प्रदान करने की नीति। यदि दो विधवाएं, वे दोनों साथ-साथ दो पेंशन प्राप्त करती हैं, वे एक-दूसरे के साथ 'सह-अस्तित्व' का दावा कर सकती है; और यदि उनमें से किसी एक की मृत्यु हो जाती है तो दूसरी आजीवन चार पेंशन प्राप्त करने का दावा कर सकती है।

ये लोकलुभावन नीतियां सस्ती नहीं हैं। अर्जेंटीनावासियों ने 2006 से 2015 के बीच 1990 के दशक के मुकाबले 694 बिलियन डॉलर अधिक करों का भुगतान किया।

बहुत से अर्जेंटीनी इन आर्थिक समस्याओं को समझते हैं जो समृद्धि में बाधक हैं, लेकिन वे यह भी जानते हैं कि जिन्न को वापस बोतल में बंद करना अधिक कठिन है। एक बार जब सरकारी नौकरशाही का विस्तार आरंभ हो जाता है, तो इसे रोकना मुश्किल होता है। 2015 में, राष्ट्रपति मैक्री के नेतृत्व वाली नवनिर्वाचित सरकार ने राजकोषीय घाटे और सरकारी व्यय को कम करने की सोची, लेकिन उनके प्रयासों को रोक दिया गया है।

आईएमएफ ने वित्तीय सहायता नई शर्तों के साथ जारी की, जिसमें कड़ी राजकोषीय ज़िम्मेदारी अनिवार्य है तथा घाटे के खर्च पर रोक और मुद्रा हेरफेर पर प्रतिबंध भी शामिल है। अर्जेंटीना के लिए यह एक अभिप्रेरणा है तथा जवाबदेही स्थापित करने का अच्छा मौका है। लेकिन ऋणों का भुगतान करने से अर्थव्यवस्था पर स्थाई प्रभाव नहीं पड़ने वाला जब

तक कि अर्जेंटीनी वास्तविकताओं के साथ भागीदारी नहीं करते तथा परिवर्तनकारी, उदारवादी नीतियों का समर्थन नहीं करते।

परियोजना

एलवाइपी ने तत्कालीन संकट में से भी अवसरों को पहचाना। क्योंकि अंतत: लोग सुधारों में दिलचस्पी लेंगे इसलिए एलवाइपी ठोस नीतिगत सिफारिशें तैयार करना चाहता है। इस लक्ष्य की प्राप्ति हेतु उन्होंने फ्रेजर इंस्टीट्यूट तथा एटलस नेटवर्क के साथ मिलकर एक आर्थिक स्वतंत्रता संपरीक्षा (ईएफए) आयोजित करने का फैसला लिया। इसका प्रयोजन सुदृढ़ और संपन्न अर्थव्यवस्था के मार्ग में आने वाली बाधाओं की पहचान करना तथा उनके समाधान के उपाय विकसित करना था। ऐसे समाधान जो उन्हें नागरिकों का समर्थन प्राप्त कराने और इसके प्रति भरोसा जगाने में पर्याप्त रूप से प्रेरक होंगे।

एलवाइपी के समन्वयक कैंडेलारिया डी एलिजाल्डे के अनुसार 'हमें विश्वास है कि हमारे देश में आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ने से समृद्धि का नया युग आएगा, गरीबी कम होगी और विकास तथा रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।' हमारा उद्देश्य मात्र नीतियों में परिवर्तन कराना नहीं है अपितु प्रत्येक नागरिक के दैनिक जीवन में सुधार लाना है। एलिजाल्डे ने बताया 'एलवाइपी ने अर्जेंटीना में आर्थिक नीतियों का विश्लेषण करने की परियोजना आरंभ की, जिसका उद्देश्य आर्थिक स्वतंत्रता बढ़ाना तथा अर्जेंटीना वासियों के जीवन में समृद्धि लाना था।'

तीन संगठनों ने मिलकर अर्जेंटीना के हितधारकों और शीर्ष नेताओं के समूह को इस परियोजना पर काम करने के लिए एकत्रित किया। प्रतिभागियों में उद्योग विशेषज्ञों का एक ग्रुप भी शामिल था, जिसमें पूर्व वित्तमंत्री, केंद्रीय बैंक के उपाध्यक्ष, केंद्रीय बैंक के महाप्रबंधक, व्यापार सचिव तथा अन्य सहयोगी लोग भी थे। इस स्तर की भागीदारी ने इस मौन स्वीकृति का खुलासा किया कि अर्जेंटीना के नेताओं को वहां की समस्या की जानकारी है। वे यथास्थिति से असंतुष्ट हैं तथा परिवर्तन में शामिल होने के इच्छुक है। एलवाइपी जानता था कि उपरोक्त सामाजिक परिवर्तन के निर्माण खंड है और वह इस अवसर का फायदा उठाना चाहता था।

एलवाइपी ने संपरीक्षा (ऑडिट) से पहले उन संगठनों से संपर्क किया, जिन्होंने ईएफए को सफलतापूर्वक पूरा किया था। दो अन्य विशेषज्ञों के प्रतिनिधि—समृद्धि फाउंडेशन, नेपाल में मुक्त बाजार के विशेषज्ञ; सीईडी (सेंटरो डी एस्टुडियोस डी पैरा एल डिसारोल्लो) उरुग्वे के विशेषज्ञ ने ईएफए आयोजित कर अपने विचार साझा किये। उन्होंने सफलतापूर्वक ईएफए के आयोजित करने का परामर्श भी दिया।

संपरीक्षा (ऑडिट) की आधार रेखा स्थापित करने के लिए, एलवाइपी ने प्रत्येक घटक का विश्लेषण करते हुए फ्रेजर की ईएफडब्ल्यू सामग्री का गहराई से अध्ययन किया। प्रत्येक संपरीक्षा (ऑडिट) के लिए, फ्रेज़र इंस्टीट्यूट एक बुकलेट तैयार करता है, जिसमें सूचकांक में वर्णित 42 चरों के आधार पर देश की आर्थिक स्वतंत्रता का स्तर तय किया जाता है। निष्कर्षों को प्रासंगिक बनाने के लिए तथा उन्हें परिप्रेक्ष्य में लाने के लिए सूचकांक में प्रत्येक चर में शीर्ष 10 देशों को दर्शाया जाता है, 10 शीर्ष औसत, क्षेत्रीय औसत तथा विश्व औसत के स्कोर भी प्रस्तुत किये जाते हैं।

फ्रेजर के आंकड़े अधिकतर विश्व बैंक की 'डूइंग बिजनेस रिपोर्ट' से आते हैं, जो 189 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने की सुविधा का मापन करता है तथा वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा वर्ल्ड कॉम्पटिटिवनेस रिपोर्ट को भी शामिल किया जाता है जिसमें 138 देशों का विश्लेषण किया जाता है। उन सामग्रियों की जांच के द्वारा एलवाइपी ने प्रत्येक चर के लिए अर्जेंटीना के प्रदर्शन का स्तर निर्धारित किया कि यह विश्व की तुलना में तथा पड़ोसी देशों की तुलना में कैसा था और इसमें किन सुधारों की आवश्यकता थी।

फ्रेज़र इंस्टीट्यूट की सामग्री की समीक्षा करने व उनसे परामर्श करने के उपरांत एलवाइपी ने बहुदिवसीय विचार मंथन का आयोजन किया। उन्होंने दो दिवसीय कार्यक्रम में सात कार्यशालाओं की एक श्रृंखला का आयोजन किया। प्रत्येक सत्र में कुछ संशोधन के साथ ईएफडब्ल्यू सूचकांक के सभी घटकों पर ध्यान केंद्रित किया गया। अर्जेंटीना के सामने आने वाली विशेष चुनौतियों को ध्यान में रखते हुए सरकार की श्रेणी को दो सत्रों में विभाजित किया गया। पहला, 'सार्वजनिक व्यय' दूसरा, 'कराधान'। विनियमन श्रेणी को भी दो सत्र दिए गए : 'व्यापार' एवं 'श्रम'। तीसरा तत्त्व, 'ऋण विनियमन' को 'सुदृढ़ धन' के सत्र के साथ जोड़ा गया। एलवाइपी को एक महत्वपूर्ण बाधा को तुरंत दूर करने की आवश्यकता थी। उन्हें सुधार की आवश्यकता वाले क्षेत्रों की पहचान करके वहां नीतियों का लाभ उठाने के लिए उत्कृष्ट परिपाटियों को खोजना चाहिए। उन्हें आयोजन में उपस्थित लोगों का एक समूह बनाने की भी जरूरत थी जो गहन विशेषज्ञता और राजनीतिक ज्ञान को संतुलित करे। ईएफए तथा किसी भी संपूर्ण अभियान की सफलता इस बात पर निर्भर करती थी कि उसके पास सही लोग हैं।

एलवाइपी ने ये जानने के लिए कि कौन से हितधारकों तक पहुंचना चाहिए; विभिन्न आंतरिक परियोजना के अग्रणी लोगों तथा संगठनों के निदेशकों के साथ कई बैठकें कीं। अपने व्यापक सामाजिक और व्यावसायिक नेटवर्क का उपयोग करके एलवाइपी ने लक्षित लोगों को निमंत्रण भेजा तथा सामाजिक नजदीकियां बढ़ाईं, जिसे स्थापित करने के लिए एलवाइपी के नेतृत्व ने वर्षों तक काम किया।

एक बार प्रारंभिक संपर्क स्थापित हो जाने के बाद इसे जारी रखने का काम स्टाफ को सौंप दिया गया। निमंत्रण की स्थिति पर नज़र रखने के लिए टीम ने सेल्सफोर्स (जिसे सीआरएम

भी कहा जाता है) सॉफ्टवेयर का उपयोग भी किया जो कि सम्प्रेषण, विश्लेषण तथा विभिन्न स्वचालनों को एकीकृत करता है, जिससे प्रशासनिक बोझ काफी हद तक कम हो जाता है।

प्रत्येक विषय के सत्र में अपनाए गए इस इरादतन दृष्टिकोण ने प्रभावशाली प्रतिभागियों को आकर्षित किया जिसमें वक्ता और प्रतिभागी दोनों शामिल थे। कार्यशालाओं में उपस्थित होने वाले 46 प्रतिभागियों में अर्थशास्त्री, सलाहकार, वकील, सार्वजनिक नीति विशेषज्ञ, निर्वाचित अधिकारी व आर्थिक नीति विश्लेषक शामिल थे।

प्रोफेसर मार्टिन क्रूस, जो ब्यूनस आयर्स विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र के प्रोफेसर तथा कैटो इंस्टीट्यूट के सहायक विद्वान थे, उन्होंने परियोजना की रिपोर्ट लेखन में केंद्रीय भूमिका निभाई। उन्होंने कार्यशाला के प्रत्येक सत्र को अपने प्रयासों से सुगम बनाया।

प्रत्येक सत्र के आरंभ में क्रूस ने प्रतिभागियों को हर मुद्दे की कुछ प्रमुख अवधारणाओं को पेश करने के लिए कहा, जिससे विषयों में विविधता और व्यापकता आई। सोयाबीन पर निर्यात शुल्क से लेकर, बजट से बाहर सरकारी व्यय तक, म्युनिसिपल गवर्नर की धूर्धता से लेकर स्टार्टअप के लिए निवेश, वाहनों की मंजूरी देने तक अनेक विषय उठाये गये। सत्रों ने प्रतिभागियों को रास्ता दिखाया तथा विभिन्न प्रतिभागियों के बीच खुलकर चर्चा हुई। प्रतिभागियों की गहन विशेषज्ञता ने एलवाइपी को नीतियों में सुधार व आगामी जांच हेतु नये विचार प्रदान किये।

चुनौती : वाह्य आघात

आजोयन की व्यवस्था से जुड़े मुद्दे अप्रत्याशित और विध्वंसकारी हो सकते हैं। संपरीक्षा के पहले दिन, एक राष्ट्रीय हड़ताल ने सार्वजनिक परिवहन को विराम लगा दिया। इसी तरह, सम्मेलन के दिन, एंजेला मर्केल की अर्जेंटीना यात्रा के कारण ब्यूनस आयर्स में सुरक्षा बढ़ा दी गई, जिससे बैठक स्थल तक लोगों की पहुंच सीमित हो गई। इन मुद्दों के लिए, एलवाइपी को जल्दी से जल्दी संचार योजनाओं को विकसित और कार्यान्वित करना था। संगठन का रिकार्ड रखने में अभ्यस्त होने व सीआरएम के प्रयोग से प्रतिभागियों से संपर्क अन्यों की बजाय अधिक कुशलता से हो गया। इस तरह के अंतर्निहित उपकरण व प्रक्रियाएं अप्रत्याशित परिस्थितियों के लिए त्वरित प्रतिक्रिया संभव बनाती हैं। बिना तामझाम के संगठनात्मक छोटी-छोटी बातों पर ध्यान देना किसी परियोजना की सफलता या विफलता के बीच अंतर करता है।

ईएफए का अनुसरण करते हुए प्रोफेसर क्रूस ने अंतिम रिपोर्ट लिखी। फ्रेड मेकमहोन के साथ काम करते हुए, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के एक सहयोगी, जिसने ईएफए प्रक्रिया पर विशेषज्ञता प्रदान की, उसने दो अन्य विद्वानों के साथ मिलकर संपरीक्षा के परिणामों को

रणनीतिक रूप से वितरित करने के लिए एक संचार योजना बनाई, जिसमें दो प्रेस साक्षात्कार, नीति निर्माताओं व अन्य नेताओं के साथ बैठकें तथा दो शहरों ब्यूनस आयर्स और तुकुमान में प्रस्तुतियां शामिल थीं। विशेष रूप से क्रूस ओर मेकमहोन ने फ्रेडरिक न्यूमन फाउंडेशन के कार्यालय में राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधियों के साथ भी मुलाकात की। प्रतिनिधि संपरीक्षा, इसके जांच परिणामों और कुछ नीतियों की अनुशंसाओं से प्रभावित थे, जो भविष्य में नये अवसरों का निर्माण करती थीं।

मेकमहोन ने अर्जेंटीना के विशेषज्ञों के समक्ष भी प्रस्तुतियां दीं। वे फाउंडेसियन इंस्टीट्यूटो डेविड ह्यूम में उन शिक्षाविदों और प्रोफेसरों के समक्ष प्रस्तुति देने गये जो आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक से अपरिचित थे। 'ट्युकमैन' में मेकमहोन ने एक युवा दल को संबोधित किया, जिसे फ़ेडरेशन फ़ॉर फेड्रलिज़्म एंड लिबर्टी द्वारा एकत्रित किया गया था। यह युवा विशेषज्ञों का एक दल था, जिसे यूनिवर्सिटी ऑफ पेन्सिलवेनिया के 'ग्लोबल गो टू थिंक टैंक' सूचकांक द्वारा 'शीर्ष 100 थिंक टैंक टू वॉच' में स्थान दिया गया था। इन व्यक्तिगत मुलाकातों ने अर्जेंटीना के नीति निर्माण में शामिल प्रभावशाली लोगों के हाथों में सीधे कार्रवाई करने योग्य जानकारी सौंप दी।

योजना से नीति तक : कार्यस्थल सुधार

संपरीक्षा का महत्व केवल रिपोर्ट में ही नहीं अपितु नीतिगत परिणामों और निरंतर वैचारिक परिवर्तनों में भी निहित है। एलवाइपी कम से कम एक नीतिगत जीत का दावा कर सकता है जो अब तक इसकी संपरीक्षा से उभर कर आई है। विनियमन पर कार्यशाला के दौरान विशेषज्ञों ने विशेष रूप से अर्जेंटीना की श्रम बाजार नियामक योजना पर बहस की। संपरीक्षा रिपोर्ट में बताया गया कि श्रमिकों को काम पर रखने की लागत इतनी अधिक है कि व्यवसायी उन्हें काम पर रखने में अनिच्छुक हैं। भावी पीढ़ी के लिए रोजगार उपलब्ध करवाना अर्जेंटीना की प्राथमिकता है लेकिन अभी भी इसके नियम और कानून रास्ते में बाधा बन के खड़े हैं।

रिपोर्ट के समय, अर्जेंटीना के श्रम बाजार के नियमों ने उच्च लागत थोप दी। 'हायरिंग रूल्स एंड मिनिमम वेज' ऑडिट श्रेणी में अर्जेंटीना ने 10 में से 2.23 अंक प्राप्त किये और 'हायरिंग एंड फायरिंग रूल्स' श्रेणी में 10 में से 1.9 अंक प्राप्त किये। 'लेबर मार्केट विनियमन' की सभी श्रेणियों में कुल मिलाकर अर्जेंटीना ने 10 में से 2.52 अंक हासिल किये। जबकि संयुक्त राज्य के अंक 9.2 तथा दक्षिण अमेरिकी देशों के औसत 5.3 अंक थे।

कार्यशाला में चर्चा के दौरान खुलासा हुआ कि मैक्री प्रशासन ने एक बार 'प्रथम नौकरी बिल' के माध्यम से श्रम बाजार के मुद्दों को सुधारने का प्रयास किया था, जिससे 18-24 साल के बच्चों के लिए नौकरी खोजना आसान हो जाता लेकिन सदन की श्रम समिति ने कभी भी इस विधेयक पर विचार नहीं किया।

कार्यशाला के आदान-प्रदान ने किसी भी श्रम सुधार की आवश्यकता वाले विचारों की एक श्रृंखला तैयार कर दी।

- अर्जेंटीना को 'काम की संस्कृति' पर लौटने की आवश्यकता होगी। इस संस्कृति में लौटने के लिए एक अच्छा चैनल सामाजिक अनुदान प्राप्त करने वालों को काम को बढ़ावा देकर मौजूदा लोककल्याण कार्यक्रमों को कार्यकल्याण कार्यक्रमों में बदलना होगा।
- सार्वजनिक क्षेत्र को अपने अतिरिक्त कर्मचारियों को निजी क्षेत्र में स्थानांतरित कर देना चाहिए।
- प्रौद्योगिकी से उत्पन्न लचीलेपन के लिए 'श्रम अनुबंध कानून' को सामयिक बनाने की आवश्यकता है।
- 'हड़ताल के कानून' को अतिरेक होने से रोकने के लिए अधिक विनियमन की आवश्यकता है।

इन कार्यशालाओं में विकसित हुए विचारों से एलवाइपी ने ऑडियो के साथ-साथ एक वीडियो भी बनवाया, जिसका शीर्षक था 'अर्जेंटीना असफल क्यों हुआ'। वीडिओ में रोजगार एवं श्रम सुधार समस्याओं पर प्रकाश डाला गया। इसमें बताया गया कि अर्जेंटीना के 8 मिलियन लोग काम करते हैं व सरकारी अनुदान प्राप्त करने वाले 20 मिलियन लोगों को पालते हैं। अपने इस काम व संदेश के लिए एलवाइपी ने एटलस नेटवर्क का लाइट्स, कैमरा, लिबर्टी फिल्म फेस्टिवल अवार्ड जीता।

'अर्जेंटीना क्यों असफल हुआ' वीडियो ने मीडिया का ध्यान अपनी ओर खींचा और इस वीडियो को 4,20,000 ने देखा, जिससे सरकार का ध्यान भी इस ओर आकर्षित हुआ। सरकार ने जून, 2017 में आरंभ किए गए कनेक्शन प्रोग्राम में कुछ प्रस्तावित सुधारों को शामिल किया, जो सामाजिक कल्याण के नाम पर उद्योगों को औसतन प्रति व्यक्ति 4,430 डॉलर की सब्सिडी देते थे। कनेक्शन प्रोग्राम का उद्देश्य लोगों को उत्पादक रोजगार के रास्ते पर ले जाना था। सब्सिडी दो साल के लिए काम करती है, और व्यवसाय उन कर्मचारियों के लिये सीमित है जो कार्यक्रम में भाग ले सकते हैं। कार्यक्रम अभी परीक्षण चरण में है, इसमें 12,280 प्रतिभागी हैं। इस कार्यक्रम की भारी मांग है और इसे 70,000 उम्मीदवारों के प्रशिक्षण कार्य तक बढ़ाना है।

कनेक्शन प्रोग्राम एक भरोसेमंद नीति है जो एलवाइपी के संपरीक्षा में प्रस्तुत किए गए कार्य पर आधारित है। इसके अतिरिक्त, यह दर्शाता है कि संपरीक्षा (ऑडिट) सिर्फ एक उत्पाद भर ही नहीं है बल्कि इससे कहीं अधिक है; यह समाधानों को पहचानने और बातचीत आरंभ करने की भी एक प्रक्रिया है। कार्यक्रम यह भी दर्शाता है कि सफलतापूर्वक अनुगमन किया जाए तो इसके जबरदस्त परिणाम निकल सकते हैं।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

एलवाइपी के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती अर्जेंटीनियों को शालीनता के साथ प्रेरित करने की थी। प्रारंभिक आर्थिक सफलता ने जीवन का एक आरामदायक तरीका स्थापित कर दिया था तथा अनेक प्रत्यक्ष नागरिक भत्तों के गठन की अनुमति दी। लेकिन समस्या यह थी कि इससे देश पंगु हो रहा है, यह किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। देश अपने अंतर्राष्ट्रीय ऋणदाताओं को खुश करने के लिए थोड़े सुधार के साथ कई कल्याणकारी कार्यक्रमों को जारी रखता है, लेकिन यह रास्ता उन कई महान अवसरों को बंद कर देगा जो भविष्य मिल सकते थे।

एलवाइपी ने परिणामजन्य नीति सिफारिशों तथा ईएफए की गति बनाये रखने हेतु व्यक्तिगत आकांक्षाओं को समृद्ध के प्रति जागृत किया। श्रम नीति को ध्यान में रखते हुए बहुत ही व्यक्तिगत अवधारणाओं के प्रति आह्वान करना एक ऐसी चीज थी जो नीति निर्धारणों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है साथ ही साथ समाज में सभी को प्रभावित भी करती थी। इसने नीतिगत बातचीत को वैचारिक की बजाय व्यावहारिक बना दिया। एलवाइपी को एक दबाव बिंदु मिल गया जो वहां के निवासियों के बहुत ही समीप था। इसको व्यापक परिवर्तन लाने के लिए उत्प्रेरक के रूप में प्रयोग किया गया।

एक सफल संपरीक्षा नीति बदलाव तथा वैचारिक परिवर्तन ला सकती है। किसी संगठन की पृष्ठभूमि और कौशल सफलता के लिए मंच सजा सकती है, लेकिन यह समीकरणों का केवल एक हिस्सा है। प्रतिभागियों के विविधतापूर्ण एवं सशक्त जानकारी का उपयोग करते हुए विषय तैयार करना व समाधान सुझाना, दूसरा अच्छे व्यावसायिक संचालन तथा भागीदारों के मजबूत नेटवर्क के साथ इन तत्त्वों के संयोजन से एक नीति सुधार परियोजना की सफलता की संभावना बढ़ जाती है। एलवाइपी की संपरीक्षा ने वास्तविक नीति समाधानों का नेतृत्व किया जो अर्जेंटीना में निरंतर व महत्वपूर्ण बदलाव का आधार बन सका।

कार्यशाला और बैठक की प्रक्रिया के माध्यम से, विशेषज्ञों और नेताओं ने अनिवार्य आवश्यकताओं की एक श्रृंखला तैयार की, जिसमें गंभीर श्रम सुधार प्रयासों को भी शामिल किया जाना चाहिए। इस शोध को वीडियो के साथ जोड़ा गया, यह प्रतीत होता है कि अर्जेंटीना की सरकार इस सरकारी खामी को स्वीकार करती है तथा इसे कम करने के लिए प्रयासरत है। वर्तमान कनेक्शन प्रोग्राम, यद्यपि अपने प्रारंभिक चरण में है पर यह दर्शाता है कि ईएफए को सफलतापूर्वक लागू करना और उसका पालन करना निरंतर वैचारिक बदलाव और नीतिगत परिवर्तन को प्राप्त कर सकता है।

चर्चागत प्रश्न

- संस्कृति ने 'ओवर्टन विंडो' को कैसे प्रभावित किया, जिसका एलवाइपी ने सामना किया? नीतिगत सुधारों को आगे बढ़ाते हुए आपके संगठन को किन-किन सांस्कृतिक बाधाओं का सामना करना पड़ता है?
- किन अनपेक्षित घटनाओं ने उन परियोजनाओं में बाधा डाली, जिनमें आपने काम किया? क्या आपने भावी उपक्रमों के लिए आकस्मिकताओं का निर्माण किया? यदि हां, तो वे क्या थे? यदि नहीं, तो क्या आपकी परियोजनाओं को अप्रत्याशित चरों से खतरा हो सकता था?
- एलवाइपी दिखाई न देने वाली मुसीबतों पर कैसे काबू पा सकता था?
- किस तकनीकी या व्यावसायिक प्रक्रिया से आपके काम को तुरंत लाभ मिल सकता है? लंबी अवधि में क्या होगा?
- आपके लक्षित बाजार में कौन से नीतिगत मुद्दे व्यक्तिगत रूप से लोगों व उनके दैनिक जीवन को प्रभावित करते हैं?

आज़ादी को पुनर्परिभाषित करना

सेंटरो डी डाइवुलजेसियन डेल कोनोसिमेंटो
इकोनोमिको पैरा ला लिबरटेड (सीईडीआईसीई)
वेनेजुएला

कभी वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध देश था। इसका प्रमुख कारण आर्थिक स्वतंत्रता था। दरअसल, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड (ईएफडब्ल्यू) की रिपोर्ट के अनुसार 1970 में वेनेजुएला का आर्थिक स्तर लैटिन अमेरिका में उच्चतम स्तर पर था और वह दुनिया में 10वें स्थान पर था। दुर्भाग्यवश, समृद्धि अविवेकी सामाजिक और आर्थिक नीतियों की ओर ले गई। कमोडिटी की कीमतों में बदलाव, तेजी से सार्वजनिक रोजगार का विस्तार और प्रतिबंधात्मक आर्थिक नीतियों के संयोजन के परिणामस्वरूप ठहराव और फिर गिरावट आई, जो कि लोकलुभावन राजनीतिक नेताओं द्वारा बदतर की गई जो लगातार अस्थिर सामाजिक कार्यक्रमों का विस्तार करते रहे।

वेनेजुएला में गरीबी का स्तर अब 90 प्रतिशत को पार कर गया है। राशन की दुकानों के बारह कतारें शहर के ब्लॉकों के चारों ओर फैली जाती हैं और मुद्रा के अवमूल्यन के चलते साधारण सामान खरीदने के लिए भारी मात्रा में धन चुकाना पड़ता है और घंटों इंतजार करना पड़ता है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट की ईएफडब्ल्यू रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में वेनेजुएला अब सबसे कम रैंक वाला देश है, जो कि 10 में से 2.92 अंक के साथ 159वें स्थान पर है। ध्यान देना जरूरी है कि यह स्कोर 2016 के आंकड़ों पर आधारित है, और तब से स्थितियाँ और बदतर हो गई हैं।

जब बेहतर जीवन की आशा में लाखों लोग पड़ोसी देशों में विस्थापित हो रहे हैं, एक स्थानीय थिंक टैंक सुधार के लिए डट कर काम कर रहा है और अपने ही देश में लाखों नागरिकों की आशाओं को साकार करने का प्रयास कर रहा है। सीईडीआईसीई (सेंटरो डी डाइवुलजेसियन डेल कोनोसिमेंटो इकोनोमिको पैरा ला लिबरटेड) एक गैर-लाभकारी थिंक टैंक है जो वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था का अध्ययन 1984 से कर रहा है। इसकी स्थापना देश के नीतिगत माहौल से असंतुष्ट उद्यमियों द्वारा की गई थी। पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय द्वारा 2017 में जारी हुई लोकप्रिय अंतर्राष्ट्रीय थिंक टैंक इंडेक्स रिपोर्ट के

अनुसार सीईडीआई दुनिया के शीर्ष 100 थिंक टैंकों में से एक है, जो लैटिन अमेरिका में नौवें स्थान पर है, और जो सबसे प्रभावकारी सार्वजनिक नीति को लेकर 15वें स्थान पर है।

सीईडीआईसीई खुले बाज़ार और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के सिद्धांतों के मूल्यों को एक फलते-फूलते समाज के केंद्रीय रूप के लिए जरूरी मानकर उनका बचाव करता है, प्रचार प्रसार करता है और प्रशिक्षण देता है। यह संगठन बदलाव लाने के लिए अलग-अलग तरह के कार्यक्रम चलाता है, जिसमें शामिल इकोनॉमिक फ्रीडम ऑडिट (ईएफए) वेनेज़ुएला की अर्थव्यवस्था को परेशान करने वाली मूल समस्याओं का समाधान निकालने और देश को वापस स्वतंत्रता और समृद्धि के रास्ते पर लाने वाली योजनाओं और नीतियों से संबंधित विषयों का गहराई से अध्ययन की रूपरेखा तैयार करता है।

सीईडीआईसीई के बारे में

सेडिस का विचार है कि मुक्त बाजार का सिद्धांत और व्यक्तिगत स्वतंत्रता एक स्वतंत्र, नैतिक और ज़िम्मेदार नागरिकों के समाज के निर्माण का आधार है। यह संगठन एक स्वतंत्र और समृद्ध वेनेज़ुएला के लिए संघर्ष करता है जहां उसके नागरिकों का जीवन और संपत्ति सुरक्षित हो। बच्चों, युवाओं और पत्रकारों के लिए आर्थिक प्रोग्राम जैसी विविध गतिविधियों; कंट्री ऑफ ओनर्स प्रोग्राम जो कि निजी संपत्ति के महत्व का प्रचार करता है और एक सेंटर फॉर एथिक्स एंड कॉर्पोरेट सिटिजनशिप के माध्यम से – सीईडीआईसीई सामाजिक और नैतिक बदलाव के लिए लड़ता है। और यह संगठन उल्लेखनीय रूप से प्रभावी है।

वर्ष 2012 में सीईडीआईसी को उसके पत्रकारों के लिए ट्रेनिंग प्रोग्राम हेतु प्रतिष्ठित टेंपल्टन फ्रीडम अवॉर्ड से नवाजा गया, जो कि मीडिया कर्मचारियों को शास्त्रीय उदारवादी विचारों और सीईडीआईसीई के विस्तृत समुदाय से परिचित कराता है। वेनेज़ुएला में मीडिया दमन का एक लंबा इतिहास रहा है और सीईडीआईसीई के काम ने पत्रकारिता पर सरकार की कार्रवाई को चुनौती दी है।

देश की पृष्ठभूमि

वर्ष 2018 में, आर्थिक स्वतंत्रता वेनेजुएला में लगभग पूरी तरह से अनुपस्थित है, जहां भ्रष्टाचार और अपराध है, यहां तक कि देश अधिकांश जरूरी सामानों की कमी से प्रभावित है। देश ने आर्थिक प्रदर्शन और जीवन की गुणवत्ता के मामले में हाल ही में नाटकीय गिरावट देखी है। लेकिन हमेशा से ऐसा नहीं था।

प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध वेनेजुएला ने 20वीं शताब्दी के अंत में व्यापक कृषि उद्यम विकसित किए, मुक्त व्यापार समझौतों द्वारा सुविधा प्रदान कर दुनिया भर में कोको और फिर कॉफी का निर्यात किया। अर्थव्यवस्था बाद में तेल में स्थानांतरित हो गई, जिसने अप्रवासी श्रमिकों को और ज्यादा आकर्षित किया और फलस्वरूप अधिक आर्थिक विकास किया। 20वीं सदी के अंत तक व्यापार और खरीदारी से व्यस्त शहर की सड़कों पर क्षेत्र के किसी भी अन्य देश की तुलना में श्रमिक अधिक मजदूरी का आनंद लेते थे। समाचारपत्रों में चेवी कामारोज़ के विज्ञापन भरे होते थें, जिनका निर्माण वेनेजुएला में ही होता था। दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार के चलते अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की मांग बढ़ने और कीमतों में उछाल आने पर वेनेजुएला ने इसका पूंजीकरण किया। लेकिन देश की वृद्धि विशेष रूप से तेल तक सीमित नहीं थी, और इसी कारण से 1960 के दशक में तेल की कीमतों में गिरावट आने के बावजूद वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था बढ़ती रही।

हालांकि, विस्तार की इस अवधि के बाद, वेनेजुएला ने भारी-भरकम सरकारी नीतियों को अपनाना शुरू कर दिया, जिसमें आर्थिक नियोजन एजेंसियों की स्थापना, कृषि भूमि पुनर्वितरण, मूल्य और विनिमय दर नियंत्रण, आयकरों को तिगुना करना और केंद्रीय बैंक और तेल उद्योग जैसे कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण शामिल थे। फिर भी 1980 तक वेनेजुएला दक्षिण अमेरिका में सबसे अमीर और आर्थिक रूप से सबसे उदार राष्ट्रों में से एक था, जिसे ईएफडब्ल्यू की रिपोर्ट में ऑस्ट्रेलिया के ठीक पीछे 13वां स्थान दिया गया था।

1990 तक कार्लोस आंद्रेस पेरेज़ के राष्ट्रपति काल के दौरान खराब नीतियों का प्रभाव इतना ज्यादा गहरा हो गया कि वेनेजुएला ईएफडब्ल्यू की रैंकिंग में गिरकर 53वें स्थान पर पहुंच गया। बाद में उनको राष्ट्रपति कार्यालय से जबरदस्ती हटा दिया गया और सार्वजनिक धन के गबन का दोषी ठहराया गया।

वेनेजुएला तुलनात्मक रूप से एक युवा लोकतांत्रिक देश है, जिसने स्पेन से आज़ादी प्राप्त करने केलगभग 140 साल बाद 1959 में सभी को मत देने का अधिकार प्रदान किया। उस समय देश में कई तरह की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्थाएं काम कर रही थीं, जिसमें लोकलुभावन विचार अक्सर जीतते रहे। इसने खर्चीले कल्याणकारी नीतियों को जन्म दिया, जो वर्षों तक गुब्बारे की तरह फूलता ही रहा। डूबते जहाज के नियंत्रण के लिए मर

रहे समाजवादियों और छद्यम पूंजीवादियों ने अक्सर अधिक जोखिम लेने में अल्पकालिक लाभ का अहसास किया है। उभरती अर्थव्यवस्था और राजनीतिक आकांक्षाओं से बाहर निकलने वाली नीतियां अब अर्थव्यवस्था में बाधा बन रही हैं।

वर्ष 2000 में, ह्यूगो चावेज़ के शासन काल में, वेनेजुएला की आर्थिक स्वतंत्रता लुढ़कती रही और और गिरकर ईएफए रैंकिंग में 88वें स्थान पर पहुंच गई। 2005 से वेनेजुएला दुनिया में सबसे कम आर्थिक रूप से मुक्त देशों में से एक रहा है। अपने मौजूदा राष्ट्रपति निकोलस मादुरो के शासनकाल में वेनेजुएला ने सरकारी कार्यक्रमों में कटौती किए बिना धन की आपूर्ति बढ़ा दी है, जिससे देश उच्च मुद्रास्फीति का सामना कर रहा है। आईएमएफ ने आशंका जताई है कि 2018 में मुद्रास्फीति की दर 10,00,000 प्रतिशत से अधिक होगी।

आर्थिक संकट और अपनी प्रतिज्ञाओं को पूरा करने में सरकार की अक्षमता ने उसमें व्यापक अविश्वास को जन्म दिया है। सरकारी नेताओं ने तनाव को और बढ़ा दिया है। उदाहरण के लिए, मादुरो की सरकार ने दो लोकप्रिय राजनेताओं, हेनरिक कैप्रिल्स और लियोपोल्डो लोपेज़ को उस समय के राष्ट्रपति के खिलाफ चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित कर दिया। पिछले चुनाव में, वेनेजुएला के केवल 46 प्रतिशत लोगों ने वोट देने की तकलीफ उठाई, जो कि 1960 और 1970 के दशक में 90 प्रतिशत की उपस्थिति से बहुत दूर है। राजनीतिक अविश्वास ने अन्य रूप भी धारण कर लिए हैं, और देशवासी पड़ोसी देशों में जा रहे हैं। कोलंबिया में पिछले दो वर्षों में वेनेजुएला के 5 लाख से अधिक शरणार्थी गए हैं।

आर्थिक और राजनीतिक अस्थिरता के कारण अपराध दरें आसमान छू चुकी हैं। 2017 में राजधानी शहर काराकास दुनिया में दूसरा सबसे अधिक हिंसक शहर था, जिसमें प्रति 1,00,000 निवासियों में से 111 लोगों हत्याएं हुईं। (एक तुलना के रूप में संयुक्त राज्य अमेरिका में सबसे अधिक हिंसक शहर बाल्टीमोर, मैरीलैंड है, जिसमें प्रति 1,00,000 निवासियों में से 56 लोगों की हत्याएं हुई - काराकास का लगभग आधा।) अपराध में तेज़ बढ़ोतरी ने अदालतों को निगल लिया है, जहां 70,000 से अधिक लोगों की सुनवाई लंबित है।

जबकि अधिकांश वेनेजुएला के लोग समस्याओं का सामना कर रहे हैं, कई अमीर, उत्कृष्ट लोग राजनीतिक व्यवस्था का उपयोग करके पूरे समाज की कीमत पर खुद को समृद्ध करने के लिए विशेषाधिकारों का आनंद ले रहे हैं।

- 1984 से 1994 तक, राष्ट्रपति जयमे लुसिन्ची ने सार्वजनिक निधि में अनुमानित 36 बिलियन डॉलर का गबन किया।
- अपने राष्ट्रपति काल में, शावेज़ ने संविधान और अन्य नियमों का उल्लंघन करते हुए 65 मिलियन डॉलर का एयरबेस खरीदा।

- वर्तमान में, शावेज़ परिवार के पास 17 कंट्री एस्टेट हैं जिसका आकार 1,00,000 एकड़ से अधिक हैं, और शावेज़ की बेटी वेनेजुएला की सबसे अमीर महिला है।

परियोजना

वेनेजुएला की गिरती अर्थव्यवस्था के मद्देनज़र वहां की सही तस्वीर पेश कर पाना मुश्किल है कि वहां वास्तव में क्या चल रहा है और अर्थव्यवस्था कैसे पटरी पर लौटेगी। इस मुद्दे को हल करने के लिए, सीईडीआईसीई ने 2016 में फ्रेजर इंस्टीट्यूट और एटलस नेटवर्क के साथ एक इकोनॉमिक फ्रीडम ऑडिट (ईएफए) का आयोजन किया। ऑडिट का उद्देश्य एक स्वस्थ, संपन्न अर्थव्यवस्था के लिए विशिष्ट बाधाओं की पहचान करना था। ईएफए फ्रेजर इंस्टीट्यूट और एटलस नेटवर्क के दिमाग की उपज हैं, जिन्होंने ईएफडब्ल्यू रिपोर्ट में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले देशों में थिंकटैंक की सहायता के लिए एक साझेदारी बनाई है। फ्रेजर इंस्टीट्यूट मूल्यांकन विशेषज्ञता प्रदान करता है, जबकि एटलस नेटवर्क लक्षित देशों में कनेक्शन बनाने के लिए थिंकटैंकों के अपने व्यापक वैश्विक नेटवर्क को आकर्षित करता है।

सीईडीआईसीई, एटलस नेटवर्क और फ्रेजर इंस्टीट्यूट ने साथ में वेनेजुएला के लिए ईएफए की प्रक्रिया शुरू की। सेडिस के अर्थशास्त्री और वेनेजुएला के ईएफए के समन्वयक कार्लोस गोएडर ने बताया, 'हमारा उद्देश्य सूचकांक में मापे गए आयामों को सत्यापित करना, रैंकिंग के लिए विचार किए गए सभी चर (वेरियेबल) का विश्लेषण करना, उनकी गिरावट पर नज़र रखना और इस तरह के महत्वपूर्ण कमजोर प्रदर्शन के कारणों को तलाशना था।'

अपना ऑडिट शुरू करने से पहले, सीईडीआईसीई के कर्मचारी अन्य संगठनों से जुड़े जो पहले से ही अन्य देशों में ईएफए को सफलतापूर्वक पूरा कर चुके थे। नेपाल में एक फ्री-मार्केट थिंकटैंक, समृद्धि फाउंडेशन की सह-संस्थापक और अनुसंधान और विकास सलाहकार अर्पिता नेपाल ने एक सफल ईएफए के संचालन के लिए अपने अनुभव साझा किये और सलाह दिये। इस तरह की गहन परियोजना को शुरू करने से पहले अंतर्दृष्टि प्राप्त करना और सर्वोत्तम तौर तरीके सीखना एक महत्वपूर्ण कदम था। परियोजना के आरंभ से पहले ही प्रारंभिक पाठ्यक्रम सुधार और संशोधन, संसाधनों और सामाजिक पूंजी दोनों को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है।

इसके बाद, सीईडीआईसीई ने फ्रेज़र इंस्टिट्यूट द्वारा बनाए किये गए 42 अलग-अलग चर डाउनलोड किए जो देश के ईएफडब्ल्यू रिपोर्ट स्कोर तैयार करते हैं (डेटा सार्वजनिक रूप से 162 देशों के लिए उपलब्ध है)। तब इसने परिणामों को सत्यापित किया और प्रत्येक चर की तुलनात्मक रैंकिंग और ऐतिहासिक प्रदर्शन की जांच की। फ्रेजर के डेटासेट अक्सर दो

रिपोर्ट से आते हैं - वर्ल्ड बैंक की डूइंग बिजनेस रिपोर्ट, जो 189 अर्थव्यवस्थाओं में व्यापार करने में आसानी को मापता है, और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम द्वारा तैयार वर्ल्ड कॉम्पटिटिवनेस रिपोर्ट, जो 138 देशों का विश्लेषण करती है। साहित्य की समीक्षा का संचालन करना और स्थानीय हितधारकों के साथ जुड़ने और उन्हें कार्यशाला में भाग लेने के लिए आमंत्रित करने की अपनी आउटरीच योजना को लागू करने में मार्च से जुलाई, 2016 तक कुल पांच महीने लगे।

एक बार जब उपयुक्त डेटा एकत्र हो गया तब तारीख निर्धारित की गईं, निमंत्रण भेजे गए और विशेषज्ञों के पैनल ने सूचकांक के प्रत्येक क्षेत्र की अपनी समीक्षा शुरू की। अप्रैल से जून तक, सीईडीआईसीई ने संभावित हितधारकों से संपर्क किया और ईएफडब्ल्यू रिपोर्ट की प्रत्येक श्रेणी के लिए सात कार्यशालाओं का आयोजन किया।

चुनौती : भागीदारी में बाधाएं

सफलतापूर्वक योग्य प्रतिभागियों को इकट्ठा करना सीईडीआईसीई की प्रमुख चुनौतियों में से एक था। वेनेजुएला की आर्थिक और राजनीतिक स्थिति गंभीर है, और हितधारकों को इकट्ठा करने की कोशिश करते समय सीईडीआईसीई को बाधाओं का सामना करना पड़ा। सामान्य लॉजिस्टिक मुद्दों के अलावा, काराकस के निवासियों के पास कार्यक्रम को अनदेखा करने के और भी कई कारण हैं। सबसे पहले, कमी और लंबी कतारों के चलते भोजन या सेवाएं खरीदना एक समय लेने वाला काम है। काम के घंटे सीमित हैं, और बिना किसी वित्तीय मुआवजे के एक कार्यशाला में जाने के लिए मजबूत प्रतिबद्धता की आवश्यकता होती है। दूसरा, सरकार और उसकी नीतियों के दुश्मन के रूप में पहचाने जाने का डर। वेनेजुएला में एक 'विरोधाभासी' माने जाने का परिणाम नौकरी खोने, सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने में जटिलताएं झेलने और यहां तक कि संभावित प्रतिबंधों के साथ अभियोजन भी हो सकता हैं। अंत में, जैसा कि पहले ही बताया जा चुका है, काराकास दुनिया में अधिकतम हत्या दर वाले शहरों में से एक है, और काम के घंटों के बाद बाहर रहना खतरनाक है।

भर्ती किए गए विशेषज्ञों को ईएफए के विभिन्न क्षेत्रों के अनुसार वर्गीकृत किया गया। वेनेजुएला सरकार द्वारा उत्पीड़न से बचने के लिए सीईडीआईसीई ने प्रत्येक विशेषज्ञ को राय की गोपनीयता की गारंटी दी। इस तरह की सुरक्षा मतदान और उपस्थिति के लिए एक शक्तिशाली प्रोत्साहन थी। इन कार्यशालाओं के दौरान, 48 संगठनों के प्रतिनिधियों ने आर्थिक स्वतंत्रता के परस्पर संबंधित पहलुओं पर चर्चा की। इन कार्यशालाओं में गैर-लाभकारी संस्थाओं, परामर्श फर्मों, कानून फर्मों, विश्वविद्यालयों, यूनियनों और यहां तक कि काराकस चैंबर ऑफ कॉमर्स भी शामिल थे।

हितधारकों को इकट्ठा करने में सीईडीआईसीई की सफलता उस सामाजिक पूंजी के कारण थी, जो संगठन के इतिहास के दौरान बनाई गई थी। 1984 से, सीईडीआईसीई ने कई आयोजनों की मेजबानी की और प्रसिद्ध प्रकाशनों को प्रकाशित किया। उन्होंने साथियों, प्रचारकों और वार्ताकारों के एक डेटाबेस को भी बनाए रखा है, जो सीईडीआईसीई के काम को विश्वसनीय और गंभीर मानते हैं, भले ही वे संगठन के राजनीतिक रायों से असहमत हों। अन्य वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त संगठनों ने प्रतिभागियों को आकर्षित करने में और वैधता देने में ईएफए की मदद की।

अंततः, सीईडीआईसीई ने 25-28 जुलाई, 2016 तक मिलने के लिए 108 विभिन्न हितधारकों को इकट्ठा किया। हितधारकों में विश्वविद्यालयों, सार्वजनिक एजेंसियों, यूनियनों, मीडिया, नागरिक समाज संगठनों, बैंकों और कंपनियों के प्रतिनिधि, नेता और उद्यमी शामिल थे। उपस्थित व्यक्तियों में व्यापक ऐतिहासिक और मात्रात्मक ज्ञान के साथ-साथ अपने पेशों से जुड़े ऐसे लोगों को भी शामिल किया गया, जिनके पास अपने उद्यम के बारे में महत्वपूर्ण गुणात्मक और अंतर्निहित ज्ञान था।

चुनौती : डेटा से तेज़ चलना

सीईडीआईसीई के सामने एक और महत्वपूर्ण चुनौती यह थी कि 2016 की ईएफडब्ल्यू रिपोर्ट, जिसका वह शुरू में उपयोग कर रही थी, 2014 के आंकड़ों पर आधारित थी। यह डेटा अधिकांश देशों के लिए पर्याप्त रूप से सटीक होता, लेकिन 2014 के बाद से वेनेजुएला की तेजी आर्थिक गिरावट के कारण वास्तविकता का इस डेटा से सही आर्थिक स्थिति का आंकलन करने और लागू करने योग्य नीतिगत सुझावों में उपयोगी होने के लिए बहुत वियोजित होने का खतरा था। परिणामस्वरूप, सीईडीआईसीई ने अपनी रिपोर्ट को तब तक स्थगित करने का फैसला किया जब तक कि ईएफडब्ल्यू डेटा स्रोत 2016-2017 के डेटा के साथ प्रकाशित नहीं हुए। नया डेटा अक्तूबर, 2016 में जारी किया गया था। अद्यतन डेटा की प्रतीक्षा में सीईडीआईसीई के ईएफए रिपोर्ट के नियोजित प्रकाशन में देरी हुई। हालांकि, सीईडीआईसीई ने तय किया कि अधिक सटीक डेटा का लाभ इस लागत से अधिक महत्वपूर्ण है, जिसने बेहतर व्यापक आर्थिक संकेतक प्रदान किए। अंत में, अपडेट किए गए डेटा ने वेनेजुएला की एक गंभीर तस्वीर को चित्रित किया, लेकिन इसने अधिक विश्वसनीय आधार रेखा भी प्रदान करी कि किस आधार पर सुधारों का निर्माण होना चाहिए।

ईएफए कार्यशालाओं को रोलआउट करने के लिए, फ्रेजर इंस्टीट्यूट के फ्रेड मेकमहोन ऑडिट को लागू करने के लिए सीईडीआईसीई टीम में शामिल हुए। उन्होंने प्रत्येक सत्र को

मुक्त अर्थव्यवस्थाओं के प्रदर्शन की समीक्षा के साथ खोला और बताया कि वे वेनेजुएला की आर्थिक प्रणाली कैसे भिन्न हैं। मेकमहोन ईएफए के दौरान एक महत्वपूर्ण सहयोगी थे, क्योंकि वे पिछले ऑडिट के लिए पहले ही अन्य देशों का दौरा कर चुके थे। सीईडीआईसीई के लोग इस बात से चिंतित थे कि फ्रेजर इंस्टीट्यूट जैसे हाई-प्रोफाइल थिंक टैंक को कैसी प्रतिक्रिया मिलेगी! आखिरकार, सरकारी अधिकारी और यूनियन नेता वर्कशॉप में भाग ले रहे थे। लेकिन मुख्य स्रोतों और अच्छे पारस्परिक कौशल से मेकमहोन की जानकारी के वितरण ने उन्हें दर्शकों तक पहुंचाया।

सीईडीआईसीई और मेकमहोन ने काराकास में ब्रिटिश दूतावास के अर्थशास्त्र और सतत विकास विभाग का भी दौरा किया। विभाग ने रिपोर्ट रूची दिखाई और पूरे व्यापारिक समुदाय में रिपोर्ट के निष्कर्षों को प्रसारित करने की बात कही। इसके अतिरिक्त, सम्मेलन के दौरान, मेकमहोन ने एक गैर-लाभकारी स्थानीय व्यापार संघ, कंसेकोमेर्सियो का दौरा किया। वहां, उन्होंने लगभग 50 व्यापारियों और प्रबंधकों के साथ आर्थिक स्वतंत्रता के लाभों पर चर्चा की। गहन अनुभव और मज़बूत ज्ञान रखने वाले संगठनों के साथ साझेदारी करना एक नई परियोजना के रोलआउट का समर्थन करने का एक मूल्यवान तरीका है।

ईएफए की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि कार्यशाला की चर्चाएं पूरी तरह से बर्बाद नहीं थीं, या केवल विशुद्ध रूप से मात्रात्मक डेटा की जांच करने पर केंद्रित नहीं थीं। संख्याओं को परिशिष्ट करने में मदद करने के लिए दमनकारी वेनेजुएला की अर्थव्यवस्था के माध्यम से संघर्ष कर रहे नागरिकों ने अपनी व्यक्तिगत गवाही प्रस्तुत की।

ओसवाल्डो बोनिलो नाम के एक प्रतिभागी ने अपनी कहानी साझा की। बोनिलो एक मेकेनिकल वर्कशॉप का मालिक था, जिसे 2011 में वेनेजुएला सरकार ने जब्त कर लिया था। हालांकि, उस पर कभी औपचारिक रूप से आरोप नहीं लगाया गया था और न ही उसे सज़ा हुई, पर सरकार ने उनकी संपत्ति को ज़ब्त कर लिया था। उस व्यक्ति के 50 सालों की कड़ी मेहनत से अर्जित संपत्ति को सरकारी एजेंसी के एक मनमाने फैसले ने मात्र 48 घंटों में लूट लिया। बोनिलो ने कानूनी प्रणाली और संपत्ति के अधिकार पर कार्यशाला के दौरान कहा, 'मैंने निजी संपत्ति के मामलों पर ध्यान देना तब शुरू किया, जब मैं ज़ब्ती का शिकार हुआ।'

बोनिलो की कहानी असामान्य नहीं है। सीईडीआईसीई द्वारा प्रायोजित ऑब्जर्वेटरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स के अनुसार, वेनेजुएला सरकार ने 2015 में 28,000 निजी उद्यमों को बंद कर दिया और चार मिलियन वर्ग मीटर से अधिक निजी भूमि को जब्त कर लिया। बोनिलो को कभी मुआवजा नहीं दिया गया था, और न्यायपालिका का निर्णय आना अभी बाकी है।

कार्यशाला में शामिल एक वकील ने कहा कि 'निजी संपत्ति का स्वामित्व वेनेजुएला में अपराध है'। 2015 में, प्रति दिन छोटे व्यवसायों पर औसतन 256 हमले हुए। इसके

अलावा, निजी संपत्ति को लेकर उपेक्षा, वेनेजुएला के संविधान में अनुच्छेद 115 और 116 में क़ानून सहित उल्लिखित है, जिसके अनुसार 'संपत्ति ऐसे योगदान, प्रतिबंध और दायित्वों के अधीन होगी, जो जनता की सेवा में कानून द्वारा या सामान्य हित में स्थापित की जा सकती है।'

इन कार्यशालाओं से वेनेजुएला के संपत्ति के अधिकार संरक्षण स्कोर को बढ़ाने में मदद करने के लिए और निजी संपत्तियों के सरकारी जब्ती से प्रभावित वास्तविक लोगों को सकारात्मक बदलाव प्रदान करने के लिए नीति प्रस्तावों की एक श्रृंखला उभरी। कानून के छात्रों के एक समूह ने संपत्ति अदालतों के निर्माण का सुझाव दिया। वर्तमान में, वेनेजुएला के पास संपत्ति विवादों को निपटाने के लिए विशेष अदालतों का अभाव है। बोनिलो की तरह, जिनकी संपत्ति का निष्कासन होता है, उनके पास कानूनी सहारे के लिए कोई व्यवहार्य माध्यम नहीं है। ये नई स्थापित संपत्ति अदालतें जब्त की गई संपत्ति लौटा देंगी और उन्हें एकमात्र आदेश होगा कि वे ज़ब्ती के निर्देश दे सकें। इसके अलावा, संपत्ति के अधिकारों की व्यापक सांस्कृतिक अवहेलना को संबोधित करने में मदद करने के लिए, प्रतिभागियों ने आवास सब्सिडी के लाभार्थियों के लिए आवास स्वामित्व के दस्तावेजों के निर्माण का सुझाव दिया। इस विचार के आधार पर कि अधिक गृहस्वामी बनाने से वेनेजुएला वासियों को निजी संपत्ति के संदर्भ में पेश करने से फायदा हो सकता है।

अन्य कार्यशालाओं के दौरान भाषणों और चर्चाओं के परिणामस्वरूप अतिरिक्त सार्वजनिक नीति के प्रस्ताव आए। इन सब का लक्ष्य 'त्वरित जीत' था, जिसका व्यावहारिक समायोजन अपेक्षाकृत कम कठिनाइयों या लागतों के साथ लागू होने के दौरान एक बड़ा प्रभाव डाल सकता है। इन छोटे समायोजनों से वेनेजुएला के लोगों के जीवनस्तर में सुधार हो सकता है।

चुनौती : सरकार की भूमिका की थोपी हुई दृष्टि

वेनेजुएला समाज का एक विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण तत्त्व अर्थव्यवस्था में सरकारी हस्तक्षेप का पक्ष लेने की प्रवृत्ति है। ईएफए कार्यशालाओं से खुलासा हुआ कि मुक्त बाजारों के विचार से सहमत लोगों के मन में भी सरकारी हस्तक्षेप को सही मानने की भावना दृढ़ता से जुड़ी हुई है। सीईडीआईसीई ने पाया कि न तो सरकारी नौकरशाह और न ही विपक्षी दल सही उदारीकरण में विश्वास करते हैं, बल्कि वे केवल उदार सरकारी नियमों और नियंत्रणों का समर्थन करने के लिए तैयार हो सकते हैं। सीईडीआईसीई के पिछले कार्य, जैसे कि पत्रकार प्रशिक्षण कार्यक्रम ने व्यवसाय, उदारीकरण और उद्यमियों के महत्व के बारे में नैरेटिव को बदलने पर ध्यान केंद्रित किया है। ईएफए के दौरान, यह 'त्वरित जीत' पर ध्यान केंद्रित करने का एक कारण था।

कार्यशालाओं में संभावित विरोधी विचारधारा के लोगों को साथ लाने में मदद करने के लिए, सीईडीआईसीई और मेकमहोन ने त्वरित परिचर्चाएं लिखीं, जिन्होंने तथ्यों, आंकड़ों और हाल ही में समाचारों का उपयोग किया ताकि वे उत्तेजित हो सकें और चर्चा शुरू कर सकें। उदाहरण के लिए, मज़बूत मुद्रा पर सत्र के दौरान, उन्होंने मुद्रास्फीति, मौद्रिक आधार वृद्धि और सीपीसी मुद्रास्फीति के वैकल्पिक उपायों पर सबसे हालिया संख्याएं एकत्र और प्रस्तुत कीं। इसका समापन अर्थव्यवस्था के 'डॉलरीकरण' के लिए एक प्रस्ताव के रूप में हुआ, जो कि अन्य दक्षिण अमेरिकी देशों द्वारा लागू की गई नीतियों की तरह अमेरिकी डॉलर को पूर्ण समर्पण है। यूएस 3 डॉलर के आसपास मंडराता न्यूनतम वेतन और भारी मुद्रास्फीति वाले देश में, इस तरह के विचार दर्शकों के एक व्यापक समुदाय के लिए आकर्षक है। वास्तव में, मज़बूत मुद्रा पर कार्यशाला के समापन के बाद, यूनियन नेताओं ने मेकमहोन के साथ तस्वीरों का अनुरोध किया।

ईएफए की सफलता की एक कुंजी सभी सिफारिशों को सुनने और नीति सिफारिशों का मसौदा तैयार करने के लिए वैचारिक शुद्धता पर जोर नहीं देने की इच्छा थी। यद्यपि अंतिम लक्ष्य विनिमय दर और मूल्य नियंत्रण का विघटन है, अल्पकालिक नीतियां भी महत्वपूर्ण हैं, और व्यस्तता का वातावरण प्रदान करने से लंबी अवधि में अधिक प्रभावी ढंग से नीति को प्रभावित करने की क्षमता है।

अतिरिक्त नीति सिफारिशों में निजी कंपनियों के लिए पंजीकरण में ढील, निर्यात/आयात प्रलेखन और एकल आधिकारिक वेबपेज में शुल्क और सरकार के नियंत्रण में गैर-कानूनी संपत्ति का निजीकरण करना, और सार्वजनिक कंपनियों के शेयरों के एक अंश को शेयर बाजार में घरेलू रूप से या विदेश में सूचीबद्ध करने की अनुमति देना शामिल थे।

बोनिलो की कहानी, कार्यशाला की चर्चाएं, और नीतिगत अनुशंसाएं बनाने में भागीदारी सीईडीआईसीई के ईएफए के सफल होने के तरीके को प्रदर्शित करती है। ऑडिटर ने विशेषज्ञ की गवाही, मात्रात्मक डेटा, व्यक्तिगत कहानियों के संयोजन और फ्रेजर इंस्टीट्यूट के इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ द वर्ल्ड रिपोर्ट की आर्थिक स्वतंत्रता में परिभाषित श्रेणियों में से प्रत्येक के लिए नीति प्रस्ताव के माध्यम से काम किया।

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

एक सफल ऑडिट से गंभीर नीतिगत परिवर्तन और वैचारिक बदलाव हो सकते हैं, इसलिए सफलता सुनिश्चित करने वाले कारकों का निर्धारण करना महत्वपूर्ण है। सीईडीआईसीई के ईएफए से चार महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं।

1. सीईडीआईसीई के शोधकर्ताओं ने उपलब्ध आंकड़ों को अच्छी तरह से समझा, यहां तक कि रोलआउट में देरी कर इस बात को सुनिश्चित किया कि उनके ऑडिट में उनके देश का सटीक प्रतिनिधित्व हो।
2. सीईडीआईसीई ने अपने नेटवर्क के अनुभव का उपयोग वेनेजुएला के नेताओं और उद्योगों के प्रभाव क्षेत्र तक पहुंचने के लिए किया। समृद्धि फाउंडेशन और फ्रेड मेकमहोन जैसे सहयोगियों के पास ईएफए को सफल बनाने के लिए आवश्यकताओं के बारे में विस्तृत अनुभव था। ऑडिट पूरा कर चुके अन्य लोगों से संपर्क करना अनुभव से सीखने और गलतियों से बचने का एक आसान तरीका है।
3. ऑडिट में भाग लेने वाले हितधारक और नेता योग्य, अनुभवी, विविध और परिवर्तन के लिए प्रतिबद्ध थे। सेडिस ने हितधारकों को इकट्ठा किया जो उदारीकरण के लिए प्रतिबद्ध थे और अन्य जो शुरू में विरोधी थे। सामान्य सूत्र यह था कि हर कोई अपने ढहते राष्ट्र के पुनर्निर्माण के लिए इकट्ठा हुआ था और अपने और अपने हमवतनों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए विचारों की पेशकश की थी।
4. प्रस्तुतियों और भाषणों में मात्रात्मक और गुणात्मक सामग्री का संतुलन दिखाई दिया। विभिन्न क्षेत्रों और उद्योगों के लोग कार्यशालाओं में शामिल हुए। इनमें प्रोफेसरों से लेकर नौकरशाह और यूनियन प्रतिनिधि तक शामिल थे। इस प्रकार उत्पादक सहभागिता को सुविधाजनक बनाने के लिए सत्र को सभी के लिए सुलभ रखना अत्यावश्यक था।

वेनेजुएला की सामाजिक और आर्थिक अवस्था इतनी बदतर हो गई है जितना किसी ने 50 साल पहले अनुमान भी नहीं लगाया होगा, और पुनरुद्धार के मार्ग को हासिल करना पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हो गया है। बावजूद इसके कि वर्तमान और भविष्य की संभावनाएं अभी भी मंद हैं, यह तथ्य कि एक आर्थिक स्वतंत्रता ऑडिट न केवल संभव हुआ, बल्कि इस तरह मजबूत भागीदारी प्रमाणकारी है। वेनेजुएला के विभिन्न क्षेत्रों में नेताओं द्वारा भागीदारी यह दर्शाता है कि नागरिक एक समाजवादी शासन की समस्याओं को पहचानते हैं और परिवर्तन के लिए लड़ने को तैयार हैं। ईएफए की सफलता एक छोटे थिंकटैंक को प्रभावित करने के लिए एक वसीयतनामा भी है जो प्रभावी कार्यक्रमों और परिचालन अधिवक्ताओं से भरा हो सकता है जब प्रभावी कार्यक्रमों, परिचालन विशेषज्ञता और संपर्कों के एक कार्रवाई योग्य नेटवर्क से लैस हो।

क्रॉस-पार्टिशन द्वारा विकसित की गई नीतिगत सिफ़ारिशें, विविध रूप से संबद्ध ईएफए कार्यशालाएं वेनेजुएला की समृद्धि की ओर लौटने का एक मजबूत और सकारात्मक पहला कदम हैं। ऑडिट द्वारा तैयार की गई रिपोर्ट सीईडीआईसीई को और अधिक बौद्धिक विश्वसनीयता प्रदान करती है क्योंकि यह सामाजिक परिवर्तन के कार्य को आगे बढ़ाती

रहती है। ईडीए के सीईडीआईसीई का अनुकरणीय कार्यान्वयन, घोर विरोध की स्थिति में आर्थिक स्वतंत्रता के अन्य पैरोकारों को प्रेरणा और एक प्रतिकृति प्लेबुक प्रदान करता है।

चर्चागत प्रश्न

- आपकी संस्था कौन-सी परियोजना चला सकती है जो आपके संगठन को लाभ नहीं पहुंचाएगी, लेकिन मापने योग्य नीति में बदलाव ला सकती है? यदि आपके संगठन को कभी भी इसके काम का श्रेय नहीं मिलता है, तो क्या यह इसके लायक है?
- नीतिगत परिवर्तन के निर्माण में डेटा कितना उपयोगी है? क्या आपके पास कभी बहुत अधिक डेटा हो सकता है?
- ऐसी कौन सी संगठनात्मक साझेदारी हैं जो आपके संगठन को सहयोग के माध्यम से अपने मिशन को बेहतर ढंग से प्राप्त करने में मदद कर सकती हैं? विस्तृत रूप में वह सहयोग कैसा दिखता है (जैसे, कौन क्या भूमिकाएं निभाता है)?
- क्या देश की अर्थव्यवस्था किसी ऐसे बिंदु पर पहुंच सकती है जहां से लौटना संभव न हो? यदि हां, तो आप कैसे जानते हैं जब आप उस बिंदु पर पहुंच गए हैं? यदि नहीं, तो क्यों नहीं?
- आपके संगठन ने ऐसी कौन-सी कुर्बानियां दीं जो आपके लक्षित दर्शकों द्वारा जुड़ाव को प्रोत्साहित कर सकती हैं? कम (या अधिक) वैचारिक रूप से विवश होना? क्या अंत, साधन का औचित्य साबित करता है?

आशा की किरण

इजिप्टियन सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीज़ (ईसीपीपीएस)
इजिप्ट

पानी सदियों से मिस्र के लिए समृद्धि लेकर आया है। नील नदी और उपजाऊ मिट्टी द्वारा प्रदान की गई समृद्धि ने ऐतिहासिक रूप से कृषि उत्पादन का वरदान प्रदान किया है। लेकिन आधुनिक समय में, पानी का एक निकटवर्ती निकाय स्वेज नहर अपने साथ वाणिज्य का बाढ़ लाया। 1869 में खोली गयी यह नहर एक कृत्रिम जलमार्ग है जो भूमध्य सागर को लाल सागर के माध्यम से उत्तरी हिंद महासागर से जोड़ता है। प्रत्येक वर्ष, यह 17,550 जहाजों (पनामा नहर की तुलना में 25 प्रतिशत अधिक यातायात) को प्रत्येक दिशा में 4,000 मील की समुद्री यात्रा को बायपास करने की अनुमति देता है।

उद्घाटन के बाद से, स्वेज नहर समृद्धि के अपने वादे के साथ राजनीतिक शक्ति के लिए एक कड़ी रही है। मिस्र राजनीतिक तनाव से अनजान नहीं है। जबसे इसका इतिहास शुरू हुआ, तब से इस पर नियंत्रण के लिए मरने वाली शक्तियां मौजूद रही हैं जैसे कि फारसी, रोमन, अरबी, तुर्क और अंग्रेज़। बाहर के दलों ने मिस्र के लोगों के दैनिक शासन को बेहतर या बदतर के लिए प्रभावित किया है।

हाल ही के वर्षों में, देश के प्रदर्शन पर राजनीतिक ताकतों के प्रभाव को मापना अधिक संभव हो गया है। विकास को अनलॉक करने के इच्छुक सामाजिक वैज्ञानिकों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने नीति निर्धारण को सूचित करने के लिए मापने के नए उपकरण विकसित किए हैं। ऐसा ही एक संकेतक है फ्रेजर इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया गया इकोनॉमिक फ्रीडम ऑफ वर्ल्ड (ईएफडब्ल्यू) रिपोर्ट। आर्थिक स्वतंत्रता व्यक्तियों और संपूर्ण समाजों के कल्याण के अन्य मैट्रिक्स के साथ दृढ़ता से संबंधित है। ईएफडब्ल्यू सूचकांक सार्वजनिक नीति संकेतकों की एक सीमा पर प्रदर्शन को दर्शाता है, जिसमें सरकार का आकार, कानूनी प्रणाली और संपत्ति अधिकारों की सुरक्षा, मज़बूत मुद्रा, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार करने की स्वतंत्रता और विनियमन शामिल हैं।

मिस्र इनमें से प्रत्येक क्षेत्र में अविकसित रहा है। वास्तव में मिस्र ईएफडब्ल्यू रिपोर्ट के नवीनतम संस्करण में सबसे कम रैंक वाले देशों में से एक है, जो 159 में से 140वें स्थान

पर है। 10.73 में से 5.73 के स्कोर के साथ व्यक्तिगत स्वतंत्रता के मामले में मिस्र 156वें स्थान पर है। लेकिन हालात हमेशा से ऐसे नहीं थे। मिश्र हालांकि रिपोर्ट की तालिका में कभी भी शीर्ष पर नहीं रहा, लेकिन पिछले एक दशक से लगातार मध्य के आस पास था। 2000 में, मिस्र आर्थिक स्वतंत्रता के मामले में 123 में से 72वें स्थान पर था, जिसका अर्थ है कि शीर्ष के 39 प्रतिशत देशों में शामिल रहने वाला देश तालिका में नीचे के 12 प्रतिशत देशों के बीच आ गिरा है।

विभक्ति बिंदु को अरब स्प्रिंग से जोड़ा जा सकता है। 25 जनवरी, 2011 को, मिस्र के लोग राजनीतिक और आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि के विरोध में काहिरा के तहरीर चौक की सड़कों पर उतर आए। पुलिस के साथ झड़पों में 800 से अधिक लोगों की मौत हो गई थी। प्रदर्शन के परिणामस्वरूप मिस्र के लंबे समय तक तानाशाह होस्नी मुबारक को हटा दिया गया। उथल-पुथल से बाहर, मुस्लिम ब्रदरहुड के मोहम्मद मोर्सी राष्ट्रीय नेता के रूप में उठे, लेकिन वह दौर अल्पकालिक था। आगे चलकर राष्ट्रीय उथल-पुथल का दौर एक बार फिर शुरु हुआ, विरोध प्रदर्शन हुए तथा एक और शासन परिवर्तन हुआ।

सरकार ने लंबे समय से अधिक व्यय के माध्यम से जनता को खुश करने की कोशिश की है। इस तरह की नीतियों ने देश में नए प्रकार के विपत्तियां ला दी हैं : सब्सिडी, मुद्रास्फीति, और ऋण। सार्वजनिक ऋण जीडीपी के 100 प्रतिशत को पार कर गया है। ईंधन, पानी और भोजन पर भारी सब्सिडी दी जाती है। उदाहरण के लिए, मिस्र के लोग ईंधन की लागत का केवल 59 प्रतिशत भुगतान करते हैं, और राज्य बाकी का भुगतान करता है (पांच वर्षों में 30 बिलियन डॉलर की राशि हो गई है)। ये सब्सिडी मिस्र के सार्वजनिक व्यय का लगभग एक-तिहाई और जीडीपी का 13 प्रतिशत है। इसने अर्थव्यवस्था में बाजार की विकृतियों को जन्म दिया है, जिसने निवेश को ठंडा कर दिया है।

सार्वजनिक खर्च में वृद्धि के बावजूद, आवश्यक संस्थान टूट गए हैं और समाज लोगों के सत्ता के साथ संबंधों के आधार पर खंडित हो गया है। मेज के नीचे से भुगतान (रिश्वत) महत्वपूर्ण हो गया है और खराब तरीके से लागू किए गए कानून और गहराई तक जड़ जमा चुके भ्रष्टाचार के कारण कुछ व्यवसायियों ने संबंधों और बिचौलियों का फायदा उठाया, जबकि अन्य विशेष सुलूक का आनंद उठाते हैं। 2016 में, सार्वजनिक सेवाओं का इस्तेमाल करने वाले मिस्र के करीब आधे लोगों ने रिश्वत दी। एक-चौथाई कारोबारियों ने वर्तमान मिस्र की कोर्ट प्रणाली को देश में व्यापार करने की उनकी क्षमता में एक प्रमुख बाधा के रूप में चिह्नित किया है।

अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने नोटिस लिया है, और कुछ समूहों ने रचनात्मक परिवर्तन किया है। 2016 में, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ने मिस्र की सरकार के अनुरोध पर किश्तों में 12 बिलियन डॉलर का ऋण देना शुरू किया। अब तक मिस्र सरकार ने इससे कुछ आर्थिक सुधार किए हैं।

- मिस्र ने अपनी मुद्रा का अवमूल्यन किया, मिस्र के पाउंड को लचीला बना दिया और बाजार को इसका मूल्य निर्धारित करने की अनुमति दी।
- शेयरधारकों के अधिकारों में वृद्धि करके और उन्हें बड़े कॉर्पोरेट निर्णयों में अधिक से अधिक भूमिका प्रदान करके अल्पसंख्यक निवेशक सुरक्षा को मजबूत किया।
- ऊर्जा और ईंधन सब्सिडी में कटौती के लिए प्रतिबद्धता जाहिर की है।
- यह संकेत दिया गया है कि यह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उभरते बाजार बांड सूचकांकों में शामिल किया जाएगा।

हालांकि, यह स्पष्ट नहीं है कि परिवर्तन आत्मविश्वास को मजबूत बनाएंगे या नहीं, और इसके अलावा किसी भी परिवर्तन से महत्वपूर्ण संस्थानों में संरचनात्मक रूप से सुधार होगा या नहीं। और क्या कोई परिवर्तन संरचनात्मक रूप से महत्वपूर्ण संस्थानों में सुधार करेगा। मिस्र के राजनीतिक परिदृश्य के प्रतीक, इस महत्वपूर्ण समय में प्रभाव के लिए उठने वाले आवाज़ों में विविधता है। लेकिन एक मजबूत आवाज मिस्र के सेंटर फॉर पब्लिक पॉलिसी स्टडीज (ईसीपीपीएस) से आती है, जिसका न केवल इस तरह के उथल-पुथल के भीतर संचालन करने का एक प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड है, बल्कि वास्तविक नीति परिवर्तन को प्रभावित करने की क्षमता रखता है।

परियोजना

मिस्र का अशांत वातावरण बदलाव के लिए मौका तो प्रदान करता है, लेकिन बहुत सारी समस्याएं भी हैं जिनको दूर करने की जरूरत है।। मौजूदा समय में समस्या को देखना सरसरी तौर पर पहला कदम है जबकि प्रगति को प्रभावित करने के लिए वास्तविकता की बारीकियों को समझना वास्तविक कुंजी है। जबकि ईसीपीपीएस का व्यापक लक्ष्य समाज को बेहतर बनाना है और इसने फैसला किया कि आर्थिक आजादी को प्रतिबंधित करने वाले कारकों को पहचान कर उनमें सुधार करना है।

इन महत्वपूर्ण क्षेत्रों का निर्धारण करने के लिए ईसीपीपीएस ने आर्थिक मूल्यांकन में मजबूत अनुभव वाले दो संगठनों फ्रेजर इंस्टीट्यूट और एटलस नेटवर्क के साथ गठजोड़ किया। विशेष रूप से, उन्होंने एक आर्थिक स्वतंत्रता लेखा परीक्षा (ईएफए) शुरू की। यह परियोजना न केवल मिस्र के आर्थिक संकट की जड़ का पता लगाएगी, बल्कि यह अधिक से अधिक स्वतंत्रता और समृद्धि के लिए एक रोडमैप प्रदान करेगी।

ईसीपीपीएस क्या है

द इजिप्टियन सेंटर फॉर पब्लिक स्टडीज़ (ईसीपीपीएस) एक अपेक्षाकृत युवा थिंक टैंक है, लेकिन इसका पहले से ही गौरवशाली एक अतीत रहा है। यह इजिप्टियन यूनियन ऑफ लिबरल यूथ - (ईयूएलवाइ) का उत्तराधिकारी है, जिसकी स्थापना 2007 में मिस्र में एक सांस्कृतिक आंदोलन के निर्माण के लिए की गई थी जो आजादी को महत्व देता है। मिस्र की आधी से अधिक आबादी 25 वर्ष से कम आयु की है, इसलिए सामाजिक परिवर्तन को प्रभावित करने के लिए युवा लोगों तक पहुंचना सबसे महत्वपूर्ण है। ईयूएलवाइ का महत्वाकांक्षी मिशन न केवल देश में युवा लोगों के लिए उदार विचारों का प्रसार करना था, बल्कि उन्हें एक साथ लाना और उदार संस्कृति, जैसे कला, साहित्य और प्रतिनिधि राजनीति के परिणाम के लिए प्रोत्साहन के वातावरण का निर्माण करना था।

2009 में, एटलस नेटवर्क ने अपने निबंध प्रतियोगिता के लिए ईयूएलवाई को स्वतंत्रता को बढ़ावा देने में उत्कृष्टता के लिए टेम्पल्टन स्वतंत्रता पुरस्कार से सम्मानित किया, जिसका तात्कालिक विषय था 'मैं उदार क्यों हूं'। इस पहल को छह प्रमुख समाचारपत्रों, एक युवा रेडियो स्टेशन और मिस्र के दो प्रमुख राजनीतिक दलों द्वारा प्रचारित प्रसारित किया गया था। 2011 में मिस्र के समाज पर बड़े पैमाने पर व्यापक प्रभाव पैदा करने के लिए ईयूएलवाई को एक थिंकटैंक- ईसीपीपीएस में बदल दिया गया। ईसीपीपीएस का मिशन मिस्र में कानूनी और आर्थिक प्रणाली में सुधार लाने (जैसे मुक्त बाजार, सीमित सरकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और कानून के शासन के सिद्धांतों को बढ़ावा देना) के उद्देश्य से सार्वजनिक नीतियों का प्रस्ताव करना है। ईसीपीपीएस आर्थिक, नागरिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कानूनी सुधारों और सार्वजनिक नीतियों का समर्थन करने के लिए साक्ष्य-आधारित शोध प्रदान करता है। वे अपने अर्जित प्रभाव का उपयोग देश को स्वतंत्रता और सुधार की ओर झुकाने (मोड़ने) के लिए करते हैं।

ऑडिट शुरू करने से पहले, ईसीपीपीएस ने मिस्र की वर्तमान स्थिति और एक सफल ईएफए का संचालन कैसे किया जाए, दोनों के गहन मूल्यांकन का प्रयास किया। उन्होंने फ्रेजर द्वारा मुहैया कराई गई विशेष सामग्री पर ड्राइंग के आधार पर पांच मुख्य ईएफडब्ल्यू श्रेणियों और 42 उप संकेतकों की कठोर समीक्षा शुरू की। उन्होंने अन्य संगठनों की भी समीक्षा की जिन्होंने सफल ईएफए को पूरा किया था। इस जांच के बाद, ईसीपीपीएस ने विशेष रूप से ईएफडब्ल्यू सूचकांक के चार लाभ वाले उप घटकों - बौद्धिक संपत्ति, गैर टैरिफ व्यापार बाधाओं, मौद्रिक और राजकोषीय नीतियों, और सब्सिडी को लक्षित करने के लिए ईएफए के दायरे को सीमित कर दिया।

चार नीतिगत विषय ऐसे क्षेत्रों के रूप में उभरे हैं, जो ठोस सुधारों के लिए तैयार हैं, जिससे मिस्र की आर्थिक स्वतंत्रता की गिरावट में नाटकीय रूप से सुधार हो सकता है, जबकि समाज के भीतर पर्याप्त समूहों की आवाज बनकर यह परिवर्तन संभव हो सकता है। एक बार लक्षित नीति क्षेत्रों की पहचान करने के बाद ईसीपीपीएस ने अपने प्रस्तावों को ठोस रूप देने के लिए एक शोध योजना बनाई। प्रत्येक चार लक्ष्य क्षेत्रों के लिए शोध पत्रों में विशिष्ट आउटपुट शामिल किए गए।

चुनौती : भीड़ में अलग दिखना

सुधार की पहल का मुकाबला करना ईसीपीपीएस के प्रस्तावों के प्रभाव को खतरे में डाल सकता है। ऑडिट के समय, मिस्र पहले ही आईएमएफ के निर्देशन में आर्थिक सुधारों के दौर से गुजर रहा था। हालांकि, ईसीपीपीएस ने इसे प्रतियोगिता के बजाय उनके प्रभाव को बढ़ाने के एक अवसर के रूप में देखा। परिस्थितियों ने उसे प्रगति की समीक्षा करने और सरकार को अपने स्थानीय विशेषज्ञता के आधार पर ध्यान केंद्रित करने के उद्देश्य से सुधार के लिए क्षेत्रों का सुझाव देने की अनुमति दी। तब उसके विचारों को पूरक या मौजूदा सुधार के प्रयासों के लिए प्रशंसा के अतिरिक्त प्रयास के रूप में देखा जा सकता है।

वैयक्तिक रूप से ऑडिट कार्यशालाओं के लिए ईसीपीपीएस ने चिन्हित क्षेत्रों के प्रत्यक्ष संपर्कों वाले हितधारकों की पहचान की। तब उन्हें उन तक पहुंचने की जरूरत थी।

ईसीपीपीएस के पास पहले से ही संपर्कों का एक व्यवस्थित डेटाबेस था, जिसने उन्हें आमंत्रित करने के लिए प्राथमिक संपर्कों को जल्दी से पहचानने में मदद की। इसने उन्हें उन हितधारकों तक पहुंचने के लिए एक बहुस्तरीय आउटरीच योजना बनाने में समय बिताने से बचा लिया जिनके साथ उनकी पूर्व में सहभागिता नहीं थी। ईसीपीपीएस ने दूतावासों, मंत्रालयों, सरकारी निकायों, राजनीतिक दलों, सार्वजनिक हस्तियों और यहां तक कि विश्व बैंक और यूएसएआईडी जैसे कुछ अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को निमंत्रण भेजा।

उन्होंने आउटरीच गतिविधियों के लिए एक सोशल मीडिया अभियान भी लागू किया। उन्होंने उन विशिष्ट लोगों को, जिनको ऑडिट के लिए महत्वपूर्ण समझा, उनको फोन पर व्यक्तिगत रूप से निमंत्रित किया ।

चुनौती : सही लोगों को राज़ी करना

ईएफए की सफलता ईसीपीपीएस हितधारकों पर निर्भर थी जो लोगों को जोड़ने में सक्षम थे, क्योंकि वे सुधार को अभ्यास में लाने की शुरुआत कर चुके हैं। यह उन सबसे महत्वपूर्ण बाधाओं में से एक है, जिसपर थिंकटैंकों को विजय हासिल करना ही होगा। ईसीपीपीएस की सफलता का सीधा संबंध उस सॉफ्ट पावर और व्यक्तिगत कनेक्शन से था जो उनके संगठन के पास था। उन्होंने अपने समुदाय के भीतर कई सामाजिक हलकों के साथ कई वर्षों तक गुणवत्ता के काम और आउटरीच के आधार पर विश्वास बनाया था। इसलिए वे ईएफए में दूसरों को जोड़ने की बेहतर स्थिति में थे। हालांकि, व्यापक नेटवर्क और उनके साथ अपने मैत्रीपूर्ण संबंधों के बाद भी हितधारकों के कुछ वर्गों तक पहुंचने में कठिनाई थी, विशेष रूप से कुछ सरकारी एजेंसियों के प्रतिनिधियों तक। प्रत्येक लक्षित दर्शक तक पहुंचना कठिन था, लेकिन एक मजबूत आउटरीच योजना विकसित करके, ईसीपीपीएस ने अंतर्निहित आकस्मिकताओं को सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण और व्यापक प्रतिक्रिया एकत्र की थी।

ईएफए का प्रारंभिक सम्मेलन 30 जुलाई, 2018 को ज़मालेक के गोल्डन ट्यूलिप फ्लेमेंको होटल में आयोजित किया गया था। इसमें सभी लक्षित समूहों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। हितधारकों में योजना और बजट कमेटी से जुड़े एक संसद सदस्य, आर्थिक कमेटी से जुड़े एक संसद सदस्य, टेरस मिस्र फाउंडेशन फॉर डेवलेपमेंट के संस्थापक और अध्यक्ष, उप वित्तमंत्री, मिस्र के सीमा शुल्क प्राधिकरण के अधिकृत आर्थिक संचालन के केंद्रीय प्रशासन के प्रमुख और मिस्र के पेटेंट कार्यालय के प्रमुख शामिल थे। यह आयोजन विभिन्न मीडिया आउटलेट्स में भी कवर किया गया था, जो सुधार प्रस्तावों के साथ जनता तक पहुंचने में ईसीपीपीएस की प्राथमिकताओं में से एक था।

ईसीपीपीएस कर्मचारियों ने सम्मेलन के बाद ईएफए परिणामों की पहुंच को बढ़ाने के लिए एक संचार रणनीति तैयार की। आउटरीच योजना में नागरिक नेताओं के साथ बैठकें, जनता, सांसदों के साथ आमने-सामने की बैठकें और सांसद कर्मचारियों के लिए कार्यशालाएं शामिल हैं। सरकारी अधिकारियों के साथ बैठक विशेष रूप से चिन्हित क्षेत्रों में मिस्र की रैंकिंग, सुधार के गुण और सुधार के प्रस्तावित समाधानों पर केंद्रित रही। हालांकि सम्मेलन जुलाई, 2018 में आयोजित किया गया था लेकिन यह पहले से ही स्पष्ट है कि ईसीपीपीएस द्वारा सुधार किए गए उपायों के लिए उनमें एक भूख है।

ज़ूमिंग इन : अनुरूपित सामग्री के माध्यम से विश्वसनीयता बढ़ाना

मिस्र की असाधारण परिस्थितियों ने ईसीपीपीएस के ईएफए के लिए एक दिलचस्प चुनौती पेश की। देश के प्रतिस्पर्धा करने वाले गुटों के दृष्टिकोण और उनके लंबे इतिहास को देखते हुए, और प्रभावित करने के प्रयासों के बारे में हितधारकों की तीव्र संवेदनशीलता, ईसीपीपीएस ने जिन तरीकों से अपना संदेश दिया वह शायद संदेश से ज्यादा मायने रखता था।

मिस्र के लोग अपनी समस्याओं के निराकरण का वादा करने वाले किसी भी व्यक्ति के प्रति स्वाभाविक रूप से संशयी होते हैं, क्योंकि अक्सर इसका परिणाम विपरीत होता है। फिर भी वे दुविधा में हैं और बहुतायत नीतिगत विकल्पों का सामना कर रहे हैं। सुधार के लिए किसी भी प्रस्ताव को प्रस्तुत करते समय विश्वसनीयता को महत्व दिया जा रहा है। इसे पहले से जानते हुए, टीम ने समावेशी प्रस्तुतियों और विश्वसनीयता को बढ़ावा देने वाली प्रस्तुतियों पर विशेष रूप से ध्यान केंद्रित किया।

यह ईएफए सम्मेलन के परिचयात्मक सत्र के प्रारूप में स्पष्ट रूप से देखने को मिला। सत्र को तीन व्यक्तियों के बीच विभाजित किया गया था। ईसीपीपीएस के कार्यकारी निदेशक अहमद रगब, फ्रेजर इंस्टिट्यूट के फ्रेड मेकमहोन; और ईसीपीपीएस में आर्थिक अनुसंधान के प्रमुख अहमद अब्द अल-वहाब।

एक जाने-माने शोधकर्ता और विचारवान नेता रगब ने आयोजन के शुरुआत में मिस्र के समक्ष पेश आ रही आर्थिक मुश्किलों का जिक्र एक उदाहरण के तौर पर किया, जिसे दर्शक बहुत अच्छी तरह से जानते थे। इसमें अनौपचारिक क्षेत्र में बड़ी मात्रा में आर्थिक गतिविधि, भारी भरकम बजटीय घाटा, पूंजी सृजित करने में बाधाएं और मुद्रास्फीति शामिल थी। उन्होंने मिस्र के आर्थिक सुधारों की भी चर्चा की और कहा कि आईएमएफ के नेतृत्व में हो रहे आर्थिक सुधारों ने मिस्र को वापस पटरी पर लौटा दिया है। प्रारंभिक भाषण ने कार्यक्रम की विषयवस्तु को निर्धारित किया और उपस्थित लोगों के बीच साझा उद्देश्य और सामुदायिक भावना को बढ़ावा दिया।

मेकमहोन सत्र ने ईएफए का लक्ष्य प्रस्तुत किया : नीतिगत सुधारों की पहचान करना जो आर्थिक विकास, समृद्धि, और समावेशी राजनीतिक संस्थानों को बढ़ावा देंगे। उन्होंने बोत्सवाना, आयरलैंड, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया जैसे आर्थिक रूप से स्वतंत्र देशों के उदाहरण पेश किए जिससे कि मिस्रवासी समझें और अनुकरण करने के लिए आकर्षित हों। उन्होंने अपने दावों को पक्ष में और दर्शकों की विश्वसनीयता हासिल करने के उद्देश्य से अनुभवजन्य साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए फ्रेजर इंस्टीट्यूट के डेटा का उपयोग किया।

इसका अंतिम हिस्सा अब्द अल-वहाब के नेतृत्व में संचालित किया गया। इसमें सामान्य रूप से ईएफए और दर्शकों के लिए अगले सत्र का एक रोडमैप प्रस्तुत किया गया। उन्होंने सुधारों के लिए लक्षित चार नीति क्षेत्रों को पेश किया। ईसीपीपीएस के मुख्य आर्थिक शोधकर्ता के रूप में अपनी विशेषज्ञता का खाका पेश करते हुए उन्होंने आगे अपनी रणनीति का खुलासा किया और नीतियों के प्रति विश्वास जाहिर किया। उन्होंने बताया कि ईसीपीपीएस शोध करेगा, हितधारकों और नेताओं के साथ बातचीत की एक श्रृंखला की मेजबानी करेगा। उन्होंने बताया कि नीति सिफारिशों को बढ़ावा दिया जाएगा। इससे यह संदेश गया कि जिन सुधारों की बात की जा रही है वह स्थानीय स्वामित्व के तहत की जा रही है।

प्रत्येक प्रस्तोता ने एक विशेष शक्ति का खुलासा किया, जिसने कार्यक्रम की विश्वसनीयता को बढ़ा दिया। जबकि प्रस्तुत कॉन्सर्ट की सहायता से बाहरियों के प्रभाव विरोधी मानसिकता को दूर करने का प्रयास किया गया।

ईएफए में उद्घाटन सम्मेलन एक महत्वपूर्ण बिंदु होता है क्योंकि यह सबको विचार के एक समान बिंदु पर लाने का सबसे अच्छा मौका होता है और यह करतब पूरे प्रोजेक्ट के दौरान लाभ पहुंचा सकती है। वहां मौजूद लोग विभिन्न पृष्ठभूमि, कौशल और ज्ञान के साथ पहुंचते हैं। ईएफए का प्रभाव बढ़ाने के लिए, ईसीपीपीएस ने विभिन्न तरह की जानकारियों से लैस प्रतिभागियों को इस तरह से संबोधित किया, जिससे अधिक प्रभावी और कुशल चर्चा हुई। उनकी रणनीति में निम्नलिखित चीजें शामिल हैं : -

- समुदाय की साझा भावना स्थापित करना
- लक्ष्य को प्रस्तुत करना और सहयोग प्राप्त करना
- समाधान में दर्शकों को शामिल करना

महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि

ईसीपीपीएस के लिए एक समान लक्ष्य के प्रति असमान हितों को एकजुट करना एक अनूठी चुनौती थी। उनके उतार-चढ़ाव भरे इतिहास के कारण, मिस्र के तमाम लोग सुधार के आह्वान के प्रति संशय में रहते हैं। और फिर भी, वही लोग अन्य राष्ट्रों की संपन्नता को देखते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल होने और अपनी क्षमता का अहसास करने की इच्छा रखते हैं। यह मजबूत नीति विचारों को स्पष्ट रूप से अपनाने और विश्वसनीयता के साथ अपनाने के लिए एक छोटा-सा अवसर प्रस्तुत करती है।

ईसीपीपीएस ने पूरे ईएफए प्रोजेक्ट में सांस्कृतिक तनाव को आंतरिक कर दिया। यह सामान्य ज्ञान पर आधारित था कि नीति में परिवर्तन आसन्न है और जनता और

जनप्रतिनिधियों ने मीडिया की सुर्खियों में जो देखा तो उससे उनकी पूर्व धारणाएं और मजबूत हो गईं। फिर इसने बाकी प्रतिभागियों को समाधान में भाग लेने का माध्यम प्रदान किया। विश्वसनीय डाटा और मीडिया हेड लाइन की सहायता से ईसीपीपीएस ने स्पष्ट रूप से परिभाषित नीति सुधार प्रस्तावों को प्रस्तुत करके अपने आपको एक कर्मठ, विश्वसनीय और तत्पर एक जन समर्थक के रूप में स्थापित कर लिया है। यह प्रस्ताव जनसाधारण के रोजमर्रा के संघर्षों को प्रतिबिंबित करता है।

एक सफल ऑडिट से गंभीर नीतिगत बदलाव और वैचारिक बदलाव हो सकते हैं, इसलिए ईएफए की सफलता सुनिश्चित करने वाले कारकों को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है। ईसीपीपीएस के अनुभव से, कई महत्वपूर्ण सबक मिलते हैं।

सबसे पहले, ईसीपीपीएस ने अपने देश की गंभीर आर्थिक स्थिति को पहचाना। यदि आर्थिक स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का कोई समय है, तो यही है। महत्वपूर्ण यह है कि वर्तमान में सुझावों के लिए सहानुभूतिपूर्ण सुनवाई हो सकती हैं। इसमें उच्च स्तर के सरकारी कर्मचारियों में से कई लोगों की भागीदारी अनुकरणीय है। दूसरा, ईसीपीपीएस ने मिस्र के इन नेताओं तक पहुंचने के लिए अपने नेटवर्क के अनुभव का उपयोग किया। तीसरा, ईसीपीपीएस ने एक कुशल, सूचित वातावरण बनाने के लिए अपने परिचयात्मक सम्मेलन का उपयोग किया - जो एक ईपीएफए की सफलता के लिए महत्वपूर्ण है।

हालांकि, वर्तमान में ईएफए चल रहा है। ईसीपीपीएस का ऑडिट मिस्र में ठोस जमीनी स्तर पर कार्य करने में अधिक स्थिरता और ठोस बदलाव ला सकता है। ईसीपीपएस की योजना ईएफए का उपयोग वर्तमान सुधारों की जांच करने के लिए है, जबकि नए प्रस्ताव भी हैं। माहौल तैयार है बस कार्रवाई बाकी है।

सवालों पर परिचर्चा

- अपने सामाजिक नेटवर्क से बाहर संपर्क से आउटरीच बढ़ाने में ईसीपीपीएस कैसे सक्षम हुआ?
- आपके संगठन का सामना किस प्राकृतिक स्वरूप या ऐतिहासिक जड़ता से होता है?
- अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं आर्थिक स्वतंत्रता का समर्थन करने वाली नीतियों को आगे बढ़ाने में कैसे मदद या बाधा डाल सकती हैं?
- आपके देश में कौन से सांस्कृतिक तनाव हैं जो नीतिगत प्रस्तावों को प्रभावित करते हैं या आगे कर सकते है? ये तनाव कैसे शिफ्ट हो सकते हैं? आप उनसे कैसे बचते हैं और उनके जरिए कैसे काम कर सकते हैं?

- किसी विशिष्ट कार्यक्रम या संगठन के मिशन के साथ एक विशिष्ट आयु जनसांख्यिकीय को लक्षित करने के क्या फायदे (और नुकसान) हैं?
- आपके देश में सामाजिक परिवर्तन कैसे होता है? परिवर्तन के उन चैनलों का संचालन करने के लिए आपके कार्यक्रम कैसे सुसज्जित हैं? आप इसे करने में किस तरह असहाय हैं?
- राजनैतिक रूप से संभव परिवर्तनों को लाने के लिए आपके संगठन ने किस प्रकार अपनी क्षमताओं में वृद्धि की है? आपने उस प्रक्रिया से क्या सीखा है? आपने संगठन में सीखे गए पाठों को कैसे आत्मसात किया है?

इस पुस्तक का उपयोग कैसे करें

थिंकटैंक की टीमों के लिए मार्गदर्शन

इस प्रकाशन का प्राथमिक उद्देश्य हमारे नेटवर्क के थिंकटैंक सहयोगियों के बीच प्रभावशाली परियोजनाओं की जानकारी पहुंचाना है। हालांकि, एटलस नेटवर्क थिंकटैंक को सुझाव देता है कि वे इन परियोजनाओं को गुण दोष को वगैर परखे दोहराने की कोशिश न करें। बल्कि, इस खंड में प्रस्तुत विषय अवलोकन का उपयोग दिलचस्प चर्चाओं को थिंकटैंक टीमों के बीच तेज करने के लिए किया जाना चाहिए ताकि बदलाव के संबंध में वे अपना दर्शन विकसित कर सकें। प्रत्येक विषयावलोकन के लिए, परिचर्चा में शामिल प्रश्न सुझाए गए हैं जो विमर्शों को निर्देशित करने में मदद कर सकते हैं। इस प्रकार, विषयावलोकन हमें मुख्य रूप से महत्वाकांक्षी और रचनात्मक सोच के लिए एक साझा महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु प्रदान करते हैं।

साथ ही सामान्य बातों के दोहराव से बचने के कई अवसर हैं, और हमने यह पाया है कि अधिकांश थिंकटैंक सहयोगी अन्य संगठनों के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं, जो उसी तरह का कार्य करने में रुचि दिखाते हैं और जो मूल परियोजनाओं के कुछ पहलुओं की प्रतिकृति बनाना चाहते हैं। बेशक, किसी भी पाठक को संवाद करने के लिए उसके इरादे सुनिश्चित होने चाहिए और जहां भी उपयुक्त हो, विषय से अनुमति लेना चाहिए।

नीचे केवल एक सुझाव दिया गया है जो संलग्न मामले का उपयोग करने में रुचि रखने वाली टीमों के अध्ययन के लिए विचार विमर्श के अभ्यास के लिए है।

पहला चरण : अपनी पूरी टीम को पढ़ने के लिए एक से तीन केस स्टडीज की पहचान करें, और निर्धारित समय में पूरा करने के लिए रीडिंग असाइन करें। ध्यान दें इस पुस्तक की सभी केस स्टडी AtlasNetwork.org/training पर उपलब्ध हैं इसे अलग से डाउनलोड कर सकते हैं।

दूसरा चरण : एक या दो विशिष्ट संगठनात्मक प्राथमिकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार मंथन का सत्र निर्धारित करें और अपनी टीम के साथ साझा करें। उदाहरण के लिए, हो सकता है आपका संगठन व्यापार के विषय पर एक नई अनुसंधान परियोजना बना रहा

हो। उनसे कहिए कि वे सौंपी गई केस स्टडी का अध्ययन करें और प्रोजेक्ट, प्रोजेक्ट के लक्ष्य के बारे में विचार करें।

तीसरा चरण : जब आप बुलाते हैं, तो तय करें कि आपकी टिप्पणियों को कौन नोट करने जा रहा है। फिर, मंथन के लिए कुछ जमीनी नियम स्थापित करें और लेखक को कहें कि ऐसी जगह पर लिखे जहां से सबको दिखाई पड़े। कुछ सामान्य नियम शामिल हैं :-

- एक बार में एक व्यक्ति ही बोले।
- बहुत अधिक और बहुत कम न बोले। प्रत्येक व्यक्ति को अपने विचारों का योगदान देना चाहिए जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि सभी विचारों को शामिल किया गया है।
- इस अवस्था में कभी भी एक-दूसरे से असहमति में समय न गवाएं। मंथन का उद्देश्य जितना संभव हो सके, अलग-अलग तरह के विचारों को धरातल पर लाना है। यदि आप एक-दूसरे की टिप्पणियों का जवाब देने में समय खर्च करते हैं, तो इससे समय नष्ट होगा। इससे खुलापन और ईमानदारी हतोत्साहित हो सकती है।
- मंथन के दौरान अगर वे चाहते हैं तो अतिरिक्त ज़मीनी नियमों के बारे में सुझाव देने के लिए टीम को आमंत्रित करें।

चौथा चरण : संदर्भ अध्ययन के रूप में केस स्टडी का उपयोग करने के लिए समूह के लिए कम से कम तीन खुले प्रश्नों (ओपेन एंडेड) को चिन्हित कीजिए और केस स्टडीज को संदर्भ पाठ बनाकर उत्तर देने के लिए कहिये। समूह के आकार के आधार पर तीन या चार टीमें बनाएं, और फिर 20-30 मिनट के बाद बड़े समूह में वापस रिपोर्ट करें। कुछ नमूना प्रश्न निम्नलिखित हैं :-

- विचार मंथन से पूर्व हम केस स्टडीज को पढ़ेंगे और अगले प्रोजेक्ट के लिए उपयोगी जानकारियां जुटाएंगे जो हम अपनी आगामी परियोजना पर लागू कर सकते हैं?
- सफलता के अपने अवसरों को बढ़ाने के लिए हमें क्या अलग से करना चाहिए, जिससे हमारी आगामी परियोजना की सफलता के मौके बढ़ जाएं?
- हमारे स्थानीय संदर्भ के कुछ अनूठे पहलू क्या हैं जिनकी हमारी योजना में हिस्सेदारी की आवश्यकता होगी?
- एक संगठन के रूप में हम क्या अच्छा कर रहे हैं जिसके संरक्षण और/या पालन-पोषण का हमें ध्यान रखना चाहिए?
- कुछ चुनौतियां क्या हैं, अगर हम उन पर काबू पा सकें, जो हमारे संगठन को अगले स्तर की सफलता तक ले जाने में सहायता देगा?

पांचवां चरण : संक्षेप में विवरण प्रदान कीजिए और प्राप्त फीडबैक की समीक्षा कीजिए। सुनिश्चित कीजिए की टीम ने जो भी कुछ गलत समझा है या छोड़ दिया है वे सारी चीजें स्पष्ट हों।

छठा चरण : अंत में, चर्चा करें कि अगले चरण में क्या कुछ विशिष्ट हो सकते हैं। कई बार यह विचार मंथन के दौरान किए गए किसी भी अपरिवर्तनीय निर्णय का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, लेकिन आगे की चर्चा करता है जैसे कि

- आगामी परियोजना की विप्णन नीति तैयार करने के लिए अनुसंधान और संचार टीमें सप्ताह में एक बार अवश्य मिलें।
- बैठक के दौरान उठने वाले एक या दो प्रमुख सवालों पर बोर्ड के प्रमुख सदस्यों से उनके इनपुट का आग्रह किया जाए।
- आगामी परियोजना के लिए महत्वपूर्ण कौशल की आपूर्ति करने के लिए नेतृत्व एक नई भर्ती या ठेकेदार पर विचार करने जा रहा है।

इस तरह के अभ्यासों के लिए, नेतृत्व को टीम के सदस्यों के इनपुट में वास्तविक रुचि प्रदर्शित करनी चाहिए। यह पहचानते हुए कि 'लोग अपनी बनाई हुई चीजों का समर्थन करते हैं।' अंतिम निर्णय लेने का अधिकार को संरक्षित कर इस दृष्टिकोण को एक नेता की इच्छा के साथ हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है। इस कारण, यह सुझाव दिया जाता है कि विचार मंथन बैठकों में यह अपेक्षा न की जाए कि उस दौरान बड़े फैसले किए जाएंगे बल्कि इसके बजाय कि इनपुट का उपयोग उन निर्णयों को उचित और जब संभव हो सूचित करने के लिए किया जाएगा। अधिकांश टीमें समझती हैं कि हर दृष्टिकोण को समायोजित नहीं किया जा सकता है, लेकिन नेतृत्व की ओर से एक वास्तविक इच्छा उन विचारों से अवगत होने के लिए प्रामाणिक रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह एक उत्पादक तरीका है कि संगठन में सभी ज्ञान महत्वपूर्ण निर्णयों को स्वीकार करने के लिए लाए जा रहे हैं।

एटलस नेटवर्क के बारे में

उद्देश्य

एटलस नेटवर्क स्वतंत्र नागरिक संगठनों के एक वैश्विक नेटवर्क को मजबूत करके अवसर और संपन्नता को बढ़ावा देता है जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता को बढ़ावा देते हैं और मानवता समृद्धि की राह में आने वाली बाधाओं को दूर करते हैं।

व्यापक रणनीति

एटलस नेटवर्क भागीदारों का एक नेटवर्क विकसित करता है जो एक मुक्त, समृद्ध और शांतिपूर्ण दुनिया का दृष्टिकोण साझा करते हैं जहां कानून, निजी संपत्ति और मुक्त बाजारों का सरकारों द्वारा बचाव किया जाता है और जिनकी शक्तियां सीमित हैं। अपने भागीदारों की उनके स्थानीय समुदायों के बीच उपलब्धि की गति में तेजी लाने के लिए, एटलस नेटवर्क अपने कोच, कम्पीट, सेलिब्रेट वाले रणनीतिक मॉडल के तहत कार्यक्रमों को लागू करता है।

- **कोच :** एटलस नेटवर्क व्यावसायिकता को प्रेरित करने और अपने स्वतंत्र भागीदारों के बीच प्रदर्शन में सुधार करने के लिए विश्वस्तरीय प्रशिक्षण और सलाह देता है।
- **प्रतिस्पर्धा :** एटलस नेटवर्क अनुदान और पुरस्कार प्रतियोगिताओं की पेशकश करता है जो असाधारण परिणामों को प्राप्त करने के लिए उसके भागीदारों के प्रयासों को प्रोत्साहित करता है।
- **उत्सव मनाना :** एटलस नेटवर्क अपने आयोजनों और मीडिया आउटरीच के माध्यम से सहयोगियों की सबसे बड़ी उपलब्धियों का जश्न मनाते हुए उनके बीच भाईचारे और महत्वाकांक्षा को बढ़ावा देता है।

अलग तरह से विकास करने के बारे में

एटलस नेटवर्क तमाम दूसरे अन्य विद्वानों, पेशेवरों और कार्यकर्ताओं को जोड़ता है जो विकास को अलग तरीके से शुरू करने के आंदोलन का समर्थन करते हैं। अपनी तरफ से, हम आर्थिक स्वतंत्रता में वृद्धि के लिए प्रतिबद्धता के संयोजन की अपनी अनूठी रणनीति की पेशकश करते हैं और परिवर्तन के स्थानीय दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। अपने 485

स्थानीय थिंकटैकों के नेटवर्क का उपयोग कर, हम कम आय वाली जनसंख्या को अपने प्रोजेक्ट की जरिए सहयोग कर उनके लिए आर्थिक अवसरों को बढ़ाने का लक्ष्य रखते हैं ताकि महत्वपूर्ण सरकारी संस्थानों-संपत्ति के अधिकार, कानून का शासन और मुक्त बाजार को मजबूत किया जा सके और उन संस्थागत अवरोधों को हटा सकें जो गरीबों की सफलता की राह में मुश्किलें खड़ी करते हैं।

अधिक जानकारी के लिए AtlasNetwork.org/Difference को देखिए।

प्रकाशन टीम के बारे में

मैट वार्नर एटलस नेटवर्क के अध्यक्ष हैं। सीईओ के निर्देशन में, वह रणनीति, प्रोग्रामिंग और कार्मिक प्रबंधन के लिए जिम्मेदार हैं। मैट एक शोध एजेंडा के विकास का भी नेतृत्व करते हैं जो आगे दुनियाभर में आजादी हासिल करने में थिंक टैंकों की अमूल्य भूमिका को प्रदर्शित करता है। मैट अर्थशास्त्र, संस्था निर्माण, गैर-लाभकारी प्रबंधन, माप, और प्रभाव लोकोपकार के विषयों पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लिखते, बोलते और परामर्श देते हैं।

मैट ने 'वाह्य घटकों की दुविधा' शब्द की रचना की है, जो कि कम आय वाले देशों को विकास करने में सहायता करने की राह मे आने वाली चुनौतियों की व्याख्या करता है। उनके लेख केटो जर्नल, फोर्ब्स, हार्वर्ड के एजुकेशन नेक्स्ट, रियल क्लियर मार्केट्स, फ़ाउंडेशन फ़ॉर इकोनॉमिक एजुकेशन, एकॉनटॉक और वॉशिंगटन टाइम्स व अन्य में प्रकाशित होते हैं। 2010 में एटलस नेटवर्क में शामिल होने से पहले, मैट ने गैर-लाभकारी थिंकटैंकों में ऊर्जा, शिक्षा और संपत्ति के अधिकारों पर ध्यान केंद्रित करने के लिए विभिन्न नीतिगत नेतृत्वकारी पदों पर कार्य किया।

मैट के पास जॉर्ज मेसन विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री हैं और संगठनात्मक विकास परामर्श में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय द्वारा प्रमाणित है। वह अमेरिकन एंटरप्राइज इंस्टीट्यूट के लीडरशिप नेटवर्क के सदस्य भी हैं और नेशनल एंडोमेंट फॉर डेमोक्रेसी के पेन कम्बेल फेलो और अमेरिका के फ्यूचर फाउंडेशन के 2019 बकले अवार्ड से सम्मानित हैं। मैट अपनी वकील पत्नी क्रिसी और अपने चार बच्चों के साथ वियेना, वर्जीनिया में रहते हैं।

केसी पिफर एटलस नेटवर्क में संस्थान संबंधों की निदेशक हैं। वह एटलस नेटवर्क के अनुदान और पुरस्कार कार्यक्रमों का प्रबंधन करती है, जिसमें प्रतिष्ठित टेम्पलटन फ्रीडम अवार्ड भी शामिल है। मूल रूप से वेस्ट वर्जीनिया की रहने वाली केसी 2014 में एटलस नेटवर्क में इवेंट टीम में शामिल हुई थीं, लेकिन बाद में वह इस पद को सुशोभित कर रही हैं। वह पश्चिमी वर्जीनिया में पली बढ़ीं और पश्चिमी वर्जीनिया विश्वविद्यालय से अर्थशास्त्र और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की।

मेलिसा मान 2018 में पार्टनरशिप के निदेशक के रूप में एटलस नेटवर्क में शामिल हुईं और 2019 में संचार की उपाध्यक्ष बनीं। एटलस नेटवर्क में शामिल होने से पहले, मेलिसा ने रीज़न फाउंडेशन में डायरेक्टर आफ डेवलपमेंट के तौर पर सत्रह साल बिताए। रीजन फाउंडेशन एक सार्वजनिक नीति और मीडिया संगठन है जो उदारवादी सिद्धांतों को प्रोत्साहित कर, लागू कर और विकसित कर एक अत्याधुनिक मुक्त समाज का विकास करता है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, मुक्त बाजार और कानून के शासन का प्रचार करता है। वह एटलस नेटवर्क के थिंकटैंक एमबीए प्रोग्राम में 2016 की स्नातक हैं।

मेलिसा ने लॉस एंजेलिस के ऑक्सीडेंटल कॉलेज से डिप्लोमेसी और वर्ल्ड अफेयर्स में स्नातक की डिग्री प्राप्त की और सारब्रुकेन और राईनिस्के-फ्रेडरिक-विल्हेल्म्स-यूनिवर्सिटी बॉन में यूनिवर्सिटेट डेस सारलैंड्स में सार्वजनिक नीति और कानून में स्नातक किया, दोनों तब पश्चिम जर्मनी में थे। लॉस एंजिल्स में अपने घर में, मेलिसा अपना खाली समय स्वतंत्रता-विषयक नॉनफिक्शन पढ़ने में बिताती हैं; विज्ञापनों के लिए वॉयसओवर, वीडियोगेम और टेलीफोन आंसरिंग सिस्टम के साथ बिताती हैं; और घर के पिछवाड़े चारों ओर घूमते मोरों का पीछा करके समय व्यतीत करती हैं।

एजे सिएरा एटलस नेटवर्क में 2016 में शामिल हुए थे। उन्होंने प्राग में चार्ल्स विश्वविद्यालय में विदेश में एक सेमेस्टर पढ़ने के बाद मियामी (एफएल) विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, जहां से उन्होंने सुम्मा कम लाड के साथ इतिहास और राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री ली। विप्पणन और संचार के एसोसिएट निदेशक के रूप में अपनी भूमिका में, वह ईमेल, वेब, प्रिंट, वीडियो और सोशल मीडिया प्लेटफार्मों पर एटलस नेटवर्क की सामग्री रणनीति को तैयार करने और उसे सुविधाजनक बनाने में मदद करते हैं।

ए.जे. एटलस नेटवर्क की फोटोजर्नलिज्म और फिल्म प्रोजेक्ट के लिए अपनी 'डूइंग डेवलेपमेंट डिफरेंटली' प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं, जो लैटिन अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और यूरोप में एटलस नेटवर्क के सबसे प्रभावी भागीदारों द्वारा सफलतापूर्वक मुक्त बाजार सुधारों के डाउनस्ट्रीम लाभार्थियों के व्यक्तित्व की वास्तविक कहानियां पेश करती हैं। वह चार्ल्स कोच इंस्टीट्यूट के साथ तीन पेशेवर विकास कार्यक्रमों में स्नातक और कांग्रेसमैन रैंडी हॉल्टग्रेन (आईएल-14) के लिए काम करने वाले इलिनोइस स्टेट सोसायटी छात्रवृत्ति के प्राप्तकर्ता हैं। वह मूल रूप से शिकागो के उत्तर-पश्चिमी उपनगर के रहने वाले हैं और वर्तमान में एर्लिंटग्टन वर्जीनिया में रहते हैं।

अधिक जानें

Books

Why Nations Fail,
Daron Acemoglu and James Robinson

Building State Capability,
Matt Andrews, Lant Pritchett,
Michael Woolcock

The Origin of Wealth, Erick Beinhocker

Doing Bad by Doing Good, Chris Coyne

The Great Escape, Angus Deaton

Tyranny of Experts, William Easterly

How Change Happens, Duncan Green

The Atlas of Economic Complexity,
Richard Hausmann

Navigation by Judgment, Dan Honig

The Alternative, Mauricio Miller

Dead Aid, Dambisa Moyo

The idealist, Nina Munk

The Bright Continent, Dayo Olopade

The Power of Positive Deviance,
Richard Pascale, Jerry Sternin,
Monique Sternin

Aid on the Edge of
Chaos, Ben Ramalingam

Development and Freedom, Amartya Sen

Why We Lie About Aid, Pablo Yanguas

Videos

Stories of Impact
PovertyandFreedom.org

Made in Mékhé
FEE.org

Poverty, Inc.
PovertyInc.org

Resources

Global
Directory of Think Tanks
AtlasNetwork.org/Directory

Case Studies Online
AtlasNetwork.
org/ Case-studies

Events

AtlasNetwork.org/Events

" गरीबी उन्मूलन के लिए किये जाने वाले प्रयासों में गरीबों को वह सबकुछ दे देना शामिल है जो उनके पास नहीं है, मसलन पैसा या भोजन। दूसरा दृष्टिकोण, उन बाधाओं को दूर करना है जो गरीबों को स्वावलंबी होकर फलने-फूलने से रोकती है। यह पुस्तक उन बाधाओं को दूर करने में थिंक टैंक्स की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में बताती है।"

— रॉस रॉबर्ट्स, हूवर इंस्टीट्यूशन, स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, एकॉनटॉक

क्या होता है जब अर्जेंटीना में लैपटॉप पर से टैरिफ हटा दिया जाता है?
क्या होता है जब भारत में स्ट्रीट वेंडर्स को रोजगार का कानूनी हक दिया जाता है?
क्या होता है जब संयुक्त राज्य अमेरिका में पुलिस का मौके पर नकदी जब्त करने का अधिकार समाप्त कर दिया जाता है?

अपनी निर्धनता का समाधान स्वयं ढूंढने वाले सफल होने लगते हैं।

दरअसल, गरीबी उन्मूलन के परंपरागत दृष्टिकोण में बदलाव की जरूरत है। अब तक समृद्ध और शिक्षित इलाकों में रहने वाले लोग निर्धन इलाकों के गरीब लोगों की समस्या दूर करने की कोशिश करते रहे हैं। यही वजह है कि गरीबी की समस्या का कारगर समाधान नहीं हो सका है। सही मायनों में गरीबी का वास्तविक समाधान स्थानीय व्यक्ति या समुदाय की भागीदारी से ही संभव है, न कि बाहरी लोगों के द्वारा। हमें उनके नेतृत्व के अनुगमन की जरूरत है।

'निर्धनता और आज़ादी' पुस्तक दर्शाती है कि दुनिया के तमाम देशों में हम में से जो भी इस दुनिया को बेहतर बनाना चाहते हैं, उन्हें स्थानीय प्रयासों के जरिये, स्थानीय लोगों द्वारा उनकी स्वतंत्रता को सीमित करने वाली संस्थागत बाधाओं को दूर करने के विकल्प चुनने का समर्थन करना चाहिए। यह पुस्तक विषय अवलोकन के जरिये स्थानीय थिंक टैंक्स के उन प्रेरक कार्यों प्रदर्शित करती है जो विश्व की असुरक्षित आबादी की स्वतंत्रता का विस्तार करते हैं।

संपादक के बारे में

पुस्तक के संपादक मैट वार्नर एक गैर-लाभकारी संगठन एटलस नेटवर्क के अध्यक्ष हैं। यह संस्था दुनियाभर में स्वतंत्रता और आर्थिक अवसरों को विस्तार देने के लिए प्रतिबद्ध है। बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी मैट वार्नर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अर्थशास्त्र, संस्था निर्माण, गैर-लाभकारी प्रबंधन, मूल्यांकन और परोपकारिता के प्रभाव आदि विषयों पर लेखन, संभाषण और परामर्श देते हैं।
समृद्धि के स्थानीय और स्वभाविक तौर तरीकों को प्रभावित किये बिना निम्न आय वाले देशों की सहायता करने की राह में आने वाली चुनौतियों की व्याख्या मैट ने 'बाहरियों की दुविधा' (द आऊटसाइडर्स डिलेमा) शब्द गढ़कर की है। उन्होंने जॉर्ज मेसन यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र में मास्टर डिग्री तथा संगठनात्मक विकास में जॉर्जटाउन विश्वविद्यालय से प्रमाणपत्र हासिल किया है। वे नेशनल एंडॉमेंट फॉर डेमोक्रेसी में पेन कम्बेल फेलो हैं और अमेरिका फ्यूचर फाउंडेशन के बकले अवार्ड से सम्मानित हैं।

आवरण चित्र : बर्नट परेरा
आवरण सज्जा : दि किलस्विच कलेक्टिव

ATLAS NETWORK